ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

जुलाई 2024
वर्ष : 06 | अंक : 09
मूल्य : ₹140

dhyeyaias.com

सपनों की जीत: विश्व कप फिर से भारत में

» मुख्य विशेषताएं

राज्य समाचार
ब्रेन बूस्टर
पॉवर पैक्ड न्यूज
वन लाइनर
यूपीएससी प्री मॉक पेपर

» विशेष

मेंस स्पेशल

» इतिहास, कला एवं संस्कृति

मेंस मॉडल आंसर

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

लक्ष्यभेद

Offline & Online

"The more we sweat in peace, the less we bleed in war"

ALL INDIA CIVIL SERVICES EXAMINATION (PRELIMS) TEST-SERIES 2025

Starting From

4th August 2024

TOTAL TESTS : 40

- Unit-1: 15 Sectional Tests
- Unit-2: 10 Full Length Tests
- Unit-3: 10 Current Affairs Tests
- Unit-4: 5 CSAT Tests

For More Information
SCAN ME

★ **Students can also take Admission in any unit Separately (Every Unit has Different Fee Structure).**

- **Doubt Clearing Session through webinar on Google Meet.**
- **One to One Interaction & Personal Mentorship to Aspirants.**
- **6 Month Subscription of Perfect-7 Current Affairs Monthly Magazine.**
- **Supplementary Material through Telegram Channel.**
- **Test Result within a week (with All India Ranking).**

OFFLINE CENTRES

Delhi (Mukherjee Nagar) Ph: 9289580074 / 75 | Delhi (Laxmi Nagar) Ph: 9205212500 / 9205962002 | Greater Noida Ph: 9205336037/ 38 | **Varanasi Ph: 7408098888** | Prayagraj Ph: 0532-2260189/8853467068 | Lucknow (Aliganj) Ph: 0522-4025825/9506256789 | Lucknow (Gomti Nagar) Ph: 7234000501/ 7234000502 | Lucknow (Alambagh) Ph: 7518373333/7518573333 | Kanpur Ph: 7887003962/7897003962 | Gorakhpur Ph: 0551-2200385/7080847474

पहला पन्ना

एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास असीमित ज्ञान हो, बल्कि उसमें सही मात्रा का ज्ञान और उस ज्ञान का उचित निष्पादन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सार सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी सही अभिव्यक्ति और किसी भी स्थिति में उसका सही क्रियान्वयन है। यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से लेकर देश के महत्त्वपूर्ण मुद्दे सँभालने तक, कुछ भी हो सकती है। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण तो जरूर है परंतु सार्थक है।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं में चयनित सिविल सेवकों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न अंग रही है। यह पत्रिका खुद भी, बदलते पाठ्यक्रम के साथ ही बदलावों और सुधारों के निरंतर उतार चढ़ाव से गुजरी है।

अब, यह पत्रिका आपके समक्ष मासिक स्वरूप में प्रस्तुत है, मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की इस रोमांचक यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

टीम परफेक्ट 7

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध निदेशक	:	क्यू. एच. खान
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	विवेक ओझा
सह-संपादक	:	आशुतोष मिश्र
उप-संपादक	:	भानू प्रताप
	:	ऋषिका तिवारी
डिजाइनिंग	:	अरूण मिश्र
आवरण सज्जा	:	सोनल तिवारी

-: For any feedback Contact us :-
+91 9369227134
perfect7magazine@gmail.com

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य

Yearly Subscription

Price	Issue	Total	After Discount
140	12	1680	1200

Half Yearly Subscription

Price	Issue	Total	After Discount
140	6	840	600

*Postal charges exta

OFFLINE CENTRE

Delhi (Mukherjee Nagar) Ph: 9289580074 / 75 | Delhi (Laxmi Nagar) Ph: 9205212500 / 9205962002 | Greater Noida Ph: 9205336037 / 38 | Prayagraj Ph: 0532-2260189/8853467068 | Lucknow (Aliganj) Ph: 0522-4025825/9506256789 | Lucknow (Gomti Nagar) Ph: 7234000501/ 7234000502 | Lucknow (Alambagh) Ph: 7518373333/7518573333 | Kanpur Ph: 7887003962/7897003962 | Gorakhpur Ph: 0551-2200385/7080847474 Varanasi Ph: 7408098888, 9838529010

ध्येय IAS
most trusted since 2003

परफेक्ट

मासिक समसामायिकी पत्रिका

इस अंक में ...

1. राष्ट्रीय 06-17

- ☑ औपनिवेशिक कानूनों की जगह लाए गए नए आपराधिक कानूनों के मायने
- ☑ वैधानिक जमानत का प्रावधान
- ☑ अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) की नई पहल
- ☑ नोटा के पक्ष में ज्यादा मतदान
- ☑ आरटीआई अधिनियम
- ☑ लिविंग विल
- ☑ केंद्र में नई सरकार का गठन
- ☑ एकीकृत साइबरस्पेस सिद्धांत
- ☑ केरल प्रवासन सर्वे
- ☑ नेता प्रतिपक्ष का चयन
- ☑ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी
- ☑ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024
- ☑ डाकघर अधिनियम 2023

2. अन्तर्राष्ट्रीय 18-30

- ☑ सागर विजन और इंडो पैसिफिक रणनीति को धार देती नवनियुक्त भारत सरकार
- ☑ जापान का सुरक्षा विमर्श
- ☑ बायोफार्मास्युटिकल एलायंस
- ☑ पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन और भारत की सहायता
- ☑ ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक
- ☑ कफाला प्रणाली के अंतर्गत श्रमिक
- ☑ जिग-जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण मुद्रा
- ☑ जी7 शिखर सम्मेलन
- ☑ परमाणु शस्त्रागार पर सिपरी (SIPRI) रिपोर्ट का प्रकाशन
- ☑ भारत और कंबोडिया संयुक्त कार्य समूह बैठक
- ☑ भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी बैठक
- ☑ उभरती हुई महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की बैठक
- ☑ भारत-कतर निवेश व व्यापार संबंध
- ☑ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का भारत दौरा

3. पर्यावरण 31-43

- ☑ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्टः पर्यावरण बनाम विकास का मुद्दा
- ☑ जलाशयों के जल भंडारण स्तर में कमीः केंद्रीय जल आयोग
- ☑ वायु प्रदूषण और असामयिक मृत्यु में संबंध
- ☑ प्रेजवाल्स्की घोड़े
- ☑ बिहार के दो वेटलैंड्स रामसर सूची में शामिल
- ☑ वैश्विक मृदा भागीदारी
- ☑ जलवायु वित्त पर ओइसीडी रिपोर्ट
- ☑ विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति 2024
- ☑ उथला जलभृत प्रबंधन
- ☑ बायेसियन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (BCNN)
- ☑ स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर (सोगा) रिपोर्ट
- ☑ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) पर अध्ययन
- ☑ ATCM-46 और CEP-26
- ☑ नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का वैश्विक मूल्यांकन
- ☑ गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीता पुनरूत्पादन परियोजना

4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 44-54

- ☑ डीप सी मिशन से भारत की स्वदेशी क्षमता का होगा विस्तार
- ☑ तृष्णा मिशन
- ☑ प्रीफायर मिशन

- ☑ वायरल संक्रमणों का पता लगाने के लिए नया प्रकाश-आधारित उपकरण
- ☑ निडोवायरस
- ☑ स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम
- ☑ H5N2 बर्ड फ्लू
- ☑ मेथनॉल विषाक्तता
- ☑ अग्निबाण सबऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर (SOrTeD)
- ☑ रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस
- ☑ पोर्टेबल ऑप्टिकल परमाणु घड़ियाँ
- ☑ अर्थकेयर मिशन

5. आर्थिकी 55-65

- ☑ भारत में कॉरपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी का बढ़ता दायराः संभावनाएं और आयाम
- ☑ बाजरा पर आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24
- ☑ वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024
- ☑ उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23
- ☑ स्व-नियामक संगठनों के लिए आरबीआई का ढाँचा
- ☑ भारत का व्यापार घाटा
- ☑ लागत मुद्रास्फीति सूचकांक
- ☑ वैश्विक ऋण संकट
- ☑ भारत में अनौपचारिक श्रम बाजार
- ☑ विश्व निवेश रिपोर्ट 2024
- ☑ भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नई पहल
- ☑ GAAR पर फैसला
- ☑ बीमा कंपनियों के लिए नए कॉर्पोरेट प्रशासन नियम

6. विविध 66-77

- ☑ भारत में मानव अंगों के खरीद फरोख्त को रोकने के लिए सख्त केंद्र सरकार
- ☑ थाली से गायब पोषणः दुनिया में खाद्य निर्धनता और बच्चों की स्थिति
- ☑ पहाड़ी बच्चों में कुपोषण एवं नाटापन
- ☑ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025
- ☑ नाता प्रथा
- ☑ बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर संधि
- ☑ फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस
- ☑ रज पर्व
- ☑ वैश्विक विस्थापित जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की रिपोर्ट
- ☑ PAROS (बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकना)
- ☑ इंडिकोनेमा, एक नया डायटम जीनस
- ☑ नालंदा विश्वविद्यालय के नये परिसर का उद्घाटन
- ☑ राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान (NIIMH)

7. क्विक लर्न 78-150

ब्रेन बूस्टर 78-89

- ☑ ग्रीन अमोनिया
- ☑ विश्व नारकोटिक दिवस
- ☑ पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (आरएलवी)
- ☑ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट
- ☑ छोटे विकासशील द्वीप राज्यों पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
- ☑ लोकसभा अध्यक्ष
- ☑ मानसून
- ☑ आर्थिक सुधार और आर्थिक वक्र
- ☑ एमएसपी में बढ़ोतरी
- ☑ विशेष राज्य का दर्जा
- ☑ एमएसएमई क्षेत्र के लिए दो नई योजनाएँ
- ☑ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

प्रमुख चर्चित स्थल 90-91

राज्य समाचार 92-99

पावर पैक्ड न्यूज 100-109

वन लाइनर्स 110-112

मुख्य परीक्षा विशेष इतिहास व कला एवं संस्कृति 113-128

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 129-135

प्रीलिम्स आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 136-150

औपनिवेशिक कानूनों की जगह लाए गए नए आपराधिक कानूनों के मायने

वर्तमान केंद्र सरकार लंबे समय से इस बात पर विचार कर रही थी कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के कानूनों को आज के समय में बनाए रखना कितना उचित है, इसीलिए समय समय पर पुराने और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा समितियों का भी गठन किया गया था। विशेषकर ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान बनाए गए आपराधिक कानूनों की समीक्षा अधिक आवश्यक हो गई थी। भारतीय दंड संहिता जिसे अंग्रेजों ने 1860 में बनाया था वो उस समय और देशकाल की परिस्थितियों और चुनौतियों के लिहाज से बनाया था। उस दौर में अपराध और अपराधी अलग प्रकृति के थे। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति, हिंसा, विद्रोह या दंगा करने वालों के लिए दंड देने का प्रावधान ब्रिटिशर्स ने किया। तब से लेकर अब तक हत्या, लूट, आगजनी, आपराधिक षड्यंत्र और आर्थिक अपराधों की प्रकृति में बड़ा अंतर देखा गया है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की प्रकृति में भी बड़े स्तर पर बदलाव और गंभीरता देखी गई है। इसलिए नए सिरे से कानूनों को बनाने या उन्हें पुनर्परिभाषित करने की जरूरत महसूस की गई।

केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में ब्रिटिश गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। इसी कड़ी में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए और अंग्रेजी संसद द्वारा पारित किए गए इंडियन पीनल कोड, 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (1898), 1973 और इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 कानूनों में केंद्र सरकार ने कई विसंगतियां देखी जिसके चलते हाल ही में 1 जुलाई से भारत ने अपने औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलते हुए तीन नए दंड कानूनों के साथ लागू कर दिया है। 1860 के भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता (BNS) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इन कानूनों को पहली बार केंद्र ने पिछले साल 11 अगस्त को पेश किया था, जिसके बाद उन्हें समीक्षा के लिए सांसद बृज लाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। संशोधित विधेयकों को बाद में 12 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया गया और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली।

भारत सरकार का मानना है कि समाप्त होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे और उनका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब जो तीन नए कानून लागू हुए हैं उनका मूल लक्ष्य भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना है। इनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा। नए कानूनों के तहत राजद्रोह को खत्म करने का अति महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। नए आपराधिक कानूनों में राजद्रोह पूरी तरह से समाप्त हो गया है क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और सबको बोलने का अधिकार है। राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त करने वाला फैसला दूरगामी परिणाम वाला साबित होगा।

भारत में आपराधिक कानूनों को नए सिरे से प्रबंधित करने का प्रावधानः

ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे, इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था, कुल 475 जगह गुलामी की इन निशानियों को समाप्त कर दिया है। इसके प्रस्तावित प्रावधान हैं:

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसने CrPC को प्रतिस्थापित किया है, उसमें अब 533 धाराएं रहेंगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है।
- भारतीय न्याय संहिता, जिसने IPC को प्रतिस्थापित किया है, उसमें पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी, 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और

22 धाराओं को निरस्त किया गया है। वहीं भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, जिसने Evidence Act को प्रतिस्थापित किया है, उसमें पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी, 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं।

- कानून में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ई-मेल, सर्वर लॉग्स, कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल, मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है। FIR से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है।
- इस कानून को न्यायोचित बनाने और उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के हिसाब से काम करने देने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें नया प्रावधान यह है कि सर्च और जब्ती के समय वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा, पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी, इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी।
- 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को कंपल्सरी किया जा रहा है, इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
- पहली बार ई-FIR का प्रावधान जोड़ा जा रहा है, हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना करेगा।
- यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान कंपल्सरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपल्सरी कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना कंपल्सरी होगा।

आरोप पत्र और आरोपित व्यक्ति के संबंध में नए प्रावधानः

- अपराध की स्थिति में सबसे जरूरी प्रक्रिया है अपराधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना और आरोपपत्र दाखिल करने का तरीका इस प्रकार का होना जरूरी है कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से झूठे मामले में न फसाया जा सके और चार्जशीट फाइल करने वाले प्राधिकारी गलत आरोप पत्र न दायर करें। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नए आपराधिक कानूनों में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समयसीमा तय कर दी गई है और परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिनों की अनुमति और दे सकेंगी, इस प्रकार 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे, बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा, इससे सालों तक निर्णय लंबित नहीं रहेगा और फैसला 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा।

महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध पर नया दंड विधानः

- केंद्र सरकार ने तीन नए आपराधिक कानूनों में यह नया प्रावधान किया है कि शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को पहली बार अपराध की श्रेणी में लाया गया है। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है जबकि 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ अपराध के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान रखा गया है। मॉब लिंचिग के लिए 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड के तीनों प्रावधान रखे गए हैं। मोबाइल फोन या महिलाओं की चेन की स्नेचिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसके लिए भी प्रावधान नए कानून में रखा गया है। बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है, अनेक अपराधों में जुर्माने की राशि को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

आतंकवाद की व्याख्याः

- भारत के पास जो भी ब्रिटिश कालीन आपराधिक कानून थे उनमें पहले आतंकवाद की कोई व्याख्या नहीं थी लेकिन अब जब भारतीय दंड संहिता, 1860 को हटा कर भारतीय न्याय संहिता 2023 आई है तो उसमें आतंकवाद और इसके दायरे की व्याख्या की गई है। अब सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। इसके अलावा अंतरराज्यीय गिरोह और संगठित अपराधों के विरूद्ध अलग प्रकार की कठोर सजा का नया प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा जा रहा है। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का प्रावधान भी किया गया है। मॉब लिंचिग जैसे जघन्य अपराधों के लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है।
- गंभीर चोट के कारण निष्क्रियता की स्थिति और मामूली चोट लगने के मामले, दोनों में 7 साल की सजा का प्रावधान था, दोनों को अलग कर दिया है। हमेशा के लिए अपंगता या ब्रेन डेड होने की स्थिति में 10 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। अनेक अपराधों में जुर्माने की राशि को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। हिरासत से भाग जाने वाले अपराधियों के लिए भी 10 साल की सजा का प्रावधान है। सजा माफी को राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करने के कई मामले देखे जाते थे, लेकिन अब मृत्यु दंड को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास को कम से कम

7 साल की सजा और 7 साल के कारावास को कम से कम 3 साल तक की सजा में ही बदला जा सकेगा।

चुनौतियाँ एवं आशंकाएँ:

- व्यापक आशंकाओं के बीच देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं लेकिन पुलिस और न्यायिक प्रणालियाँ अभी तक उनके कार्यान्वयन के लिए तैयार नहीं हैं। स्टेशन-हाउस पुलिस कर्मियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण, कभी-कभार कार्यशालाओं और इलेक्ट्रॉनिक शिकायत दर्ज करने की सुविधा के लिए अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम को अपग्रेड करने की रिपोर्टों को छोड़कर, पुलिस के ऊपरी और निचले स्तरों के बीच तैयारी का सटीक स्तर अस्पष्ट बना हुआ है।
- ऐसी चिंताएँ हैं कि संसद की एक स्थायी समिति द्वारा मसौदे की समीक्षा करने और कुछ बदलावों की सिफारिश करने के बावजूद, विधानमंडल में कानूनों पर पूरी तरह से बहस नहीं की गई, न ही नागरिक समाज के साथ व्यापक रूप से चर्चा की गई। कुछ लोगों को चिंता है कि कुछ नए प्रावधान, जैसे कि कई चरणों में पुलिस हिरासत की अनुमति देने वाला प्रावधान, पुलिस की शक्तियों को काफी बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा विशेष आतंकवाद-रोधी कानून के साथ-साथ सामान्य दंड कानून में 'आतंकवाद' को अपराध के रूप में शामिल करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।
- फिर भी, केंद्र की यह घोषणा कि राज्य अपने संशोधन करने के लिए स्वतंत्र हैं, सकारात्मक है, साथ ही प्रक्रियागत सुधार जैसे क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना एफआईआर का अनिवार्य पंजीकरण और तलाशी और जब्ती के लिए वीडियोग्राफी की शुरुआत भी सकारात्मक है।

केंद्र सरकार का मानना है कि अभी तक के कानूनों में मानव हत्या या स्त्री के साथ दुराचार जैसे जघन्य अपराधों को बहुत नीचे रखा गया और राजद्रोह, खजाने की लूट शासन के अधिकारी पर हमले जैसे अपराधों को इनसे ऊपर रखा गया था। भारत सरकार ने इस दृष्टिकोण को इन तीनों कानूनों के माध्यम से बदलने का प्रयास किया है। भारत सरकार का मत है कि शासन की जगह नागरिक को केन्द्र में लाने का बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर ये कानून लाए गए हैं।

राष्ट्रीय संक्षिप्त मुद्दे

वैधानिक जमानत का प्रावधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू के पूर्व छात्र और स्टूडेंट एक्टिविस्ट शरजील इमाम को 2020 के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े राजद्रोह के आरोपों में वैधानिक जमानत दी है।

पृष्ठभूमि:

- अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 के संबंध में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शरजील इमाम पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया, जिसे जनवरी 2020 में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।
- इसके बाद इनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13 लगाई गई, जिसमें अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है।
- शरजील इमाम को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 436-ए के तहत तकनीकी आधार पर जमानत दी गई, जहां किसी आरोपी को जिसने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि का आधा हिस्सा कारावास में हो तो उसे जमानत दी जाती है।

वैधानिक जमानत:

- सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत वैधानिक जमानत का प्रावधान उन मामलों में हिरासत पर एक वैधानिक सीमा लगाता है जहां मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस प्रावधान के अनुसार, यदि कोई विचाराधीन कैदी किसी अपराध (ऐसे मामलों को छोड़कर जहां मृत्युदंड उस अपराध की संभावित सजा है) के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि के आधे से अधिक समय तक हिरासत में रहा है, तो वे जमानत के साथ या बिना जमानत के अपने निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
- हालाँकि, अगर न्यायालय इस वैधानिक राहत से मना करता है, तो उसे मना करने के लिए लिखित कारण बताने होंगे। इसके अतिरिक्त, हिरासत अवधि की गणना करते समय, विचाराधीन व्यक्ति द्वारा कार्यवाही में की गई किसी भी देरी को कुल समय अवधि से बाहर रखा जाता है।

महत्वपूर्ण मामले:

सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, 2022:

- जस्टिस संजय किशन कौल और एम.एम. सुन्दरेश पीठ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वैधानिक जमानत के प्रावधान का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और अगर

देरी आरोपी की वजह से नहीं होती है तो जमानत आवेदन की जरूरत नहीं है।

- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, वैधानिक जमानत से इनकार करने की शक्ति का संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राहत यूएपीए, पीएमएलए और एनडीपीएस अधिनियम जैसे विशेष कानूनों पर भी लागू होती है, जब तक कि विशिष्ट प्रावधानों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2022):

- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः कहा कि सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत वैधानिक जमानत पीएमएलए मामलों में भी लागू होगी जहां कड़े प्रावधानों के कारण नियमित जमानत प्राप्त करना लगभग असंभव है।

विचाराधीन कैदियों के लिए अन्य सुरक्षाएं:

- 2022 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि देश भर में 63,502 ऐसे विचाराधीन कैदी हैं जिन पर दो साल से कम की सजा वाले अपराधों का आरोप है।
- यदि कोई आरोपी जमानत बांड भरने के लिए तैयार हो तो सीआरपीसी की धारा 436 के तहत अदालतों को सभी जमानती अपराधों के लिए जमानत दे देनी चाहिए तथा गैर-जमानती अपराधों में जमानत देना अदालत के विवेक पर निर्भर करता है।
- धारा 167(2) सीआरपीसी के तहत, पुलिस के पास ज्यादातर अपराधों के लिए जांच पूरी करने और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 60 दिन का समय होता है, जिसके बाद लंबी अवधि तक जेल में कैदियों के रहने से बचने के लिए अदालतें वैधानिक जमानत दे देती हैं।
- मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए यह अवधि 90 दिनों तक बढ़ाई जाती है। अगर पुलिस इन अवधियों के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं करती है, तो वैधानिक जमानत दी जाती है। यूएपीए जैसे सख्त कानून लंबी जांच की समयसीमा की अनुमति देते हैं।

विचाराधीन कैदियों की समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदम:

- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) में धारा 436ए का समावेश।
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय XXI-A में संशोधन कर 'प्ली बार्गेनिंग' (धारा 265 ए से 265 एल) के तहत दलील सौदेबाजी की अवधारणा शुरू की गई है, जो प्रतिवादी और अभियोजन पक्ष के बीच पूर्व-परीक्षण बातचीत को सक्षम बनाती है।
- ई-प्रिजन्स सॉफ्टवेयर, जो कि अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ एकीकृत एक जेल प्रबंधन अनुप्रयोग है। यह राज्य जेल प्राधिकारियों को कैदियों के डेटा तक त्वरित और कुशल तरीके से पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है और उन कैदियों की पहचान करने में उनकी मदद करता है जिनके मामले विचाराधीन समीक्षा समिति आदि के समक्ष विचारार्थ आने वाले हैं।
- सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को के लिए जारी किये गए आदर्श जेल मैनुअल 2016 में 'कानूनी सहायता' और 'विचाराधीन कैदियों' आदि पर विशिष्ट अध्याय हैं, जो विचाराधीन कैदियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं पर विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं, जैसे कानूनी बचाव, वकीलों के साथ साक्षात्कार, सरकारी लागत पर कानूनी सहायता के लिए न्यायालयों में आवेदन आदि।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने जेलों में विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किए हैं, जो जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने विचाराधीन समीक्षा समितियों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है , जिसे गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को भेजा गया है, ताकि इसका सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके और कैदियों को राहत प्रदान की जा सके।

-: प्रीलिम्स इनसाइट :-

विचाराधीन कैदी:

- विचाराधीन कैदी एक ऐसा आरोपी व्यक्ति होता है जिसे अदालत में सुनवाई के दौरान न्यायिक हिरासत में रखा जाता है।
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436-ए के अनुसार, किसी विचाराधीन कैदी को, जो आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय किसी अपराध का आरोपी नहीं है, यदि उस अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अवधि की आधी अवधि तक हिरासत में रहा हो, तो रिहा कर दिया जाना चाहिए।

विचाराधीन कैदियों को प्राप्त अधिकार:

- शीघ्र और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार
- अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार
- कानूनी सहायता का अधिकार
- परिवार से मिलने का अधिकार

निष्कर्ष:

विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 2005 में शुरू किया गया वैधानिक जमानत का प्रावधान विशेष रूप से कम सजा वाले अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए कैदियों के लिए उपयोगी है। इससे कैदियों को लंबी अवधि तक जेल में रहने से बचाया जा सके।

अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) की नई पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के तहत भारत में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए दो पहलें शुरू की हैं।

एआईएम–आईसीडीके जल चैलेंज 4.0:

यह एआईएम-आईसीडीके जल नवाचार चैलेंज का चौथा संस्करण है, जो एआईएम, भारत में डेनमार्क दूतावास, इनोवेशन सेंटर डेनमार्क (आईसीडीके) और डेनमार्क तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) के बीच सहयोग है। यह अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) द्वारा आविष्कारशील समाधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण जल-संबंधी चुनौतियों का समाधान करने की पहल है।

मुख्य बिंदु:

- चयनित टीमें वैश्विक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल एक्शन कार्यक्रम में भाग लेंगी।
- नौ देशों की युवा प्रतिभाओं के साथ जुड़ाव। कोपेनहेगन में डिजिटल टेक समिट में नवाचारों को प्रदर्शित करने का अवसर।
- दो प्रवेश ट्रैक: छात्र और युवा उद्यमी (दोनों 35 वर्ष से कम)।
- डिजिटल समाधान, समावेशन और सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना।

आपके लिए नवाचार पुस्तिका (5वां संस्करण):

- यह पुस्तिका भारत में उन उद्यमियों पर प्रकाश डालती है जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में काम कर रहे हैं।
- इस संस्करण में भारत के विभिन्न हिस्सों से 60 उद्यमी शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक सतत नवाचारों के माध्यम से सामाजिक बेहतरी में योगदान दे रहे हैं।

अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के बारे में:

- अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे नीति आयोग के तहत 2016 में लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य है- देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम और नीतियां विकसित करना।
- हितधारकों के बीच सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना।
- नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की देखरेख के लिए जागरूकता और संरचना बनाना।

एआईएम की प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- **अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल):** स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देना।
- **अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी):** स्टार्टअप और उद्यमियों का समर्थन करना।
- **अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र (एसीआईसी):** वंचित क्षेत्रों की सेवा करना।
- **अटल न्यू इंडिया चौलेंज (एएनआईसी):** उत्पाद और सेवा नवाचारों को बढ़ावा देना।
- **एआरआईएसई-एएनआईसी चुनौतियां:** स्टार्टअप/एमएसएमई नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- **मेंटर ऑफ चेंज:** मेंटरशिप और साझेदारी।
- **आईसीआरईएसटी:** एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इनक्यूबेटर क्षमताओं में वृद्धि करना।

नोटा के पक्ष में ज्यादा मतदान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में नोटा को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले, जिसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। यह भारत के इतिहास में नोटा को मिले सबसे ज्यादा वोट हैं। पिछला रिकॉर्ड बिहार के गोपालगंज में 2019 के चुनावों में 51,660 वोटों के साथ बना था।

नोटा के बारे में:

- नोटा का मतलब है इनमें से कोई नहीं। यह चुनावों में एक मतपत्र विकल्प है जो मतदाताओं को यह संकेत देने की अनुमति देता है कि वे सूचीबद्ध उम्मीदवारों या विकल्पों में से किसी का समर्थन नहीं करते हैं।
- नोटा का इस्तेमाल अक्सर उन चुनावों में किया जाता है जहाँ मतदाता सभी उम्मीदवारों से असंतुष्ट होते हैं या उपयुक्त उम्मीदवार की कमी का विरोध करना चाहते हैं।

नोटा के बारे में कुछ मुख्य पहलू:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 के पीयूसीएल बनाम भारत संघ के फैसले में भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभाओं के चुनावों में नोटा को शामिल करने का निर्देश दिया था।
- नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल 2013 में चार राज्यों- छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में किया गया था।
- निर्वाचन आयोग ने कहा है कि भले ही नोटा के खिलाफ वोटों की संख्या उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या से अधिक हो, लेकिन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।
- 2013 में जारी एक स्पष्टीकरण में, ईसीआई ने कहा है कि नोटा के लिए डाले गए वोटों को सुरक्षा जमा की जब्ती का निर्धारण करने के लिए नहीं माना जा सकता है।
- 2014 में, ईसीआई ने राज्यसभा चुनावों में नोटा की शुरुआत की।

हालाँकि, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनावों में 'इनमें से कोई नहीं' (NOTA) विकल्प को खत्म कर दिया।

- 2015 में, भारत के चुनाव आयोग ने 'इनमें से कोई नहीं' विकल्प के लिए प्रतीक की घोषणा की, जिसका डिजाइन राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (NID), अहमदाबाद द्वारा किया गया था।
- अब तक नोटा ने कई चुनावों में भाग लेने वाले कई राजनीतिक दलों की तुलना में अधिक वोट प्राप्त किए हैं।

आगे की राह:

अब, यह समय की मांग है कि उन चुनावों के लिए परिणाम का अर्थ हो जहाँ NOTA जीतता है, जैसे कि फिर से चुनाव या उम्मीदवारों को चुनाव से बाहर करना। इससे लोकतंत्र अधिक जीवंत और प्रतिनिधि त्वपूर्ण बनेगा।

आरटीआई अधिनियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सूचना आयोग (टीएनआईसी) द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें एक सहकारी समिति को उसके द्वारा दिए गए ऋणों के बारे में विवरण देने का निर्देश दिया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सहकारी समितियां सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अधीन नहीं हैं।

फैसले के मुख्य पहलुओं में शामिल हैं:

- तमिलनाडु सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियाँ आरटीआई अधिनियम की धारा 2(एच) के अंतर्गत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' की परिभाषा में नहीं आती हैं।
- न्यायालय ने सहकारी समिति को अपने सदस्य को ऋण विवरण प्रकट करने का निर्देश देने वाले आदेश को रद्द कर दिया तथा कहा गया कि सहकारी समितियाँ स्वायत्त निकाय हैं और आरटीआई अधिनियम द्वारा बाध्य नहीं हैं।
- यह फैसला 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और 2015 के मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है, जिसमें कहा गया था कि सहकारी समितियाँ आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती हैं।
- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सहकारी समितियाँ सार्वजनिक कार्य करने वाली वैधानिक संस्थाएँ नहीं हैं और संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत परिभाषित 'राज्य' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के बारे में:

- सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 भारत में एक ऐतिहासिक कानून है जो नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

मुख्य प्रावधान:

- **सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा:** अधिनियम में सभी संवैधानिक प्राधिकरण, सरकारी निकाय और सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थान शामिल हैं।
- **नागरिकों के अधिकार:** नागरिकों को सूचना तक पहुँचने, दस्तावेजों का निरीक्षण करने और प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने का अधिकार है।
- **छूट:** राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित जानकारी प्रकटीकरण से मुक्त है।
- **सार्वजनिक सूचना अधिकारी (PIO):** प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना प्रदान करने के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक सूचना अधिकारी को नामित करना चाहिए।
- **प्रक्रिया:** नागरिक सार्वजनिक सूचना अधिकारी को अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन्हें 30 दिनों (जीवन या स्वतंत्रता के मामलों में 48 घंटे) के भीतर जवाब देना होगा।
- **अपील:** पीड़ित पक्ष केंद्रीय/राज्य सूचना आयोगों सहित उच्च अधिकारियों से अपील कर सकते हैं।
- **दंड:** सूचना प्रदान करने में विफलता या जानबूझकर देरी के लिए सार्वजनिक सूचना अधिकारी को दंड का सामना करना पड़ सकता है।
- **स्वप्रेरणा प्रकटीकरण:** सार्वजनिक प्राधिकरणों को स्वेच्छा से कुछ जानकारी, जैसे उनके कार्य और गतिविधियाँ, का खुलासा करना चाहिए।

निष्कर्ष:

आरटीआई अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है जो सार्वजनिक प्राधिकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम धारा 8 के अनुसार रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत विवरण से संबंधित सूचनाओं सहित कुछ श्रेणियों की जानकारी को प्रकटीकरण से छूट देता है। हालांकि, अधिनियम का उद्देश्य कुछ मामलों में पारदर्शिता की आवश्यकता और गोपनीयता की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना है। कुल मिलाकर, आरटीआई अधि नियम भारत के शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है और इसके प्रावधान और छूट यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि नागरिकों को ऐसी जानकारी तक पहुँच हो जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के कामकाज के लिए आवश्यक है।

लिविंग विल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच में कार्यरत न्यायमूर्ति एम एस सोनक गोवा में लिविंग विल पंजीकृत करने वाले पहले व्यक्ति बन गए।

क्या है लिविंग विल?

- यह वास्तव में एक दस्तावेज है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इच्छा बताता है कि वह भविष्य में गंभीर बीमारी की हालत में किस तरह

का इलाज कराना चाहता है।
- यह वास्तव में इसलिए तैयार किया जाता है, जिससे गंभीर बीमारी की हालत में अगर व्यक्ति खुद फैसले लेने की हालत में नहीं रहे तो पहले से तैयार दस्तावेज के हिसाब से उसके बारे में फैसला लिया जा सके।

लिविंग विल का इतिहास:

- **1994 और 1996:** भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पी. रथिनम बनाम भारत संघ और ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामलों में इस बात पर विचार किया कि क्या 'मरने का अधिकार' 'जीवन के अधिकार' में शामिल है।
- **2011:** जब पिंकी विरानी ने अरुणा शानबाग के लिए जीवन-सहायता समाप्त करने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, तो निष्क्रिय इच्छामृत्यु का मुद्दा जोर पकड़ने लगा, जो 1973 में यौन उत्पीड़न के बाद से वानस्पतिक अवस्था में थी।
- **2018:** सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध बनाया और 'लिविंग विल' या अग्रिम चिकित्सा निर्देश के लिए एक प्रक्रिया बनाई।
- **2019:** चंडीगढ़ में भारत की पहली लिविंग विल निष्पादित की गई।
- **जनवरी 2023:** न्यायालय ने न्यायिक अनुमोदन की आवश्यकता को हटाते हुए लिविंग विल बनाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया।
- **मार्च 2024:** केरल के त्रिशूर में 30 लोगों ने लिविंग विल निष्पादित की।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बारे में:

- निष्क्रिय इच्छामृत्यु से तात्पर्य चिकित्सा उपचार या जीवन-सहायक उपायों को वापस लेना या रोकना है, जिससे एक लाइलाज रूप से बीमार रोगी को स्वाभाविक रूप से मरने की अनुमति मिलती है। इसे 'अप्रत्यक्ष इच्छामृत्यु' या 'नकारात्मक इच्छामृत्यु' के रूप में भी जाना जाता है।
- भारत में, 2018 में कॉमन कॉज (ए रजिस्टर्ड सोसाइटी) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध बनाया गया था। न्यायालय ने रोगियों को 'लिविंग विल' या अग्रिम चिकित्सा निर्देश निष्पादित करने की अनुमति दी, जिसमें वे संवाद करने में असमर्थ होने की स्थिति में चिकित्सा उपचार के बारे में अपनी प्राथमिकताएँ निर्दिष्ट कर सकते हैं।

भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु के मुख्य पहलू:

- वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब जैसे जीवन-रक्षक उपचार को वापस लेना।
- एंटीबायोटिक्स या सर्जरी जैसे चिकित्सा उपचार को रोकना।
- अंतर्निहित बीमारी के बढ़ने के कारण प्राकृतिक मृत्यु।
- असाध्य रूप से बीमार रोगियों पर लागू होता है जिनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है।
- लिविंग विल या अग्रिम चिकित्सा निर्देश की आवश्यकता होती है।
- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा परिवार के सदस्यों या नामित अभिभावक की सहमति से कार्यान्वित किया जाता है।
- निष्क्रिय इच्छामृत्यु सक्रिय इच्छामृत्यु से अलग है, जिसमें जीवन को समाप्त करने के लिए घातक पदार्थ का प्रशासन शामिल है और यह अभी भी भारत में कानूनी नहीं है।
- इच्छामृत्यु के इर्द-गिर्द बहस नैतिक और कानूनी सवाल उठाती है, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता और जीवन के अधिकार को उपशामक देखभाल और दुरुपयोग की संभावना के बारे में चिंताओं के साथ संतुलित करती है।

निष्कर्ष:

न्यायमूर्ति एम एस सोनक द्वारा लिविंग विल पंजीकृत करने का निर्णय गोवा और भारत में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है। स्वायत्तता और सम्मान के अपने अधिकार का प्रयोग करके, वह अग्रिम देखभाल योजना के महत्व और किसी के चिकित्सा उपचार में अपनी बात रखने के महत्व को प्रदर्शित करता है। यह विकास जीवन के अंत की देखभाल और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के संबंध में भारत के कानूनी ढांचे में हुई प्रगति को उजागर करता है, जो व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में सूचित विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाता है। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, उनका फैसला दूसरों को लिविंग विल निष्पादित करने पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

केंद्र में नई सरकार का गठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई एनडीए सरकार के केंद्रीय मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, मंत्रिपरिषद में पिछले कार्यकाल की तुलना में अधिक सदस्य हैं, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, पांच राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं।

मंत्रिपरिषद के बारे में:

- केंद्रीय मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और सरकार की नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **संवैधानिक प्रावधान:** मंत्रिपरिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत किया जाता है।
- **सहायता और सलाह:** केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देना होता है (अनुच्छेद 74)।
- **सामूहिक जिम्मेदारी:** अनुच्छेद 75(3) के अनुसार परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है।
- **राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति:** राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है (अनुच्छेद 75)।
- **परिषद की भूमिका:** अनुच्छेद 73 के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी नीतियों और निर्णयों को तैयार करने की है।
- **पद की शपथ:** मंत्री अनुच्छेद 75(4) में निर्दिष्ट अनुसार पद और

गोपनीयता की शपथ लेते हैं।

- **संसद के प्रति जिम्मेदारी:** परिषद संसद को प्रश्नों का उत्तर देने और जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है (अनुच्छेद 75(2))।
- **मंत्री का कार्यकाल:** एक मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ समाप्त होता है, जब तक कि वे इस्तीफा न दें या उन्हें हटा न दिया जाए (अनुच्छेद 75(5))।
- **संवैधानिक वैधता:** केंद्रीय मंत्रिपरिषद के निर्णय और कार्य न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे संविधान के अनुरूप हैं।
- इस केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है।
- अनुच्छेद 88 मंत्रियों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बोलने या अन्यथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है, साथ ही दोनों सदनों के किसी भी संयुक्त सत्र या किसी भी संसदीय समिति का वे हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि, यह उन्हें वोट देने के अधिकार की गारंटी नहीं देता है।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है?

- प्रधानमंत्री कार्यकारी क्षमता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख हैं। उनके पद को अक्सर "बराबर के लोगों में प्रथम" के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री की एक अनूठी भूमिका होती है और उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्राथमिक नेता माना जाता है, लेकिन फिर भी वे अपने मंत्रियों के बराबर होते हैं।
- प्रधानमंत्री सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों और अन्य विभागों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए जाते हैं।
- प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिवालय के प्रमुख के रूप में भी कार्य करते हैं, जो सरकारी निकाय है जो सरकार के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन और मंत्रालयों के बीच व्यापार के संचालन की निगरानी करता है। इसके अतिरिक्त, वे नीति आयोग और कैबिनेट की नियुक्ति समिति के प्रमुख भी होते हैं।

कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं?

- कैबिनेट मंत्रियों को परिषद में सबसे वरिष्ठ माना जाता है, जो प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। वे केंद्र सरकार के रणनीतिक और महत्वपूर्ण मंत्रालयों की देखरेख करते हैं जैसे- गृह मामलों, वित्त, रक्षा आदि से संबंधित।
- मंत्रियो के पास महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने के अधिकार होता है।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कौन हैं?

- राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कनिष्ठ सदस्य होते हैं। एक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को कैबिनेट मंत्रियों या केंद्र सरकार के अन्य सदस्यों की निगरानी के बिना अपने संबंधित मंत्रालय का प्रशासन करने का अधिकार होता है।

राज्य मंत्री कौन होते हैं?

- राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के विपरीत, एक राज्य मंत्री किसी मंत्रालय पर सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, लेकिन वह कैबिनेट मंत्री की सहायता करते है और अपने वरिष्ठ द्वारा उन्हें सौंपे गए विशिष्ट कार्यों के लिए जिम्मेदार होते है।

कैबिनेट समितियों के बारे में:

- कैबिनेट समितियाँ का संविधान में उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री इन समितियों का गठन करते हैं और इन समितियों को विशिष्ट कार्य सौंपते हैं। आवास पर कैबिनेट समिति और संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति को छोड़कर सभी समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
- प्रत्येक समिति की सदस्यता तीन से आठ तक होती है। आमतौर पर, केवल कैबिनेट मंत्री ही इन समितियों के सदस्य होते हैं। हालाँकि, गैर-कैबिनेट मंत्रियों का समितियों का सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य होना असामान्य नहीं है। यदि प्रधानमंत्री स्वयं ऐसी किसी समिति के सदस्य हैं, तो वे उस समिति के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं।
- समितियाँ मुद्दों का समाधान करती हैं और मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्ताव तैयार करती हैं तथा उन्हें सौंपे गए मामलों पर निर्णय लेती हैं। मंत्रिमंडल को निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार है।
- मनमोहन सिंह सरकार में दर्जनों मंत्रिसमूहों (जीओएम) और अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूहों (ईजीओएम) के अलावा 12 कैबिनेट समितियाँ थीं।
- वर्तमान में आठ कैबिनेट समितियाँ हैं- कैबिनेट की नियुक्ति समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति, रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति और आवास पर कैबिनेट समिति। निवेश और रोजगार पर समितियाँ 2019 में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई नवीन कैबिनेट समिति थीं।

सुरक्षा पर कैबिनेट समिति:

- सुरक्षा संबंधी मामलों पर कैबिनेट समिति (CCS) भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।
- सुरक्षा पर कैबिनेट समिति में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री शामिल हैं।
- सुरक्षा पर कैबिनेट समिति राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और विदेश नीति से संबंधित संवेदनशील मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए जिम्मेदार है।
- यह सैन्य अभियानों, रक्षा अधिग्रहणों और रणनीतिक साझेदारी जैसे मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।
- यह खतरों का आकलन करके और उनका मुकाबला करने के उपायों को लागू करके देश की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करती है।
- सुरक्षा पर कैबिनेट समिति नई तकनीकों और हथियार प्रणालियों के अधिग्रहण सहित सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की देखरेख करती है।
- यह आतंकवाद से निपटने के लिए रणनीति विकसित करती है और

खुफिया एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करती है।
- यह भारत के परमाणु सिद्धांत को तैयार करने और देश की परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
- यह साइबर सुरक्षा खतरों को संबोधित करती है और भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए उपाय विकसित करती है।
- सुरक्षा पर कैबिनेट समिति प्राकृतिक आपदाओं या भू-राजनीतिक तनाव जैसी संकट स्थितियों के लिए सरकार की प्रतिक्रिया का समन्वय करती है।

एकीकृत साइबरस्पेस सिद्धांत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) की बैठक के दौरान साइबरस्पेस संचालन के लिए 'संयुक्त सिद्धांत' जारी किया है।

एकीकृत साइबरस्पेस सिद्धांत के बारे में:

- इस ऐतिहासिक प्रकाशन का उद्देश्य सैन्य कमांडरों को आधुनिक साइबर युद्ध की जटिलताओं को पहचानने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना है, जिससे समन्वित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सके।
- यह सिद्धांत भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में साइबरस्पेस संचालन को निष्पादित करने और समझने के लिए एक सुसंगत ढांचा प्रदान करता है।

भारत में साइबर खतरों की सीमा:

- साइबर सुरक्षा खतरे कई तरह के स्रोतों से उत्पन्न होते हैं और विघटनकारी गतिविधियों का परिणाम होते हैं जो व्यक्तियों, व्यवसायों, राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे और सरकारों को समान रूप से लक्षित करते हैं।
- 2023 में, भारत ने प्रति संगठन 2,138 साप्ताहिक साइबर हमले दर्ज किए, जो 2022 से 15% की वृद्धि है। यह भारत को ताइवान के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे अधिक लक्षित राष्ट्र बनाता है।

'संयुक्त सिद्धांत' की आवश्यकता:

- भूमि, समुद्र और वायु के पारंपरिक डोमेन के अलावा, साइबरस्पेस आधुनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है।
- साइबरस्पेस में शत्रुतापूर्ण दृष्टि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, सामाजिक सामंजस्य, राजनीतिक निर्णय लेने और खुद का बचाव करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए साइबरस्पेस संचालन के लिए नया संयुक्त सिद्धांत आधुनिक युद्ध में महत्वपूर्ण हो गया है, विशेष रूप से मजबूत साइबर युद्ध और साइबर जासूसी क्षमताओं को विकसित करने के बाद चीन के द्वारा उत्पन्न साइबर खतरों से सुरक्षा हेतु आवश्यक हैं।
- चीन ने साइबर युद्ध में प्रमुख क्षमताएँ विकसित की हैं, जिसमें एक वास्तविक गतिज युद्ध शुरू होने से पहले ही किसी विरोधी की सैन्य संपत्ति, रणनीतिक नेटवर्क और ऊर्जा, बैंकिंग, परिवहन और संचार ग्रिड जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को नष्ट करने या नष्ट करने के लिए साइबर हथियार शामिल हैं।
- भारत इस क्षेत्र में बहुत पीछे है। 2019 में, सरकार ने सशस्त्र बलों की इच्छा के अनुसार पूर्ण साइबर कमांड के बजाय केवल एक छोटी त्रि-सेवा रक्षा साइबर एजेंसी के निर्माण को मंजूरी दी।

साइबर सुरक्षा के लिए अन्य पहल:

- **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In):** यह भारत के साइबरस्पेस में घटना प्रतिक्रिया, भेद्यता प्रबंधन और सुरक्षा प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- साइबर स्वच्छता केंद्र मैलवेयर विश्लेषण के लिए नि:शुल्क उपकरण प्रदान करता है और सिस्टम और उपकरणों की सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद करता है।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 एक सुरक्षित साइबर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है और इसका उद्देश्य सूचना और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) के साथ शुरू किए गए साइबर सुरक्षित भारत का उद्देश्य भारत में नवीनतम साइबर अपराधों और साइबर सुरक्षा चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- देश में महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा केंद्र (NCIIPC) की स्थापना की गई थी।
- साइबर अपराध के मुद्दों को व्यापक और समन्वित तरीके से संबोधित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की शुरुआत की गई थी।

निष्कर्ष:

यह सिद्धांत ऐसे समय में आया है जब सेना साइबरस्पेस डोमेन को संभालने के लिए अपने छह परिचालन या क्षेत्रीय कमांड में से प्रत्येक में समर्पित विशेष इकाइयों का संचालन कर रही है। ये कमांड साइबर ऑपरेशन और सपोर्ट विंग अपने नेटवर्क की सुरक्षा करने और युद्ध के इस आयाम में तैयारी के स्तर को बढ़ाने में मदद करेंगे। इस पहल से पारंपरिक संचालन और ग्रे जोन युद्ध दोनों के लिए सेना की साइबर-सुरक्षा स्थिति को समग्र रूप से मजबूत किया जा सकेगा।

केरल प्रवासन सर्वे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल प्रवास सर्वेक्षण 2023, सर्वेक्षण में प्रवासियों, वापस लौटने वाले प्रवासियों, दूसरे राज्यों में प्रवासियों और भारत के भीतर दूसरे

राज्यों से लौटने वालों की चिंताओं पर है।

इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

पलायन में थोड़ी कमी:

- पिछले साल केरल से 22 लाख लोगों ने पलायन किया। वर्ष 2018 में यह संख्या 21 लाख थी। 1998 में जब यह सर्वेक्षण शुरू हुआ था, तब केरल से 14 लाख लोग पलायन कर चुके थे।
- वर्ष 2013 में यह संख्या बढ़कर 24 लाख हो गई। लेकिन उसके बाद से इसमें धीरे-धीरे कमी आ रही है। अनुमान है कि करीब 50 लाख मलयालम भाषी भारत से बाहर रहते हैं।

लोगों का अपने गृह राज्य में लौटना:

- वर्ष 2018 में 12 लाख मलयालम भाषी भारत लौटे। जबकि वर्ष 2023 में यह संख्या बढ़कर 18 लाख हो गई।
- पिछले पांच वर्षों में केरल से लौटने वाले लोगों की संख्या में 38.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

खाड़ी देशों के प्रति आकर्षण में कमी:

- मलयालम भाषी प्रवासियों में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई के प्रति आकर्षण कम हुआ है। इनकी तुलना में अन्य देशों के प्रति वरीयता में 19.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- 2023 में खाड़ी देशों के बाद मलयालम भाषी प्रवासियों ने ब्रिटेन (6%), कनाडा (2.5%), अमेरिका (2.2%) और ऑस्ट्रेलिया को चुना।

प्रवासी छात्रों की संख्या में वृद्धि:

- प्रवास करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 2023 में प्रवास करने वाले सभी मलयालम-भाषी लोगों में से 11.3 प्रतिशत छात्र थे।

महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी:

- 2018 में महिला प्रवासियों की हिस्सेदारी 15.8 थी, जो 2023 में बढ़कर 19.1 हो गई। इनमें से 71.5 महिलाएँ स्नातक हैं। जबकि पुरुषों में यह आँकड़ा सिर्फ 34.7 प्रतिशत है।

हिंदु से ज्यादा मुस्लिम प्रवासन:

- प्रवासी मलयालम-भाषियों में 41.9 प्रतिशत मुस्लिम और 35.2 प्रतिशत हिंदू हैं। जबकि ईसाई प्रवासियों का 22.3 प्रतिशत हिस्सा हैं।

विदेश से धन भेजना:

- प्रेषित धन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2018 में जहाँ 85,092 करोड़ रुपये भेजे गए, वहीं 2023 में 2,16,893 करोड़ रुपये वापस भेजे गए।

आगे की राह:

प्रवासियों के लिए कौशल विकास के प्रयासों से बेहतर रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और जीसीसी देशों से परे प्रवासी गंतव्यों में विविधता आ सकती है। वापस लौटने वाले प्रवासियों की पुनर्वास और पुन: एकीकरण की जरूरतों को संबोधित करना उभरते हुए प्रवास परिदृश्य को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण है।

नेता प्रतिपक्ष का चयन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर नियम के तहत नेता प्रतिपक्ष के लिए लोकसभा की कुल संख्या का 10% सदस्य होना जरूरी है, इसलिए लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद पिछले 10 वर्षों से रिक्त था।

मुख्य बिंदु:

- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के वेतन, भत्ते और अधिकारों को उल्लेखित करने के लिए 'लीडर ऑफ अपोजिशन इन पॉर्लियामेंट एक्ट 1977' को अधिनियमित किया गया, जिसे बाद में संशोधित करके 'संसद में विपक्ष के नेता (वेतन और भत्ता) अधिनियम, 1977' कर दिया गया।
- इस अधिनियम के अनुसार, संसद के किसी भी सदन में विपक्ष के नेता का अर्थ सरकार या सत्ता पक्ष के बाद विपक्ष में सबसे बड़े दल का वह नेता जिसे राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष मान्यता देता है।
- यह अधिनियम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को संसद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है।

जी.वी. मावलंकर नियम:

- हालाँकि जीवी मावलंकर नियम कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है, परन्तु फिर भी यह नियम लोकसभा के साथ राज्यसभा, विधानसभा और अन्य निकायों में भी लागू किया जाता है। इसी नियम के तहत ही पहली, दूसरी, तीसरी, छठी, सातवीं और आठवीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था।
- 8 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने "मावलंकर के 10 प्रतिशत नियम" को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि सदन में अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता।
- इसके पश्चात 16वीं और 17वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद रिक्त रहा।
- हालाँकि वैधानिक नियमो के अनुसार नेता प्रतिपक्ष को विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों और चयन समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है जोकि रिक्त था, ऐसे में केंद्र सरकार ने सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को इसमें शामिल किया था।

नेता प्रतिपक्ष के अधिकार:

- 'संसद में विपक्ष के नेता (वेतन और भत्ता) अधिनियम, 1977' के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधा ठीक वैसे ही होते हैं, जो एक कैबिनेट मंत्री के 'संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954' के अनुसार होते हैं।
- नेता प्रतिपक्ष विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों और चयन समिति के सदस्य होते हैं, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सूचना आयुक्त और

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के प्रमुख आदि शामिल हैं।

- नेता प्रतिपक्ष लोक लेखा समिति में सदस्य या अध्यक्ष पद पर भी होता है। यह समिति सरकार के वित्तीय खांतो की जांच भी करती है तथा यह उन रुपयों के हिसाब की जांच करती है जो संसद के माध्यम से सरकार को खर्च करने के लिए दिया जाता है।

निष्कर्ष:

नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर मावलंकर का नियम कोई वैधानिक प्रावधान न होकर, बल्कि सदन चलाने के लिए सदन के अध्यक्ष द्वारा विकसित की गई प्रक्रिया थी। परन्तु कुछ दशकों से वैधानिक प्रावधान होते हुए भी नेता प्रतिपक्ष का चयन पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से होना चिंता का विषय है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण को मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के बारे में:

- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है।
- इस कार्यक्रम को 1985 में इंदिरा आवास योजना (IAY) के रूप में शुरू किया गया था, जिसका नाम 2015 में बदल दिया गया।
- कार्यक्रम के तहत, मैदानी इलाकों में घरों के निर्माण के लिए 1,20,000 और दुर्गम इलाकों (ऊंचे भूभाग) में 1,30,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- घर महिला के नाम पर या पति और पत्नी के बीच संयुक्त रूप से आवंटित किए जाते हैं।
- इस कार्यक्रम में शौचालयों के निर्माण, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और पेयजल की व्यवस्था हेतु स्वच्छ भारत अभियान शौचालय, उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस कनेक्शन और सौभाग्य योजना बिजली कनेक्शन जैसी अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण भी शामिल है। 1985 में अपनी स्थापना के बाद से इस कार्यक्रम ने 25 मिलियन से अधिक घरों का निर्माण किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बारे में:

- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे 25 जून, 2015 को लॉन्च किया गया था।
- मिशन का लक्ष्य भारत में निम्न और मध्यम आय वाले निवासियों, विशेष रूप से शहरी गरीबों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है।
- मिशन का लक्ष्य वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना को चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है: लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण/संवर्द्धन, भागीदारी में किफायती आवास, इन-सीटू स्लम पुनर्विकास और ऋण लिंक्ड सब्सिडी योजना।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्मित घरों के लिए अधिकतम कारपेट एरिया 30 वर्ग मीटर है, लेकिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इसे बढ़ाने की छूट है।
- सरकार ने इस योजना के तहत 6,83,724 घरों के निर्माण के लिए 43,922 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। लाभार्थियों द्वारा 20 वर्ष की अवधि के लिए गए आवास ऋण पर सरकार द्वारा 6.5% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण पर्यावरण अनुकूल तकनीक के माध्यम से किया जाएगा।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो सभी के लिए आवास प्रदान करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्र ने NEET और UGC-NET परीक्षाओं को लेकर विवादों के बीच पेपर लीक और धोखाधड़ी को रोकने के लिए फरवरी में पारित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को अधिसूचित किया है।

अधिनियम का उद्देश्य है:

- धोखाधड़ी और पेपर लीक को रोकना।
- सार्वजनिक परीक्षाओं की अखंडता की रक्षा करना।
- सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करना।
- डिग्री और प्रमाणपत्रों की विश्वसनीयता को बनाए रखना।
- परीक्षा प्रणाली को मजबूत करना।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:

- कानून के तहत, पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कम से कम तीन साल की जेल की सजा मिलेगी।
- इसे 10 लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ पांच साल तक बढ़ाया

जा सकता है। अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

- नए कानून के अनुसार, परीक्षा सेवा प्रदाता जिन्हें किसी संभावित अपराध के बारे में जानकारी है, लेकिन वे इसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं, उन पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- जांच के दौरान, यदि यह प्रमाण मिल जाता है कि सेवा प्रदाता के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने अपराध करने की अनुमति दी थी या उसमें शामिल था, तो उसे कम से कम तीन साल की कैद होगी, जो 10 साल तक हो सकती है और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- यदि परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता कोई संगठित अपराध करता है, तो जेल की अवधि न्यूनतम पांच साल और अधिकतम 10 साल होगी, और जुर्माना 1 करोड़ रुपये रहेगा।
- परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को कानून के दंडात्मक प्रावधानों से छूट दी गई है और वे परीक्षा बोर्ड के मौजूदा अनुचित साधनों के नियमों के अधीन होंगे।
- **अनुचित साधनों की परिभाषा:** कम से कम 15 कार्य जो अनुचित साधनों का उपयोग करने के बराबर हैं, जिसमें प्रश्नपत्र, उत्तर कुंजी का लीक होना और उम्मीदवारों की शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए आवश्यक किसी भी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करना शामिल है।
- **जांच और प्रवर्तन:** प्रस्तावित कानून के तहत अपराधों की जांच पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे के अधिकारी नहीं करेंगे।

निष्कर्ष:

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 भारत में सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी और पेपर लीक को रोकने और दंडित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कानून है। यह अधिनियम परीक्षा प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने, शैक्षणिक ईमानदारी को बढ़ावा देने और शिक्षा के मूल्य को बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन से परीक्षा प्रणाली में विश्वास बनाने, छात्रों के भविष्य की रक्षा करने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान करने में मदद मिलेगी।

डाकघर अधिनियम 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में डाकघर अधिनियम, 2023, जिसे भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद 18 जून, 2024 को प्रभावी हुआ। नया कानून भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की जगह लेगा।

डाकघर अधिनियम 2023 के मुख्य प्रावधान:

- यह अधिनियम केंद्र को राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा या अन्य कानूनों के उल्लंघन के हित में किसी भी डाक आइटम को रोकने, खोलने या रोकने और सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंपने की अनुमति देता है।
- यह अधिनियम डाकघर और उसके अधिकारियों को 'डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के दौरान किसी भी नुकसान, गलत डिलीवरी, देरी या क्षति के कारण किसी भी देयता' से छूट देता है, सिवाय ऐसी देयता के जो निर्धारित की जा सकती है।
- यह अधिनियम 1898 अधिनियम के तहत डाकघर के अधिकारियों द्वारा किए गए कदाचार, धोखाधड़ी और चोरी जैसे सभी दंड और अपराधों को हटा देता है।
- यह अधिनियम निजी कूरियर सेवाओं को अपने दायरे में लाकर उन्हें नियंत्रित करने का प्रावधान करता हैं।
- डाक सेवाओं के महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। उन्हें सेवाओं के लिए शुल्क और डाक टिकटों की आपूर्ति सहित विभिन्न मामलों पर नियम बनाने का अधिकार होगा।
- अधिनियम में डाक अधिकारी द्वारा डाक वस्तुओं को अनधिकृत रूप से खोलने के लिए कोई अपराध या दंड निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
- यह डाकघर को ऐसी सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति देता है जो केंद्र सरकार निर्धारित करे।
- यह केंद्र सरकार को भारत और उक्त देश या क्षेत्र के बीच डाक सेवाओं के लिए विदेशी देशों या क्षेत्रों के साथ की गई व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाने का निर्देश देता है।

भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को क्यों बदला गया?

- भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को 1898 में डाकघर के कामकाज को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, जोकि मुख्य रूप से डाकघर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली मेल सेवाओं से संबंधित था।
- वर्तमान में डाकघर के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं में विविधता आ रही है और डाकघर नेटवर्क विभिन्न प्रकार की नागरिक-केंद्रित सेवाओं के वितरण का माध्यम बन रहा है।
- इसके अलावा, डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ बैंकिंग सेवाएँ भी शुरू की हैं, जिसके कारण एक नए कानून की आवश्यकता थी।

निष्कर्ष:

डाकघर अधिनियम 2023 एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य भारतीय डाक सेवा, इंडिया पोस्ट को आधुनिक बनाना और उसे अधिक कुशल और ग्राहक-केंद्रित संगठन में बदलना है। अत: अधिनियम का उद्देश्य डाक सेवा को और अधिक कुशल, ग्राहक-अनुकूल और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उसमें सुधार करना है, साथ ही देश के वित्तीय समावेशन और ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी भूमिका को बढ़ाना है।

सागर विजन और इंडो पैसिफिक रणनीति को धार देती नवनियुक्त भारत सरकार

हिंद महासागर क्षेत्र में ब्लू वॉटर नेवी फोर्स के रूप में भारत को समुद्री क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने और इसके लिए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को संस्थागत रूप देने का प्रयास करने वाले देश भारत के प्रधानमंत्री पुनः सत्ता ग्रहण कर चुके हैं। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी देश खासकर हिंद महासागर के महत्वपूर्ण देशों मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, मारीशस को आमंत्रित किया और इसके जरिए सागर विजन एवं इंडो पैसिफिक रणनीति से जुड़ी कूटनीति को फिर से ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया है।

हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं समुद्री खतरों को रोकने हेतु विभिन्न पक्षों व देशों के मध्य सहयोग को बढ़ाने एवं साझा समुद्री लाभ को प्राप्त करने हेतु संवाद एवं सहचर स्थापित किया जा रहा है। इसी संदर्भ में, हाल ही में भारत ने हिंद महासागर में द्वीपीय कूटनीति और विस्तारित पड़ोसी (एक्सटेंडेड नेबरहुड) की नीति के औचित्य को विभिन्न पहलों के माध्यम से व्यक्त किया है। इसके अंतर्गत भारत ने मारीशस को अपना विस्तारित पड़ोसी देश घोषित किया है। साथ ही भारत व्यापक अर्थों में हिंद महासागर क्षेत्र को भी अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड के रूप में देखता है। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल प्रचंड को भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया। दरअसल, हाल के समय में जिस तरह से नेपाल के साथ काला पानी, लिपुलेख विवाद उभरता रहा है और फिर नेपाल ने अपनी मुद्रा पर इन क्षेत्रों को दर्शाया है, उसके बाद से यह माना जा रहा था कि नेपाल के साथ संबंधों को और सामान्य करने के लिए भारत सरकार कुछ न कुछ सकारात्मक कदम उठाएगी और इसके लिए नेपाल को आमंत्रित किया गया।

उल्लेखनीय है कि हाल के समय में नेपाल और भारत के बीच पहली बार मनी लांड्रिंग से निपटने को लेकर बैठक हुई है जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि भारत नेपाल के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही भारत सरकार यह भी जानती है कि अपनी संबंधों में चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। इसका प्रमाण भी हाल के समय में मिला है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान विवादित मुद्दों को फिर से उठाया है। नेपाल के विवादित नक्शे वाले 100 रुपये के नोट के बाद अब प्रचंड ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से कालापानी सीमा विवाद को सुलझाने और सार्क को फिर से आगे बढ़ाने के लिए कहा है। पाकिस्तान की आतंकी चाल को देखते हुए भारत ने सार्क को किनारे कर दिया है जो नेपाल को रास नहीं आ रहा है। नेपाल में ही सार्क का मुख्यालय है और पाकिस्तान लगातार दबाव डाल रहा है कि इस दक्षिण एशियाई संगठन को फिर से आगे बढ़ाया जाए। अब भारतीय कूटनीति पर निर्भर करता है कि भारत इस मुद्दे से कैसे निपटता है। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू को आमंत्रित कर भारत ने मालदीव को भी एक नया अवसर दिया है कि वो भारत से अपने तनावपूर्ण संबंधों को ठीक कर सके।

वहीं दूसरी तरफ भारत अपने नए नेतृत्व के जरिए हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता को बढ़ावा देने की मंशा रखता है। भारत चाहता है कि ऐसे देश उसे विशुद्ध रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखें और ऐसा हो भी रहा है। भारत ने कोविड महामारी के दौरान हिंद महासागर के देशों के मन में उस विश्वास का बीजारोपण करने में प्रभावी बढ़त हासिल कर ली है जिसे चीन जैसे देश नैतिक रूप से हासिल कर पाने में कभी सक्षम नहीं होंगे और यही भारत की उपलब्धि भी है। भारत के विदेश मंत्री की मालदीव और मॉरीशस यात्रा के दौरान भारत ने दोनों देशों के उन आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश पर ध्यान दिया है जो इन दोनों को कुछ जरूरी आर्थिक सामरिक, प्रतिरक्षा मामलों में सशक्त और समर्थ बनाए।

भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और सहभागिता समझौता किया गया जो इस बात का प्रतीक है कि भारत हिन्द महासागर के इस देश के साथ अपने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देने की इच्छा रखता है। ऐसे समझौते ही आगे कभी मुक्त व्यापार समझौते में तब्दील हो जाते हैं।

भारत ने मॉरीशस के साथ 100 मिलियन डॉलर का एक डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता भी संपन्न किया था। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे को सर्जिकल उपकरणों, मेडिसिन और टेक्सटाइल उत्पादों आदि पर वरीयतामूलक पहुंच अपने अपने बाजारों तक देंगे। इसके तहत मॉरीशस भारतीय बाजार तक 40 हजार टन चीनी के निर्यात के लिए वरीयता मूलक पहुंच की सुविधा प्राप्त करेगा। इससे मॉरीशस को भारत से प्रतिरक्षा परिसंपत्तियों और उपकरणों की प्राप्ति करने में मदद मिलेगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री इकाई के रूप में उभर रहे मॉरीशस को ऐसी सुविधा प्राप्त करना औचित्यपूर्ण भी है। मॉरीशस की सुरक्षा भारत की सुरक्षा और मॉरीशस की संपन्नता भारत की संपन्नता है। इस दृष्टिकोण पर काम करते हुए यह तय किया गया है कि मॉरीशस भारत से एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट प्राप्त करेगा और साथ ही एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव पट्टे पर प्राप्त करेगा जिससे उसकी सामुद्रिक सुरक्षा क्षमता में वृद्धि हो सकेगी।

हिंद महासागर में आत्म निर्धारण के अधिकार पर बलः

- भारत और मॉरीशस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्व ीप विवाद पर भी चर्चा किया। इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र एक द्विपीय संप्रभुता और सतत विकास के मुद्दे के रूप में देखता है। वर्ष 2019 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में चागोस द्वीप पर ब्रिटेन की बजाय मॉरीशस के स्वामित्व को मान्यता देने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था।
- भारत उन 116 देशों में शामिल था जिन्होंने यह मांग की थी कि ब्रिटेन मॉरीशस के इस द्वीप पर अपना उपनिवेशीय प्रशासन खत्म करे। चूंकि भारत अपनी विदेश नीति के तहत तृतीय विश्व के देशों सहित हिंद महासागर के देशों के आत्म निर्धारण के अधिकार को मान्यता देता है, अतः हाल के समय में उसने अपनी आइलैंड डिप्लोमेसी के तहत हिंद महासागर के द्विपीय देशों की सुरक्षा, संप्रभुता, विकास के मुद्दे को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए काम किया है।
- भारत ने स्पष्ट किया है कि चागोस द्वीप के मामले पर भारत मॉरीशस को दृढ सैद्धांतिक समर्थन देना जारी रखेगा। मॉरीशस का कहना है कि चागोस द्वीप 18 वीं शताब्दी से ही उसका भाग रहा है और तब तक रहा जब तक कि ब्रिटेन ने 1965 में इसे उपनिवेश के रूप में अपने नियंत्रण में नहीं ले लिया। मॉरीशस के ब्रिटेन से आजाद होने के तीन वर्ष पूर्व ही ब्रिटेन ने मॉरीशस के प्रादेशिक अखंडता से खिलवाड़ करते हुए चागोस द्वीप के सामरिक स्थल डियागो ग्रेसिया को अमेरिका को अपना सैन्य अड्डा खोलने के लिए पट्टे पर दे दिया था।
- यही नहीं ब्रिटेन ने सेशेल्स से अल्दाब्रा, फरकुहर और डेशरोचेज द्वीपों को लेकर ब्रिटिश इंडियन ओसियन टेरीटोरी का निर्माण किया था। जून, 1976 में जब सेशल्स को ब्रिटेन से आजादी मिली तब ब्रिटेन ने इन द्वीपों को सेशेल्स को वापस सौंप दिया था।
- हिन्द महासागर में मालदीव के क्षेत्र में स्थित अंतरराष्ट्रीय समुद्री जहाजी मार्ग मध्य पूर्व से तेल की आपूर्ति भारत जापान और चीन को करते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से भारत का 97 प्रतिशत से अधिक और मूल्यात्मक दृष्टि से 75 प्रतिशत से अधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार हिन्द महासागर में बैठे मालदीव के अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शिपिंग मार्ग के जरिए होता है। मालदीव भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी अथवा सागरीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भी यह जरूरी है।

हिंद महासागर में सागर विजन और सागर मिशनः

- मई, 2020 में भारत ने मिशन सागर लॉन्च किया था जिसका उद्देश्य हिंद महासागर के क्षेत्रों में अपनी मेडिकल डिप्लोमैसी की धार तेज करते हुए क्षेत्र के देशों को कोविड 19 से जुड़ी सहायता प्रदान करना था। इस मिशन के भाग के रूप में आईएनएस केशरी ने मालदीव, मॉरीशस, मेडागास्कर, कोमोरॉस और सेशल्स की यात्रा की थी और अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड की धारणा के तहत इन समुद्री पड़ोसियों कोविड महामारी से बचाने के लिए मदद दी गई। 55 दिनों तक 7,500 नॉटिकल मील की यात्रा करते हुए आईएनएस केशरी ने भारत के सागर विजन को साकार करने के लिए मिशन सागर को आकार दिया।
- मॉरीशस और कोमोरोस द्वीप को तो भारत ने मानवतावादी सहायता के नाम पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं, दवाइयों, आयुर्वेदिक औषधियों की आपूर्ति की थी और इन दोनों देशों में मेडिकल एसिस्टेंस टीम भी भेजी थी। मिशन सागर भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 में अपनाए गए सागर विजन का ही मूर्तमान स्वरूप है। सागर विजन का आशय है, हिंद महासागर क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और संवृद्धि।

इंडो पैसिफिक रणनीति को धार देता भारतः

- 2018 में सिंगापुर में शांगरी-ला संवाद में भारतीय प्रधानमंत्री ने इंडो पैसिफिक की धारणा को स्पष्ट करते हुए बताया था कि इसमें समूचे हिंद महासागर से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक का क्षेत्र शामिल है। इसमें भारतीय दृष्टिकोण से अफ्रीका, अमेरिका और जापान के क्षेत्र शामिल हैं। भारत का इंडो पैसिफिक रणनीति इन सब भौगोलिक आयामों को शामिल करते हुए आसियान केंद्रीयता को भारतीय इंडो पैसिफिक रणनीति का आधार स्तंभ मानती है।
- समावेशिता और खुलापन भारत की इस नीति के अनिवार्य अंग हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय हितों की रक्षा के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब एक्ट इंडो पैसिफिक पॉलिसी में बदलती नजर आ रही है। दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया के देशों के साथ चलते हुए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत अपने हितों के क्रम में चीन को प्रतिसंतुलित करने का प्रयास करता रहा है और इसके साथ ही अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को इंडो पैसिफिक की सुरक्षा रणनीति का भाग बनाने में भारत काफी हद तक सफल भी रहा है लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह

है कि फ्री एंड ओपेन इंडो पैसिफिक रणनीति को आज यूरोपीय देशों द्वारा मान्यता मिलने लगी है। वर्ष 2018 में फ्रांस ने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की थी जबकि अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और क्वाड सुरक्षा समूह से अपने गठजोड़ के चलते भारत आज भारतीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महासागरीय संप्रभुता की सुरक्षा को एक वैश्विक महत्व का मुद्दा बनाने में लगा है और इसका परिणाम यह मिला है कि जर्मनी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लोकतांत्रिक देशों के साथ भागीदारी मजबूत करने के लिए नई इंडो पैसिफिक पॉलिसी बनाई है जिसका समर्थन भारत, जापान और आसियान देशों ने कर दिया है।

- भारत ने सागरों और महासागरों की सुरक्षा को विश्व और क्षेत्रीय राजनीति में एक नया आयाम दिया है। भारत ने हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर में नौ गमन की स्वतंत्रता, महत्त्वपूर्ण वाणिज्यिक समुद्री मार्गों से अबाधित आवाजाही को एक नया वैश्विक आंदोलन बना दिया है जिसमें उसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत आसियान, पूर्वी एशियाई और अफ्रीकी देशों का सहयोग मिला है। यही कारण है कि भारत ने 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना था। इस पॉलिसी में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ सहयोग के अलावा एशिया पैसिफिक के अन्य देशों के साथ सहयोग, समन्वय पर बल दिया गया।
- इस पॉलिसी के एक अपरिहार्य हिस्से के रूप में भारत ने जापान की पहचान की और यही कारण है कि वर्ष 2015 में दोनों देशों ने 'जापान भारत विजन 2025 विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी' की घोषणा की जिसका मुख्य उद्देश्य हिन्द प्रशांत क्षेत्र और विश्व में शांति और समृद्धि के लिए काम करना है। हाल ही में कनाडा ने भी जापान के साथ मिलकर मुक्त और स्वतंत्र इंडो पैसिफिक क्षेत्र की आवश्यकता पर बल देते हुए अपनी इंडो पेसिफिक पॉलिसी बनाने का संकेत दिया है। ब्रिटेन ने भी इंडो पैसिफिक रणनीति में रुचि लेनी शुरू कर दी है। इस प्रकार चीन द्वारा वैश्विक विधियों के अतिक्रमण को रोकने के लिए यूरोप के कई देश लगातार इंडो पैसिफिक के मुद्दे पर लामबंद हो रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय संक्षिप्त मुद्दे

जापान का सुरक्षा विमर्श

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और जापान के मध्य नई दिल्ली में संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक आयोजित की गई जिसमें राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों सहित आतंकवाद के खतरों और चुनौती से एकजुट होकर निपटने के तरीकों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

बैठक की मुख्य बातें:

- दोनों पक्षों ने अपने-अपने क्षेत्रों में आतंकवादी खतरों पर विचारों का आदान-प्रदान किया, जिसमें दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व में राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद, साथ ही अफगान-पाक क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियाँ शामिल हैं।
- दोनों पक्षों ने आतंकवादियों द्वारा नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग, आतंकवादी उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का दुरुपयोग, कट्टरपंथ और आतंकवाद के वित्तपोषण सहित आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का आकलन किया। आतंकवाद के वित्तपोषण, संगठित अपराध और नार्को-आतंक नेटवर्क का मुकाबला करने पर भी चर्चा हुई।
- दोनों पक्षों ने सूचना के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अभ्यासों और संयुक्त राष्ट्र,फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) और क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के माध्यम से आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया।
- दोनों पक्षों ने टोक्यो में आतंकवाद निरोध पर जेडब्ल्यूजी की 7वीं बैठक पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की।

आतंकवाद-विरोधी मुद्दों पर जापान:

- जापान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर खतरों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाने के लिए FATF जैसे महत्वपूर्ण मंचों के माध्यम से चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
- जापान, अफ्रीका में शांति और स्थिरता के लिए नए दृष्टिकोण (NAPSA) के तहत अफ्रीकी नेतृत्व वाले प्रयासों का समर्थन करता है, जिसे 7वें टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी विकास सम्मेलन (TICAD 7) में लॉन्च किया गया था। इसमें G5 साहेल और पड़ोसी देशों में स्थानीय प्रशासन क्षमताओं को मजबूत करना शामिल है।
- 'जापान और भारत विजन 2025' का एक महत्वपूर्ण तत्व भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और जापान की 'गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए साझेदारी' के बीच संरेखण है, जिसका उद्देश्य

गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के माध्यम से क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। मार्च 2022 में अपनी भारत यात्रा के दौरान, जापानी प्रधानमंत्री किशिदा ने अगले पांच वर्षों के लिए भारत में 5 ट्रिलियन येन (लगभग $37 बिलियन) के निवेश लक्ष्य की घोषणा की।

युद्ध के बाद जापान का शांतिवाद:

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जापान ने शांतिवाद की नीति अपनाई। इसने महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण, सीमित रक्षा खर्च और संघर्षों में सैन्य भागीदारी से दूरी बनायी। यह शांतिवाद जापान की युद्ध-पूर्व वर्षों में अपने सैन्यवादी और साम्राज्यवादी कार्यों के लिए प्रायश्चित करने की इच्छा से उपजा था।
- तब जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक द्विपक्षीय सैन्य गठबंधन बनाया। एशिया में अमेरिका के संरक्षण में, जापान अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर सकता था।
- 1960 के दशक के अंत तक, जापान एक वाणिज्यिक और तकनीकी महाशक्ति के रूप में उभरा था। 1970 के दशक की शुरुआत में, यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी, जो केवल अमेरिका से पीछे थी।
- 21वीं सदी में जापान के पुनर्निर्देशन में कई कारकों ने योगदान दिया है।

बाहरी मोर्चे पर, चार तत्व एक साथ आए हैं:

- चीन का उदय और उसका सैन्य दावा, विशेष रूप से जापान के साथ क्षेत्रीय विवादों पर इंडो-पैसिफिक में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों की पृष्ठभूमि में, भारत और जापान ने एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और लचीले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। जापान की मुक्त और खुली इंडो-पैसिफिक (FOIP) रणनीति और भारत की इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (IPOI) क्षेत्र में उनकी रणनीतिक साझेदारी और सहयोग को गहरा करने के लिए रूपरेखा के रूप में काम करती है।
- बीजिंग और मॉस्को के बीच गहराते सैन्य संबंध और उत्तर पूर्व एशिया में उनकी नीतियों का समन्वय।
- उत्तर कोरिया की बढ़ती सैन्य क्षमताएँ और यह आशंका कि अमेरिका जापान और अन्य एशियाई सहयोगियों को अपनी सुरक्षा सुरक्षा वापस ले सकता है।
- टोक्यो में रूढ़िवादी जापान को एक 'सामान्य शक्तिशाली देश' बनने की वकालत करते हैं। उनका तर्क है कि जापान ने एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के रूप में अपनी साख को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित किया है और अब उसे अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और क्षेत्रीय व्यवस्था में योगदान देना चाहिए।

भू-राजनीतिक शक्ति बनने के लिए जापान द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम:

- **रक्षा व्यय में वृद्धि:** जापान ने रक्षा व्यय पर अपनी पुरानी सीमा हटा दी है, जो पहले अनौपचारिक रूप से सकल घरेलू उत्पाद के 1% पर निर्धारित थी। विश्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि 2020 में, जापान का सैन्य व्यय छह दशकों में पहली बार सकल घरेलू उत्पाद का 1% तक पहुंच गया, जो 2022 में बढ़कर 1.1% हो जाएगा।
- किशिदा सरकार ने 2027 तक वार्षिक रक्षा खर्च को दोगुना करके लगभग 10 ट्रिलियन येन ($68 बिलियन) करने का संकल्प लिया है, जिससे जापान संभवत: अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन जाएगा।
- **बढ़ती हुई जवाबी हमला क्षमता:** जापान ने क्रूज मिसाइलों के माध्यम से अपनी खुद की जवाबी हमला क्षमता हासिल कर ली है और उसे और विकसित कर रहा है। अमेरिका के साथ हाल ही में हुए एक समझौते के तहत जापान को 400 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें खरीदने की अनुमति मिल गई है, जो चीन और उत्तर कोरिया में अंदर तक हमला करने में सक्षम हैं।

घातक हथियारों के निर्यात प्रतिबंध में ढील:

- जापान की कैबिनेट ने मित्र देशों को घातक हथियारों के निर्यात पर अपने द्वारा लगाए गए प्रतिबंध में ढील दी हैं।
- जापान ने अमेरिका को जापानी निर्मित पैट्रियट मिसाइलों की खेप को मंजूरी दी।
- जापान प्रस्तावित छठी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर बीएई सिस्टम को विकसित करने के लिए यू.के. और इटली के साथ ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहा है।
- किशिदा की यात्रा के दौरान, जापान और अमेरिका ने हथियारों के सह-उत्पादन की सुविधा के लिए एक संयुक्त सैन्य-औद्योगिक परिषद के निर्माण को अंतिम रूप दिया।

निष्कर्ष:

पिछले दो दशकों में जापान के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों ने एक राजनीतिक चरित्र हासिल कर लिया है। एक राजनीतिक रूप से दृढ़ और सैन्य रूप से मजबूत जापान जो एक स्थिर एशियाई संतुलन का निर्माण कर सकता है, जो भारतीय दृष्टिकोण से एक सकारात्मक विकास है। यह एक बहुध्रुवीय दुनिया में एक बहुध्रुवीय एशिया के निर्माण के भारत के उद्देश्य में योगदान देता है।

बायोफार्मास्युटिकल एलायंस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ (ईयू) ने बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने हेतु गठबंधन शुरू करने का निर्णय लिया हैं।

मुख्य बिंदु:

- कोविड-19 महामारी के दौरान दवा आपूर्ति में कमी को देखते हुए यह गठबंधन बनाया गया। इसके सदस्यों ने एक विश्वसनीय और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला के महत्त्व पर जोर दिया और अपने-अपने देशों की जैव नीतियों, विनियमों और अनुसंधान और विकास सहायता उपायों का समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की।

➢ उन्होंने स्वीकार किया कि आवश्यक कच्चे माल और सामग्री का उत्पादन कुछ ही देशों में केंद्रित है और एक विस्तृत दवा आपूर्ति श्रृंखला मानचित्र बनाने पर सहयोग करने के लिए सहमत हुए। इस गठबंधन का उद्घाटन सैन डिएगो में बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान किया गया था।

–: प्रीलिम्स इनसाइट :–

बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के बारे में:

➢ बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए अग्रणी कार्यक्रम है, जिसमें वैश्विक स्तर पर 20,000 से अधिक नेता एकत्रित होते हैं।

➢ इसमें सार्वजनिक दवा कंपनियों, बायोटेक स्टार्टअप, शिक्षाविदों, गैर-लाभकारी संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों सहित संपूर्ण बायोटेक पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है।

बायोफार्मास्युटिकल्स क्या हैं?

➢ बायोफार्मास्युटिकल्स बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाई गई चिकित्सा दवाएँ हैं। इनमें प्रोटीन (जैसे एंटीबॉडी) और न्यूक्लिक एसिड (डीएनए, आरएनए, या एंटीसेंस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड) शामिल हैं जिनका उपयोग चिकित्सीय या इन विवो डायग्नोस्टिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

➢ वे किसी देशी, गैर-इंजीनियर्ड जैविक स्रोत से सीधे निष्कर्षण के अलावा अन्य तरीकों से उत्पादित किए जाते हैं। चिकित्सीय उपयोग के लिए स्वीकृत पहला बायोफार्मास्युटिकल पुन: संयोजक मानव इंसुलिन था, जिसे जेनेंटेक द्वारा विकसित किया गया था और 1982 में एली लिली द्वारा विपणन किया गया था।

भारत में दवा उद्योग:

➢ भारत दुनिया भर में दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माता के रूप में तीसरे स्थान पर है, जो लगभग 200 देशों/क्षेत्रों को निर्यात करता है।

➢ भारतीय दवा उद्योग टीकों की वैश्विक मांग का 62% आपूर्ति करता है और डीपीटी (डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस), बीसीजी (बैसिलस कैलमेट-गुएरिन, मुख्य रूप से तपेदिक के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है) और खसरे के टीकों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। WHO के कम से कम 70% टीके (आवश्यक टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार) भारत से प्राप्त होते हैं।

निष्कर्ष:

भारत ने अपने मजबूत जेनेरिक दवा उद्योग के कारण 'विश्व की फार्मेस' का खिताब अर्जित किया है, जो वैश्विक स्तर पर सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ प्रदान करता है। एचआईवी/एड्स महामारी के दौरान यह प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई थी जब भारतीय कंपनियों ने अफ्रीकी देशों को सस्ती एंटीरेट्रोवायरल दवाइयाँ उपलब्ध कराई थीं। इस योगदान ने न केवल कम लागत पर आवश्यक दवाओं का उत्पादन करने की भारत की क्षमता को उजागर किया, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। यह गठबंधन वैश्विक स्वास्थ्य सेवा चुनौतियों का समाधान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे विश्व मंच पर इसकी स्थिति और मजबूत होगी।

पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन और भारत की सहायता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित देश पापुआ न्यू गिनी को तत्काल सहायता के रूप में $1 मिलियन की राशि प्रदान की है। इस आपदा में जान-माल की बहुत हानि हुई है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु:

➢ हाल ही में हुए भूस्खलन ने पापुआ न्यू गिनी के लगभग 4,000 निवासियों वाले एक गांव यंबली के समुदाय को तबाह कर दिया है।

➢ आपदा ने राजधानी पोर्ट मोरेस्बी से 600 किलोमीटर (370 मील) उत्तर-पश्चिम में स्थित, गांव की निर्वाह खेती के लिए महत्वपूर्ण सभी खाद्य उद्यानों को नष्ट कर दिया है और पीने का पानी उपलब्ध कराने वाली तीन जलाशयों को नुकसान पहुचायां।

➢ पापुआ न्यू गिनी की चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है, जहां प्रमुख शहरों के बाहर कुछ ही सुलभ सड़कें हैं, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच में बाधा आ रही है।

➢ आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ताओं को मलबे में संभावित रूप से परेशान करने वाले शवों से संबंधित जोखिमों और सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं के कारण खुदाई के लिए भारी मशीनरी का उपयोग करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

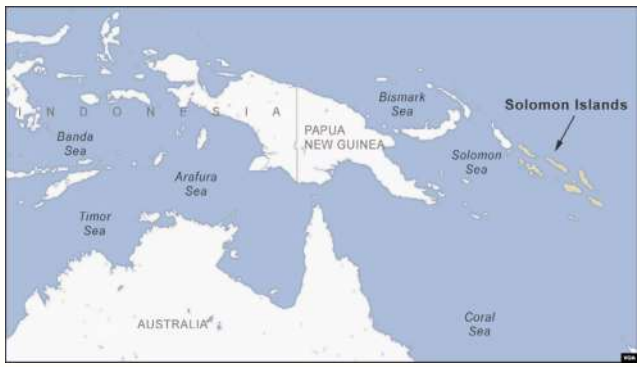

पापुआ न्यू गिनी के बारे में:

➢ पापुआ न्यू गिनी दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है, जिसमें न्यू गिनी द्वीप (दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा

द्वीप) का पूर्वी भाग शामिल है।

- द्वीप का पश्चिमी आधा हिस्सा इंडोनेशियाई प्रांतों पापुआ और पश्चिमी पापुआ का हिस्सा है।
- इसके पड़ोसियों में पश्चिम में इंडोनेशिया, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व में सोलोमन द्वीप शामिल हैं।
- पापुआ न्यू गिनी का गठन करने वाले द्वीपों पर 40,000 वर्षों की अवधि में लोगों के मिश्रण द्वारा बसाया गया था, जिन्हें आम तौर पर मेलानेशियन कहा जाता है।
- पापुआ न्यू गिनी भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC) का सदस्य है। भारत FIPIC के माध्यम से प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ सहयोग को बढ़ावा दे रहा है।

–: प्रीलिम्स इनसाइट :–

भारत–प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC):

- FIPIC 2014 में शुरू किया गया एक मंच है, जिसका उद्देश्य 14 प्रशांत द्वीप देशों (PIC) - कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वानुअतु (सभी प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में स्थित हैं) के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है।

भारत में भूस्खलन के बारे में:

- भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष पाँच भूस्खलन-प्रवण देशों में से एक माना जाता है, जहाँ हर साल भूस्खलन के कारण प्रति 100 वर्ग किमी में कम से कम एक मौत होती है।
- वर्षा की परिवर्तनशीलता देश में भूस्खलन का प्राथमिक कारण है, जिसमें हिमालय और पश्चिमी घाट विशेष रूप से संवेदनशील हैं। बर्फ से ढके क्षेत्रों को छोड़कर, भारत के भौगोलिक भूमि क्षेत्र का लगभग 12.6% (0.42 मिलियन वर्ग किमी) भूस्खलन से ग्रस्त है।
- उत्तर-पश्चिमी हिमालय में भूस्खलन की 66.5% घटनाएं होती हैं, उत्तर-पूर्वी हिमालय में 18.8% और पश्चिमी घाट में 14.7%।

निष्कर्ष:

भारत ने 2018 के भूकंप और 2019 और 2023 में ज्वालामुखी विस्फोटों जैसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान पापुआ न्यू गिनी का लगातार समर्थन किया है। नवंबर 2019 में भारत में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई भारत की इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (IPOI) का एक आवश्यक घटक आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन है। भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) के लिए समर्पित है, एक विश्वसनीय और अटूट प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखता है।

ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 10 जून को रूस के निजनी नोवगोरोड में ब्रिक्स देशों के विदेश मामलों के मंत्रियों की बैठक हुई। यह 2023 में ब्रिक्स विस्तार के बाद पहली मंत्रिस्तरीय बैठक थी, जब मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए थे।

बैठक की मुख्य बातें:

- ब्रिक्स ने सदस्य देशों के बीच व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ाने का आह्वान किया।
- मंत्रियों ने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के व्यापक सुधार का आह्वान किया।
- मंत्रियों ने पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के 2025 शेयरधारक समीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने का आग्रह किया।
- मंत्रियों ने एक मजबूत, कोटा-आधारित और पर्याप्त रूप से संसाधन वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ एक मजबूत वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट का समर्थन किया।
- मंत्रियों ने IMF शासन सुधार की निरंतर प्रक्रिया पर जोर दिया, जिसमें इसके सदस्यों के आर्थिक आकार को दर्शाते हुए एक नया कोटा फॉर्मूला बनाना शामिल है।
- मंत्रियों ने अपनी ऋण देने की क्षमता बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDB) की नीतियों और प्रथाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।
- मंत्रियों ने नए विकास बैंक को सदस्य-नेतृत्व और मांग-संचालित सिद्धांत का पालन करने, विविध स्रोतों से वित्तपोषण जुटाने के लिए अभिनव वित्तपोषण तंत्र को नियोजित करने, क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।
- मंत्रियों ने विकास बैंक को 21वीं सदी के एक नए प्रकार के बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में विकसित करने पर सहमति व्यक्त की।
- मंत्रियों ने ब्रिक्स देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने का इरादा व्यक्त किया और सस्ती, सुलभ, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास पर चर्चा की।

ब्रिक्स के बारे में:

- संक्षिप्त नाम BRIC, जिसमें शुरू में दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था, 2001 में तत्कालीन गोल्डमैन सैक्स के मुख्य अर्थशास्त्री जिम ओशनील द्वारा एक शोध पत्र में ब्रिक गढ़ा गया था, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन की विकास क्षमता को रेखांकित किया गया था।
- ब्लॉक की स्थापना 2009 में एक अनौपचारिक क्लब के रूप में की गई थी ताकि इसके सदस्यों को संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के प्रभुत्व वाली विश्व व्यवस्था को चुनौती देने

के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके।
- इसके निर्माण की पहल रूस ने की थी।
- यह समूह संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक या पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) जैसा औपचारिक बहुपक्षीय संगठन नहीं है। सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख सालाना बैठक करते हैं और प्रत्येक देश एक साल के लिए समूह की अध्यक्षता करता है।

ब्रिक्स समूह के सदस्य देश:
- ब्राजील
- रूस
- भारत
- चीन
- दक्षिण अफ्रीका
- ईरान (1 जनवरी, 2024 को शामिल हुआ)
- मिस्र (1 जनवरी, 2024 को शामिल हुआ)
- इथियोपिया (1 जनवरी, 2024 को शामिल हुआ)
- संयुक्त अरब अमीरात (1 जनवरी, 2024 को शामिल हुआ)

निष्कर्ष:
ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने अपने आर्थिक सहयोग को मजबूत करने, वैश्विक वित्तीय प्रशासन में सुधार करने और विकास और स्थिरता का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की क्षमता बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है।

कफाला प्रणाली के अंतर्गत श्रमिक

चर्चा में क्यों?
हाल ही में कुवैत के मंगाफ में लगी आग में 49 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर कफाला व्यवस्था में निहित व्यवस्थागत समस्याओं और शोषण को उजागर किया है।

कफाला प्रणाली क्या है?
- कफाला या प्रायोजन प्रणाली विदेशी कर्मचारियों और उनके स्थानीय प्रायोजक या कफील के बीच संबंधों को परिभाषित करती है, जो आमतौर पर उनका नियोक्ता होता है।
- इसका इस्तेमाल खाड़ी सहयोग परिषद के देशों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ-साथ जॉर्डन और लेबनान में भी किया गया है।
- इस प्रणाली के अंतर्गत, राज्य स्थानीय व्यक्तियों या कंपनियों को विदेशी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रायोजन परमिट देता है।
- प्रायोजक यात्रा व्यय वहन करता है और आवास उपलब्ध कराता है।
- किसी व्यक्ति को सीधे तौर पर नौकरी पर रखने के बजाय, प्रायोजक कभी-कभी श्रमिकों को खोजने और मेजबान देश में उनके प्रवेश को सुगम बनाने के लिए मूल देश में निजी भर्ती एजेंसियों का उपयोग करते हैं।

कफाला प्रणाली की चुनौती:
कफाला प्रणाली के अंतर्गत श्रमिकों को अनेक प्रकार के दुर्व्यवहारों का सामना करना पड़ता है। इनमें शामिल हैं:
- **प्रतिबंधित आवागमन और संचार:** नियोक्ता नियमित रूप से पासपोर्ट, वीजा और फोन जब्त कर लेते हैं तथा घरेलू कामगारों को उनके घरों तक ही सीमित रखते हैं।
- **ऋण बाध्यता:** यद्यपि अधिकांश मेजबान देशों में नियोक्ताओं को भर्ती शुल्क का भुगतान करना होता है, लेकिन अक्सर यह शुल्क श्रमिकों पर डाल दिया जाता है, जो इसे चुकाने के लिए ऋण लेते हैं या भर्तीकर्ता के ऋणी हो जाते हैं।
- **वीजा व्यापार:** प्रायोजक कभी-कभी आधिकारिक प्रायोजक बने रहते हुए किसी श्रमिक का वीजा अवैध रूप से किसी अन्य नियोक्ता को बेच देते हैं।

कफाला प्रणाली से लाभ:
कफाला प्रणाली पर विश्व की प्रतिक्रिया:
- श्रम अधिकार अधिवक्ता लंबे समय से इस प्रणाली में सुधार या इसे समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, इन मांगों पर 2020 में दुनिया भर में हुए नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनों के मद्देनजर अधिक ध्यान दिया गया।
- 2022 फीफा विश्व कप ने मेजबान देश कतर द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों पर भी प्रकाश डाला है।

आगे की राह:
यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित बहुराष्ट्रीय संगठनों ने भी कफाला प्रणाली की आलोचना की है, हालांकि किसी ने भी इसके खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इस प्रणाली को खत्म करने और प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के लिए मजबूत सुरक्षा स्थापित करने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। इन उपायों में प्रायोजन की आवश्यकता को समाप्त करना, कानूनी सुरक्षा लागू करना, भर्ती शुल्क समाप्त करना, न्याय तक पहुँच बढ़ाना, श्रमिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना और पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाना शामिल है।

जिग-जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण मुद्रा

चर्चा में क्यों?
हाल ही में जिम्बाब्वे ने दशकों से देश को त्रस्त करने वाली मुद्रा

अस्थिरता और अत्यधिक मुद्रास्फीति को कम करने के प्रयास में, ZiG या जिम्बाब्वे गोल्ड नामक एक नई स्वर्ण-आधारित मुद्रा शुरू की।

संकट की उत्पत्तिः

- 2008 में, मुद्रास्फीति की दर अत्यधिक बढ़ गई, जिसके कारण जिम्बाब्वे डॉलर का मूल्य गिर गया और सरकार को 2009 में इसे त्यागना पड़ा। तब से अमेरिकी डॉलर और अन्य विदेशी मुद्राओं का अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता रहा है।
- हाल के वर्षों में जिम्बाब्वे की मुद्रास्फीति दर 500% से अधिक हो गई है। मार्च 2024 में, मूल्य वृद्धि की वार्षिक दर 55.3% है, जो सात महीने का उच्चतम स्तर है।
- कई जिम्बाब्वेवासी अमेरिकी डॉलर के लेनदेन को पसंद करते हैं, जो लगभग 85% लेन-देन के लिए जिम्मेदार है। जिससे इसकी अर्थव्यवस्था पर सीमित नियंत्रण हो गया।

नई मुद्रा के प्रभावः

- जिग एक नई मुद्रा है जो स्वर्ण आधारित है, जिसका उद्देश्य स्थिरता प्रदान करना तथा मुद्रा अवमूल्यन को रोकना है।
- जिम्बाब्वे ने आधिकारिक विनिमय दर पर लेनदेन न करने पर जुर्माना लगाया है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि उद्योगों के विकास और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए स्थिर मुद्राएं और विश्वसनीय आर्थिक स्थितियां महत्वपूर्ण हैं।
- जिग, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और वर्षों की मुद्रा अस्थिरता के बाद जिम्बाब्वे की वित्तीय प्रणाली में जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए एक स्थिर आधार स्थापित करके जिम्बाब्वे की पिछली आर्थिक चुनौतियों से दूर एक अधिक सुरक्षित मौद्रिक भविष्य की ओर बदलाव का प्रतीक है।
- पूरे अफ्रीका में स्थानीय मुद्राओं के लिए भुगतान प्रणाली को बेहतर बनाने के प्रयास चल रहे हैं। उदाहरण के लिए, पैन-अफ्रीकन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (PAPSS) जो कि जिग जिंबॉब्वे के स्थानीय मुद्रा का प्रतीक होगा।

आगे की राहः

जिम्बाब्वे की मुद्रा संबंधी समस्या दक्षिणी अफ्रीकी देश का 15 वर्षों में स्थिर स्थानीय मुद्रा स्थापित करने का छठा प्रयास है। राष्ट्रपति एमर्सन मनांगाग्वा के उन विदेशी निवेशकों को वापस अपने पक्ष में लाने के प्रयासों को मजबूत कर दिया है, जिन्हें उनके अपदस्थ पूर्ववर्ती रॉबर्ट मुगाबे के कार्यकाल में दरकिनार कर दिया गया था।

जी7 शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही मे इटली में 50वां जी7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत ने जी7 शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच देश के रूप में भाग लिया, जो इसकी 11वीं भागीदारी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी लगातार पाँचवीं बार शिखर सम्मेलन में शामिल हुए।

50वें जी7 शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँः

- **यूक्रेन का समर्थनः** जी7 देशों ने $50 बिलियन की नई वित्तपोषण योजना के साथ यूक्रेन के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।
- **आर्थिक सुरक्षाः** जी7 ने आर्थिक सुरक्षा, गैर-बाजार नीतियों और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पर ध्यान दिया।
- **जलवायु और ऊर्जाः** जी7 ने जलवायु कार्रवाई में तेजी लाई, 1,500 गीगावाट लंबी अवधि के ऊर्जा भंडारण का लक्ष्य निर्धारित किया और परमाणु ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में मान्यता दी।
- **एआई गवर्नेंसः** जी7 नेताओं ने अपने एआई गवर्नेंस दृष्टिकोणों के बीच अंतर-संचालन को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई।
- **वैश्विक अवसंरचनाः** जी7 ने $40 ट्रिलियन अवसंरचना अंतर को कम करने के लिए वैश्विक अवसंरचना और निवेश (पीजीआईआई) के लिए साझेदारी को बढ़ावा दिया।
- **क्षेत्रीय समर्थनः** लोबिटो कॉरिडोर, लूजोन कॉरिडोर और मिडिल कॉरिडोर सहित विभिन्न क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए समर्थन किया गया।
- **खाद्य सुरक्षाः** खाद्य सुरक्षा में संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए अपुलिया खाद्य सुरक्षा पहल शुरू की गई।
- **स्वास्थ्यः** जी7 ने टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए महामारी कोष और वैक्सीन एलायंस, गावी का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्धता जताई।

लोबिटो कॉरिडोर, लूजोन कॉरिडोर और मिडिल कॉरिडोर के बारे में:

- **लोबिटो कॉरिडोरः** यह कॉरिडोर एक रेलवे परियोजना है जो लोबिटो के अंगोलन बंदरगाह को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के कोलवेजी शहर से जोड़ती है। यह परियोजना अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच प्रदान करने में मदद कर सकती है।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC):

- यह कॉरिडोर एक कनेक्टिविटी परियोजना है जो भारत, अरब प्रायद्वीप, भूमध्यसागरीय क्षेत्र और यूरोप के बीच व्यापार को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढाँचे के बंदरगाह, रेलवे, सड़क, समुद्री रेखाएँ और पाइपलाइन विकसित करना चाहती है। इस परियोजना का उद्देश्य अफ्रीकी महाद्वीप तक अधिक पहुँच भी है।

लूजोन आर्थिक गलियाराः

- 11 अप्रैल, 2024 को पहले अमेरिकी-जापान-फिलीपींस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित एक परियोजना है। यह एक कनेक्टिविटी परियोजना है जो फिलीपींस में सुबिक बे, क्लार्क, मनीला और बटांगस के बीच कनेक्टिविटी का समर्थन करेगी।

वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी

(PGII) के बारे में:

- वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी (PGII) एक जी7 पहल है जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र से धन जुटाकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बुनियादी ढाँचा विकास प्रदान करना है।

जी7 के बारे में:

- जी7 की स्थापना 1975 में फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम जर्मनी द्वारा ग्रुप ऑफ सिक्स (G6) के रूप में की गई थी। अगले वर्ष कनाडा इसमें शामिल हो गया। रूस 1998 में समूह में शामिल हुआ, जिसके कारण इसका नाम बदलकर ग्रुप ऑफ ऐट (G8) कर दिया गया। हालाँकि, क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद 2014 में रूस को समूह से हटा दिया गया और समूह को फिर से जी7 कहा जाने लगा।

निष्कर्ष:

भारत के साथ समन्वय व सहयोग करके, जी7 प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में अपनी ताकत का लाभ उठा सकता है, साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी बढ़ावा दे सकता है। जैसे-जैसे वैश्विक परिदृश्य विकसित होता जा रहा है, जी7 और भारत के बीच साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के भविष्य को आकार देने और आम वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में महत्त्वपूर्ण होगी।

परमाणु शस्त्रागार पर सिपरी (SIPRI) रिपोर्ट का प्रकाशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में SIPRI (स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट) ने परमाणु शस्त्रागार पर अपनी रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित की, जिसमें कुछ देशों द्वारा परमाणु शस्त्रागार को बढ़ाने की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- चीन ने जनवरी 2023 में अपने परमाणु शस्त्रागार को 410 वॉरहेड से बढ़ाकर जनवरी 2024 में 500 वॉरहेड कर दिया है।
- भारत ने जनवरी 2023 में अपने परमाणु शस्त्रागार को 164 वॉरहेड से बढ़ाकर जनवरी 2024 में 172 वॉरहेड कर दिया है।
- भारत अब परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान से आगे है, लेकिन भारत का परमाणु शस्त्रागार अभी भी चीन से छोटा है।
- जनवरी 2023 से पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार 170 वॉरहेड पर बना हुआ है।
- रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास संयुक्त रूप से दुनिया के लगभग 90% परमाणु हथियार हैं।
- फ्रांस, यूके और उत्तर कोरिया भी अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहे हैं।
- चीन शायद पहली बार शांति काल में मिसाइलों पर वारहेड तैनात कर रहा है।
- परमाणु शस्त्रागार के आधुनिकीकरण और विस्तार ने परमाणु बलों के बारे में पारदर्शिता और संवाद में कमी के बारे में चिंताएँ बढ़ाई हैं, खासकर रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच।

वॉरहेड:

- किसी उपकरण का वह भाग जिसमें विस्फोटक एजेंट या विषाक्त (जैविक, रासायनिक या परमाणु) सामग्री होती है जिसे मिसाइल, रॉकेट, टारपीडो या बम द्वारा छोड़ा जाता है।

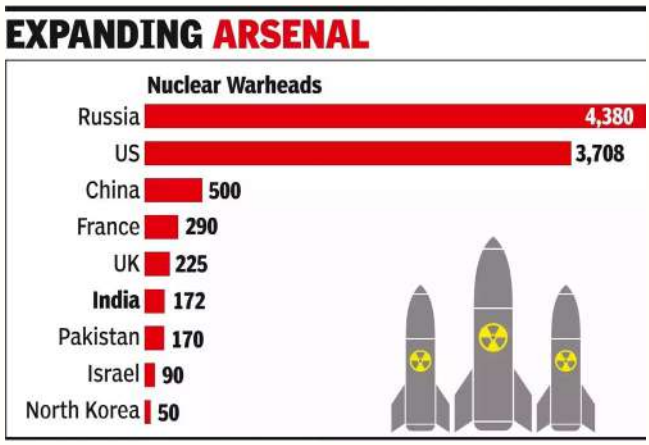

रिपोर्ट का महत्व:

- **पारदर्शिता:** सिपरी परमाणु हथियारों पर सटीक और विश्वसनीय डेटा प्रदान करता है, परमाणु-हथियार वाले राज्यों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
- **वैश्विक सुरक्षा:** रिपोर्ट नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और जनता को परमाणु शस्त्रागार की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित करती है, जिससे वैश्विक सुरक्षा जोखिमों और खतरों का आकलन करने में मदद मिलती है।
- **निरस्त्रीकरण प्रयास:** सिपरी के डेटा और विश्लेषण परमाणु हथियारों को कम करने और खत्म करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करते हैं, निरस्त्रीकरण और अप्रसार को बढ़ावा देते हैं।
- **शस्त्र नियंत्रण वार्ता:** रिपोर्ट हथियार नियंत्रण वार्ता के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, जिससे राज्यों को परमाणु कटौती और सीमाओं के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।

सिपरी के बारे में:

- SIPRI (स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट) एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है।

सिपरी के बारे में मुख्य तथ्य:

- 1966 में स्टॉकहोम, स्वीडन में स्थापित।
- वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर अनुसंधान और विश्लेषण करना।
- सैन्य व्यय, हथियारों के हस्तांतरण और परमाणु हथियारों पर डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान करना।
- सिपरी वर्ष पुस्तिका और सिपरी तथ्य पत्रक सहित वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना।
- निरस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण पर नीति विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करना।
- सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज के साथ सहयोग करना।
- सिपरी को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर एक अग्रणी प्राधिकरण के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है और इसके अनुसंधान और डेटा का उपयोग दुनिया भर की सरकारों, विद्वानों और मीडिया द्वारा किया जाता है।

निष्कर्ष:

परमाणु शस्त्रागार पर सिपरी की रिपोर्ट परमाणु हथियारों के मुद्दों पर आवश्यक जानकारी, विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करके सुरक्षित दुनिया को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

भारत और कंबोडिया संयुक्त कार्य समूह बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और कंबोडिया ने निवेश संधि, यूपीआई और पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग पर चर्चा की तथा भारत ने व्यापार और निवेश पर भारत-कंबोडिया संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजीटीआई) की दूसरी बैठक की मेजबानी की।

निवेश संधि की मुख्य विशेषताएं:

- भारत और कंबोडिया व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई-आधारित डिजिटल भुगतान पर सहयोग पर बातचीत कर रहे हैं।
- दोनों देशों ने अपने व्यापार में विविधता लाने, द्विपक्षीय निवेश संधि और फार्मा क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की।
- बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को गहरा करना था, वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 366.44 मिलियन डॉलर हो चुका है।
- भारत और कंबोडिया के बीच वित्त वर्ष 20 24 में द्विपक्षीय व्यापार 403.8 मिलियन डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2017 की तुलना में 2.9 गुना अधिक था।
- कंबोडिया से आयात में 50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण, वित्त वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार पिछले वर्ष की तुलना में 10.2 प्रतिशत बढ़ा है।

भारत-कंबोडिया संबंध, परिवर्तनशील युग में कूटनीति में विविधता:

- दुनिया के मौजूदा भू-राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बीच, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता के कारण, राज्यों को अपने लिए रणनीतिक स्थान बनाना मुश्किल लगता है।
- हालाँकि, भारत और कंबोडिया इन चुनौतियों के अन्तर्गत काम कर रहे हैं और स्वतंत्र रणनीतियों को क्रियान्वित कर रहे हैं, खासकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करके।
- यह विविधीकरण द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दक्षिण पूर्व एशिया में सहयोग बढ़ाने, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हितों के अभिसरण पर आधारित है।
- भारत ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए कंबोडिया को वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था।
- नई दिल्ली के समावेशी दृष्टिकोण जिसमें विकासशील देशों के हित के मुद्दों पर बहुपक्षवाद पर जोर दिया गया, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद।
- दोनों देशों की स्वतंत्र विदेश नीतियाँ अमेरिका और चीन के बीच एक आवश्यक विकल्प के रूप किसी गुट देश की तरफ झुकाव नहीं रखते हैं।

आगे की राह:

इस स्थिति में, भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना उसकी भू-राजनीतिक और रणनीतिक जरूरतों के लिहाज से उचित लगता है। नियम-आधारित व्यवस्था और स्वायत्तता का पालन करने के लिए नई दिल्ली का दृढ़ संकल्प कंबोडिया को चीन के मुकाबले अधिक सहज रखता हैं।

भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें जी7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए दक्षिणी इटली के अपुलिया पहुंचे। अपने एक दिवसीय दौरे में, प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन सत्र में भाग लिया और भारत और इटली के रणनीतिक साझेदारी पर भी चर्चा हुई।

भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा:

- दोनों नेताओं ने स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के लिए अपने साझा दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी चर्चा की।
- हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों के बीच, दोनों नेताओं ने स्वतंत्र और खुले महासागर के अपने साझा दृष्टिकोण को साकार करने के लिए हिंद-प्रशांत महासागर पहल ढांचे के तहत संयुक्त गतिविधियों को क्रियान्वित करने की इच्छा

व्यक्त की।

- बढ़ते व्यापार और आर्थिक सहयोग पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा, विनिर्माण, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों में वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने का आह्वान किया ताकि लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाई जा सके।
- इस संदर्भ में, उन्होंने हाल ही में औद्योगिक संपत्ति अधिकार पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया जो पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क पर सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

जी7 आउटरीच सत्र की मुख्य बातें:

- एआई और ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रधानमंत्री ने ऊर्जा उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य और स्वीकार्यता के लिए भारत के चार प्रमुख सिद्धांतों पर जोर दिया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक समुदाय को उन्नत प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिए काम करना चाहिए। इससे समावेशी समाज बनाने और सामाजिक असमानताओं को कम करने में मदद मिलेगी।
- भारत ने वैश्विक दक्षिण के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व मंच पर रखना अपना दायित्व समझा है। भारत इन प्रयासों में अफ्रीका को उच्च प्राथमिकता दी है।
- भारत समय से पहले अपनी सभी सीओपी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला पहला देश है और 2070 तक 'नेट जीरो' तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।

आगे की राह:

जी7 शिखर सम्मेलन में भारत और इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को गहरा करने की प्रतिबद्धता से चिह्नित थी। शिखर सम्मेलन ने उनके साझा मूल्यों और सामान्य लक्ष्यों को मजबूत किया, जिससे मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का मार्ग प्रशस्त हुआ।

उभरती हुई महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने नई दिल्ली में उभरती हुई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पर भारत-अमेरिका पहल (आईसीईटी) की अपनी दूसरी बैठक की।

बैठक की मुख्य बातें:

- दोनों पक्षों ने नवाचार में आगे रहने और भारत, अमेरिका और उनके वैश्विक भागीदारों के लोगों के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ समन्वय करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
- उन्होंने देशों की संवेदनशील और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के रिसाव को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी सुरक्षा उपायों को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला।
- दोनों पक्षों ने वाणिज्यिक और नागरिक अंतरिक्ष क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय रणनीतिक व्यापार, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग में लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आने वाले महीनों में ठोस कार्रवाई करने की भी प्रतिबद्धता जताई।

–: प्रीलिम्स इनसाइट :–

MQ-9B:

- MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन जोकि एक मानव रहित हवाई वाहन है, में स्काईगार्डियन RPAS का समुद्री-केंद्रित MQ-9B सीगार्डियन संस्करण शामिल है। अपनी सहनशक्ति के लिए जाने जाने वाले ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (HALE) ड्रोन सैटेलाइट कनेक्टिविटी का उपयोग करके लगातार 40 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भर सकते हैं।
- भारत ने कुल 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन हासिल करने की योजना बनाई है। नौसेना के लिए 15 सीगार्डियन ड्रोन और सेना और भारतीय वायु सेना के लिए भूमि-आधारित स्काईगार्डियन संस्करण के आठ-आठ ड्रोन।

भारत-अमेरिका रणनीतिक सहयोग में चर्चा के प्रमुख क्षेत्र:

रक्षा नवाचार और औद्योगिक सहयोग को गहरा करना:

- चर्चाओं में भारत द्वारा "MQ-9B प्लेटफॉर्म के नियोजित अधिग्रहण, भूमि युद्ध प्रणालियों के संभावित सह-उत्पादन और अन्य सह-उत्पादन पहलों पर प्रगति" जैसे भारत के लड़ाकू बेड़े को शक्ति प्रदान करने के लिए इंजनों की GE एयरोस्पेस-HAL परियोजना शामिल थी।

सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना:

- देशों ने सटीक-निर्देशित गोला-बारूद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा-केंद्रित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने 'निकट अवधि के अवसरों' की पहचान करने और पूरक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी प्रणालियों के दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग समूहों के साथ साझेदारी करने का भी लक्ष्य रखा।

नागरिक और रक्षा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहयोग में शामिल:

- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा और इसरो अंतरिक्ष यात्रियों के बीच पहले संयुक्त प्रयास के लिए एक वाहक को सुरक्षित करना।
- अंतरिक्ष में अंतर-संचालन को गहरा करने के लिए मानव अंतरिक्ष

उड़ान सहयोग के लिए रणनीतिक रूपरेखा।

- नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार के प्रक्षेपण की तैयारी, एक संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह जो हर 12 दिनों में दो बार पृथ्वी की सतह की संपूर्णता का मानचित्रण करेगा।
- मई 2024 में पेंटागन में आयोजित दूसरे उन्नत डोमेन रक्षा वार्ता के माध्यम से रक्षा अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करना, जिसमें भारत-अमेरिका अंतरिक्ष टेबल-टॉप अभ्यास शामिल था और इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उभरते डोमेन पर द्विपक्षीय विशेषज्ञ आदान-प्रदान शामिल थे।

स्वच्छ ऊर्जा और एक महत्वपूर्ण खनिज साझेदारी:

- "दक्षिण अमेरिका में लिथियम संसाधन परियोजना और अफ्रीका में एक दुर्लभ पृथ्वी भंडार में सह-निवेश के माध्यम से" खनिज सुरक्षा साझेदारी में भारत की "महत्वपूर्ण भूमिका" को बढ़ावा देना।
- 'भारत-अमेरिका उन्नत सामग्री अनुसंधान एवं विकास मंच" अमेरिकी और भारतीय विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और निजी क्षेत्र के शोधकर्ताओं के बीच सहयोग का विस्तार करने के लिए।

निष्कर्ष:

सुलिवन की भारत यात्रा भारत-अमेरिका संबंधों में वर्तमान चुनौतियों से मेल खाती है, विशेष रूप से खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़ी एक कथित हत्या की साजिश के संबंध में साजिश के एक आरोपी निखिल गुप्ता को एनएसए की यात्रा से कुछ दिन पहले 14 जून को चेक गणराज्य से अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया। हाल की बैठक महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भारत-अमेरिका पहल (आईसीईटी) के शुभारंभ द्वारा रखी गई नींव पर बनी है। इस पहल का केंद्र अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के व्यापक स्पेक्ट्रम में सहयोग को आगे बढ़ाना।

भारत-कतर निवेश व व्यापार संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत द्वारा कतर के साथ नई दिल्ली में निवेश पर संयुक्त कार्य बल (JTFI) की उद्घाटन बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे क्षेत्रों में त्वरित विकास हेतु संवाद स्थापित करना है।

निवेश पर संयुक्त कार्य समूह:

- कतर और भारत के बीच निवेश पर संयुक्त कार्य समूह की उद्घाटन बैठक की सह-अध्यक्षता कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अवर सचिव महामहिम मोहम्मद बिन हसन अल मलिकी और वित्त मंत्रालय में भारत के आर्थिक मामलों के विभाग के अवर सचिव महामहिम अजय सेठ ने की।
- महामहिम अल मलिकी ने कहा कि कतर और भारत के बीच व्यापार 2023 में लगभग 13.46 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जिससे भारत कतर का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। उन्होंने भारतीय बाजार में कतर के निगमों और निजी क्षेत्र की सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डाला और कतर राष्ट्रीय विजन 2030 के प्रमुख स्तंभ के रूप में आर्थिक विविधीकरण पर जोर दिया।
- कतर की तीसरी राष्ट्रीय विकास रणनीति उद्योग, रसद सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल और वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा सहित साझेदारी और निवेश के लिए कई आशाजनक क्षेत्रों की पहचान करती है। अल मलिकी ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के संयुक्त प्रयासों से अधिक सफलता, समृद्धि और आपसी निवेश में वृद्धि होगी।

भारत और कतर संबंध:

व्यापार गतिविधियाँ:

- कतर मुख्य रूप से भारत को एलएनजी, एलपीजी, रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और एल्युमीनियम लेख निर्यात करता है।
- कतर को भारत के मुख्य निर्यात में अनाज, तांबा, लोहा और इस्पात लेख, सब्जियाँ, फल, मसाले, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, विद्युत मशीनरी, प्लास्टिक उत्पाद, निर्माण सामग्री, वस्त्र, परिधान, रसायन, कीमती पत्थर और रबर शामिल हैं।
- 2022-23 में भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय व्यापार 18.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत ने कतर को 1.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर का माल निर्यात किया और कतर से 16.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का माल आयात किया।
- भारत, चीन और जापान के साथ कतर के शीर्ष तीन निर्यात गंतव्यों में से एक है और इसके शीर्ष तीन आयात स्रोतों में से एक भी है।

द्विपक्षीय समझौते:

- भारत और कतर के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं। कतर भारत अधिकांश एलएनजी आयात करता है। 2024 की शुरुआत में, भारत के पेट्रोनेट एलएनजी ने कतर से सालाना 7.5 मिलियन टन एलएनजी खरीदने के लिए 20 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो 1999 के सौदे को आगे बढ़ाता है जो जुलाई 2028 तक आपूर्ति को कवर करता है।
- 2023 में, भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी), जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं, ने एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत फिर से शुरू की।
- इस एफटीए से नए व्यावसायिक अवसर पैदा होने की उम्मीद है। भारत ने पहले ही यूएई के साथ द्विपक्षीय एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे 2022 से व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

नए निवेश के अवसर:

- संयुक्त कार्य समूह का उद्देश्य रणनीतिक रोडमैप बनाकर निवेश संबंधों को बढ़ावा देना है। इसमें दीर्घकालिक निवेश साझेदारी का निर्माण करना, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वित्तीय संसाधनों को निर्देशित करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच सहयोग बढ़ाना, इनोवेटर्स का समर्थन करना और कंपनियों को "मेड इन इंडिया"

और "मेड इन कतर" जैसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए मार्गदर्शन करना शामिल है।

- समूह निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए नए निवेश क्षेत्रों की खोज करने और निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने की भी योजना बना रहा है।
- फरवरी 2024 में, कतर के शाही परिवार के सदस्य और एक वित्तीय सेवा फर्म के अध्यक्ष शेख मंसूर बिन खलीफा अल थानी ने भारत के शिक्षा, स्टार्टअप और कृषि क्षेत्रों में निवेश के अवसरों की खोज करने की योजना की घोषणा की।

निष्कर्ष:

भारत और कतर के बीच संयुक्त निवेश टास्क फोर्स भारत के कृषि, स्टार्टअप, शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे बढ़ते क्षेत्रों को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकता है। दोनों देशों के नेताओं ने प्रमुख निवेश क्षेत्रों पर चर्चा की और रणनीतिक साझेदारी की खोज कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 2018-19 से 2022-23 तक द्विपक्षीय व्यापार में 6.45 बिलियन डॉलर की वृद्धि अन्य मध्य पूर्वी देशों को भारत के साथ अपने निवेश और व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का भारत दौरा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आई। राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। दोनों पक्षों ने डिजिटल डोमेन, समुद्री क्षेत्र, नीली अर्थव्यवस्था, रेलवे, अंतरिक्ष, हरित प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

समझौते के बारे में:

भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में हुए समझौते से दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती आई है, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जैसे-

- **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA):** आर्थिक संपर्क को बढ़ाना और निवेश को बढ़ावा देना।
- **समुद्री सहयोग और नीली अर्थव्यवस्था:** समुद्री संसाधनों का दोहन करना, समुद्री संपर्क में सुधार करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** रक्षा उत्पादन को बढ़ाना, सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करना और क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना।
- **डिजिटल और हरित भागीदारी:** अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- **रेलवे संपर्क:** माल और यात्रियों के आवागमन को सुविधाजनक बनाना, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
- **स्वास्थ्य सेवा पहल और ई-मेडिकल वीजा:** भारत में चिकित्सा उपचार प्रदान करना और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना।
- **साझा नदियों पर जल विज्ञान सहयोग:** साझा जल संसाधनों का प्रबंधन करना और आम जल विज्ञान चुनौतियों का समाधान करना।

भारत बांग्लादेश संबंधों के बारे में:

- **मान्यता:** भारत दिसंबर 1971 में बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था।
- **ऐतिहासिक संबंध:** भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन किया 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता।
- **आर्थिक सहयोग:** बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।
- **रणनीतिक साझेदारी:** भारत और बांग्लादेश आतंकवाद-रोधी अभियानों में घनिष्ठ रणनीतिक साझेदार हैं।
- **साझा सांस्कृतिक संबंध:** बांग्लादेश और पूर्वी भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा बंगाली भाषी सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं।
- **सीमा प्रबंधन:** भारत और बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, सीमा विवादों को सुलझाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
- **जल संसाधन:** भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे की संधि सहित जल संसाधनों को साझा करने के समझौते हैं।
- **सुरक्षा:** बांग्लादेश भारत की पड़ोसी पहले नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और भारत बांग्लादेश की सुरक्षा में प्रभावशाली है।
- **पर्यावरण सहयोग:** भारत और बांग्लादेश जलवायु परिवर्तन और साइबर सुरक्षा जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर मिलकर काम कर रहे हैं।

मतभेद:

- भारत और बांग्लादेश के बीच अतीत में सीमा विवाद रहे हैं, हालाँकि उन्होंने अपने सीमा मुद्दों को सुलझा लिया है।
- भारत और बांग्लादेश के बीच जल संसाधनों, विशेष रूप से गंगा नदी को लेकर मतभेद रहे हैं।
- भारत और बांग्लादेश की विदेश नीतियाँ अलग-अलग हैं।

निष्कर्ष:

भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे दो राष्ट्र एक साथ मिलकर एक मजबूत और सार्थक साझेदारी बना सकते हैं। चुनौतियों के बावजूद, दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और अपने लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखा है।

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्टः पर्यावरण बनाम विकास का मुद्दा

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इस समय विकास बनाम पर्यावरण के बहस से घिर गया है। विपक्षी दलों ने इस प्रोजेक्ट पर अपनी कठोर आपत्ति जाहिर की है। उनका कहना है ग्रेटर निकोबार द्वीप समूह पर 72 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट पारिस्थितिक और मानवीय आपदा के लिए एक घातक प्रयोग है। इससे पहले सरकार ने 2023 में बताया था कि इस प्रोजेक्ट के लिये 9 लाख से अधिक पेड़ों को काटा जाएगा और इसके बदले में 10 लाख पेड़ हरियाणा में लगाये जाएंगे। इस आधार पर इस प्रोजेक्ट पर सवाल भी खड़े किए गए हैं।

हाल ही में नीति आयोग ने 72000 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट पेश किया, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विकास का खाका पेश किया गया है। इसमें ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट और टाउनशिप बनाने की प्लानिंग है। इस प्रोजेक्ट को 'होलिस्टिक डेलेपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स' का नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट के साथ ही सतत विकास, हरित विकास, धारणीय विकास, जनजातीय न्याय के प्रश्न भी उभर गए हैं।

ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, समुद्र तल से 642 मीटर (माउंट थुलियर) की ऊँचाई तक पहुँचने वाली पर्वत शृंखलाएँ और तटीय मैदानों सहित पारिस्थितिकी तंत्रों की एक विस्तृत शृंखला है। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। सही अर्थों में ये एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ग्रेट निकोबार इस द्वीपसमूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। इसमें 103 870 हेक्टेयर अद्वितीय और संकटग्रस्त उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। यह समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का घर है, जिसमें एंजियोस्पर्म, फर्न, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स आदि की 650 प्रजातियाँ शामिल हैं। जीवों के संदर्भ में यहाँ 1800 से अधिक प्रजातियाँ हैं, जिनमें से कुछ इस क्षेत्र के लिए स्थानिक (Endemic) हैं।

ग्रेट निकोबार को लेकर नीति आयोग का प्रोजेक्ट क्या है?

- नीति आयोग के द्वारा ग्रेट निकोबार के संदर्भ में जिस प्रस्तावित बंदरगाह की बात प्रोजेक्ट में की गई है, उससे क्षेत्रीय और वैश्विक मैरिटाइम इकोनॉमी में ग्रेट निकोबार की हिस्सेदारी बढ़ेगी और वह कार्गो शिपमेंट में एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरेगा। एयरपोर्ट के बनने से मैरिटाइम सर्विसेज का विकास होगा और ग्रेट निकोबार द्वीप से देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे पर्यटन क्षेत्र को अधिक मजबूती मिल सकेगी।
- हालांकि नीति आयोग ने इस प्रोजेक्ट को इसके मौजूदा स्वरूप में पेश किया है। ग्रेट निकोबार में बंदरगाह बनाने की योजना साल 1970 से चल रही है, जब ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो अब इंडिया ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गनाइजेशन है, उसने टेक्नो-इकोनॉमी रूप से व्यवहारिक स्टडी कराई थी। इसका उद्देश्य दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग (मलक्का जलडमरूमध्य) के करीब एक बंदरगाह बनाना था, जिससे दुनिया के समुद्री व्यापार में उसकी हिस्सेदारी बढ़ सके। लेकिन ग्रेट निकोबार के भौगोलिक पर्यावरणीय स्थिति और उसकी ट्राइबल प्रोफाइल के चलते निर्णय नहीं लिया जा सका।
- ग्रेट निकोबार आइलैंड भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर है और यह अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का हिस्सा है, जिसमें 600 द्वीप हैं। यह पहाड़ी इलाका हरे-भरे वर्षावनों का घर है, जहां हर साल 3500 मिलीमीटर बारिश होती है। इतना ही नहीं ये जंगली इलाका और इसके तट कई दुर्लभ प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है, जिसमें विशाल लेदरबैक कछुआ भी शामिल है। ग्रेट निकोबार का क्षेत्रफल 910 वर्ग किमी है और इसके तट पर मैंग्रोव और पांडन वन हैं।
- इस द्वीप पर दो आदिवासी समुदाय रहते हैं- शोमपेन और निकोबारी।

शोमपेन की आबादी कुल 250 लोगों की है और ये जंगलों के बहुत अंदर रहते हैं और बाकी दुनिया से इनका कोई नाता नहीं है। ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं और इनको हिंसक आदिवासी समूह माना जाता है। इन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। निकोबारी समुदाय खेती और मछली पकड़ने का काम करते हैं। इनमें भी दो ग्रुप हैं- ग्रेट निकोबारी और दूसरा लिटिल निकोबारी। इन लोगों की शोमपेन की तरह अपनी अलग भाषा है। साल 2004 में सुनामी आने से पहले तक ग्रेट निकोबारी द्व ीप के साउथ ईस्ट और वेस्ट तट पर रहते थे। इसके बाद सरकार ने उनका कैंपबेल बे में पुनर्वास कराया। आज 450 ग्रेट निकोबारी द्वीप पर रहते हैं जबकि लिटिल निकोबारी की संख्या करीब 850 के आसपास है और ये ग्रेट निकोबार में आफरा खाड़ी में रहते हैं। कुछ पुलोमिलो और लिटिल निकोबार में रहते हैं।

- ग्रेट निकोबार में अधिकतर लोग वही हैं जो मेनलैंड इंडिया से आकर यहां बसाए गए। साल 1968 से लेकर 1975 तक भारत सरकार ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से मिलिट्री से रिटायर हुए लोगों और उनके परिवारों को यहां बसाया। करीब 330 लोगों को द्वीप के पूर्वी तटों पर बसे सात गांवों में 15 एकड़ जमीन दी गई। ये सात गांव थे- कैंपबेल बे, गोविंदनगर, जोगिंदरनगर, विजयनगर, लक्ष्मी नगर, गांधी नगर।

प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट की प्रगतिः

- भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा पिछले साल ग्रेट निकोबार द्वीप में गैलाथिया खाड़ी का दौरा किया गया था और प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (आईसीटीपी) की प्रगति की समीक्षा की गई थी। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के साथ-साथ अमृत काल विजन 2047 की प्रमुख परियोजनाओं में से एक में इसकी परिकल्पना की गई है। लगभग 44,000 करोड़ के कुल अनुमानित लागत के साथ एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है।
- यह परियोजना देश के लिए रणनीतिक रूप से और पूरे क्षेत्र के आर्थिक और ढांचागत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने 11 नवंबर, 2022 को पर्यावरण संबंधी मंजूरी दे दी। इसके अतिरिक्त, चरण 1 की वन संबंधी मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है और आईसीटीपी परियोजना की डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- इस मेगा कंटेनर टर्मिनल का विकास ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास का एक हिस्सा है। परियोजना तीन प्रमुख चालकों पर केंद्रित है, जिसके परिणामस्वरूप इसे एक अग्रणी कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा सकता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग व्यापार मार्ग के साथ निकटता (40 समुद्री मील) में रणनीतिक स्थान, 20 मीटर से अधिक की प्राकृतिक जल गहराई की उपलब्धता और भारतीय बंदरगाहों सहित आसपास के सभी बंदरगाहों से माल ढुलाई वहन क्षमता।
- उल्लेखनीय है कि भारत में मेगा बंदरगाह स्थापित करने और वैश्विक बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अच्छी-खासी क्षमता है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत चार प्रमुख हस्तक्षेप क्षेत्र रेखांकित किए गए हैं, जिनमें क्षमता वृद्धि, विश्व स्तरीय मेगा बंदरगाहों का विकास करना, दक्षिणी भारत में ट्रांसशिपमेंट हब का विकास और बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण शामिल हैं। वर्तमान में, भारत में 100 एमटीपीए से अधिक क्षमता वाले 5 प्रमुख बंदरगाह और 2 गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं।
- इसके साथ ही भारत के लिए मेगा पोर्ट स्थापित करने और वैश्विक बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। मेगा बंदरगाहों के लिए प्रमुख मानदंडों और क्लस्टरों की उभरती विकास क्षमता के विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर, 3 मेगा बंदरगाहों -वधावन-जेएनपीटी क्लस्टर, पारादीप बंदरगाह और दीनदयाल बंदरगाह को 300 एमटीपीए क्षमता से अधिक वाले मेगा बंदरगाहों में विकसित करने के लिए पहचाना गया है।

मेगा बंदरगाहों को स्थापित करने के लाभः

- वर्तमान में, भारत का लगभग 75 प्रतिशत ट्रांसशिप्ड कार्गो भारत के बाहर के बंदरगाहों पर संभाला जाता है। कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग इस कार्गो के 85 प्रतिशत से अधिक को संभालते हैं, जबकि 45 प्रतिशत कार्गो को कोलंबो बंदरगाह पर संभाला जाता है। गैलाथिया खाड़ी की रणनीतिक स्थिति एक्जिम व्यापार के लिए एक बड़ा लाभ है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग पर स्थित है।
- गैलाथिया खाड़ी में आईसीटीपी के विकास के साथ, भारतीय बंदरगाह अधिक ट्रांसशिपमेंट कार्गो को आकर्षित करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, गैलाथिया बे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को विकसित करने से विदेशी मुद्रा बचत, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अन्य भारतीय बंदरगाहों पर आर्थिक गतिविधि में वृद्धि, लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे में वृद्धि और इस प्रकार, दक्षता, रोजगार सृजन और राजस्व हिस्सेदारी में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे।

ग्रेट निकोबार द्वीप में पर्यटन की संभावनाओं पर कामः

- ग्रेट निकोबार द्वीप में पर्यटन क्षमता का पता लगाने के लिए ग्रेट निकोबार द्वीप में भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा प्वाइंट का भी दौरा भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा किया गया है। भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा संबंधित अधिकारियों को इंदिरा प्वाइंट क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की संभावना तलाशने और इसके लिए आवश्यक पर्यटन सुविधाएं और सुविधाएं विकसित करने का निर्देश दिया है।
- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा कैंपबेल बे पोर्ट परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण करीब 17 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कैंपबेल खाड़ी में मौजूदा घाट बड़े आकार के

जहाजों की बर्थिंग के लिए अपर्याप्त हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बड़े जहाजों की सुरक्षित बर्थिंग की सुविधा के लिए घाट को 50 मीटर तक विस्तारित किया गया। परियोजना के पूरा होने पर, 150 मीटर लंबे जहाज बर्थ करने में सक्षम होंगे जो ग्रेट निकोबार और अन्य द्व ीपों के बीच अधिक यात्री और कार्गो आवाजाही प्रदान करेगा। इस विस्तार से डबल बर्थिंग की सुविधा भी मिलेगी, जिससे बंदरगाह की क्षमता बढ़ेगी। ग्रेट निकोबार द्वीप के भविष्य के विकास और पर्यटकों और व्यापारियों में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, यह घाट द्वीप के यातायात विकास को संभालने के लिए उपयोगी होगा। चेन्नई से ये आइलैंड करीब 1600 किमी की दूरी पर है जबकि इंडोनेशिया की सीमा से ग्रेट निकोबार सिर्फ 170 किमी की दूरी पर मौजूद है।

- विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के जरिए भारत को इस इलाके में रणनीतिक बढ़त मिलेगी। इस पोर्ट की मदद से भारतीय नौसेना के युद्धपोत, फाइटर जेट्स और मिसाइलों की तैनाती होगी। साथ ही इस इलाके से ही भारत पूरे हिंद महासागर पर नजर रख पाएगा। इस पोर्ट के शुरु होने से जो कार्गो शिप पहले दूसरे देशों में जाते थे वो भारत में आएंगे यानी भारत सरकार की विदेश मुद्रा बचेगी। आगे चलकर देश के दूसरे बंदरगाहों पर ट्रैफिक बढ़ेगा और विदेशी निवेश आएगा।

पर्यावरणीय संक्षिप्त मुद्दे

जलाशयों के जल भंडारण स्तर में कमी: केंद्रीय जल आयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा 150 प्रमुख जलाशयों के लिए जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, कम से कम आठ जलाशयों में जल भंडारण शून्य है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- सीडब्ल्यूसी द्वारा निगरानी किए जाने वाले 150 प्रमुख जलाशयों की सम्मिलित जल भंडारण क्षमता 178.784 बीसीएम है, जो देश में निर्मित कुल जल भंडारण क्षमता का लगभग 69.35 प्रतिशत है।
- कुल उपलब्ध जल भंडारण क्षमता 41.705 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है, जो कुल क्षमता का 23 प्रतिशत है। परिणामस्वरूप, वर्तमान जल भंडारण पिछले वर्ष के स्तर का केवल 77 प्रतिशत और सामान्य जल भंडारण का 94 प्रतिशत है।
- यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज किए गए 53.832 बीसीएम और 44.511 बीसीएम के सामान्य जल भंडारण स्तर से उल्लेखनीय कमी है।
- पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान जल भंडारण 38 प्रतिशत था। वर्ष के इस समय सामान्य संग्रहण 31 प्रतिशत है।
- कम से कम आठ जलाशयों में शून्य संग्रहण था। ये जलाशय महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में थे। जबकि आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक चार अन्य राज्यों में जलाशय ऐसे थे जिनमें 10 प्रतिशत से कम संग्रहण था।

क्षेत्रीय जल संग्रहण स्तर:

- **उत्तरी क्षेत्र:** हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान - 19.663 बीसीएम की लाइव संग्रहण क्षमता वाले 10 जलाशय हैं। यह घटकर 5.864 बीसीएम (कुल क्षमता का 30 प्रतिशत) रह गया है।
- **पूर्वी क्षेत्र:** असम, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड और बिहार - 23 जलाशय हैं जिनकी कुल लाइव संग्रहण क्षमता 20.430 बीसीएम है। उपलब्ध संग्रहण 5.645 बीसीएम है, जो कुल क्षमता का 28 प्रतिशत है।
- **पश्चिमी क्षेत्र:** गुजरात और महाराष्ट्र - 49 जलाशय हैं जिनकी कुल लाइव संग्रहण क्षमता 37.130 बीसीएम है। वर्तमान में जल संग्रहण 8.833 बीसीएम है, जो कुल क्षमता का 24 प्रतिशत है।
- **मध्य क्षेत्र:** उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ - इसमें 26 जलाशय हैं, जिनकी कुल जल संग्रहण क्षमता 48.227 बीसीएम है।
- **दक्षिणी क्षेत्र:** आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु- इसमें 42 जलाशय हैं, जिनकी कुल जल संग्रहण क्षमता 53.334 बीसीएम है।

भारतीय नदी बेसिनों में जल संग्रहण स्तर:

- रिपोर्ट में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मणी और बैतरणी, नर्मदा, तापी और साबरमती बेसिनों में सामान्य से बेहतर जल संग्रहण पर पाया गया है।
- इसमें सुवर्णरेखा, बराक, माही, गोदावरी, महानदी शामिल हैं। कच्छ तथा सौराष्ट्र से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, जिनमें लूनी और तापी से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ भी शामिल है।
- महानदी और पेन्नार के मध्य पूर्व की ओर बहने वाली कम से कम 13 नदियों में लगातार नौ सप्ताह तक पानी नहीं रहा। इनमें

रुशिकुल्या, बहुदा, वम्सधारा, नागावली, सारदा, वराह, तांडव, एलुरु, गुंडलकम्मा, तमिलेरु, मूसी, पलेरु और मुन्नेरु शामिल हैं।

- 19 नदी घाटियों में से 18 में 50 प्रतिशत से कम जल भंडारण था, केवल ब्रह्मपुत्र में इसकी कुल क्षमता का 58.58 प्रतिशत दर्ज किया गया। गंगा नदी बेसिन में भंडारण इसकी क्षमता का 31.99 प्रतिशत था, जो पिछले साल के भंडारण से कम है, लेकिन इसी अवधि के में 'सामान्य' (पिछले 10 वर्षों का औसत) भंडारण से अधिक है।

निष्कर्ष:

भारत में नदी प्रणालियाँ सिंचाई, पीने, घरेलू उपयोग, सस्ते परिवहन और बिजली के लिए जल उपलब्ध कराती हैं इसके अतिरिक्त यह ग्रीष्मकालीन फसलो (रबी और खरीफ मौसम के बीच बोई गई) की पैदावार हेतु जल उपलब्ध कराती है। ऐसे में जलाशयों की जल भंडारण में कमी चिंताजनक है।

वायु प्रदूषण और असामयिक मृत्यु में संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सिंगापुर के नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के शोध कर्ताओं के एक अध्ययन के अनुसार 1980 से 2020 तक वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में लगभग 13.5 करोड़ लोगों की असामयिक मृत्यु हुई।

अध्ययन के प्रमुख बिंदु:

असामयिक मृत्यु की संख्या:

- 1980 से 2020 के बीच पीएम 2.5 प्रदूषण के कारण दुनिया भर में 13.5 करोड़ लोगों की असामयिक मृत्यु हुई।
- इनमें से 9.81 करोड़ मौतें एशिया में हुई, जिनमें चीन में 4.9 करोड़ और भारत में 2.61 करोड़ मौतें शामिल हैं।

पीएम 2.5 के प्रभाव:

- पीएम 2.5 कण 2.5 माइक्रोमीटर व्यास या उससे छोटे कण होते हैं।
- ये कण वाहनों के उत्सर्जन, औद्योगिक प्रक्रियाओं, जंगल की आग और धूल के गुबार जैसे स्रोतों से आते हैं।
- ये कण बहुत छोटे होते हैं और आसानी से फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे स्ट्रोक, इस्केमिक (कोरोनरी) हृदय रोग, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:

- अल नीनो-दक्षिणी दोलन, हिंद महासागर द्विध्रुव और उत्तरी अटलांटिक दोलन जैसी जलवायु परिवर्तन की घटनाओं ने महीन कण पदार्थ के प्रदूषण को बढ़ाया और असामयिक मृत्यु दर में 14 प्रतिशत की वृद्धि की।
- तापमान में वृद्धि, हवा के पैटर्न में बदलाव और बारिश में कमी के कारण प्रदूषकों की मात्रा बढ़ गई।

स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- अध्ययन के अनुसार, असामयिक मौतों में से एक तिहाई स्ट्रोक (33.3%) और एक तिहाई इस्केमिक हृदय रोग (32.7%) से जुड़ी थीं।
- कमजोर समूहों जैसे बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों वाले लोगों के लिए पीएम 2.5 कण विशेष रूप से खतरनाक होते हैं।

उपग्रह डेटा का उपयोग:

- शोधकर्ताओं ने नासा के उपग्रह डेटा का उपयोग करके पृथ्वी के वायुमंडल में महीन कणों के स्तर का अध्ययन किया।
- पिछले चार दशकों में 363 बड़ी वायु प्रदूषण की घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें 2002 में सबसे अधिक 15 घटनाएं हुई।

भविष्य की दिशा:

- शोधकर्ता स्थानीय वायु प्रदूषण पैटर्न की गहरी समझ के लिए और अधिक विस्तृत अध्ययन करेंगे।
- स्वास्थ्य एजेंसियों को पीएम 2.5 प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के लिए संसाधनों का उचित आवंटन करना चाहिए।

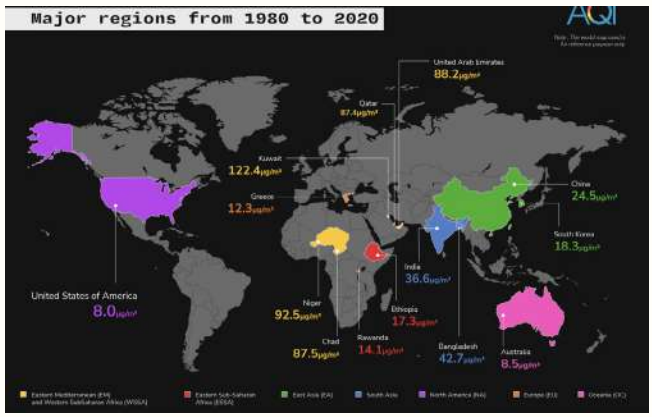

पी.एम. व पी.एम. 2.5:

- पी.एम. को पर्टिकुलेट मैटर (Particulate Matter) या कण प्रदूषण (Particle Pollution) भी कहा जाता है, जो कि वातावरण में मौजूद ठोस कणों और तरल बूंदों का मिश्रण है। हवा में मौजूद कण इतने छोटे होते हैं कि आप नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते हैं।
- कुछ कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करके पता लगाया जा सकता है। कण प्रदूषण में PM 2.5 और PM 10 शामिल हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। PM 2.5 वायुमंडलीय कण पदार्थ को संदर्भित करता है जिसमें 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास होता है, जो मानव बाल के व्यास के लगभग 3% है।

निष्कर्ष:

यह अध्ययन दर्शाता है कि पीएम 2.5 प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली असामयिक मौतें एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए

तैयार रहना चाहिए और सरकारों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन में सुधार करना चाहिए।

प्रेजवाल्स्की घोड़े

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रेजवाल्स्की के घोड़ों को लगभग 200 वर्षों के बाद कजाकिस्तान के मैदानों में फिर से लाया गया है। इसे दुनिया के अंतिम जंगली घोड़ों को उनके मूल निवास स्थान में फिर से लाने की महत्वाकांक्षी योजना के एक हिस्से के रूप में पेश किया गया है।

प्रेजवाल्स्की घोड़ों के बारे में:

- प्रेजवाल्स्की घोड़े मध्य एशिया में पाए जाने वाले लुप्तप्राय रेतीले भूरे रंग के घोड़े हैं। वे कजाकिस्तान जैसी कठोर सर्दियों को झेलने में सक्षम हैं, जहाँ तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है और भोजन दुर्लभ हो जाता है।
- कजाकिस्तान में, उनका फिर से आगमन संरक्षण प्रयासों का हिस्सा है, क्योंकि घोड़े कई तरह की घास खाते हैं, जिससे बीज फैलने में मदद मिलती है और इस तरह पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने में मदद मिलती है।
- दुनिया के जंगली घोड़ों की आखिरी नस्लों के रूप में जाने वाले, इन घोड़ो का नाम रूसी भूगोलवेत्ता निकोले प्रेजवाल्स्की के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में उन्हें खोजा था जब उनका दायरा पश्चिमी मंगोलिया तक सीमित हो गया था।
- 1960 के दशक के अंत तक, प्रेजवाल्स्की के घोड़े जंगल से गायब हो गए थे। उन्हें चीन और पश्चिमी मंगोलिया में फिर से लाया गया है, जहाँ अब उनकी संख्या 850 है।

-: प्रीलिम्स इनसाइट :-

भारत में बहाली की पहलः नमामि गंगे कार्यक्रम

- 2014 में शुरू की गई, सरकार के नेतृत्व वाली नमामि गंगे पहल का उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों का कायाकल्प, सुरक्षा और संरक्षण करना है। यह गंगा बेसिन के कुछ हिस्सों में वनीकरण, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने और नदी डॉल्फिन, सॉफ्टशेल कछुए, ऊदबिलाव और हिल्सा शाद मछली सहित प्रमुख वन्यजीव प्रजातियों को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है।
- जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण और सिंचाई के कारण हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक 2,525 किलोमीटर के मार्ग पर गंगा का क्षरण हुआ है।

अटलिन डाला संरक्षण पहल के बारे में:

- कजाकिस्तान के मध्य भाग का अल्टीन डाला या गोल्डन स्टेपी क्षेत्र, घास के मैदान और आर्द्रभूमि का एक विशाल क्षेत्र है, जो लगभग 7,000 वर्ग किलोमीटर (2,700 वर्ग मील) में फैला हुआ है।
- कजाकिस्तान में अल्टीन डाला संरक्षण पहल 2005 से, सैगा मृग की ऐतिहासिक सीमा के भीतर स्टेपी, अर्ध-रेगिस्तान और रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए काम कर रही है, जो कभी शिकार और आवास के नुकसान से गंभीर रूप से खतरे में थे। साइगा की आबादी, जो 2006 में 50,000 तक गिर गई थी, 2022 में 1.3 मिलियन तक बढ़ गई।
- स्टेपी को पुनर्जीवित करने और संरक्षित करने के अलावा, इस पहल ने लगभग 10 मिलियन प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि को संरक्षित किया है, जिसमें मिलनसार लैपिंग, लाल-छाती वाले हंस, सफेद सिर वाले बत्तख और साइबेरियाई क्रेन जैसी प्रमुख प्रजातियाँ शामिल हैं।

निष्कर्षः

चेक गणराज्य में प्राग चिड़ियाघर, जो इस प्रजाति के लिए स्टडीबुक का प्रबंधन करता है, जिसका लक्ष्य कजाकिस्तान में अल्टीन डाला या गोल्डन स्टेप में प्रेजवल्स्की घोड़ों को वापस लाना शुरू करना है। कजाकिस्तान में, प्रेजवल्स्की घोड़ा एकमात्र लुप्तप्राय प्रजाति नहीं है जिस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक समय विलुप्त होने के कगार पर पहुँच चुका गोल-थूथन वाला साइगा मृग भी इस पहल का एक प्रमुख हिस्सा है।

बिहार के दो वेटलैंड्स रामसर सूची में शामिल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार के दो वेटलैंड्स नकटी और नागी को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है, जिससे भारत में ऐसे मान्यता प्राप्त पारिस्थितिकी तंत्रों की कुल संख्या 82 हो गई है।

मुख्य बिंदु:

- बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता दी गई है। ये मानव निर्मित जलाशय जमुई के झाझा वन क्षेत्र में स्थित हैं और पहाड़ियों और शुष्क पर्णपाती जंगलों से घिरे जलग्रहण क्षेत्र हैं।
- दोनों अभयारण्यों को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर अंतरराष्ट्रीय महत्त्व के वेटलैंड्स घोषित किया गया था।

नकटी पक्षी अभयारण्य के बारे में:

- नकटी पक्षी अभयारण्य मुख्य रूप से नकटी बांध के निर्माण के

साथ सिंचाई के लिए बनाया गया था। तब से, वेटलैंड और इसके आसपास का क्षेत्र पक्षियों, स्तनधारियों, मछलियों, जलीय पौधों, सरीसृपों और उभयचरों की 150 से अधिक प्रजातियों का घर बन गया है।

- इनमें वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियाँ शामिल हैं, जैसे लुप्तप्राय भारतीय हाथी (एलिफस मैक्सिमस इंडिकस) और एक असुरक्षित देशी कैटफिश (वालगो अट्टू)।
- 1984 में पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित, यह आर्द्रभूमि कई प्रवासी प्रजातियों के लिए सर्दियों के आवास के रूप में महत्त्वपूर्ण है, जहाँ सर्दियों के महीनों के दौरान 20,000 से अधिक पक्षी एकत्रित होते हैं। इसमें इंडो-गंगा के मैदान पर लाल-क्रेस्टेड पोचार्ड (नेट्टा रूफिना) का सबसे बड़ा जमावड़ा शामिल है।

–: प्रीलिम्स इनसाइट :–

- **रामसर साइट:** यह एक वेटलैंड साइट है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है, जिसे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, यह यूनेस्को के तत्वावधान में 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है।
- **बर्डलाइफ इंटरनेशनल:** इसकी स्थापना 1922 में अमेरिकी पक्षी विज्ञानी टी. गिल्बर्ट पियर्सन और जीन थियोडोर डेलाकॉर ने की थी, पक्षियों, उनके आवासों और वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए समर्पित संरक्षण संगठनों (एनजीओ) की एक वैश्विक साझेदारी है। शुरू में इसका नाम इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रोटेक्शन रखा गया था, लेकिन कई बार इसका नाम बदला गया और 1993 में इसका नाम बर्डलाइफ इंटरनेशनल हो गया। यह एक त्रैमासिक पत्रिका, वर्ल्ड बर्डवॉच प्रकाशित करता है, जिसमें पक्षी संरक्षण पर समाचार और लेख शामिल होते हैं। यह इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) के लिए पक्षियों के लिए आधिकारिक रेड लिस्ट प्राधिकरण भी है और महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों (IBA) की सूची प्रकाशित करता है।

नागी पक्षी अभयारण्य के बारे में:

- नागी पक्षी अभयारण्य की स्थापना नागी नदी पर बांध बनाए जाने के बाद की गई थी, जिससे साफ पानी और जलीय वनस्पति वाले जल निकायों का निर्माण हुआ।
- 1984 में स्थानीय रूप से पक्षी अभयारण्य के रूप में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र (आईबीए) के रूप में मान्यता प्राप्त, यह प्रवासी पक्षी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण है।
- वेटलैंड और इसके आस-पास के क्षेत्र में 75 से ज्यादा पक्षी प्रजातियाँ, 33 मछली प्रजातियाँ और 12 जलीय पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उल्लेखनीय रूप से, अभयारण्य में बार-हेडेड गीज (एंसर इंडिकस) का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है जो भारत-गंगा के मैदान पर होता है।

निष्कर्ष:

हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की वैश्विक सूची में दो वेटलैंड्स को शामिल किए जाने से पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के प्रयासों में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी, जिससे वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के व्यापक लक्ष्य में योगदान मिलेगा।

वैश्विक मृदा भागीदारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वैश्विक मृदा भागीदारी (जीएसपी) की 12वीं पूर्ण सभा की मेजबानी की गई, जिसमें मृदा तन्यकता (लचीलापन) और स्थिरता को बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई।

मुख्य बिंदु:

- तीन दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, वैश्विक मृदा भागीदारी (जीएसपी) ने 2030 तक दुनिया की कम से कम 50% मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने और बनाए रखने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर प्रकाश डाला।
- मुख्य आकर्षण मृदा भागीदार दिवस था, जो सतत मृदा प्रबंधन में सहयोग को बढ़ावा देने और अनुभवों को साझा करने पर केंद्रित था। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी 'अनुकूलित फसलों और मृदाओं के लिए विजन (VACS) पहल' प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य स्वस्थ मिट्टी पर उगाई जाने वाली जलवायु-अनुकूलित फसलों के माध्यम से लचीली खाद्य प्रणाली बनाना है।
- थाईलैंड साम्राज्य ने मृदा स्वास्थ्य के एक दशक के प्रस्ताव के ढांचे के भीतर अपनी सफलता की कहानियों का प्रदर्शन किया, जिसमें किसानों ने सतत मृदा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भूमिका पर जोर दिया।
- अन्य उल्लेखनीय प्रतिभागियों में उज्बेकिस्तान गणराज्य, अंतर्राष्ट्रीय '4 प्रति 1000' पहल, कृषि वानिकी में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICRAF), इंस्टीट्यूट डी रिसर्च पोर ले डेवलपमेंट (IRD), ऑफिस चेरिफियन डेस फॉस्फेट्स (OCP) समूह, वैश्विक संरक्षण कृषि नेटवर्क (GCAN), लेइटैट टेक्नोलॉजिकल सेंटर और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) शामिल थे।

सॉइलएफईआर के बारे में:

- मध्य अमेरिका और अफ्रीकी देशों में अग्रणी, मृदा मानचित्रण के लिए लचीली कृषि खाद्य प्रणाली (सॉइलएफईआर) को नीति को सूचित करने और राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर उर्वरक उपयोग को अनुकूलित करने के लिए महत्वपूर्ण मृदा डेटा एकत्र

करने के लिए डिजाइन किया गया है।

'4 प्रति 1000' पहल:

- यह पहल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में कार्बन खेती से कार्बन सिंक की भूमिका पर जोर देती है। इसे पेरिस में कॉप 21 जलवायु वार्ता के दौरान लॉन्च किया गया था और यह वैश्विक कार्बन बजट के बुद्धिमान प्रबंधन की वकालत करता है।

ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप के बारे में:

- ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप (GSP) एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त तंत्र है। इसकी स्थापना 2012 में वैश्विक एजेंडे पर मिट्टी को स्थान देने तथा संधारणीय मृदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के मिशन के साथ की गई थी।
- FAO द्वारा आयोजित, यह उत्पादक मृदा सुनिश्चित करने के लिए मृदा शासन में सुधार करने का काम करता है, जिससे खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन, तथा सभी के लिए संधारणीय विकास को बढ़ावा मिलता है।

ग्लोबल सॉयल हेल्थ पार्टनरशिप द्वारा प्रमुख उपलब्धियाँ:

दिसंबर 2012 में अपनी स्थापना के बाद से, ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप ने वैश्विक एजेंडे पर मिट्टी को स्थान देने में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जिनमें शामिल हैं:

- मिट्टी पर एक अंतर-सरकारी तकनीकी पैनल तथा मृदा के मामलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की स्थापना।
- 5 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र विश्व मृदा दिवस तथा 2015 में मृदा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने का प्रस्ताव तथा वार्षिक उत्सव।
- संशोधित विश्व मृदा चार्टर का समर्थन।
- विश्व के मृदा संसाधन 2015 की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करना।
- पोषण के लिए मिट्टी पर तकनीकी दिशा-निर्देश विकसित करना।
- सतत मृदा प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय मृदा भागीदारी और स्वैच्छिक दिशा-निर्देश स्थापित करना।

निष्कर्ष:

वैश्विक चुनौतियों के सामने जीएसपी का काम पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सतत मृदा प्रबंधन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता दुनिया भर में कृषि खाद्य प्रणालियों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सहयोग, नवाचार और स्थानीय समुदाय की भागीदारी पर जोर देकर, जीएसपी का लक्ष्य मृदा स्वास्थ्य और लचीलापन बढ़ाना है, जो सतत कृषि, खाद्य सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन के लिए जरूरी है।

जलवायु वित्त पर ओइसीडी रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी की गई "विकसित देशों द्वारा 2013-2022 में प्रदान किया गया और जुटाया गया जलवायु वित्त" रिपोर्ट के अनुसार, OECD ने पहली बार 100 बिलियन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पार कर लिया है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- 2013 से 2022 तक विकसित देशों द्वारा प्रदान किया गया और जुटाया गया जलवायु वित्त, 2009 में सहमत UNFCCC लक्ष्य की दिशा में प्रगति का OECD का सातवाँ आकलन है।
- इस लक्ष्य का उद्देश्य 2020 तक सालाना 100 बिलियन डॉलर जुटाना था, जिसे बाद में 2025 तक बढ़ा दिया गया, ताकि जलवायु परिवर्तन को कम करने और उससे निपटने में विकासशील देशों की सहायता की जा सके।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के नए आंकड़ों के अनुसार, जलवायु वित्त में 2021 से 30% की वृद्धि हुई है, जो 26.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जिसमें विकसित देश 2022 में विकासशील देशों के लिए 115.9 बिलियन डॉलर का जलवायु वित्त प्रदान और जुटाएंगे।
- OECD के आंकड़े अनुकूलन कार्यों के लिए आवंटित जलवायु वित्त में वृद्धि को भी दर्शाते हैं। 2021 में मामूली गिरावट के बाद, अनुकूलन वित्त 2022 में 32.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो 2016 के स्तर से तीन गुना अधिक है।
- 2019 में, OECD द्वारा ट्रैक किए गए सार्वजनिक अनुकूलन वित्त की राशि 18.8 बिलियन डॉलर थी, जो जुटाए गए निजी वित्त को शामिल करने पर बढ़कर 20.3 बिलियन डॉलर हो गई।
- इन आंकड़ों के आधार पर, विकसित देश COP26 ग्लासगो जलवायु समझौते के 2025 तक अनुकूलन वित्त के प्रावधान को दोगुना करने के आह्वान को पूरा करने के करीब पहुंच चुके हैं।

-: प्रीलिम्स इनसाइट :-

- पेरिस जलवायु समझौता जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है।
- इसे दिसंबर 2015 में पेरिस में पार्टियों के सम्मेलन COP 21 में 196 देशों द्वारा अपनाया गया था। भारत इस समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता है।

नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (NCQG):

- NCQG उस नई वार्षिक राशि को संदर्भित करता है जिसे विकसित देशों को विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई के वित्तपोषण के लिए 2025 से आगे जुटाना होगा, जो 2020 से वादा किए गए लेकिन अप्राप्त प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर से अधिक है।
- NCQG विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जिस पर कुछ वर्षों से चर्चा चल रही है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में दो दिवसीय मंत्री-स्तरीय जलवायु बैठक में, जो 22 मार्च को समाप्त हुई, NCQG को निर्धारित करने के लिए कुछ तकनीकी कार्यों को अंतिम रूप दिया गया।

जलवायु वित्त क्या है?

- जलवायु वित्त जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने या उसके अनुकूल होने के उद्देश्य से की जाने वाली कार्रवाइयों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण निवेश को संदर्भित करता है।

- अनुकूलन में जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों का पूर्वानुमान लगाना और उनके कारण होने वाले नुकसान को रोकने या कम करने के लिए उचित कार्रवाई करना शामिल है। अनुकूलन उपायों का एक उदाहरण तटीय समुदायों को समुद्र-स्तर की वृद्धि से बचाने के लिए बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना है।

निष्कर्ष:

विकसित देश विकासशील देशों को जलवायु वित्त में सालाना 100 बिलियन डॉलर प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा करने का दावा करते हैं, यह प्रक्रिया अस्पष्टता और अपर्याप्तता से भरी हुई है। अधिकांश फंडिंग को अनुदान के बजाय ऋण के रूप में फिर से तैयार किया जाता है और अक्सर मौजूदा सहायता के साथ जोड़ा जाता है, जिससे वास्तविक वित्तीय सहायता की रेखाएँ धुंधली हो जाती हैं। संचित निधियों को विभिन्न आवश्यकताओं- शमन, अनुकूलन, हानि और अन्य में वितरित करने की आवश्यकता है। हालाँकि, जलवायु वित्त प्रवाह वर्तमान में शमन कार्यों की ओर बहुत अधिक झुका हुआ है, जबकि विकासशील देश अनुकूलन और अन्य गतिविधियों के लिए अधिक धन की माँग करते हैं।

विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति का 2024 संस्करण जारी किया गया था, जिसमें ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन की कार्रवाई को दर्शाया गया था।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में पकड़ी गई प्रजातियों की संख्या में बहुत भिन्नता रही है, जिसमें क्षेत्र दर क्षेत्र प्रमुख अंतर हैं।
- व्हाइटलेग झींगा (पेनियस वन्नामेई), 6.8 मिलियन टन के साथ, 2022 में उत्पादित शीर्ष जलीय प्रजाति थी।

अन्य प्रजातियों का क्रम:

- कप्ड ऑयस्टर नी (क्रैसोस्ट्रिया एसपीपी., 6.2 मिलियन टन)।
- ग्रास कार्प (जिसे व्हाइट अमूर भी कहा जाता है; सेटेनोफेरींगोडन इडेलस, 6.2 मिलियन टन)।
- नाइल तिलापिया (ओरियोक्रोमिस निलोटिकस, 5.3 मिलियन टन)।
- सिल्वर कार्प (हाइपोफथाल्मिचथिस मोलिट्रिक्स, 5.1 मिलियन टन।
- एंकोवेटा (जिसे पेरूवियन एंकोवी के नाम से भी जाना जाता है। एंग्राउलिस रिंगेंस, 4.9 मिलियन टन)।
- एंकोवेटा के बाद जापानी कार्पेट शेल और कैटला का स्थान आता है, जिसके बाद कॉमन कार्प और अलास्का या वॉली पोलक का स्थान आता है।
- 2022 में, पकड़े गए 75% फिनफिश में से आधे समुद्री प्रजातियाँ थीं, जबकि 44% मीठे पानी की प्रजातियाँ थीं। समुद्री फिनफिश कुल उत्पादित जलीय जानवरों का 38% हिस्सा थीं, जिसमें मीठे पानी की मछलियाँ 33% थीं।
- 1970 के दशक के अंत तक, फिनफिश, जिसे सच्ची मछलियों (मोलस्क या क्रस्टेशियन जैसे अन्य जलीय जानवरों से अलग) के रूप में भी जाना जाता है, जलीय जानवरों के कुल उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा बनाती थी, जबकि 2022 में यह 75% हो जाएगी।
- कार्प्स, बारबेल और अन्य साइप्रिनिड्स 2022 में उत्पादित प्रजातियों का प्राथमिक समूह थे, जो जलीय जानवरों के उत्पादन का 18% प्रतिनिधित्व करते थे। इसके बाद कई मीठे पानी की प्रजातियाँ (11%) और क्लूपीफॉर्मेस जैसे हेरिंग, सार्डिन और एंकोवीज (10%) का स्थान आता है।
- जलीय कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारण मोलस्क और क्रस्टेशियन की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

भारत के सन्दर्भ में मुख्य बातें:

- भारत के संबंध में, रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में चार मिलियन टन से अधिक की कटाई के साथ कैटला 'शीर्ष दस प्रजातियों की वस्तुओं' की सूची में आठवें स्थान पर है।
- पूर्वी भारतीय राज्यों के तालाबों में पारंपरिक रूप से पाले जाने वाले कतला की खेती 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पूरे देश में फैल गई। कतला के साथ-साथ रोहू (लेबियो रोहिता) और मृगल (सिरहिनस मृगला) भारत के अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सबसे अधिक पाले जाने वाली मछलियों में से हैं।

निष्कर्ष:

रिपोर्ट में जलीय कृषि के उदय पर प्रकाश डाला गया है, जिसने 2022 में कैप्चर फिशरीज उत्पादन को पीछे छोड़ दिया, जिसमें अंतर्देशीय जलीय कृषि ने प्रमुख भूमिका निभाई। यह बदलाव जलीय पशु प्रजातियों की बढ़ती मांग का समर्थन करने के लिए टिकाऊ प्रथाओं और तकनीकी नवाचारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

उथला जलभृत प्रबंधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) ने हबसीगुडा और सैनिकपुरी में पायलट आधार पर उथला जलभृत प्रबंधन (SAM) मॉडल शुरू किया है।

उथला जलभृत प्रबंधन के बारे में:

- उथला जलभृत प्रबंधन उथले जलभृतों में भूजल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को संदर्भित करता है, जिसे आमतौर पर भूमि की सतह से 50 मीटर के भीतर जलभृत के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- शहरी जल की माँग को पूरा करने, पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने और भूजल पर निर्भर पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए उथले जलभृत महत्वपूर्ण हैं।

यह कैसे किया जाता है?

- इस परियोजना की अवधारणा 100-120 फीट की गहराई तक उथले जल इंजेक्शन बोरवेल को ड्रिल करना और उथले जलभृतों में पानी को पंप करना है।
- ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब भी बारिश हो, नीचे की परतें रिचार्ज हो जाएँ, जबकि आसपास के वाटरशेड से पानी इकट्ठा करके उसे रिचार्ज पिट के माध्यम से भेजा जाता है।
- इस प्रकार, भूमिगत परतें रिचार्ज हो जाती हैं और जल स्तर बढ़ जाता है।

भारत में शैलो एक्विफर मैनेजमेंट (एसएएम) पायलट मॉडल:

- भारत में शैलो एक्विफर मैनेजमेंट (एसएएम) पायलट मॉडल अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (एएमआरयूटी) योजना के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक पहल है।

हबसीगुडा और सैनिकपुरी में पायलट मॉडल के मुख्य पहलू:

- हबसीगुडा और सैनिकपुरी में शैलो एक्विफर मैनेजमेंट (एसएएम) पायलट मॉडल ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) द्वारा भूजल की कमी और बाढ़ को संबोधित करने के लिए पहल है।

स्थान:

- हबसीगुडा में काकतीय पार्क
- सैनिकपुरी में ई-सेक्टर पार्क

उद्देश्य:

- शहरी जल प्रबंधन तकनीक के रूप में शैलो एक्विफर मैनेजमेंट को लागू करना।
- शहरी क्षेत्रों में भूजल की कमी, बोरवेल के सूखने और तेजी से बाढ़ को संबोधित करना।

लाभ:

- भूजल पुनर्भरण को बढ़ाता है।
- बाढ़ को कम करता है।
- भविष्य में उपयोग के लिए जल उपलब्धता को बढ़ाता है।
- एक स्थायी शहरी जल प्रबंधन दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।

एसएएम पायलट परियोजनाओं के लिए चुने गए शहर:

- बेंगलुरु (कर्नाटक)
- चेन्नई (तमिलनाडु)
- धनबाद (झारखंड)
- ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
- हैदराबाद (तेलंगाना)
- जयपुर (राजस्थान)
- कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
- पुणे और ठाणे (महाराष्ट्र)
- राजकोट (गुजरात)

निष्कर्ष:

हबसीगुडा और सैनिकपुरी में पायलट मॉडल की सफलता भारत में शहरी जल प्रबंधन मुद्दों को संबोधित करने के लिए शैलो एक्विफर मैनेजमेंट (एसएएम) की क्षमता को उजागर करती है, और भविष्य के कार्यान्वयन के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है।

बायेसियन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (BCNN)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में INCOIS (भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र) ने बायेसियन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (BCNN) नामक एक नया उत्पाद विकसित किया है, जो ENSO चरण पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है। BCNN एल नीनो और ला नीना घटनाओं की भविष्यवाणी 15 महीने पहले तक कर सकता है, जो अन्य मॉडलों से बेहतर है जो केवल छह से नौ महीने पहले तक का पूर्वानुमान लगा सकते हैं।

BCNN के बारे में:

- बायेसियन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (BCNN) वास्तव में एक अत्याधुनिक तकनीक है जो एल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) चरणों से संबंधित भविष्यवाणियों को बेहतर बनाने के लिए AI, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की ताकत का लाभ उठाती है।
- धीमी समुद्री विविधताओं और वायुमंडलीय युग्मन को ध्यान में रखते हुए, BCNN एल नीनो और ला नीना घटनाओं की भविष्यवाणी करने में उत्कृष्ट है। बेहतर परिशुद्धता के साथ नीनो 3.4 सूचकांक मूल्य की गणना करने की इसकी क्षमता एक महत्वपूर्ण प्रगति है, जो अधिक विश्वसनीय और समय पर मौसम की भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाती है।
- एआई के साथ गतिशील मॉडल का एकीकरण बीसीएनएन को अन्य मॉडलों की क्षमताओं को पार करते हुए, उल्लेखनीय 15 महीने के लीड टाइम के साथ एल नीनो और ला नीना स्थितियों का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम बनाता है।
- इस तकनीक का कृषि, मत्स्य पालन और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है, जहाँ सटीक और समय पर मौसम की भविष्यवाणी महत्वपूर्ण है।

आईएनसीओआईएस (INCOIS) के बारे में:

- आईएनसीओआईएस (भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के तहत एक स्वायत्त निकाय है और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ) की एक इकाई है।
- इसका अधिदेश निरंतर महासागर अवलोकन और अनुसंधान के माध्यम से विभिन्न हितधारकों को महासागर की जानकारी और

सलाहकार सेवाएँ प्रदान करना है।

मौसम मॉडल के बारे में:

- **सांख्यिकीय मॉडल:** ये मॉडल विभिन्न स्रोतों से जानकारी का उपयोग करके ऐतिहासिक डेटा और सांख्यिकीय तकनीकों के आधार पर पूर्वानुमान उत्पन्न करते हैं।
- **गतिशील मॉडल:** ये मॉडल वायुमंडल के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने के लिए उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटर (एचपीसी) पर चलने वाले जटिल गणितीय सिमुलेशन का उपयोग करते हैं। गतिशील मॉडल आम तौर पर सांख्यिकीय मॉडल की तुलना में अधिक सटीक होते हैं, क्योंकि वे वायुमंडल को नियंत्रित करने वाली भौतिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हैं।
- बायेसियन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (BCNN) में इस्तेमाल किए जाने वाले गतिशील मॉडल था। एल नीनो और ला नीना घटनाओं जैसी जटिल मौसम संबंधी घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं।

ENSO के बारे में:

- ENSO एक जलवायु घटना है, जिसकी विशेषता मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर और उसके ऊपर के वायुमंडल के तापमान में उतार-चढ़ाव है। यह बदले में, वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को दुनिया भर में मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है।

ENSO के तीन चरण हैं:

- **तटस्थ चरण:** प्रचलित पवन प्रणालियों के कारण पूर्वी प्रशांत पश्चिमी प्रशांत की तुलना में ठंडा होता है, जो गर्म सतही जल को इंडोनेशिया की ओर बहा ले जाता है।
- **एल नीनो (गर्म चरण):** कमजोर पवन प्रणालियाँ गर्म जल को पूर्वी प्रशांत पर हावी होने देती हैं, जिससे व्यापारिक हवाएँ कमजोर हो जाती हैं और यहाँ तक कि दिशा बदल देती हैं, जिससे पश्चिमी प्रशांत से गर्म पानी अमेरिका की ओर आ जाता है।
- **ला नीना (शीत चरण):** भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में औसत से अधिक ठंडा समुद्री सतह का तापमान, तेज व्यापारिक हवाएँ और एशिया की ओर गर्म पानी को ले जाती है। भारत में, अल नीनो की स्थिति आम तौर पर कमजोर मानसून और तीव्र गर्मी की लहरों का कारण बनती है, जबकि ला नीना की स्थिति के परिणामस्वरूप मजबूत मानसून होता है।

निष्कर्ष:

बीसीएनएन में मौसम पूर्वानुमान और जलवायु पूर्वानुमान में क्रांति लाने की क्षमता है, जिससे बेहतर निर्णय लेने और अधिक प्रभावी संसाधन प्रबंधन को सक्षम किया जा सकता है। इसके अनुप्रयोगों का समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, जिससे यह अधिक लचीले और टिकाऊ भविष्य के लिए एक आशाजनक तकनीक बन जाती है।

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर (सोगा) रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 जारी की गयी। यह रिपोर्ट हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज प्रोजेक्ट के सहयोग से, यह यूनिसेफ के साथ साझेदारी में तैयार की गई है। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रभाव:

- 2021 में, पांच साल से कम उम्र के बच्चों में कुल 709,000 मौतें वायु प्रदूषण से जुड़ी थीं, यह पांच साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली सभी वैश्विक मौतों का 15% है।
- इनमें से ज्यादातर मौतें (507,500) ठोस ईंधन से खाना पकाने से होने वाले घरेलू वायु प्रदूषण से जुड़ी थीं और 201,000 मौतें PM2.5 से जुड़ी थीं।
- देश स्तर पर, सबसे अधिक मृत्यु दर चाड (159 मृत्यु/100,000 लोग), दक्षिण सूडान (129/100,000 लोग), मध्य अफ्रीकी गणराज्य (128/100,000 लोग), नाइजीरिया (109/100,000 लोग), नाइजर (108/100,000 लोग), बुर्किना फासो (108/100,000 लोग) और पापुआ न्यू गिनी (107/100,000 लोग) में देखी गई।
- अफ्रीका के कई देशों (जैसे, नाइजर, रवांडा, मलावी, सेनेगल, इथियोपिया, युगांडा और मोजाम्बिक) और एशिया के कई देशों (जैसे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत) में, पांच साल से कम उम्र के बच्चों में निचले श्वसन संक्रमण एलआरआई से होने वाली सभी मौतों में से 40% से अधिक वायु प्रदूषण के कारण होती हैं।
- हालाँकि पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में प्रदूषण से संबंधित मौतें कुछ क्षेत्रों में अधिक बनी हुई हैं, विशेष रूप से दक्षिण एशिया और पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में।
- 2021 में, भारत (169400 मौतें), नाइजीरिया (114100 मौतें), पाकिस्तान (68100 मौतें), इथियोपिया (31,100 मौतें) और बांग्लादेश (19100 मौतें) में इन बच्चों में वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे बड़ी संख्या देखी गई।

नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- 2021 में, 572,000 नवजात शिशुओं की मृत्यु वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई थी, जो कुल नवजात शिशुओं की मृत्यु का 26% है।
- सबसे ज्यादा प्रभाव एशिया और अफ्रीका के देशों में देखा गया, जहाँ लाखों परिवार खाना पकाने के लिए प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर हैं।

आगे की राह:

दुनिया की 99% आबादी PM2.5 के हानिकारक स्तरों के संपर्क में है, वायु प्रदूषण ने अकेले 2021 में 1.1 मिलियन मौतों में योगदान दिया।

वायु प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ी और बढ़ती चुनौती है। यह अब दुनिया भर में समय से पहले मृत्यु के लिए दूसरा सबसे बड़ा जोखिम कारक है।

स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) पर अध्ययन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के नए अध्ययन में 2004 से वैश्विक स्तर पर विनियमित डीडीटी जैसे 12 स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) में कमी पाई गई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा कार्यान्वित और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) द्वारा वित्त पोषित अध्ययन, पीओपी निगरानी, विकल्पों को पेश करने में सावधानी और जागरूकता और विनियमन में अंतराल को संबोधित करने के महत्व पर जोर देता है।

अध्ययन के मुख्य बिंदु:

- यह अध्ययन 42 देशों में उन क्षेत्रों में किया गया था जहाँ पीओपी पर डेटा सीमित है, जिसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन और प्रशांत द्वीप समूह शामिल हैं, ताकि 2021 तक स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध 30 पीओपी की निगरानी की जा सके। नमूने 2016 और 2019 के बीच एकत्र किए गए थे।
- अध्ययन के अनुसार पीओपी के उपयोग और उत्पादन को कम करने के प्रयासों के बावजूद, वे सर्वव्यापी बने हुए हैं।
- अध्ययन में निगरानी की गई 30 पीओपी की सूची में कीटनाशक और औद्योगिक रसायन शामिल हैं, साथ ही गैर इरादतन जारी किए गए पीओपी भी शामिल हैं जो औद्योगिक प्रक्रियाओं और अधूरे दहन (जैसे, कचरे को खुले में जलाना) के उप-उत्पाद हैं।
- यह डेटा 2004 में हुए स्टॉकहोम कन्वेंशन सूचीबद्ध 12 पीओपी के स्तरों में वैश्विक गिरावट दर्शाता है, रिपोर्ट इस प्रवृत्ति का श्रेय तब से किए गए नियामक कार्यों को देती है।
- डीडीटी जो कभी कृषि में इस्तेमाल किया जाता था और अब अत्यधिक प्रतिबंधित है, 2004 के बाद से वैश्विक औसत मानव दूध के नमूनों में 70 प्रतिशत से अधिक कम हो गया है। फिर भी, डीडीटी मानव दूध में सबसे प्रचलित पीओपी बना हुआ है, खासकर उन देशों में जहां इसका गहन उपयोग किया गया हैं
- अफ्रीकी महाद्वीप, कैरिबियन और लैटिन अमेरिका में हवा में लंबे समय से विनियमित रसायन, जैसे कि डाइलड्रिन और पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल (पीसीबी) उच्च स्तर पर पाए गए।
- उद्योग द्वारा कुछ प्रतिबंधित रसायनों को अन्य रसायनों से बदल दिया गया है, जिनमें बाद में पीओपी गुण भी पाए गए, जैसे कि प्रति-और पॉलीफ्लुओरोएल्काइल पदार्थ (पीएफएएस)।
- हजारों पीएफएएस में से, तीन प्रमुख रसायन (पीएफओएस, पीएफओए, पीएफएचएक्सएस) स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध हैं। ये सभी मानव दूध में पाए गए।
- पीएफएएस दूरदराज के द्वीपों में पीने के पानी में भी पाए गए, जिनका स्तर यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मानकों से कहीं अधिक था। नए सूचीबद्ध पीओपी की निगरानी करना दुनिया की शीर्ष प्रयोगशालाओं द्वारा भी मुश्किल होता जा रहा है।

स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के बारे में:

- स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी) लंबी दूरी तक परिवहन की अपनी क्षमता, पर्यावरण में बने रहने, पारिस्थितिकी तंत्र में जैव-आवर्धन और जैव-संचय की क्षमता के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभावों के कारण वैश्विक चिंता के रसायन हैं।
- सबसे आम तौर पर पाए जाने वाले पीओपी ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक हैं, जैसे डीडीटी, औद्योगिक रसायन, पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल (पीसीबी) और साथ ही कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के अनजाने उप-उत्पाद, विशेष रूप से पॉलीक्लोरीनेटेड डिबेंजो-पी-डाइऑक्सिन (पीसीडीडी) और डिबेंजोफुरान (पीसीडीएफ), जिन्हें आमतौर पर डाइऑक्सिन के रूप में जाना जाता है।

निष्कर्ष:

डीडीटी के स्तर में गिरावट एक सफलता की कहानी है, लेकिन अन्य पीओपी का बढ़ना निरंतर सतर्कता और कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर करता है। रिपोर्ट मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए पीओपी की निगरानी और प्रबंधन के महत्व पर जोर देती है। कुल मिलाकर, रिपोर्ट पीओपी को संबोधित करने में मिश्रित प्रगति को उजागर करती है, साथ ही अन्य हानिकारक रसायनों के बढ़ते स्तरों को संबोधित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

ATCM-46 और CEP-26

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत ने कोच्चि, केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक (ATCM-46) और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति (CEP-26) की मेजबानी की।

ATCM-46 और CEP-26 की मुख्य बातें:

- ATCM-46 और CEP-26 की मेजबानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR) गोवा के माध्यम से तथा अंटार्कटिक संधि सचिवालय के समर्थन से की। जिसका मुख्यालय अर्जेंटीना में हैं।
- इस कार्यक्रम में सभी पक्षों द्वारा अंटार्कटिक संधि (1959) और अंटार्कटिक संधि के पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल (मैड्रिड प्रोटोकॉल, 1991) की पुनः पुष्टि की गई।
- सीईपी-26 ने अनेक मुद्दों पर विचार किया तथा अंटार्कटिका में पर्यावरण प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन में योगदान दिया। समिति ने समुद्री बर्फ में परिवर्तन के प्रबंधन हेतु कार्य को प्राथमिकता देने,

प्रमुख गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को बढ़ाने, पेंगुइन की रक्षा करने और अंटार्कटिका में पर्यावरण निगरानी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ढांचा विकसित करने पर सहमति व्यक्त की।

- सीईपी की सलाह के बाद, पार्टियों ने अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्रों (एएसपीए) के लिए 17 संशोधित और नई प्रबंधन योजनाओं को अपनाया और ऐतिहासिक और स्मारक स्थलों की सूची में कई संशोधन और परिवर्तन किए।
- एटीसीएम ने अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने और अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा के जोखिमों को कम करने के लिए जैव सुरक्षा उपायों के मजबूत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया।

अंटार्कटिक संधि के बारे में:

- अंटार्कटिक संधि पर 1 दिसंबर, 1959 को वाशिंगटन में 1957-58 के अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष (IGY) के दौरान अंटार्कटिका में सक्रिय बारह देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।
- इसके मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, यूके और यूएस शामिल थे।
- यह 1961 में लागू हुआ और तब से कई अन्य राष्ट्र इसमें शामिल हो गए, जिससे पार्टियों की कुल संख्या 56 हो गई। अंटार्कटिक संधि के दो प्रकार के पक्ष हैं - परामर्शदात्री (29) और गैर-परामर्शदात्री (27)।
- यद्यपि गैर-परामर्शदात्री को परामर्शदात्री बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, वे निर्णय लेने में भाग नहीं लेते हैं। भारत 1983 से अंटार्कटिक संधि का एक परामर्शदात्री पक्ष रहा है।

अंटार्कटिक संधि के तहत एटीसीएम और सीईपी के बारे में:

- **अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक (एटीसीएम):** एटीसीएम अंटार्कटिका में पर्यावरणीय, वैज्ञानिक और शासन संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री दलों और अन्य हितधारकों के लिए मंच के रूप में कार्य करता है।
- 1961 से 1994 तक, एटीसीएम की बैठक हर दो साल में एक बार होती थी, लेकिन 1994 से, बैठकें सालाना आयोजित की जाती हैं। एटीसीएम की मेजबानी सलाहकार दलों द्वारा उनके अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम में की जाती है।

पर्यावरण संरक्षण समिति (सीईपी):

- 1991 में अंटार्कटिक संधि (मैड्रिड प्रोटोकॉल) के पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल के तहत स्थापित, सीईपी अंटार्कटिका में पर्यावरण संरक्षण पर एटीसीएम को सलाह देती है।
- अंटार्कटिक संधि सचिवालय (एटीएस): 2004 में स्थापित एटीएस, एटीसीएम और सीईपी बैठकों का समन्वय करते हुए अंटार्कटिक संधि प्रणाली के लिए प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह संधि के प्रावधानों और समझौतों के अनुपालन की निगरानी करता है, कार्यान्वयन और प्रवर्तन पर संधि पक्षों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

भारत में 46वीं एटीसीएम और 26वीं सीईपी की सफल मेजबानी अंटार्कटिका के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा और वैश्विक पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के हमारे सामूहिक संकल्प को रेखांकित करती है। संवाद, सहयोग और ठोस कार्रवाई के माध्यम से हम यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अंटार्कटिका आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति, विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बना रहे।

नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) उत्सर्जन का वैश्विक मूल्यांकन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) उत्सर्जन का वैश्विक मूल्यांकन' नामक एक रिपोर्ट अर्थ 'सिस्टम साइंस डेटा जर्नल' में प्रकाशित हुई, जो नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का वैश्विक स्थिति का मूल्यांकन करती है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, जिसने लगभग 16 प्रतिशत नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित किया है।
- भारत और चीन दोनों ने 2020 में लगभग 27 प्रतिशत उत्सर्जन में योगदान दिया। नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादातर उर्वरक क्षेत्र द्वारा किया गया है।
- 1980 से 2020 तक N_2O उत्सर्जन में 40% की वृद्धि हुई है, जिसमें कृषि, उद्योग और वन दहन प्रमुख मानव स्रोत हैं।
- उर्वरक और पशुधन खाद महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं, जो क्रमशः 70% और 30% कृषि उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं।

नाइट्रोजन उर्वरकों से संबंधित चिंता:

- पिछले चार दशकों में मानवीय गतिविधियों से N_2O उत्सर्जन में 40% (प्रति वर्ष तीन मिलियन मीट्रिक टन N_2O) की वृद्धि हुई है, 2020 और 2022 के बीच वृद्धि दर 1980 के बाद से किसी भी पिछली अवधि की तुलना में अधिक है
- अमोनिया और पशु खाद जैसे नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग करने वाले कृषि उत्पादन ने पिछले दशक में कुल मानवजनित N_2O उत्सर्जन का 74% योगदान दिया।
- मानवीय गतिविधियों से N_2O उत्सर्जन ग्रीनहाउस गैसों के प्रभावी विकिरण के 6.4% के लिए जिम्मेदार है और इसने वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग में लगभग 0.1°C जोड़ा है।
- मांस और डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग ने भी खाद उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से उत्सर्जन में वृद्धि में योगदान दिया है, जो N_2O उत्सर्जन का भी कारण बनता है। पशु आहार के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन उर्वरकों में वृद्धि ने भी वृद्धि में योगदान दिया है।
- 2020 में मानवजनित नाइट्रोजन उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से

शीर्ष पांच उत्सर्जक देश चीन (16.7%), भारत (10.9%), संयुक्त राज्य अमेरिका (5.7%), ब्राजील (5.3%), और रूस (4.6%) थे।

नाइट्रोजन उत्सर्जन के प्रभाव:

- एक बार उत्सर्जित होने के बाद, नाइट्रोजन औसत मानव जीवनकाल (117 वर्ष) से अधिक समय तक वायुमंडल में रहता है, और इसलिए इसका जलवायु और ओजोन पर प्रभाव लंबे समय तक रहता है।
- नाइट्रोजन उत्सर्जन के अतिरिक्त सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों और पशु खाद के अकुशल उपयोग से भूजल, पेयजल और अंतर्देशीय और तटीय जल का प्रदूषण भी होता है।

निष्कर्ष:

नाइट्रस ऑक्साइड बजट की यह रिपोर्ट चिंताजनक है। नाइट्रोजन उर्वरकों से N_2O उत्सर्जन के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जिन पर भारत में 80% से अधिक सब्सिडी दी जाती है। यह समय की मांग है कि भारत इस चेतावनी को गंभीरता से ले और फसल प्रणाली तथा उत्पादन पद्धतियों में बदलाव करे। उर्वरक सब्सिडी को वैकल्पिक उत्पादन प्रणालियों को समर्थन देने के लिए पुन: उपयोग में लाया जाना चाहिए।

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीता पुनरूत्पादन परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को बसाने की अपनी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

- गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, कुनो राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) के बाद भारत में चीतों का दूसरा बड़ा आवास है।
- यह अभयारण्य 64 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और तार की बाड़ से सुरक्षित है।
- कान्हा, सतपुड़ा और संजय बाघ अभयारण्यों से शिकार जानवरों को गांधी सागर में स्थानांतरित किया गया है।
- चीतों को चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है।
- अस्पताल के निर्माण पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए केएनपी से पशु चिकित्सकों की एक टीम अभयारण्य का दौरा करेगी।
- इस अभयारण्य में चीतों को बसाने के संबंध में समय और अन्य औपचारिकताओं पर निर्णय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा लिया जाएगा।

भारत में चीते के बारे में:

- एशियाई चीते कभी भारत के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे, लेकिन शिकार और जाल के कारण वे 1952 में विलुप्त हो गए।
- 2022 में, प्रोजेक्ट चीता के हिस्से के रूप में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को कुनो नेशनल पार्क में लाया गया।
- प्रोजेक्ट चीता एक भारतीय सरकारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य चीतों को फिर से लाना है।
- इसी के तहत चीतों को कुनो नेशनल पार्क में फिर से लाया गया, जिसमें लगभग 20 चीतों को पालने के लिए पर्याप्त शिकार आबादी थी। मार्च 2024 तक, राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की कुल संख्या 27 थी।

अफ्रीकी चीते के बारे में:

- **गति:** अफ्रीकी चीते पृथ्वी पर सबसे तेज जमीनी जानवर हैं, जो 70 मील प्रति घंटे (113 किमी/घंटा) तक की गति तक दौड़ते हैं।
- **निवास स्थान:** वे दक्षिण अफ्रीका से इथियोपिया तक अफ्रीका में घास के मैदानों, सवाना और खुले मैदानों में रहते हैं।
- **आहार:** चीते मुख्य रूप से छोटे से मध्यम आकार के मृगों, जैसे कि थॉमसन के हिरन और इम्पालास को खाते हैं।
- **संरक्षण स्थिति:** IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध, अनुमान है कि जंगल में केवल 6,600 चीते बचे हैं।
- **शारीरिक विशेषताएँ:** काले धब्बों वाला पीला-भूरा त्वचा, सफेद पेट और आँख से मुँह तक एक विशिष्ट काली रेखा।
- **व्यवहार:** अकेले रहने वाले जानवर, केवल संभोग के लिए एक साथ आते हैं। उनके पास एक बड़ा घरेलू क्षेत्र है, जो अक्सर अन्य चीतों के साथ ओवरलैप होता है।

एशियाई चीते के बारे में:

- **उप-प्रजाति:** एशियाई चीता (एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस) चीते की एक उप-प्रजाति है, जो कभी ईरान, भारत और पाकिस्तान में पाई जाती थी।
- **विलुप्ति:** 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया, और ईरान में गंभीर रूप से संकटग्रस्त माना जाता है, जहाँ 50 से भी कम चीते बचे हैं।
- **शारीरिक अंतर:** अफ्रीकी चीतों से छोटे, अधिक भूरे-भूरे रंग के बाल और रीढ़ के साथ एक विशिष्ट काली पट्टी।
- **निवास:** ईरान और पूर्व में भारत और पाकिस्तान में शुष्क क्षेत्रों, घास के मैदानों और रेगिस्तानों में निवास।
- **आहार:** मुख्य रूप से छोटे से मध्यम आकार के मृग, जैसे कि गजेल और खरगोश।

निष्कर्ष:

गांधी सागर अभयारण्य में चीतों का पुन: आगमन भारत के संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जंगलों में चीतों की स्थायी आबादी को फिर से स्थापित करना है, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता को बढ़ावा मिले। अभयारण्य का उपयुक्त आवास और शिकार आधार चीतों के पनपने के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है।

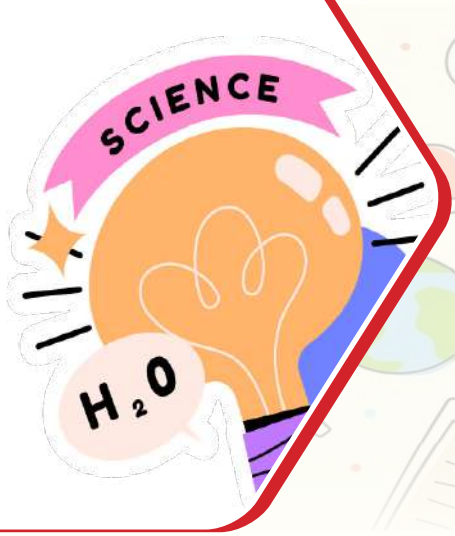

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

डीप सी मिशन से भारत की स्वदेशी क्षमता का होगा विस्तार

हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की 100 दिवसीय कार्य योजना पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कहा है कि डीप सी मिशन शुरू करने की उपलब्धि हासिल करने वाले कुछ गिने चुने देशों में भारत एक है। इस बैठक में कहा गया है कि भारत का अपना खुद का डीप सी मिशन शुरू करने वाला छठा देश होगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने संस्थानों से कहा है कि वे आजीविका के लिए सागर और उसकी ऊर्जा पर निर्भर लोगों को सशक्त बनाने के लिए एक लचीली नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ही इस महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय है।

डीप सी मिशन की रूपरेखा तैयार करते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा है कि ''यह मिशन केवल खनिज अन्वेषण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री विज्ञान का विकास और वनस्पतियों तथा जीव-जंतुओं की खोज और समुद्री जैव विविधता का संरक्षण आदि भी इसमें शामिल है।" मत्स्ययान 6000 के विकास के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) के प्रयास लगातार जारी हैं। समुद्र में 6000 मीटर गहराई तक जा सकने की क्षमता हासिल करना मत्स्ययान 6000 का लक्ष्य है। अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत में नई सरकार के गठन के बाद इस प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को सितंबर 2024 तक हार्बर ट्रेल के पहले चरण और 2026 तक बाद के परीक्षण पूरे करने का निर्देश दिया है। डीप सी मिशन में भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में अत्यधिक योगदान देने की क्षमता है।

ब्लू इकॉनमी को गति देकर यह भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को साकार कर सकता है। इसीलिए महासागरीय अर्थव्यवस्था के महत्व को केंद्र सरकार ने समझ लिया है। महासागरों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने 2021-2030 के दशक को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के दशक के रूप में घोषित किया है। इसको लेकर भारत की भूमिका अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि भारत की एक विशिष्ट समुद्री स्थिति है। भारत 7,517 किमी लंबी तटरेखा के साथ, नौ तटीय राज्यों और 1,382 द्वीपों का घर है। 2030 तक भारत सरकार के नए भारत के विजन ने ब्लू इकोनॉमी को विकास के दस प्रमुख आयामों में से एक के रूप में बताया है। डीप ओशन मिशन देश के जीडीपी में वृद्धि करने की क्षमता वाली सरकार की नीली अर्थव्यवस्था नीति की सहायता करता है और देश की आर्थिक वृद्धि, बेहतर आजीविका और नौकरियों तथा महासागर के पारिस्थितिकी तंत्र के मजबूत स्थिति के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग की परिकल्पना करता है।

डीप सी मिशन की जरूरत क्यो?

- पृथ्वी का लगभग 70 प्रतिशत भाग पानी से घिरा है, जिसमें अगल-अलग प्रकार के समुद्री जीव-जंतु हैं। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि तमाम आधुनिक तकनीक और विज्ञान के बावजूद भी गहरे समुद्र का लगभग 95.8% हिस्सा आज भी मनुष्य के लिए एक रहस्य ही है। समुद्र में 6 हजार मीटर नीचे कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं।
- इन खनिजों के बारे में अब तक अध्ययन नहीं हुआ है। इस मिशन के तहत इन खनिजों के बारे में अध्ययन एवं सर्वेक्षण का काम किया जाएगा, इसीलिए भारतीय समुद्री सीमा के अंदर आने वाले समुद्र की गहराइयों को टटोलने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने डीप ओशन मिशन (Deep Ocean Mission) को मंजूरी दी।
- केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समुद्रयान मिशन के एक भाग के रूप में भारत का लक्ष्य तीन व्यक्तियों को अन्वेषण के लिए अब समुद्र सतह से 6000 मीटर नीचे गहराई में भेजना है। केंद्र ने पांच साल के लिए 4,077 करोड़ रुपये के कुल बजट में गहन सागर मिशन को स्वीकृति दी थी। तीन वर्षों (2021-2024) के लिए पहले चरण की अनुमानित लागत 2,823. 4 करोड़ रुपये है। अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के बाद भारत भी उस विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है जिनके पास समुद्र के अंदर की गतिविधियों के लिए मानव युक्त मिशन चलाने की क्षमता है।
- डीप सी मिशन से जुड़े वाहन का डिजाइन तैयार कर लिया गया है

और वाहन के विभिन्न उपकरणों/घटकों की प्राप्ति का कार्य प्रगति पर है। यह वाहन मानव युक्त सबमर्सिबल निकल, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा तत्व, मैंगनीज आदि से समृद्ध खनिज संसाधनों की खोज में गहरे समुद्र में मानव द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन की सुविधा प्रदान करने के साथ ही विभिन्न नमूनों का संग्रह करता है, जिनका उपयोग बाद में विश्लेषण के लिए किया जा सकता है।

- गहरे समुद्र में संसाधनों और जैव विविधता मूल्यांकन का पता लगाने के लिए 6000 मीटर गहराई में एकीकृत खनन के लिए इस मशीन और मानव रहित वाहनों (टेथर्ड एंड ऑटोमेटेड) का विकास किया गया है। अधिक कुशल, विश्वसनीय और सुरक्षित मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित करने में धातु विज्ञान, ऊर्जा भंडारण, पानी के भीतर नेविगेशन और विनिर्माण सुविधाओं में उन्नत प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण होती हैं।
- डीप ओशन मिशन से जुड़ी ब्लू इकोनॉमी की महत्ता समझने के लिए इसमें छिपे आर्थिक फायदों को समझना होगा। भारत सरकार इस मिशन पर 4,077 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है जो अलग-अलग चरणों में खर्च होंगे। ग्लोबल मरीन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिपोर्ट का दावा है कि इस क्षेत्र का वैश्विक बाजार साल 2027 तक करीब लगभग 5.4 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के एक दस्तावेज में बताया गया है कि ब्लू इकोनॉमी का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और आजीविका के संरक्षण या सुधार को बढ़ावा देने के साथ-साथ महासागरों और तटीय क्षेत्रों की पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करना है। वैज्ञानिक निष्कर्षों से पता चलता है कि समुद्री संसाधन सीमित हैं। मानव गतिविधियों के कारण महासागरों के 'स्वास्थ्य' में भारी गिरावट आई है, समुद्री स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।
- भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कहना है कि यह विशिष्ट प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को समुद्र में 1000 से 5500 मीटर की गहराई में पाए जाने वाले पॉलिमेटेलिक मैंगनीज नोड्यूलस, गैस हाइड्रेट्स, हाइड्रो-थर्मल सल्फाइड्स और कोबाल्ट क्रस्ट जैसे निर्जीव संसाधनों के अन्वेषण की दिशा में सुविधा प्रदान करेगी।
- इसके लिए मानवयुक्त पनडुब्बी 'मत्स्य 6000' का प्रारंभिक डिजाइन तैयार कर लिया गया है और इसरो, आईआईटीएम तथा डीआरडीओ सहित विभिन्न संगठनों के साथ इसको मूर्त रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पानी के अंदर अन्वेषण के लिए भेजे जाने वाले वाहनों को हाई रिजोल्यूशन बैथीमेट्री, जैव विविधता का आकलन, भू-वैज्ञानिक अवलोकन, खोज गतिविधियों के साथ-साथ बचाव अभियान और इंजीनियरिंग सहायता जैसी गतिविधियों को पूरा करने में सक्षम होना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि समुद्र के भीतर की प्रौद्योगिकियों के उन्नयन से चीन द्वारा 2020 में विकसित की गई मानवयुक्त पनडुब्बी फेंडोजे ने हाल ही में 11000 मीटर की गहराई तक गोता लगाया था।

डीप सी मिशन हेतु मानवयुक्त सबमर्सिबल का इस्तेमालः

- मानवनिर्मित सबमर्सिबल को 2.1 मीटर व्यास वाले टाइटेनियम मिश्र धातु कार्मिक क्षेत्र में तीन व्यक्तियों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी सामान्य परिचालन क्षमता 12h की होगी और आपातकालीन स्थिति में इसकी परिचालन क्षमता को 96h तक किया जा सकेगा।

- मानवयुक्त सबमर्सिबल के कुछ महत्वपूर्ण उप-प्रणालियों में टीआई मिश्र धातु कार्मिक क्षेत्र का विकास, संलग्न स्थान में मानव सहायता और सुरक्षा प्रणाली, कम घनत्व वाले मॉड्यूल, गिट्टी और ट्रिम सिस्टम शामिल हैं। यह प्रेशर कम्पेनसेटेड बैटरीज और प्रॉपल्सन सिस्टम, नियंत्रण और संचार प्रणाली और लॉन्चिंग और रिकवरी सिस्टम से भी लैस होंगे।
- इसे सिस्टम डिजाइन, संचालन की अवधारणा, उप-घटकों की कार्यक्षमता और अखंडता, आपातकालीन स्थिति में बचाव, असफलता की स्थिति का विश्लेषण इत्यादि के साथ साथ 6000 मीटर की गहराई पर मानवयुक्त पनडुब्बी के मानवीय उपयोग हेतु इसकी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन सोसाइटी के नियमों के अनुसार समीक्षा की गई है और प्रमाणित किया गया है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ मिलकर 'टाइटेनियम हल' विकसित करके अत्यधिक दबाव को सफलतापूर्वक झेलने के लिए काम करने के लिए सराहना की गई है। आपातकालीन स्थितियों से निपटने और 72 घंटे तक पानी में रहने के लिए 'सेल्फ-फ्लोटेशन' तकनीक के विकास के लिए भी कार्य किया जा रहा है।

तृष्णा मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) तथा फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सीएनईएस मिलकर तृष्णा नामक एक महत्वाकांक्षी नए उपग्रह मिशन पर सहयोग कर रहे हैं। यह उपग्रह 2025 में लांच किया जायेगा।

उपग्रह के बारे में:

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सीएनईएस उच्च गुणवत्ता वाले थर्मल इन्फ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट 'तृष्णा' के जरिये पृथ्वी की सतह की निगरानी करेंगे।
- इससे पहले, इसरो और सीएनईएस ने 2011 में 'मेघा ट्रॉपिक्स' और 2013 में 'सरल अल्तिका' मिशन पर भी साथ काम कर चुके है।
- 770 किलोग्राम वजनी यह उपग्रह 761 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य-समकालिक कक्षा में लांच किया जायेगा, इसमे दो अत्याधुनिक इमेजिंग पेलोड सेंसर होंगे, एक विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड (VNIR) सेंसर व विजिबल शॉर्ट वेव इंफ्रारेड सेंसर (VSWIR)।
- तृष्णा मिशन में तापमान, सतह की चमक, तापमान और उत्सर्जन को मापने के लिए चार थर्मल बैंड हैं। तृष्णा मिशन द्वारा जलवायु परिवर्तन से जुड़े चीजो का भी अध्यन किया जायेगा, जहाँ समुद्र और भूमि की सतह का तापमान प्रमुख हैं।
- VSWIR सात बैंड में अवलोकन प्रदान करने के लिए TIR का पूरक होगा।
- यह जल उपयोग, मृदा प्रदूषण, तटीय और अंतर्देशीय जल निगरानी, शहरी सूक्ष्म जलवायु निगरानी, ज्वालामुखी निगरानी, भूतापीय अन्वेषण, वनस्पति और भूमि कवरेज, क्रायोस्फीयर निगरानी और वायुमंडल और बादलों पर जानकारी प्रदान करेगा।

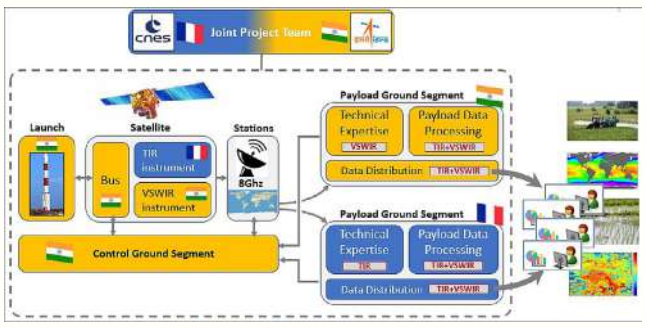

उद्देश्य:

- तृष्णा का प्राथमिक उद्देश्य महाद्वीपीय जीवमंडल के ऊर्जा और जल बजट की निगरानी करना, स्थलीय जल तनाव और जल उपयोग दक्षता का आकलन करना है। तटीय और अंतर्देशीय जल गुणवत्ता गतिशीलता के उच्च-रिजॉल्यूशन अवलोकन भी प्रदान करना है।

विशेषताऐं:

- उच्च स्थानिक रिजोल्यूशन (भूमि/तटीय के लिए 57 मीटर, महासागर/ध्रुवीय के लिए 1 किमी)
- 2-3 दिनों में सम्पूर्ण पृथ्वी के भ्रमण समय का अनूठा संयोजन
- सतह के तापमान, मृदा नमी, वाष्पोत्सर्जन दर और वनस्पति स्वास्थ्य संकेतकों जैसे प्रमुख जलवायु चरों की अभूतपूर्व निगरानी

लाभ:

- तृष्णा से प्राप्त उच्च गुणवत्ता वाले डेटा से मानवता के सामने आने वाली कुछ सबसे बड़ी जलवायु चुनौतियों से निपटने में सीधे मदद मिलेगी।
- कृषि में, यह सिंचाई को अनुकूलित करने, फसल उत्पादकता में सुधार करने और टिकाऊ जल प्रबंधन प्रथाओं को सक्षम करने में मदद करेगा।
- शहरी योजनाकारों को विस्तृत शहरी ऊष्मा द्वीप मानचित्रण से लाभ होगा, जबकि जल संसाधन प्रबंधक नदियों, झीलों और तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण की निगरानी कर सकते हैं। यह मिशन जंगल की आग और ज्वालामुखी गतिविधि का पता लगाकर आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों का भी समर्थन करेगा।
- तृष्णा द्वारा वाष्पोत्सर्जन, बर्फ/ग्लेशियर गतिशीलता और पर्माफ्रॉस्ट परिवर्तनों जैसे प्रमुख जलवायु चरों के मापन से जलवायु मॉडल को बेहतर बनाने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के माध्यम से वैश्विक शमन प्रयासों को समर्थन देने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष:

तृष्णा मिशन सतत विकास, जलवायु लचीलेपन और पर्यावरण संरक्षण में सहायता करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित कर सकता है, जिससे पृथ्वी अवलोकन में भविष्य के सहयोग और अनुप्रयोगों का मार्ग प्रशस्त होगा।

प्रीफायर मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नासा ने पृथ्वी के ध्रुवों से निकलने वाली ऊष्मा का अध्ययन करने और यह समझने के लिए कि पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र हमारे ग्रह द्वारा अवशोषित और छोड़ी जाने वाली ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके शोध के लिए प्रीफायर (पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार-इन्फ्रारेड एक्सपेरीमेंट) नामक छोटे उपग्रह को लॉन्च किया।

प्रीफायर मिशन के बारे में:

- मिशन में थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर वाले दो क्यूब सैटेलाइट का उपयोग किया गया है जो ध्रुवीय क्षेत्रों से निकलने वाली ऊष्मा को माप सकते हैं।
- प्रीफायर मिशन द्वारा एकत्र किए गए डेटा से जलवायु और बर्फ के

मॉडल को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

- मिशन यह अनुमान लगाने में भी मदद कर सकता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन मौसम, समुद्र के स्तर और बर्फ और बर्फ के आवरण को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।

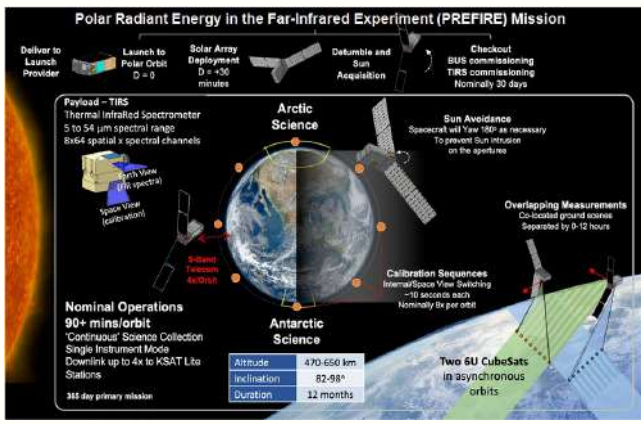

प्रीफायर मिशन का महत्त्व:

- **बेहतर जलवायु मॉडलिंग:** प्रीफायर का डेटा जलवायु मॉडल को परिष्कृत करने में मदद करेगा, जिससे भविष्य में जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों की बेहतर भविष्यवाणियाँ की जा सकेंगी।
- **ध्रुवीय ऊर्जा संतुलन को समझना:** मिशन पृथ्वी के ऊर्जा बजट के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जिससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि ध्रुवीय क्षेत्र ग्रह के तापमान को कैसे नियंत्रित करते हैं। पृथ्वी का ऊर्जा बजट सूर्य से आने वाली ऊष्मा ऊर्जा और ग्रह द्वारा छोड़ी जाने वाली ऊष्मा के बीच का संतुलन है। दोनों के बीच का अंतर ग्रह के तापमान और जलवायु को निर्धारित करता है।
- **समुद्र स्तर में वृद्धि:** ध्रुवीय ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करके, प्रीफायर वैज्ञानिकों को समुद्र स्तर में वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।
- **मौसम पैटर्न की भविष्यवाणी:** मिशन का डेटा मौसम पूर्वानुमान और चरम मौसम की घटनाओं की भविष्यवाणी में सुधार करेगा।
- **जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन:** प्रीफायर के निष्कर्ष जलवायु परिवर्तन को कम करने और अनुकूलन के लिए रणनीतियों की जानकारी देंगे।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना:** प्रीफायर पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है, साझा समझ और समाधानों को बढ़ावा देता है।

क्यूबसैट के बारे में:

- क्यूबसैट अनिवार्य रूप से लघु उपग्रह हैं जिनका मूल डिजाइन 10 सेमी x 10 सेमी x 10 सेमी (जो "एक इकाई" या "1U" के बराबर है) क्यूब है - रूबिक क्यूब से थोड़ा बड़ा और इसका वजन 1.33 किलोग्राम से अधिक नहीं होता है। नासा के अनुसार, क्यूबसैट के मिशन के आधार पर इकाइयों की संख्या 1.5, 2, 3, 6 और 12U हो सकती है।
- इन उपग्रहों को पहली बार 1999 में कैल लुइस ओबिस्पो (कैल पॉली) में कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक स्टेट यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा शैक्षिक उपकरण के रूप में विकसित किया गया था। हालांकि, पारंपरिक उपग्रहों की तुलना में उनकी कम लागत और कम द्रव्यमान के कारण, उन्हें प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, वैज्ञानिक अनुसंधान और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने लगा।

निष्कर्ष:

प्रीफायर मिशन पृथ्वी की जलवायु प्रणाली की हमारी समझ को आगे बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों को सूचित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।

वायरल संक्रमणों का पता लगाने के लिए नया प्रकाश-आधारित उपकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज और जियांग्सू विश्वविद्यालय तथा झेनजियांग के शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं में वायरल संक्रमण का पता लगाने के लिए एक प्रकाश-आधारित उपकरण विकसित किया है।

यह उपकरण निम्नलिखित सिद्धांतों और तकनीकों का उपयोग करता है:

- **कोशिका परिवर्तन:** वायरल संक्रमण कोशिकाओं पर दबाव डालते हैं, उनके आकार, माप और विशेषताओं को बदलते हैं।
- **प्रकाश विवर्तन:** संक्रमित कोशिकाओं के माध्यम से चमकने वाला प्रकाश एक विवर्तन पैटर्न बनाता है जो स्वस्थ कोशिकाओं से अलग होता है।
- **फिंगरप्रिंटिंग:** विवर्तन पैटर्न का उपयोग एक 'फिंगरप्रिंट' बनाने के लिए किया जाता है जो संक्रमित कोशिकाओं की पहचान करता है।
- **पैरामीटर:** फिंगरप्रिंट दो मापदंडों पर आधारित है: प्रकाश और गहरे रंग की धारियों के बीच का अंतर और व्युत्क्रम अंतर का समय।
- **कार्यप्रणाली:** कोशिकाओं को वायरस से संक्रमित किया जाता है और माइक्रोस्कोप का उपयोग करके उनके माध्यम से प्रकाश डाला जाता है। फिर विवर्तन पैटर्न की तुलना स्वस्थ कोशिकाओं से की जाती है।

इस उपकरण के लाभ हैं:

- **लागत-प्रभावशीलता:** उपकरण की लागत मानक विधि की तुलना में लगभग दसवां हिस्सा है।
- **समय की बचत:** मानक विधि के लिए 40 घंटे की तुलना में पता लगाने में केवल दो घंटे लगते हैं।
- **सटीकता:** प्रकाश-आधारित विधि मानक विधि से अधिक सटीक है।

- **उपयोग में आसानी:** उपकरण का उपयोग करना सरल है और इसे विभिन्न सेटिंग्स में लागू किया जा सकता है।

वायरल संक्रमण के बारे में:

- वायरल संक्रमण तब होता है जब कोई वायरस किसी मेजबान जीव में प्रवेश करता है और गुणन करना शुरू कर देता है, जिससे कई तरह के लक्षण और बीमारियाँ होती हैं। वायरल संक्रमण के कुछ मुख्य पहलू इस प्रकार हैं:

वायरल संक्रमण के प्रकार:

- श्वसन (जैसे, कोविड-19, इन्फ्लूएंजा)
- गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल (जैसे नोरोवायरस)
- त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली (जैसे हर्पीज सिम्प्लेक्स)
- रक्तजनित (जैसे एचआईवी, हेपेटाइटिस)
- न्यूरोलॉजिकल (जैसे एन्सेफलाइटिस, मेनिन्जाइटिस)

संचरण:

- प्रत्यक्ष संपर्क (स्पर्श, यौन संपर्क)
- वायुजनित (साँस लेना)
- वेक्टर जनित (मच्छर, टिक)
- दूषित भोजन और पानी
- माँ से बच्चे में (गर्भावस्था या प्रसव के दौरान)

उपचार:

- एंटीवायरल दवाएँ
- टीके (रोकथाम के लिए)
- सर्जरी (कुछ मामलों में)

निष्कर्ष:

इस अभिनव उपकरण के स्वास्थ्य सेवा, अनुसंधान और वैश्विक रोग प्रबंधन के लिए दूरगामी निहितार्थ हैं, विशेष रूप से महामारी और प्रकोप के संदर्भ में। प्रकाश की शक्ति का उपयोग करके, वैज्ञानिकों ने वायरल संक्रमण से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए नए रास्ते खोले हैं।

निडोवायरस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जर्मन कैंसर रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की कि अलग-अलग वायरस के बीच 'क्रॉसब्रीडिंग' की घटना संभावित रूप से अधिक खतरनाक लक्षणों वाले एक बिल्कुल नए, संशोधित वायरस के निर्माण को जन्म दे सकती है।

शोध के बारे में गहराई से:

- शोधकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके विभिन्न कशेरुकियों में 40 नए निडोवायरस की पहचान की। इन आरएनए वायरस में क्रॉसब्रीडिंग के माध्यम से महामारी और घातक बीमारियों का कारण बनने की क्षमता है। चमगादड़ वह जानवर हैं जहाँ ये वायरस सबसे अधिक छिपे होते हैं।
- शोधकर्ताओं ने पाया कि जब जानवर एक साथ विभिन्न वायरस से संक्रमित होते हैं, तो वायरल जीन के पुनर्संयोजन के परिणामस्वरूप एक नया वायरस उभर सकता है।
- जब पूरी तरह से अलग-अलग परिवारों के दो वायरस परस्पर क्रिया करते हैं तो यह वायरस विकास अधिक स्पष्ट और क्रांतिकारी होता है। इस तरह के विकास से वायरस जानवर में घातक और खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकता है।
- वायरस के बीच ऐसी प्राकृतिक क्रॉसब्रीडिंग प्रक्रियाएँ चमगादड़ों में आसानी से हो सकती हैं, जो अपने शरीर के अंदर बड़ी संख्या में वायरस ले जाने के लिए जाने जाते हैं। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि SARS-CoV-2 कोरोनावायरस भी चमगादड़ों में विकसित हुआ हो सकता है।

निडोवायरस के बारे में:

- निडोवायरस वायरस का एक समूह है जो निडोवायरेल्स ऑर्डर से संबंधित है। वे सकारात्मक-संवेदी आरएनए वायरस हैं जो मनुष्यों, जानवरों और मछलियों सहित कशेरुकियों को संक्रमित करते हैं।

निडोवायरस के बारे में मुख्य तथ्य:

- **विविध समूह:** निडोवायरस में कोरोनावायरस, टोरोवायरस, आर्टेरिवायरस और रोनिवायरस शामिल हैं।
- **आरएनए-आधारित:** निडोवायरस में एकल-स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम होता है।
- **सकारात्मक-संवेदी:** आरएनए जीनोम मैसेंजर आरएनए (एमआरएनए) के रूप में कार्य करता है, जो प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करता है।
- **कशेरुकी मेजबान:** निडोवायरस स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों और सरीसृपों सहित कशेरुकियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संक्रमित करते हैं।
- **जूनोटिक क्षमता:** कुछ निडोवायरस जानवरों से मनुष्यों में फैल सकते हैं, जैसे कोरोनावायरस (जैसे, SARS-CoV-2)।
- **पुनर्संयोजन:** निडोवायरस आनुवंशिक पुनर्संयोजन से गुजर सकते हैं, जिससे नए वेरिएंट और संभावित रूप से बढ़ी हुई विषाणुता हो सकती है।
- **स्पाइक प्रोटीन:** निडोवायरस में स्पाइक प्रोटीन होता है जो उन्हें मेजबान कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करता है।
- **रोगजनन:** निडोवायरस श्वसन, जठरांत्र और तंत्रिका संबंधी विकारों सहित विभिन्न बीमारियों का कारण बन सकता है।
- **विकास:** माना जाता है कि निडोवायरस 10,000 साल पहले एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुए हैं।
- **शोध:** निडोवायरस का अध्ययन वायरस के विकास, संचरण और रोगजनन के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों की जानकारी मिलती है।

कुछ उल्लेखनीय निडोवायरस में शामिल हैं:

- कोरोनावायरस (जैसे, SARS-CoV-2, MERS-CoV)

- टोरोवायरस (जैसे, बर्न वायरस)
- धमनीवायरस (जैसे, PRRSV)
- रोनिवायरस (जैसे, गिल-संबंधित वायरस)

निष्कर्ष:

निडोवायरस का क्रॉसब्रीडिंग सार्वजनिक और पशु स्वास्थ्य के लिए एक महत्त्वपूर्ण खतरा है, इन जोखिमों को कम करने के लिए निगरानी, अनुसंधान और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है।

स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जापान में एक बेहद घातक मांस खाने वाला बैक्टीरिया खोजा गया है जो संक्रमण के सिर्फ 48 घंटों के भीतर ही मौत का कारण बन सकता है।

स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम (STSS) के बारे में:

- स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम (STSS) एक दुर्लभ, गंभीर बीमारी है जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है।
- यह बुखार और गले के संक्रमण से शुरू होता है लेकिन तेजी से बढ़कर जानलेवा हो सकता है, जिससे कुछ ही दिनों में 'टॉक्सिक शॉक' और अंग विफलता हो सकती है।
- अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार, STSS से पीड़ित 10 लोगों में से तीन की संक्रमण से मृत्यु हो सकती है।
- STSS के मामलों में वृद्धि के पीछे के कारक स्पष्ट नहीं हैं। स्ट्रेप्टोकोकस के गंभीर और अचानक रूपों के पीछे के तंत्र के बारे में अभी भी कई अज्ञात कारक हैं और इसलिए उन्हें अभी तक पूरी तरह से समझाया नहीं जा सका है।
- STSS दुनिया भर में कम स्तर पर होता है, लेकिन जापान में मामलों में हाल ही में हुई वृद्धि ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच अन्य देशों में इसके संभावित प्रसार के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
- वर्तमान में, इस बात का कोई संकेत नहीं है कि STSS कहीं और सामान्य स्तर से आगे फैल रहा है। उदाहरण के लिए, यू.एस. में, CDC ने इस वर्ष अब तक 395 मामलों की रिपोर्ट की है, जो पिछले वर्ष इस समय तक रिपोर्ट किए गए 390 मामलों के समान है।

STSS की घातकता और उपचार:

- बहुत से व्यक्तियों के बिना किसी बीमारी के त्वचा पर स्ट्रेप्टोकोकस पाइोजेन्स पाए जाते हैं, लेकिन यदि यही बैक्टीरिया रक्तप्रवाह या गहरे ऊतकों में प्रवेश करते हैं, तो वे गंभीर STSS का कारण बन सकते हैं।
- यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बैक्टीरिया गहरे ऊतकों और रक्तप्रवाह में फैल जाते हैं, जिससे कोशिकाओं और ऊतकों को नष्ट करने वाले एक्सोटॉक्सिन उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसे 'मांस खाने वाले बैक्टीरिया' कहा जाता है। यदि जीवाणु संक्रमण अनियंत्रित हो जाता है, तो इससे अंग विफलता हो सकती है और यह घातक हो सकता है।
- संक्रमण के बाद अंग विफलता की तीव्र शुरुआत के कारण TSS विशेष रूप से खतरनाक है। बुखार, दर्द और मतली जैसे शुरुआती लक्षणों के बाद, निम्न रक्तचाप विकसित होने में केवल 24 से 48 घंटे लगते हैं।
- STSS का आमतौर पर अस्पताल में एम्पीसिलीन जैसे एंटीबायोटिक्स से इलाज किया जाता है। हालांकि, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेस के कुछ उपभेदों ने विभिन्न एंटीबायोटिक एजेंटों के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) प्रदर्शित किया है। शरीर में बैक्टीरिया के आगे प्रसार को रोकने के लिए, संक्रमित ऊतकों को शल्य चिकित्सा द्वारा भी हटाया जा सकता है।

निष्कर्ष:

एसटीएसएस 65 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों और मधुमेह या शराब के सेवन संबंधी विकारों जैसी स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्तियों में सबसे आम है। खुले घाव भी एसटीएसएस के जोखिम को बढ़ाते हैं। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि हाल ही में सर्जरी या वायरल संक्रमण के कारण खुले घाव (जैसे, चिकनपॉक्स या दाद) वाले व्यक्ति स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेस संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए अपने घावों को ढकें। इसमें उन व्यक्तियों के संपर्क से बचने का भी सुझाव होता है जिन्हें ग्रुप ए स्ट्रेप संक्रमण है और उनके लिए तुरंत उपचार की तलाश करें।

H5N2 बर्ड फ्लू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मेक्सिको में 59 वर्षीय व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है, जिसका कारण H5N2 नामक बर्ड फ्लू था, जो पहले कभी मनुष्यों में दर्ज नहीं किया गया था।

बर्ड फ्लू के बारे में:

- बर्ड फ्लू, या एवियन इन्फ्लूएंजा, एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है। हालाँकि, यह एक जूनोटिक बीमारी भी है, जिसका अर्थ है कि यह जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती है।
- वायरस के कुछ प्रकार मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं, जिससे गंभीर श्वसन संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं। इन प्रकारों में सबसे उल्लेखनीय H5N1 है, जो अतीत में कई मानव संक्रमणों और मौतों के लिए जिम्मेदार रहा है।
- मनुष्यों में एवियन इन्फ्लूएंजा के लक्षण सामान्य फ्लू के समान होते हैं और इसमें शामिल हैं: बुखार, खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और उन्नत मामलों में गंभीर श्वसन संकट।

–: प्रीलिम्स इनसाइट :–

इन्फ्लूएंजा के बारे में:

- इन्फ्लूएंजा, श्वसन पथ का एक तीव्र वायरल संक्रमण हैं, यह एकल-फंसे आरएनए वायरस के कारण होने वाला एक जानलेवा संक्रामक रोग है। ये वायरस मुख्य रूप से श्वासनली, ब्रांकाई और ब्रोन्किओल्स की स्तंभ उपकला कोशिकाओं को लक्षित करते हैं।
- इन्फ्लूएंजा वायरस कणों की संक्रामकता पीएच, तापमान, पानी की लवणता और अवरक्त विकिरण पर निर्भर करती है। इन्फ्लूएंजा तीन प्रकार के आरएनए वायरस के कारण होता है: इन्फ्लूएंजा प्रकार ए, बी और सी, ये सभी ऑर्थोमिक्सोविरिडे परिवार से संबंधित हैं। आम तौर पर 'फ्लू' के रूप में जाना जाने वाला यह रोग मनुष्यों में आम तौर पर इन्फ्लूएंजा ए और बी वायरस के कारण होता है।

व्यक्ति की मृत्यु चिंता का विषय क्यों है?

- मेक्सिको में हाल ही में हुआ मामला विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि पीड़ित को संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने का कोई जानकारी नहीं थी, जोकि पोल्ट्री उद्योग के साथ सीधे संपर्क के बिना मनुष्यों को संक्रमित करने की फ्लु की क्षमता को दर्शाता है।
- पोल्ट्री उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की वैश्विक प्रकृति का मतलब है कि प्रकोप जल्दी ही अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति बन सकते हैं।
- जबकि एवियन इन्फ्लूएंजा के मानव मामले दुर्लभ हैं, वायरस के मनुष्यों के बीच अनुकूल होने और फैलने की क्षमता एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है। यह वायरस के संचरण या विषाणु के एक नए स्तर का खतरा पैदा करता है जो पहले इस क्षेत्र में नहीं देखा गया था।

डब्ल्यूएचओ ने कैसे प्रतिक्रिया दी है:

- डब्ल्यूएचओ ने संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए सतर्कता और निवारक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है। मुख्य सिफारिशों में शामिल हैं:
  - बीमार या मृत पक्षियों के संपर्क से बचना।
  - यह सुनिश्चित करना कि पोल्ट्री उत्पाद अच्छी तरह से पके हुए हों।
  - नए मामलों का पता लगाने और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली लागू करना।

निष्कर्ष:

मेक्सिको का मामला वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए जूनोटिक रोगों से उत्पन्न खतरों के प्रति सतर्क रहने की निरंतर आवश्यकता को उजागर करता है। यह व्यापक प्रकोपों को रोकने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र होने के महत्व पर जोर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य अधिकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नए मामलों की जल्दी से पहचान, रोकथाम और प्रबंधन कर सकें।

मेथनॉल विषाक्तता

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु के कल्लकुरिची जिले में मेथनॉल युक्त नकली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई। मेथनॉल विषाक्तता बेहद खतरनाक है और इससे गंभीर और संभावित रूप से जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है।

मेथनॉल विषाक्तता क्या है?

- मेथनॉल विषाक्तता तब होती है जब कोई व्यक्ति मेथनॉल का सेवन करता है, उसे साँस में लेता है या उसके संपर्क में आता है, जो एक विषाक्त पदार्थ है जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है।
- मेथनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसका उपयोग आमतौर पर ईंधन, सॉल्वैंट्स और फीडस्टॉक सहित विभिन्न उद्योगों में किया जाता है।

मेथनॉल विषाक्तता का प्रभाव:

- **अंधापन:** मेथनॉल विषाक्तता ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुँचाकर स्थायी अंधापन पैदा कर सकती है। यहाँ तक कि छोटी मात्रा (शुद्ध मेथनॉल की 10 एमएल) भी अंधेपन का कारण बन सकती है।
- **गुर्दे की विफलता:** मेथनॉल विषाक्तता गुर्दे की विफलता और क्षति का कारण बन सकती है, जिससे क्रोनिक किडनी रोग या यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है।
- **मृत्यु:** मेथनॉल की औसत घातक खुराक शुद्ध मेथनॉल की 100 एमएल है, जो निगलने पर घातक हो सकती है। सेवन के 1-3 दिनों के भीतर मृत्यु हो सकती है।
- **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS) अवसाद:** मेथनॉल विषाक्तता CNS अवसाद का कारण बन सकती है, जिससे उल्टी, पेट में दर्द, चेतना में कमी, खराब समन्वय और दौरे जैसे लक्षण हो सकते हैं।
- **चयापचय अम्लरक्तता:** मेथनॉल विषाक्तता चयापचय अम्लरक्तता का कारण बन सकती है, एक ऐसी स्थिति जिसमें रक्त pH स्तर में असंतुलन होता है, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं और हृदय गति रुक जाती है।
- **श्वसन संबंधी समस्याएं:** मेथनॉल विषाक्तता श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है, जिसमें फुफ्फुसीय शोफ (फेफड़ों में द्रव का निर्माण) और तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम (ARDS) शामिल हैं।
- **हृदय संबंधी समस्याएं:** मेथनॉल विषाक्तता हृदय संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है, जिसमें हृदय गति रुकना, हाइपोटेंशन (निम्न रक्तचाप) और टैचीकार्डिया (तेज हृदय गति) शामिल हैं।

मेथनॉल के बारे में:

- मेथनॉल, जिसे मिथाइल अल्कोहल या वुड अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का अल्कोहल है जिसका उपयोग आमतौर पर विभिन्न उद्योगों में विलायक, ईंधन और फीडस्टॉक के रूप में किया जाता है। यह एक रंगहीन, वाष्पशील और ज्वलनशील तरल है जिसकी गंध बहुत तीखी होती है।

मेथनॉल का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:

- **ईंधन:** मेथनॉल का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है या तो सीधे या गैसोलीन के साथ मिश्रण के रूप में।
- **विलायक:** मेथनॉल का उपयोग विभिन्न उद्योगों में विलायक के रूप में किया जाता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, पेंट और चिपकने वाले पदार्थ।
- **फीडस्टॉक:** मेथनॉल का उपयोग विभिन्न रसायनों, जैसे कि फॉर्मलाडेहाइड, एसिटिक एसिड और ओलेफिन के उत्पादन में फीडस्टॉक के रूप में किया जाता है।
- **एंटीफ्रीज:** मेथनॉल का उपयोग ऑटोमोटिव कूलिंग सिस्टम में एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है।
- **प्रयोगशाला:** मेथनॉल का उपयोग प्रयोगशाला विलायक और अभिकर्मक के रूप में किया जाता है।

अग्निबाण सबऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर (SOrTeD)

चर्चा में क्यों?

आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप, अग्निकुल कॉसमॉस ने अग्निबाण सबऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर (SOrTeD) नामक सिंगल-पीस थ्री-डायमेंशनल (3D) प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है।

अग्निबाण SOrTeD के बारे में:

- SOrTeD मिशन, जिसे शुरू में 7 अप्रैल को लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों के कारण स्थगित कर दिया गया, आखिरकार श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थित भारत के पहले निजी लॉन्चपैड, ALP-01 से उड़ान भरी।
- इसे भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्चपैड, 'धनुष' से लॉन्च किया गया, जिसे अग्निकुल ने श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया था।
- इस मिशन में 6.2 मीटर लंबा सिंगल-स्टेज लॉन्च व्हीकल था, जिसमें एक अण्डाकार नाक शंकु और उन्नत एवियोनिक्स और ऑटोपायलट सॉफ्टवेयर इन-हाउस विकसित किया गया था।
- अग्निबाण SOrTeD (सबऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर) एक दो-चरण वाला रॉकेट है जो 300 किलोग्राम तक का भार 700 किलोमीटर की ऊँचाई तक ले जाने में सक्षम है, यह तरल ऑक्सीजन और केरोसिन द्वारा संचालित है।
- यह कम और उच्च झुकाव वाली दोनों कक्षाओं तक पहुँच सकता है और पूरी तरह से मोबाइल है, जिसे 10 से अधिक लॉन्च पोर्ट पर उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह भारत का पहला सेमी-क्रायोजेनिक इंजन-संचालित रॉकेट है, जिसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। पारंपरिक साउंडिंग रॉकेटों के विपरीत, जो गाइड रेल से लॉन्च होते हैं, SOrTeD को लंबवत रूप से उड़ान भरने और उड़ान के दौरान युद्धाभ्यास के एक सटीक ऑर्केस्ट्रेटेड सेट का प्रदर्शन करते हुए एक पूर्व निर्धारित प्रक्षेपवक्र का पालन करने के लिए डिजाइन किया गया था।

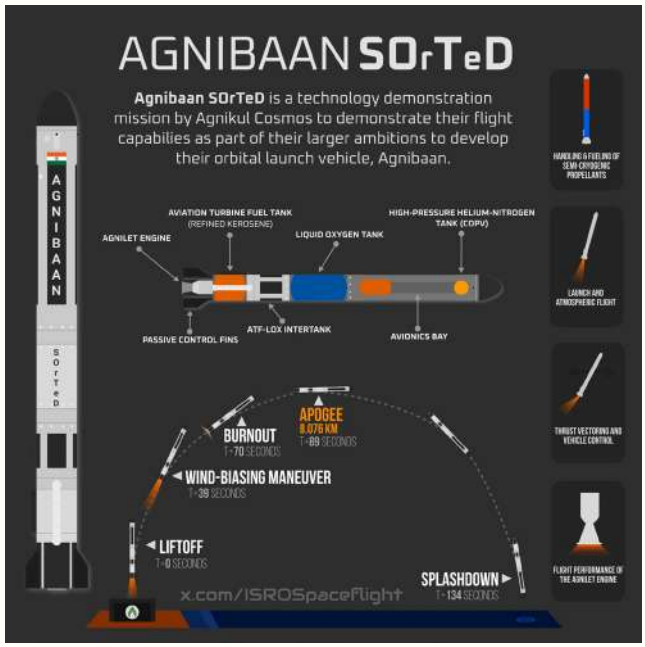

उद्देश्य:

- परीक्षण उड़ान का उद्देश्य घरेलू तकनीकों का प्रदर्शन करना, महत्वपूर्ण उड़ान डेटा एकत्र करना और अग्निकुल के कक्षीय प्रक्षेपण यान, श्अग्निबाणश के लिए प्रणालियों के इष्टतम कामकाज को सुनिश्चित करना है।

IN-SPACe के बारे में:

- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) अंतरिक्ष विभाग (DOS) के तहत एक स्वायत्त एजेंसी है जो अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाती है।
- यह प्रक्षेपण वाहनों, उपग्रहों के निर्माण और अंतरिक्ष-आधारित सेवाएँ प्रदान करने में गैर-सरकारी संस्थाओं को बढ़ावा देता है, अधिकृत करता है और उनकी देखरेख करता है। IN-SPACe DOS/ISRO के बुनियादी ढाँचे को साझा करने और नई सुविधाओं की स्थापना का प्रबंधन भी करता है।
- इसरो और निजी कंपनियों के बीच एक इंटरफेस के रूप में, IN-SPACe भारत के अंतरिक्ष संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित

करता है और अंतरिक्ष-आधारित गतिविधियों को बढ़ाता है। यह ISRO के परामर्श से शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों सहित निजी संस्थाओं की जरूरतों का आकलन और समायोजन करता है।

निष्कर्ष:

अग्निबाण SOrTeD का सफल प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, विशेष रूप से अग्निकुल कॉसमॉस के लिए। यह उपलब्धि ISRO के लिए अंतरिक्ष स्टार्टअप और गैर-सरकारी संस्थाओं का समर्थन जारी रखने, एक मजबूत अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए नवाचार और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है। यह युवा नवोन्मेषकों और उद्यमियों को भी प्रेरित करेगा जो दुनिया के पहले 3डी प्रिंटेड सेमी-क्रायोजेनिक इंजन जैसी अत्याधुनिक तकनीक के साथ भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके प्रयास भारत को वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में नेतृत्व की स्थिति की ओर अग्रसर कर रहे हैं

रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस

चर्चा में क्यों: ?

हाल ही में बायोरेक्सिव प्रीप्रिंट सर्वर पर अपलोड किए गए एक प्रीप्रिंट पेपर में, न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि बैक्टीरिया क्लेबसिएला न्यूमोनिया संक्रमण से निपटने के लिए डीएनए बना सकता है।

क्या निष्कर्ष हैं?

- जब बैक्टीरिया क्लेबसिएला न्यूमोनिया बैक्टीरियोफेज द्वारा संक्रमित होता है, तो वे रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस से जुड़ने के लिए विशिष्ट नमूनों के साथ एक गैर-कोडिंग आरएनए का उपयोग करते हैं, फिर कोशिकाओं को डीएनए बनाने का निर्देश देते हैं। इस डीएनए कॉपी में एक जीन की कई प्रतियां होती हैं जो एक विशिष्ट प्रोटीन बना सकती हैं।
- शोधकर्ताओं ने इस प्रोटीन को 'कभी न खत्म होने वाले ओपन-रीडिंग फ्रेम' के लिए 'नियो' कहा। नियो बैक्टीरिया कोशिका को एक निलंबित एनीमेशन जैसी स्थिति में डाल सकता है, जिससे इसकी प्रतिकृति रुक जाती है। यह क्रिया आक्रमणकारी बैक्टीरियोफेज की प्रतिकृति को भी रोकती है, जिससे संक्रमण प्रभावी रूप से रुक जाता है।

रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस क्या है?

- रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस की खोज हॉवर्ड टेमिन और डेविड बाल्टीमोर ने 1970 में स्वतंत्र रूप से की थी, जैसा कि नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ था।
- पहले यह माना जाता था कि सभी जीवित प्राणियों में, वंशानुगत जानकारी केवल डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन (जिसे 'केंद्रीय सिद्धांत' भी कहा जाता है) में प्रवाहित होती है।
- हालाँकि, बाद की खोजों से पता चला कि जानकारी दूसरी दिशा में भी प्रवाहित हो सकती है, जिसमें आरएनए से डीएनए का 'उत्पादन' होता है, एक प्रक्रिया जिसे अंततः रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस कहा जाता है।

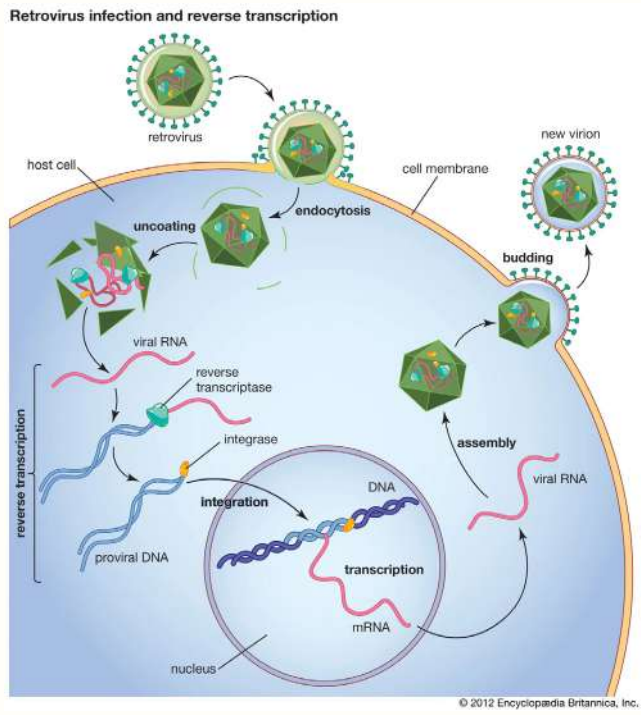

रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस के अनुप्रयोग:

- **कोविड-19 महामारी में भूमिका:** COVID-19 महामारी के दौरान, रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस डायग्नोस्टिक परीक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण हो गया, जो SARS-2 वायरस का पता लगाने के लिए स्वर्ण मानक के रूप में कार्य करता है।
- इसने जीनोम अनुक्रमण के साथ-साथ इस एंजाइम ने वायरस के प्रसार को ट्रैक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और वैक्सीन विकास संभव हुआ।

अनुसंधान और निदान पर प्रभाव:

- रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस की खोज ने आणविक जीव विज्ञान में अनुसंधान विधियों में क्रांति ला दी। इसने शोधकर्ताओं को आरएनए से डीएनए क्लोन करने और जीन कार्यों का अध्ययन करने में सक्षम बनाया।
- निदान में, रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस का उपयोग नमूनों में वायरल सामग्री का अनुमान लगाने के लिए आरएनए को डीएनए में बदलने के लिए किया जाता था, विशेष रूप से हेपेटाइटिस बी और एचआईवी जैसे आरएनए वायरस में।

एचआईवी/एड्स प्रबंधन पर प्रभाव:

- रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस ने 1980 के दशक में एचआईवी संक्रमण के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस एंजाइम को लक्षित करने वाले एंटीवायरल एजेंटों ने एचआईवी/एड्स को एक घातक

बीमारी से एक प्रबंधनीय स्थिति में बदलने में मदद की, जिससे दीर्घकालिक परिणाम और जीवित रहने की दर में सुधार हुआ।

–: प्रीलिम्स इनसाइट :–

- **रेट्रोएलिमेंट्स:** मानव जीनोम में रेट्रोएलिमेंट्स नामक अनुक्रम होते हैं, माना जाता है कि वे रेट्रोवायरस से उत्पन्न हुए हैं, और इसलिए उन्हें रेट्रोएलिमेंट्स कहा जाता है। विकासवादी जीवविज्ञानी सुझाव देते हैं कि इन रेट्रोएलिमेंट्स को विकास के लाखों वर्षों में क्षैतिज रूप से स्थानांतरित किया गया था।
- **क्षैतिज जीन स्थानांतरण:** माता-पिता से संतानों के बजाय जीवों के बीच जीन के 'स्थानांतरण' को संदर्भित करता है।

निष्कर्ष:

ये हालिया खोजें बैक्टीरियोफेज के खिलाफ बैक्टीरिया की रक्षा में रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस की क्षमता को उजागर करती हैं, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के लिए निहितार्थ हैं, विशेष रूप से रोगाणुरोधी प्रतिरोध का मुकाबला करने में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के आगे के अन्वेषण से नवीन आनुवंशिक विकास तंत्र और वायरल प्रतिरोध का पता चल सकता है, जिससे नई चिकित्सीय और जैव-प्रौद्योगिकीय संभावनाएं सामने आ सकती हैं।

पोर्टेबल ऑप्टिकल परमाणु घड़ियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में जहाजों पर इस्तेमाल के लिए डिजाइन की गई एक पोर्टेबल ऑप्टिकल परमाणु घड़ी के विषय में बताया गया। हालाँकि ये डिवाइस पोर्टेबिलिटी और मजबूती बढ़ाने के लिए कुछ सटीकता से समझौता करते हैं, लेकिन वे समुद्री अनुप्रयोगों के लिए उपलब्ध अन्य टाइमकीपिंग विकल्पों की तुलना में अधिक सटीक रहते हैं।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- नेचर अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने आणविक आयोडीन का उपयोग आवृत्ति मानक के रूप में करते हुए एक पोर्टेबल ऑप्टिकल परमाणु घड़ी विकसित की।
- पारंपरिक ऑप्टिकल परमाणु घड़ियाँ बड़ी और परिवहन के लिए कठिन होती हैं, लेकिन टीम का लक्ष्य डेटा केंद्रों, प्रयोगशालाओं और दूरसंचार सुविधाओं में उपयोग किए जाने वाले मानकीकृत रैक में अपनी घड़ी को समायोजित करना था।
- इसे प्राप्त करने के लिए, उन्होंने घड़ी के स्पेक्ट्रोमीटर, लेजर सिस्टम और फ्रीक्वेंसी कॉम्ब को छोटा कर दिया। अंतिम घड़ी का आयतन 35 लीटर था, जो एक बड़े बैकपैक के आकार का था, इसका वजन 26 किलोग्राम था और यह 85 W बिजली की खपत करती थी, जो एक तापदीप्त प्रकाश बल्ब से थोड़ा अधिक थी।

परमाणु घड़ियों के बारे में:

- परमाणु घड़ियाँ परमाणुओं की एक मौलिक संपत्ति का उपयोग करती हैं: विभिन्न ऊर्जा स्तरों के बीच वृद्धि की उनकी क्षमता। एक सामान्य डिजाइन में सीजियम के एक समस्थानिक Cs-133 का उपयोग किया जाता है।
- 1967 में, वजन और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति ने Cs-133 का उपयोग करके एक सेकंड को परिभाषित किया तथा यह एक ऐसा मानक है जिसका उपयोग भारत द्वारा समय-निर्धारण के लिए भी किया जाता है।
- इसमें ऊर्जा स्तरों को सीढ़ी पर चरणों के रूप में देखा जा सकता है। परमाणु विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके इन चरणों पर चढ़ते हैं।

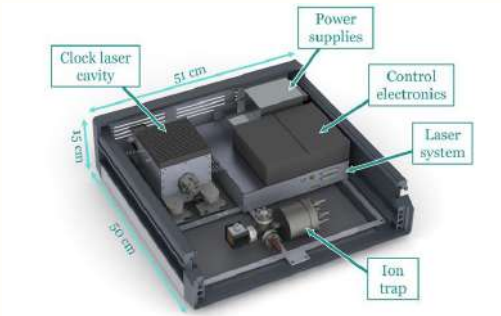

सीजियम परमाणु घड़ी कैसे काम करती है?

- Cs परमाणु घड़ी में, परमाणु को उच्च स्तर पर वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा माइक्रोवेव विकिरण की आवृत्ति से मेल खाती है, जो एक सेकंड की अवधि से जुड़ी होती है।
- शोधकर्ता Cs परमाणुओं को एक निश्चित स्थान में रखते हैं और एक विशिष्ट आवृत्ति के माइक्रोवेव विकिरण को लागू करते हैं। जब यह आवृत्ति Cs परमाणुओं की संक्रमण ऊर्जा से मेल खाती है, तो यह एक प्रतिध्वनि पैदा करती है।
- Cs-133 परमाणु इस विकिरण को अवशोषित करते हैं और केवल तभी उच्च ऊर्जा स्तर पर स्थानांतरित होते हैं जब आवृत्ति ठीक 9,192,631,770 हर्ट्ज होती है। दूसरे शब्दों में, जब Cs-133 परमाणु 9,192,631,770 दोलन पूरे करता है, तो एक सेकंड बीत जाता है।
- घड़ी की सटीकता एक फीडबैक तंत्र से आती है जो अनुनाद आवृत्ति में परिवर्तन का पता लगाता है और इसे बनाए रखने के लिए विकिरण को समायोजित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सीजियम परमाणु घड़ी हर 1.4 मिलियन वर्षों में एक सेकंड खोती या प्राप्त करती है।

ऑप्टिकल परमाणु घड़ियाँ:

- ऑप्टिकल परमाणु घड़ियाँ और भी अधिक सटीक होती हैं, जबकि

उनके पास एक ही कार्य सिद्धांत है, अनुनाद आवृत्ति ऑप्टिकल रेंज। इस रेंज में विकिरण में दृश्य प्रकाश (मनुष्यों के लिए) और पराबैंगनी और अवरक्त विकिरण शामिल हैं

निष्कर्ष:

परमाणु घड़ियाँ अत्यधिक सटीक होती हैं, 300 मिलियन वर्षों में केवल एक सेकंड का ह्रास या वृद्धि होती है, जबकि ऑप्टिकल परमाणु घड़ियाँ 300 बिलियन वर्षों में ऐसा करती हैं। नई आयोडीन घड़ी, हालांकि ऑप्टिकल परमाणु घड़ियों की तुलना में कम सटीक है, लेकिन मोबाइल और मजबूत है, जो हर 9.1 मिलियन वर्षों में केवल एक सेकंड ह्रास या वृद्धि करती है। ये प्रगति नेविगेशन, समुद्री संचार और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे पानी के अंदर भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधियों की सटीक निगरानी कर सकते हैं। अंतरिक्ष यान पर, वे सापेक्षता सिद्धांतों के परीक्षण में सहायता करते हैं और उपग्रह-आधारित नेविगेशन की लागत को संभावित रूप से कम कर सकते हैं।

अर्थकेयर मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) और जापान की जेएक्सए अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक परियोजना के तहत अर्थकेयर उपग्रह को कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग एयर बेस से लॉन्च किया गया। उपग्रह को जलवायु पर बादलों के प्रभाव की जांच करने के लिए डिजाइन किया गया है।

अर्थकेयर मिशन का उद्देश्य:

- 2.3 टन वजनी उपग्रह को कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स रॉकेट पर लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य यह अध्ययन करना था कि बादल जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं। निम्न-स्तर के बादलों को ग्रह पर उनके शीतलन प्रभाव के लिए जाना जाता है, जबकि उच्च ऊंचाई वाले बादल ग्रह पर इन्सुलेटिंग कंबल के रूप में कार्य करते हैं।
- अर्थकेयर मिशन में वायुमंडल की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए एक लेजर और रडार का उपयोग करना शामिल है, जिसका उद्देश्य इन प्रभावों के बीच नाजुक संतुलन को इंगित करना है। यह संतुलन ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते स्तरों पर जलवायु की प्रतिक्रिया के पूर्वानुमान के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर मॉडल में एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता का प्रतिनिधित्व करता है।
- अर्थकेयर लगभग 400 किमी (250 मील) की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, जिससे जलवायु विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक व्यापक अवलोकन की सुविधा मिलेगी।

अर्थकेयर सैटेलाइट के बारे में:

- अर्थकेयर की मूल विज्ञान अवधारणा को रीडिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंथनी इलिंगवर्थ और उनके सहयोगियों ने 1993 में आगे रखा था। यह उपग्रह बादलों, एरोसोल और विकिरण के अभूतपूर्व 3D अवलोकन प्रदान करने के लिए चार उपकरण ले जाता है।
- **इमेजर:** एक कैमरा जो अंतरिक्ष यान के नीचे पृथ्वी की सतह की छवियों को कैप्चर करेगा, जो शेष तीन उपकरणों द्वारा किए गए मापों के लिए आधार प्रदान करेगा।
- पतले, ऊंचे बादलों और नीचे बादलों के शीर्ष को देखने के लिए पराबैंगनी लेजर। यह वायुमंडल में छोटे कणों और बूंदों (एरोसोल) का भी पता लगाएगा जो बादलों के निर्माण और व्यवहार को प्रभावित करते हैं।
- **रडार:** बादलों को देखने और यह निर्धारित करने के लिए कि वे कितना पानी ले जा रहे हैं और यह बारिश, ओले और बर्फ के रूप में कैसे बरस रहा है?
- **रेडियोमीटर:** यह समझने के लिए कि सूर्य से पृथ्वी पर गिरने वाली कितनी ऊर्जा परावर्तित हो रही है या अंतरिक्ष में वापस विकीर्ण हो रही है।
- ये डेटा मौसम पूर्वानुमानों में सुधार करेंगे, जलवायु मॉडल को बढ़ाएंगे और पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन के बारे में समझ को गहरा करेंगे।

बादलों की निगरानी क्यों आवश्यक है?

- बादल और एरोसोल पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन को विनियमित करने में महत्वपूर्ण हैं, जो जलवायु विज्ञान में महत्वपूर्ण अनिश्चितताएं प्रस्तुत करते हैं।
- बादल आने वाले सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं, ग्रह को ठंडा करते हैं, जबकि बाहर जाने वाले अवरक्त विकिरण को भी रोकते हैं, जो इसे गर्म करता है- सटीक जलवायु मॉडलिंग के लिए बादल की ऊंचाई, मोटाई और सूक्ष्म भौतिक गुणों से प्रभावित संतुलन।
- एरोसोल, वायुमंडल में छोटे कण, सीधे विकिरण को अवशोषित कर बिखेरते हैं तथा बादल संघनन नाभिक के रूप में काम करते हैं, जो बादलों के गुणों और वर्षा पैटर्न को बदलकर अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु को प्रभावित करते हैं।
- एरोसोल सांद्रता को बदलने वाली मानवीय गतिविधियाँ क्षेत्रीय जलवायु गतिशीलता को काफी हद तक प्रभावित कर सकती हैं।

आगे की राह:

हाल के वर्षों में, दुनिया ने गंभीर हीटवेव सहित बढ़ती जलवायु आपदाओं का सामना किया है। पूर्वानुमानों के संकेतो से भविष्य में बादल आछादन में कमी देखी जा सकती है, जिससे अंतरिक्ष में सूर्य के प्रकाश का परावर्तन कम हो सकता है। इससे पृथ्वी की सतह पर अधिक सौर विकिरण अवशोषित हो सकता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के गर्म होने के प्रभाव बढ़ सकते हैं। यह कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है और जलवायु मॉडल में अनिश्चितताओं को हल करने के प्रयासों को प्रेरित करता है। इन अनिश्चितताओं के बारे में हमारी समझ में सुधार करके, अर्थकेयर जैसे मिशन वैज्ञानिकों को भविष्य के जलवायु परिदृश्यों के बारे में अधिक सटीक भविष्यवाणियां करने में सक्षम बनाते हैं।

भारत में कॉरपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी का बढ़ता दायराः संभावनाएं और आयाम

विकास और न्याय में गहरा संबंध है। विकास के बिना न्याय अधूरा है और न्याय के बिना विकास अपूर्ण। भारत जैसे लोककल्याणकारी देश में न्याय को सुनिश्चित करने के लिए जनकल्याणकारी गतिविधियों और उद्देश्यों से देश के कॉरपोरेट सेक्टर को जोड़ना जरूरी समझा गया है और इसलिए देश की कई बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कंपनियां सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक कल्याणकारी योजनाओं को शुरू कर उनका खर्च वहन कर रही हैं।

हाल ही में तेलंगाना सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर से सोशल रिस्पांसिबिलिटी से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने और वित्तीय खर्च करने का आग्रह किया है। इसके लिए राज्य में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और टॉप ब्यूरोक्रेट की मीटिंग्स की गई हैं ताकि निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। इसके लिए फार्मा कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के साथ भी बैठकें की गई हैं जिससे उनकी सीएसआर गतिविधियों को सरकारी प्रोजेक्ट्स से संबद्ध किया जा सके।

- इसके साथ ही रिलायंस ग्रुप, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, हिंदुस्तान जिंक, एसकेएफ इंडिया जैसी कंपनियों ने पेरिस ओलंपिक के मद्देनजर स्पोर्ट्स सेक्टर में कॉरपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी के तहत अपने वित्तीय दायित्व को बढ़ाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीस ने खेलों पर सबसे अधिक सीएसआर व्यय किया है। वित्त वर्ष 2019 और 2022 के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीस ने औसतन प्रति वर्ष खेलों पर 41.6 करोड़ रुपए खर्च किया है।
- चूंकि भारत 2036 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी करने का भी इच्छुक है, ऐसे में कई महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न कंपनियों ने खेलों पर खर्चा बढ़ाने की मंशा जाहिर की है। इसी तरह कर्नाटक सरकार अपने हेल्थ सेंटर्स को और मजबूती देने के लिए सीएसआर फंड्स का इस्तेमाल करने की दिशा में अग्रसर है। इस तरह हर क्षेत्र में सीएसआर फंड्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर विकास लक्ष्यों को भारत में अधिक सहभागितामूलक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
- हाल के समय में एक तरफ जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सीएसआर फंड्स को इकट्ठा कर 'एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 स्कीम' को लांच किया है वहीं एनटीपीसी और लार्सन टुब्रो जैसी कंपनियों ने एनवायरमेंट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी पर व्यय करना शुरू किया है। राष्ट्रीय तापविद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) बोंगईगांव को ग्रीनटेक फाउंडेशन के दो प्रतिष्ठित पुरस्कारों के साथ कॉरपोरेट-सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मान्यता भी दी जा चुकी है। 22वें वार्षिक ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में और 10वें वार्षिक ग्रीनटेक सीएसआर इंडिया अवाड्र्स में ग्रामीण विकास श्रेणी में ट्रॉफी से इसे सम्मानित किया गया था।
- एनटीपीसी ऑलिव रिडले टर्टल्स के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, टाटा जैसी कंपनी ने ट्राइबल धरोहरों, पेंटिंग्स के संरक्षण के लिए ओडिशा की जनजातियों के ऊपर सीएसआर फंड्स का निवेश किया है। भारत में विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आवश्यक सामग्रियों के वितरण, जनजातीय क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा, ट्राइबल लाइवलीहूड को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर व्यय किए जा रहे हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की नई सीएसआर पहलः

- मार्च, 2024 में केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा कोयला मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम में सीआईएल की नई कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहलों की शुरुआत की गई। पहली पहल के अंतर्गत, सीआईएल 70 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत करके गुणवत्तापूर्ण

शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक कदम आगे बढ़ा रहा है।

- यह 31 जनवरी 2024 को झारखंड के 11 जिलों में शुरू की गई इसी प्रकार की पहल को निरंतरता प्रदान करता है। वर्तमान परियोजना 2.42 करोड़ रुपये लागत की है जिसे एडसिल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा पूरी की जाएगी, जो भारत सरकार का एक मिनीरत्न पीएसयू है। इस पहल से छात्रों में सीखने में सुधार होने के साथ-साथ सरकारी स्कूलों एवं निजी स्कूलों के छात्रों के बीच मौजूद डिजिटल विभाजन में कमी आने का अनुमान है।
- इस अवसर पर सीआईएल की एक नई सीएसआर योजना- कोल इंडिया लोक सेवा प्रोत्साहन योजना की भी शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य कोल इंडिया लिमिटेड के कोयला खनन जिलों के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और महिला/ ट्रांसजेंडर के उम्मीदवारों के प्रति व्यक्ति को एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो वर्ष 2024 से 2026 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित सिविल सेवा/ वन सेवा परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा/ वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। पूरी आवेदन प्रक्रिया को कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) द्वारा विकसित एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जाएगा, जिस पोर्टल का शुभारंभ भी इस अवसर पर किया गया।
- भारत के कोयला मंत्री द्वारा सीएसआर गतिविधियों से जुड़ी 'नन्हा सा दिल' परियोजना की शुरुआत भी की गई है जो जरूरतमंद परिवारों को जन्मजात हृदय रोग (सीएचडी) की सर्जरी को सस्ता बनाने के लिए एक व्यापक पहल है। वर्तमान में, सीएचडी के साथ जन्म लिए 2.40 लाख बच्चों में से केवल 5 प्रतिशत ही उच्च लागत के कारण इसकी सर्जरी करवाने में सक्षम हैं। जन्मजात दोषों के कारण होने वाली सभी मौतों में सीएचडी का हिस्सा एक-तिहाई है। चूंकि इस रोग की शुरुआती पहचान होने से इसका बेहतर उपचार हो सकता है, इसलिए इस परियोजना में 176 गांवों/ ब्लॉकों और 16 जिला स्तरीय शिविरों के माध्यम से झारखंड के 4 जिलों में लगभग 18,000 बच्चों की जांच की जाएगी। परियोजना के अंतर्गत पुष्टि की गई बीमारी वाले बच्चों की सर्जरी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- नन्हा सा दिल' परियोजना सीआईएल की अनूठी प्रमुख परियोजना 'थैलेसीमिया बाल सेवा योजना' की विरासत को आगे बढ़ा रही है, जिसने आयोजन के दौरान 500 अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण कर एक प्रमुख मील का पत्थर प्राप्त किया। कोल इंडिया लिमिटेड, 2017 में बीएमटी संचालन का समर्थन करके थैलेसीमिया का उपचारात्मक उपचार करने के लिए सीएसआर परियोजना की शुरुआत करने वाला देश का पहला सार्वजनिक उपक्रम बना। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के पात्र रोगियों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता का पात्र होने के लिए, रोगियों को चिकित्सा एवं आयु संबंधी मानदंडों को पूरा करने के साथ-साथ 8 लाख रुपये से कम की वार्षिक पारिवारिक आय होनी चाहिए। 70 करोड़ रुपये की यह परियोजना वर्तमान में अपने तीसरे चरण में है। हाल ही में, परियोजना के अंतर्गत 500वीं बीएमटी पूरी की गई।
- वर्तमान में पूरे देश में फैले 11 प्रमुख अस्पताल इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसके लिए समग्र मार्गदर्शक संरचना प्रदान की गई है। थैलेसीमिक्स इंडिया, जो पिछले 25 वर्षों से थैलेसीमिया के क्षेत्र में काम करने वाला एक गैर सरकारी संगठन है, इसका समन्वय भागीदार है। इस योजना ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध 'ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड' प्राप्त किया है, जिसे जनवरी 2024 में 'ईंधन, विद्युत और ऊर्जा' क्षेत्र में सीएसआर श्रेणी वाला घोषित किया गया।
- कोल इंडिया लिमिटेड अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से समाज के जरूरतमंद लोगों के जीवन में खुशियां ला रहा है। देश में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले कॉर्पोरेट कंपनियों में से एक ने अपनी सहायक कंपनियों के साथा मिलकर वित्त वर्ष 2014-15 से 2022-23 की 9 वर्षों की अवधि में सीएसआर के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किया है। कंपनी के विषयगत फोकस क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता एवं पोषण, शिक्षा एवं आजीविका, ग्रामीण विकास, खेल को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन शामिल हैं।

भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की वैधानिक स्थिति:

- भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को कानूनी समर्थन प्राप्त है। भारत में CSR की अवधारणा कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 द्वारा शासित है।
- भारत विश्व का पहला देश है जिसने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संभावित गतिविधियों की पहचान करने के लिये एक ढाँचे के साथ CSR व्यय को अनिवार्य बनाया है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत CSR प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनका वार्षिक कारोबार 1,000 करोड़ रुपए और उससे अधिक है, या जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक है, या उनका शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक है।
- कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों के लिये एक CSR समिति गठित करने की आवश्यकता है जो निदेशक मंडल को एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की अनुशंसा करेगी और समय-समय पर उसकी निगरानी भी करेगी। यह अधिनियम कंपनियों को पिछले तीन वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करने के लिये प्रोत्साहित करता है।

CSR के तहत एक कंपनी द्वारा कौन-सी गतिविधियाँ की जा सकती हैं?

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट इन गतिविधियों में शामिल हैं:

- चरम भुखमरी और निर्धनता का उन्मूलन।
- शिक्षा, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- एचआईवी-एड्स और अन्य बीमारियों का मुकाबला करना।
- पर्यावरणीय संवहनीयता सुनिश्चित करना।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास एवं राहत के लिये स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान करना।

आर्थिक संक्षिप्त मुद्दे

बाजरा पर आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 2023-24 के लिए बाजरा पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया है कि भारत में बाजरा उत्पादन में हाल के वर्षों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि नहीं देखी गई है।

रिपोर्ट के महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- आरबीआई की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि भारत बाजरा के रकबे और उत्पादन दोनों में स्थिरता का सामना कर रहा है। हालाँकि भारत एशिया का लगभग 80 प्रतिशत और वैश्विक बाजरा उत्पादन का 20 प्रतिशत पैदा करता है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें बहुत कम वृद्धि हुई है।
- रिपोर्ट इस स्थिर उत्पादन के लिए सीमित बाजार मांग, अपर्याप्त विपणन बुनियादी ढांचे और उपभोक्ताओं के बीच बाजरा के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता की कमी को जिम्मेदार ठहराती है।
- इसके अतिरिक्त, चावल और गेहूं जैसी उच्च उपज वाली अनाज फसलों पर ध्यान केंद्रित करने से बाजरा की खेती का महत्व कम हो गया है।

भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बाजरा का महत्व:

- बाजरा कठोर और सूखा प्रतिरोधी फसलें हैं जो सीमांत मिट्टी और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगने में सक्षम हैं। यह उन्हें चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियों में किसानों के लिए एक विश्वसनीय खाद्य स्रोत और एक आदर्श फसल बनाता है।
- वे भारत में खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से वंचित आबादी के लिए। ये अत्यधिक पौष्टिक अनाज उन क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं जहां कठोर जलवायु परिस्थितियों के कारण अन्य फसलें नहीं पनप सकती हैं।

बाजरा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) वर्षा आधारित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाजरा उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए है।
- **राष्ट्रीय बाजरा संग्रहालय:** इस संग्रहालय का उद्देश्य बाजरा के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाना है। यह हैदराबाद में स्थित हैं।
- **मूल्य समर्थन योजना:** सरकार किसानों को इन फसलों की खेती और बिक्री के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बाजरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करती है।
- **बीज किट वितरण:** सरकार बाजरा की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को बीज किट और अन्य इनपुट प्रदान करती है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में बाजरा को बढ़ावा देना ताकि इसे जनता के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके और उपज के लिए एक स्थिर बाजार सुनिश्चित किया जा सके।

बाजरा की खेती को बढ़ावा देने और इसकी खपत बढ़ाने के लिए बाजरा पर राष्ट्रीय पहल:

- **बाजरा पार्कों की स्थापना:** विभिन्न राज्यों ने बाजरा उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बाजरा पार्क स्थापित किए हैं।
- **न्यूट्री-गार्डन की स्थापना:** पौष्टिक अनाजों की उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार परिवर्तन अभियान चलाया जा रहा है।

निष्कर्ष:

भारत की बाजरा क्रांति बाजरा के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता, पारंपरिक कृषि पद्धतियों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों और छोटे पैमाने के किसानों के समर्थन से प्रेरित है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने की दोहरी चुनौतियों का समाधान करता है। उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य बढ़ने से खपत को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अतिरिक्त, किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और विपणक के बीच पर्याप्त सार्वजनिक समर्थन और सहयोग बाजरा की आपूर्ति और मांग को बढ़ाने में मदद कर सकता है।

वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024 जारी किया है, जिसमें विशेष रूप से आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए नए सिरे से वैश्विक प्रतिबद्धता की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

सूचकांक की प्रमुख बातें:

- भारत दो स्थान गिरकर 129वें स्थान पर आ गया है, जबकि आइसलैंड ने रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। शीर्ष पांच में आइसलैंड के बाद फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन रहे। यूके 14वें स्थान पर था, जबकि यूएसए 43वें स्थान पर था।
- भारत बांग्लादेश, सूडान, ईरान, पाकिस्तान और मोरक्को के साथ सबसे कम आर्थिक समता स्तर वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इनमें से प्रत्येक देश में अनुमानित अर्जित आय में 30% से कम लैंगिक समानता दर्ज की गई।
- भारत दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद पांचवें स्थान पर, जबकि पाकिस्तान अंतिम स्थान पर है।
- भारत ने माध्यमिक शिक्षा नामांकन में सर्वोत्तम लैंगिक समानता प्रदर्शित की और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में अच्छा प्रदर्शन करते हुए विश्व स्तर पर 65वें स्थान पर रहा। पिछले 50 वर्षों में महिला/पुरुष राष्ट्राध्यक्षों की संख्या में समानता के लिए, भारत 10वें स्थान पर है।

–: प्रीलिम्स इनसाइट :–

विश्व आर्थिक मंच के बारे में:

- WEF एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है, जो वैश्विक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के समाधान के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एक साथ लाने पर केंद्रित है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- WEF नियमित रूप से वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट सहित विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

- 140 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ, भारत ने 2024 में अपने लिंग अंतर का 64.1% कम कर दिया। डब्ल्यूईएफ ने दर्शाया है कि भारत का आर्थिक समानता स्कोर पिछले चार वर्षों से ऊपर की ओर बढ़ रहा है।
- पिछले वर्ष 127वें स्थान से इस वर्ष 129वें स्थान पर आने का मुख्य कारण 'शैक्षणिक प्राप्ति' और 'राजनीतिक सशक्तिकरण' में मामूली गिरावट थी, जबकि 'आर्थिक भागीदारी' और 'अवसर' स्कोर में थोड़ा सुधार हुआ।
- राजनीतिक सशक्तिकरण उपसूचकांक में, भारत ने राज्य प्रमुख संकेतक पर शीर्ष -10 में स्कोर किया, लेकिन संघीय स्तर पर, मंत्री पदों (6.9%) और संसद (17.2%) में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए इसका स्कोर अपेक्षाकृत कम बना हुआ है।

निष्कर्ष:

डब्ल्यूईएफ ने कहा कि दुनिया ने 68.5% लैंगिक अंतर को कम किया है, लेकिन मौजूदा गति से, पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में 134 साल लगेंगे पांच पीढ़ियों के बराबर। पिछले वर्ष से लैंगिक अंतर 0.1 प्रतिशत अंक कम हुआ है। रिपोर्ट विशेष रूप से आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए नवाचारी उपाय एवं कानूनी समर्थन पर विशेष बल देती है।

उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 2022-23 के लिए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की।

मुख्य बिंदु:

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) 1950 में अपनी स्थापना के बाद से नियमित रूप से घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) आयोजित करता रहा है।

ग्रामीण खाद्य व्यय:

- ग्रामीण भारत में, खाद्य घरेलू उपभोग व्यय का लगभग 46% हिस्सा है। 'पेय पदार्थ, जलपान और प्रसंस्कृत खाद्य' का योगदान सबसे अधिक (9.62 प्रतिशत) था, इसके बाद दुग्ध और दुग्ध उत्पाद (8.33 प्रतिशत) और सब्जियाँ (5.38 प्रतिशत) का स्थान रहा।
- खाद्य पदार्थों पर उपभोग व्यय में अनाज और अनाज के विकल्प की हिस्सेदारी लगभग 4.91 प्रतिशत थी।
- अन्य राज्यों जैसे राजस्थान (35.5 प्रतिशत), पंजाब (34.7 प्रतिशत), गुजरात (25.5 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (22.6 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (21.5 प्रतिशत) में भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुल खाद्य व्यय में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों को 'पेय पदार्थ और प्रसंस्कृत खाद्य' से अधिक प्राथमिकता दी गई।

खाद्येतर व्यय:

- ग्रामीण भारत में, गैर-खाद्य वस्तुओं में 'वाहन' पर मासिक प्रति

व्यक्ति व्यय का सबसे अधिक हिस्सा केरल (18.9 प्रतिशत), तमिलनाडु (18 प्रतिशत), गुजरात (16.6 प्रतिशत), पंजाब (16.3 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (16 प्रतिशत) में देखा गया।

- ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-खाद्य वस्तुओं के बीच उपभोग व्यय का 13.3 प्रतिशत हिस्सा चिकित्सा व्यय का है, जो गैर-खाद्य वस्तुओं पर व्यय के प्रतिशत के रूप में केरल (17.9 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (16.8 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (16.6 प्रतिशत) में सबसे अधिक देखा गया।

शहरी खाद्य व्यय:

- शहरी भारत में, 2022-23 के लिए औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) में खाद्य का हिस्सा लगभग 39% था। ग्रामीण क्षेत्रों की तरह, शहरी क्षेत्रों में भी 'पेय पदार्थ, जलपान और प्रसंस्कृत खाद्य' पर 10.64 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ उच्च उपभोग व्यय दिखाया गया, इसके बाद दुग्ध और दुग्ध उत्पादों पर 7.22 प्रतिशत और फलों और सब्जियों पर 3.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही।

गैर-खाद्य व्यय:

- गैर-खाद्य वस्तुओं में, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में परिवारों ने परिवहन पर सबसे अधिक खर्च किया, उसके बाद टिकाऊ सामान, विविध सामान, मनोरंजन, चिकित्सा व्यय और ईंधन और प्रकाश पर खर्च किया।
- शहरी क्षेत्रों में, केरल (16.6 प्रतिशत), तमिलनाडु (16.1 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (16 प्रतिशत), गुजरात (15.7 प्रतिशत) और राजस्थान (15.6 प्रतिशत) गैर-खाद्य वस्तुओं पर व्यय के प्रतिशत के रूप में परिवहन पर सबसे अधिक हिस्सेदारी वाले राज्यों में से थे।
- शहरी भारत में, पश्चिम बंगाल (15 प्रतिशत), केरल (14.4 प्रतिशत) और पंजाब (12.4 प्रतिशत) सबसे अधिक चिकित्सा व्यय वाले राज्यों में से थे।

निष्कर्ष:

पिछले कुछ वर्षों में, गैर-खाद्य वस्तुओं पर उपभोग व्यय 50% से अधिक हो गया है। एचसीईएस सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय 2011-12 में 1,430 रुपये से बढ़कर 2022-23 में 3,773 रुपये हो गया, जो 164% की वृद्धि है। शहरी क्षेत्रों में, प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय 2011-12 में 2,630 रुपये से 146% बढ़कर 2022-23 में 6,459 रुपये हो गया।

स्व-नियामक संगठनों के लिए आरबीआई का ढाँचा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र (SRO-FT) में स्व-नियामक संगठनों को मान्यता देने के लिए रूपरेखा जारी की है, जो संस्थाओं को फिनटेक क्षेत्र में प्रतिनिधि सदस्यता रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।

मुख्य विशेषताएँ:

संरचनात्मक पर्यवेक्षण रूपरेखा:

- यह दिशा-निर्देश गतिविधि, जोखिम और पैमाने के आधार पर वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र (SRO) के लिए संरचित निरीक्षण ढाँचे के महत्व पर प्रकाश डालते हैं।
- यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि नियामक मानकों को पूरे उद्योग में सतत और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

मुख्य उत्तरदायित्व:

स्व-नियामक संगठनों की कई मुख्य जिम्मेदारियाँ हैं, जिनमें शामिल हैं:

- नियामक मानकों की स्थापना और प्रवर्तन।
- नैतिक आचरण को बढ़ावा देना।
- विवादों का समाधान।
- सदस्यों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।

प्रतिनिधि निकाय:

- RBI स्व नियामक संगठनो के प्रतिनिधि निकाय होने की आवश्यकता पर जोर देता है, जो व्यावहारिक और व्यापक रूप से स्वीकृत मानकों को विकसित करने के लिए अपने सदस्यों की सामूहिक विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ उठाते हैं।

सदस्यता:

- दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है कि स्व नियामक संगठन के पास विविध शेयरधारिता होनी चाहिए, जिसमें कोई भी एकल इकाई अपनी चुकता शेयर पूंजी का 10% से अधिक हिस्सा नहीं रखती हो। इसके अतिरिक्त, भारत के बाहर स्थित फिनटेक कंपनियाँ भी सदस्यता के लिए पात्र हो सकती हैं।
- **उपयोगकर्ता को होने वाले नुकसान को संबोधित करना:** दिशा-निर्देशों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है की स्व नियामक संगठनों के लिए 'उपयोगकर्ता को होने वाले नुकसान' जैसे धोखाधड़ी, गलत बिक्री और अनधिकृत लेनदेन के मामलों को संबोधित करने की आवश्यकता है।
- एसआरओ से ऐसी घटनाओं को प्रबंधित करने और तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तंत्र स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है।

निगरानी और प्रवर्तन:

- एसआरओ को फिनटेक गतिविधियों की निगरानी और नियामक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संरचित ढाँचे स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- गोपनीयता बनाए रखने और केवल आवश्यक जानकारी एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपवादों का पता लगाने के लिए निगरानी तंत्र तैनात किए जाने चाहिए।

उल्लंघन के परिणाम:

- नियमों और संहिताओं का उल्लंघन करने के परिणामों में परामर्श, चेतावनी, फटकार या एसआरओ से निष्कासन भी शामिल हो सकता है। यदि मौद्रिक दंड लगाया जाता है, तो वह उचित होना

चाहिए और अत्यधिक दंडात्मक भी नहीं होना चाहिए।

निष्कर्ष:

ये दिशा-निर्देश उस ढांचे को रेखांकित करते हैं जिसके भीतर स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) को काम करना चाहिए। साथ ही विकासोन्मुख निकायों और विवादों के निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में उनकी भूमिका पर जोर देते हैं। RBI के अनुसार, फिनटेक क्षेत्र में SRO स्वतंत्र संस्थाएँ होनी चाहिए, बाहरी प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए और विनियामक मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होनी चाहिए। उनसे सूचना के भंडार के रूप में काम करने की अपेक्षा की जाती है, सदस्यों को नैतिक व्यवहार और बाजार की सूचिता को बढ़ावा देते हुए स्थापित विनियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

भारत का व्यापार घाटा

चर्चा में क्यों?

हालिया आधिकारिक आकड़ो के अनुसार भारत का 2023-24 में चीन, रूस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया सहित अपने शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटा है।

मुख्य बिंदु:

- भारत ने 2023-24 में चीन, रूस, सिंगापुर और कोरिया सहित अपने शीर्ष दस व्यापारिक साझेदारों में से नौ के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया।
- पिछले वित्त वर्ष में कुल व्यापार घाटा पिछले वर्ष के 264.9 बिलियन डॉलर से घटकर 238.3 बिलियन डॉलर रह गया।
- चीन के साथ घाटा 2023-24 में बढ़कर 85 बिलियन डॉलर, रूस के साथ 57.2 बिलियन डॉलर, कोरिया के साथ 14.71 बिलियन डॉलर और हांगकांग के साथ 12.2 बिलियन डॉलर हो गया।
- चीन 118.4 बिलियन डॉलर के दोतरफा व्यापार के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया।
- भारत का 2023-24 में अमेरिका के साथ 36.74 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष था और साथ ही यूके, बेल्जियम, इटली, फ्रांस और बांग्लादेश के साथ भी। भारत का अपने चार शीर्ष व्यापारिक साझेदारों - सिंगापुर, यूएई, कोरिया और इंडोनेशिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता है।

क्या होता है व्यापार घाटा?

- व्यापार घाटा ऐसी स्थिति को कहते हैं जब देश के आयात शुल्क निर्यात से प्राप्तियों से अधिक हो। व्यापार घाटे को नकारात्मक व्यापार संतुलन भी कहा जाता है।

भारत के व्यापार घाटे के कारण और प्रभाव:

कारण:

- कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों, कोयला, कोक और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उच्च आयात मूल्य।
- भारत अपनी कच्चे तेल की 85% से अधिक जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है।
- कुछ भारतीय उद्योग आयातित कच्चे माल पर निर्भर हैं।
- निर्मित वस्तुओं का कम निर्यात।
- भारत की निर्यातित निर्मित वस्तुओं की मात्रा कम विनिर्माण क्षमताओं के कारण आयात से कम है।
- चीन और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में वैश्विक बाजार में कम प्रतिस्पर्धात्मकता।

प्रभाव:

- उच्च व्यापार घाटा डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये को कमजोर कर सकता है।
- लगातार व्यापार घाटा देश के भुगतान संतुलन (BoP) को भी प्रभावित करता है।
- उच्च आयात नागरिकों को वस्तुओं और सेवाओं की व्यापक विविधता की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- व्यापार घाटा घरेलू व्यवसायों को नवाचार में निवेश करने और आयातित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए दक्षता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

निष्कर्ष:

भारत के व्यापार घाटे को संबोधित करने के लिए एक सूक्ष्म और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है यह दृष्टिकोण विभिन्न कारकों पर विचार करता है, जिसमें विशिष्ट व्यापार भागीदार, आयात और निर्यात की प्रकृति और वैश्विक आर्थिक माहौल शामिल है। भारत सरकार को स्थिति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और व्यापार घाटे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों के संयोजन को लागू करना चाहिए।

लागत मुद्रास्फीति सूचकांक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आयकर विभाग ने अचल संपत्ति, प्रतिभूतियों और आभूषणों की बिक्री से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना करने के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआई) को अधिसूचित किया है। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआई) का उपयोग करदाता द्वारा मुद्रास्फीति के समायोजन के बाद पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है।

लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के बारे में:

- लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआई) एक सांख्यिकीय उपाय है जिसका उपयोग किसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत को मुद्रास्फीति को समायोजित करने के लिए किया जाता है।
- इसका उपयोग परिसंपत्तियों की बिक्री से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है, जैसे:
  - अचल संपत्ति (रियल एस्टेट)

- » प्रतिभूतियाँ (स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आदि)
- » आभूषण
- » कलाकृतियाँ
- » अन्य पूंजीगत संपत्तियाँ

CII एक इंडेक्सेशन तंत्र है जो निम्न में मदद करता है:

- मुद्रास्फीति के लिए किसी परिसंपत्ति के खरीद मूल्य को समायोजित करना।
- दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना करना।
- परिसंपत्ति की बिक्री पर कर देयता निर्धारित करना।
- CII को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है और इसका उपयोग अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत की गणना करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग फिर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है। इसे पहली बार 1981 में पेश किया गया।
- मुद्रास्फीति के साथ बनाए रखने के लिए सूचकांक को सालाना संशोधित किया जाता है, जिसमें आधार वर्ष को समय-समय पर रीसेट किया जाता है (वर्तमान में भारत में आधार वर्ष 2001-02 है)।
- उदाहरण के लिए, यदि आपने 2010-11 में 10 लाख रुपये में कोई संपत्ति खरीदी और 2024-25 में उसे 20 लाख रुपये में बेचा, तो सीआईआई का उपयोग मुद्रास्फीति के लिए खरीद मूल्य को समायोजित करने के लिए किया जाएगा। उदाहरण के लिए 15 लाख रुपये तब दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ 5 लाख रुपये (20 लाख रुपये - 15 लाख रुपये) होगा।
- सीआईआई करदाताओं के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर अपनी कर देयता की गणना करने और आयकर अधिनियम, 1961 के विभिन्न प्रावधानों के तहत छूट या कटौती का दावा करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

वैश्विक ऋण संकट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास (UNCTAD) द्वारा 'ऋण की दुनिया 2024: वैश्विक समृद्धि पर बढ़ता बोझ' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसने वैश्विक परिदृश्य में अभूतपूर्व वैश्विक ऋण संकट का खुलासा किया है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- **ऋण:** वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2023 में रिकॉर्ड $97 ट्रिलियन पर पहुंच गया, जिसमें विकासशील देशों का हिस्सा लगभग एक-तिहाई ($29 ट्रिलियन) है।
- **वृद्धि:** वैश्विक ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में $5.6 ट्रिलियन की वृद्धि हुई, जिसमें विकासशील देशों का ऋण 2010 में वैश्विक कुल के 16% से बढ़कर 2023 में लगभग 30% हो गया।
- **ब्याज भुगतान:** विकासशील देशों ने 2023 में शुद्ध ब्याज के रूप में $847 बिलियन का भुगतान किया, जो 2021 से 26% की वृद्धि है। विकासशील देशों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की तुलना में दो से चार गुना अधिक और जर्मनी की तुलना में छह से 12 गुना अधिक दरों पर उधार लिया।
- **संकट:** अफ्रीका में संकट और गहरा गया है, जहाँ आर्थिक उत्पादन के हिस्से के रूप में औसत सार्वजनिक ऋण बढ़कर 62% हो गया है। 60% से अधिक ऋण-से-जीडीपी अनुपात वाले अफ्रीकी देशों की संख्या 2013 और 2023 के बीच 6 से बढ़कर 27 हो गई है।
- **प्रभाव:** ऋण का बोझ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और जलवायु पहल जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को निधि देने की देशों की क्षमता को सीमित कर रहा है। 2023 में, ऐतिहासिक 54 विकासशील देशों ने सरकारी निधियों का न्यूनतम 10% ऋण ब्याज भुगतान के लिए समर्पित किया।

ऋण संकट को हल करने से संबंधित पहल:

- **अत्यधिक ऋणग्रस्त गरीब देश (HIPC) पहल:** यह पहल दुनिया के सबसे गरीब देशों को ऋण राहत प्रदान करती है, जिसमें IMF स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और गरीबी को आधार बनाता हैं।
- **ऋण प्रबंधन और वित्तीय विश्लेषण प्रणाली (DMFAS) कार्यक्रम:** DMFAS कार्यक्रम विकासशील देशों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और ऋण रिकॉर्ड करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए उपकरणों के माध्यम से जिम्मेदारी से ऋण का प्रबंधन करने में मदद करता है।
- **वैश्विक संप्रभु ऋण गोलमेज (जीएसडीआर):** इस गोलमेज की सह-अध्यक्षता आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा की जाती है और इसका उद्देश्य ऋण स्थिरता और ऋण पुनर्गठन चुनौतियों से संबंधित मुद्दों के प्रमुख हितधारकों के बीच अधिक आम समझ को बढ़ावा देना है।
- **ऋण उपचार के लिए जी20 सामान्य ढांचा:** यह पहल अस्थिर ऋण बोझ का सामना कर रहे निम्न-आय वाले देशों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है, जिसमें कोविड-19 महामारी से बदतर हुई ऋण चुनौतियों से निपटने के लिए एक समन्वित और व्यापक दृष्टिकोण शामिल है।

UNCTAD के बारे में:

- 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्थापित हुआ।
- सदस्य- 195
- मुख्यालय- जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- महासभा और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है।
- विश्व व्यापार में विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।
- दुनिया भर में गैर-सरकारी संगठनों के साथ काम करता है।
- व्यापार, सहायता, परिवहन, वित्त और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियाँ बनाता है।

- विकासशील देशों से निर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) की कल्पना और कार्यान्वयन करता है।
- नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य विकासशील और विकसित देशों के बीच आर्थिक निर्भरता और असमानता को कम करना है।
- इसकी सदस्यता को संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूहों के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

निष्कर्ष:

यह रिपोर्ट वित्तीय कुप्रबंधन में परिवर्तनकारी बदलावों का आह्वान करती है और एक ऐसे भविष्य की वकालत करती है जहाँ लोग ऋण के बोझ के बिना जीवन जी सकें।

भारत में अनौपचारिक श्रम बाजार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय स्टाफिंग फेडरेशन (ISF) ने अपनी रिपोर्ट India@ Work: Vision Next Decade," में भारत के अनौपचारिक क्षेत्र में देश के सकल घरेलू उत्पाद का आधे से अधिक उत्पादन करने पर प्रकाश डाला है। इसके लिए भारतीय श्रमशक्ति का 85% उपयोग होता हैं।

रिपोर्ट में श्रमिक/श्रमिकों को औपचारिक बनाने के लिए प्रमुख रणनीतियां:

- रोजगार की बाधाओं को कम करने और कौशल को रोजगार के अवसरों के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना है।
- उद्योग और सरकार दोनों की सुविधा प्रदान करने वाली भूमिका पर जोर देना है, खास तौर पर हाशिए पर पड़े श्रमिकों और स्थापित नियोक्ताओं के बीच की खाई को पाटने में।
- इसमें हितधारकों द्वारा प्रबंधित एक मजबूत माध्यम स्थापित करना शामिल है, ताकि कठोर प्रवेश बाधाओं वाले संगठनों में प्रवेश को सुगम बनाया जा सके।
- इसमें नीतिगत परिवर्तनों, विशेष रूप से श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, ताकि व्यावसायिक परिचालन को सुव्यवस्थित किया जा सके तथा ईपीएफ और ईएसआई जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त, औपचारिक रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाफिंग सेवाओं पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की वकालत की गई है।

आईएसएफ द्वारा रोजगार गतिशीलता में महत्वपूर्ण व्यापक सुझाव:

- लगभग 5 करोड़ घरेलू कामगारों को सरकारी सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाना।
- रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए ग्रामीण और अर्ध-शहरी प्रतिभा पूल का उपयोग करना।
- रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- श्रमिक शिविरों में आवास सहित व्यापक रोजगार समाधान प्रदान करना।
- सभी श्रमिकों के लिए चिकित्सा और बीमा कवरेज सुनिश्चित करना।
- प्रवासी श्रमिकों पर नजर रखने के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त LIN को लागू करना।
- अनौपचारिक श्रमिकों को औपचारिक भूमिकाओं में स्थानांतरित करने में सुविधा प्रदान करना।
- कम औपचारिक रोजगार वाले उद्योगों और क्षेत्रों के साथ जुड़ना।

आगे की राह:

भारत में पारंपरिक से आधुनिक अर्थव्यवस्था में लंबे समय से प्रतीक्षित "लुईसियन परिवर्तन" शायद ही हुआ हो। आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा औपचारिक पूंजीवादी उत्पादन-वितरण प्रक्रियाओं से बाहर होने के कारण आर्थिक विकास के लाभों को प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। इस प्रकार अनौपचारिक क्षेत्र वैश्विक दक्षिण के विकास के परिप्रेक्ष्य से एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।

विश्व निवेश रिपोर्ट 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट के अनुसार अपर्याप्त निधि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को प्राप्त करने के प्रयासों में बाधा बन रही है।
- वैश्विक आर्थिक मंदी और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच 2023 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 2% घटकर $1.3 ट्रिलियन रह गया।
- कुछ यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में निवेश प्रवाह में बड़े उतार-चढ़ाव को छोड़कर FDI में गिरावट 10% से अधिक है।
- FDI में गिरावट से विकासशील देश सबसे अधिक प्रभावित हुए।
- 2023 में विकासशील देशों में FDI प्रवाह 7% घटकर $867 बिलियन रह गया।
- एशिया में ग्रीनफील्ड निवेश में वृद्धि हुई, जिसमें मूल्य में 44% की वृद्धि और घोषणाओं की संख्या में 22% की वृद्धि हुई।
- एशिया में कुल विदेशी निवेश प्रवाह में कमी आई है, जो 2022 में 678 बिलियन डॉलर से घटकर 2023 में 621 बिलियन डॉलर रह गया है।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2024 और 2025 में 3.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो स्थिर लेकिन धीमी है और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होगी।

- उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में थोड़ी तेजी की उम्मीद है, जो उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मामूली मंदी से संतुलित होगी। वैश्विक मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट आने का अनुमान है, जो 2023 में 6.8% से घटकर 2024 में 5.9% और 2025 में 4.5% हो जाएगी।

FDI प्रवृत्ति में गिरावट के कारण:

- **आर्थिक अनिश्चितता:** उच्च ब्याज दरों और आर्थिक अनिश्चितता के कारण विकासशील देशों में FDI प्रवाह में 9% की गिरावट आई।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** राजनीतिक तनाव और व्यापार प्रतिबंधों ने वैश्विक निवेश प्रवाह को प्रभावित किया।
- **संरक्षणवादी नीतियाँ:** कुछ देशों में संरक्षणवाद बढ़ने से निवेश प्रवाह कम हो गया।
- **क्षेत्रीय पुनर्संरेखण:** क्षेत्रीय आर्थिक गठबंधनों और समझौतों में बदलाव ने निवेश पैटर्न को प्रभावित किया।
- **संकट:** कोविड-19 महामारी जैसे वैश्विक संकटों ने निवेश प्रवाह को बाधित किया।
- **आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण:** आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के प्रयासों ने कुछ बहुराष्ट्रीय उद्यमों को निवेश के प्रति सतर्क दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया।
- **औद्योगिक नीतियाँ:** कुछ देशों में औद्योगिक नीतियों और विनियमों में परिवर्तन ने निवेश निर्णयों को प्रभावित किया।
- **व्यापार और भू-राजनीतिक तनाव:** चल रहे तनाव और व्यापार प्रतिबंधों ने निवेश प्रवाह को प्रभावित किया।
- **विकास की कमजोर संभावनाएँ:** कुछ क्षेत्रों में धीमी आर्थिक वृद्धि ने निवेशकों को अधिक सतर्क बना दिया।

आगे की राह:

रिपोर्ट पारदर्शी और कुशल वातावरण बनाकर निवेश को आकर्षित करने में व्यापार सुविधा और डिजिटल सरकारी समाधानों के महत्व पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट में डिजिटल सरकारी सेवाओं को लागू करने हेतु सुझाव दिया गया तथा क्रमिक दृष्टिकोण को बुनियादी व्यावसायिक सेवाओं से शुरू करने और फिर अधिक क्षेत्रों में विस्तार करने का एक व्यावहारिक तरीका माना गया हैं। निवेश को बढ़ाने के लिए निवेशकों तक सूचना तक आसान पहुँच प्रदान करके, पारदर्शिता को बढ़ावा देकर और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके प्रक्रियाओं को सरल बनाना भी महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण नौकरशाही बाधाओं को कम करने और निवेशकों के लिए व्यापार करना आसान बनाने में मदद कर सकता है, अंततः निवेश को बढ़ावा देगा और आर्थिक विकास को गति देगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नई पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तीन प्रमुख पहल शुरू की हैं: प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपॉजिटरी।

प्रवाह पोर्टल के बारे में:

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया प्रवाह पोर्टल, एक डिजिटल इंटरफेस है जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत होने वाली अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह एक केंद्रीकृत, सुरक्षित वेब-आधारित प्लेटफॉर्म है जोकि व्यक्तियों या संस्थाओं को RBI से सीधे विनियामक अनुमोदन, लाइसेंस और प्राधिकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम बनाता है।
- यह पोर्टल RBI के साथ सीधे डिजिटल संचार की अनुमति देता है, जिससे अधिकृत डीलर (AD) बैंकों जैसे बिचौलियों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
- पोर्टल RBI के विभिन्न विनियामक और पर्यवेक्षी विभागों के 60 आवेदन पत्रों को कवर करता है, जिससे आवेदक अपने आवेदनों की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और समय पर निर्णय प्राप्त कर सकते हैं।

–: प्रीलिम्स इनसाइट :–

अधिकृत डीलर (AD) बैंक:

- अधिकृत डीलर (AD) बैंक एक वित्तीय संस्था है जिसे देश के केंद्रीय बैंक, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विदेशी मुद्रा लेनदेन में संलग्न होने के लिए अधिकृत किया जाता है। ये बैंक निर्यात और आयात दोनों सहित सीमा पार लेनदेन की सुविधा के लिए आवश्यक हैं।

प्रवाह पोर्टल की मुख्य विशेषताएं:

- उपयोगकर्ता पोर्टल के माध्यम से सीधे ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
- वे अपने आवेदन या संदर्भ की स्थिति को ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हैं।
- उपयोगकर्ता अपने आवेदन या संदर्भ के बारे में RBI द्वारा उठाए गए किसी भी स्पष्टीकरण या प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं।
- एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर रिजर्व बैंक से निर्णय प्राप्त कर सकते हैं।

रिटेल मोबाइल ऐप के बारे में:

- यह ऐप खुदरा निवेशकों को अपने स्मार्टफोन पर सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में लेन-देन करने का एक सहज और सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। यह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों

में जी-सेक खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को सरल बनाता है।

फिनटेक रिपॉजिटरी के बारे में:

- इस रिपॉजिटरी का उद्देश्य विनियमित और अनियमित दोनों तरह की फिनटेक फर्मों पर व्यापक डेटा प्रदान करके भारतीय फिनटेक क्षेत्र के बारे में RBI की समझ को बढ़ाना है। यह फिनटेक पर अंतर्दृष्टि प्रदान करके नीति निर्माताओं और उद्योग प्रतिभागियों का समर्थन करेगा।
- इसके साथ ही, RBI द्वारा विनियमित संस्थाओं (बैंक और NBFC) के लिए विशेष रूप से AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, DLT, क्वांटम आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों को अपनाने पर नजर रखने के लिए EmTech Repository नामक एक संबंधित रिपॉजिटरी लॉन्च की जा रही है।
- फिनटेक और EmTech Repository दोनों ही सुरक्षित वेब-आधारित अनुप्रयोग हैं, जिन्हें RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

निष्कर्ष:

अनुमोदन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण वित्त मंत्री की विनियामक दक्षता बढ़ाने की पहल का हिस्सा है, जिसमें तीव्र प्रसंस्करण समय, कम नौकरशाही और FEMA-संबंधित मामलों को संभालने में बेहतर पारदर्शिता शामिल है। इन पहलों का उद्देश्य विनियामक प्रक्रियाओं को बढ़ाना, खुदरा निवेश को सुविधाजनक बनाना और फिनटेक क्षेत्र पर व्यापक डेटा प्रदान करना है।

GAAR पर फैसला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक करदाता के खिलाफ फैसला सुनाया है, जिसके खिलाफ राजस्व विभाग ने सामान्य कर-निवारण नियम (GAAR) लागू किया था। 1 अप्रैल, 2017 को लागू होने के सात साल बाद, GAAR पर यह पहला ऐतिहासिक फैसला है।

फैसले की पृष्ठभूमि:

- करदाता अयोध्या रामी रेड्डी अल्ला ने रामकी एस्टेट एंड फार्म्स (आरईएफएल) के शेयर खरीदे थे।
- कंपनी ने बाद में अल्ला को 1:5 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए। प्रति शेयर कीमत में कमी को ध्यान में रखते हुए, करदाता ने तुरंत शेयर किसी अन्य फर्म को बेच दिए, जिसके परिणामस्वरूप 462 करोड़ का अल्पकालिक पूंजीगत नुकसान हुआ।
- करदाता ने इस नुकसान को रामकी एनवायरो इंजीनियर्स में शेयरों की बिक्री के एक अन्य लेनदेन पर किए गए दीर्घकालिक लाभ के विरुद्ध सेट ऑफ कर दिया।
- करदाता ने तर्क दिया कि चूंकि करदाता द्वारा किए गए लेनदेन आयकर अधिनियम, 1961 (आईटीए) के अध्याय X के अंतर्गत थे, जो एक विशिष्ट एंटी-एवॉइडेंस प्रावधान (SAAR) है, इसलिए GAAR को लागू नहीं किया जा सकता। चूंकि प्रासंगिक प्रावधान शेयरों के बजाय इकाइयों को संदर्भित करता है, इसलिए यह वर्तमान मामले में लागू नहीं था।
- शोम समिति का भी सन्दर्भ लिया गया गया, जिसने भी सिफारिश की थी कि यदि SAAR लागू है तो GAAR को लागू नहीं किया जाना चाहिए।
- न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह व्यवस्था मुख्य रूप से कर दायित्वों से बचने के लिए बनाई गई थी, इसमें वाणिज्यिक SAAR नहीं था और इसे आईटीए प्रावधानों का जानबूझकर किया गया दुरुपयोग माना जाना चाहिए।

फैसले के मुख्य पहलू:

- यह फैसला भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करता है और वैध कर नियोजन और अवैध कर नियोजन के बीच अंतर को उजागर करता है।
- अदालत के फैसले को भारतीय कर परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य आक्रामक कर नियोजन पर अंकुश लगाना और कर अनुपालन सुनिश्चित करना है।
- यह फैसला एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि GAAR एक व्यापक सुरक्षा जाल है जिसे अवैध कर नियोजन को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है।
- GAAR कर अधिकारियों को ऐसे लेन-देन या व्यवस्थाओं पर कर लाभ देने से मना करने का अधिकार देता है जिनका कोई वाणिज्यिक सार नहीं है और जिनका एकमात्र उद्देश्य कर से बचना है।

GAAR और SAAR के बारे में:

- GAAR (सामान्य कर-परिहार-विरोधी नियम) व SAAR (विशिष्ट कर-परिहार-विरोधी नियम) दोनों ही आयकर अधिनियम, 1961 में कर-परिहार-विरोधी प्रावधान हैं, जिनका उद्देश्य खामियों या आक्रामक कर नियोजन के माध्यम से कर चोरी को रोकना है।

GAAR:

- GAAR सामान्य प्रकृति का, सभी लेन-देन पर लागू होता है।
- यह वाणिज्यिक सार या उद्देश्य से रहित लेन-देन को लक्षित करता है।
- GAAR कर अधिकारियों को लेन-देन को पुनः परिभाषित करने या अनदेखा करने का अधिकार देता है।
- यह सभी करदाताओं पर लागू होता हैं।

SAAR:

- विशेष वर्गों या लेन-देन के लिए विशिष्ट हैं।
- विशिष्ट कर परिहार रणनीतियों को लक्षित करता है।
- विशिष्ट कर खामियों या दुरुपयोगों का मुकाबला करने के लिए कानून बनाया गया है।
- विशिष्ट करदाताओं या लेन-देन पर लागू होता है।

मुख्य अंतर:

- GAAR एक अधिक व्यापक प्रावधान है, जबकि SAAR संकीर्ण और लक्षित है।
- GAAR लेन-देन के वाणिज्यिक सार पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि SAAR विशिष्ट कर परिहार रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- GAAR को कर अधिकारियों द्वारा केस-दर-केस आधार पर लागू किया जाता है, जबकि SAAR को कानून बनाया जाता है और समान रूप से लागू किया जाता है।

निष्कर्ष:

GAAR पर तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले का भारत में करदाताओं और कर अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। यह निर्णय दर्शाता है कि GAAR कर अधिकारियों के हाथ में एक शक्तिशाली उपकरण है, जो कर नियोजन से निपटने और कर अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायक है। यह निर्णय भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करता है और भारत में वैध कर नियोजन की सीमाओं को स्पष्ट करता है।

बीमा कंपनियों के लिए नए कॉर्पोरेट प्रशासन नियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा कंपनियों के लिए नए कॉर्पोरेट प्रशासन नियम पेश किए हैं।

नए प्रशासन नियम क्या है?

- बीमा कंपनियों में बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना।
- स्वतंत्र निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों की इष्टतम संरचना सुनिश्चित करना, जिसमें न्यूनतम तीन स्वतंत्र निदेशक हों प्रबंधन और प्रमोटरों से बोर्ड की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
- पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- प्रमुख प्रबंधन पदों में हितों के टकराव को रोकना, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा व्यवसाय और नियंत्रण दोनों कार्यों को संभालना शामिल है।
- नियमों के अनुपालन पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- प्रभावी उत्तराधिकार नियोजन और व्हिसल-ब्लोअर नीतियों को सुनिश्चित करना।

लागू:

- मास्टर सर्कुलर भारत में स्थापित शाखा के माध्यम से पुनर्बीमा व्यवसाय में लगी विदेशी कंपनी को छोड़कर सभी बीमा कंपनियों पर लागू है।
- आईआरडीएआई (IRDAI) ने बीमा कंपनियों को प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 30 जून, 2024 तक का समय दिया है।

कॉर्पोरेट प्रशासन क्या है?

- कॉर्पोरेट प्रशासन नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं की प्रणाली को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक कंपनी को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है।
- इसमें कंपनी के प्रबंधन, निदेशक मंडल, शेयरधारकों, हितधारकों और व्यापक समुदाय के बीच संबंध शामिल हैं। अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी का प्रबंधन पारदर्शी, जवाबदेह और जिम्मेदार तरीके से किया जाए, जिसका लक्ष्य सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक लाभ बनाना है।

आईआरडीएआई के बारे में:

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) एक वैधानिक और स्वायत्त निकाय है जो भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित और विकसित करता है।
- आईआरडीएआई एक 10 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक सदस्य और चार अंशकालिक सदस्य होते हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- आईआरडीएआई की स्थापना 1999 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है।
- आईआरडीएआई का उद्देश्य उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ता विकल्प बढ़ाना और कीमतें कम करना, बीमा बाजार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और बीमा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना है।
- आईआरडीएआई बीमा कंपनियों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
- आईआरडीएआई ने स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं को वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष नीतियां विकसित करने और उनकी शिकायतों और दावों को संबोधित करने के लिए समर्पित चैनल स्थापित करने का निर्देश दिया है।
- IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ खरीदने की आयु सीमा हटा दी है, जो पहले 65 वर्ष थी।

निष्कर्ष:

IRDAI (बीमाकर्ताओं के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन) विनियम, 2024 के अनुसार, भारत में बीमाकर्ताओं के लिए नए कॉर्पोरेट प्रशासन विनियमों का उद्देश्य बीमाकर्ता के शासन के लिए जिम्मेदार प्रमुख हितधारकों की क्षमता को मजबूत करना और पारदर्शिता, जवाबदेही और हितधारकों के हितों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

भारत में मानव अंगों के खरीद फरोख्त को रोकने के लिए सख्त केंद्र सरकार

मानव तस्करी भारत में एक गंभीर संगठित अपराध है और हाल ही में, केंद्र सरकार ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अलर्ट किया है कि वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए मानव अंगों की खरीद फरोख्त को रोकने के प्रभावी उपाय किए जाएं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट, 1994 के तहत पैसों के लिए मानव अंगों को खरीदने बेचने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जानी चाहिए। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उन वेबसाइट्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स का भी जिक्र किया है जिन पर किडनी और अन्य मानव अंगों के लिए पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। ऐसे एजेंटों के नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है। वस्तुतः मानव या मानव अंगों का दुर्व्यापार मानवाधिकारों, मूल अधिकारों, मानव गरिमा और जीवन के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन करता है।

हाल के समय में मानव तस्करी के अन्य प्रमुख मामले:

- हाल के समय में सीबीआई ने एक बड़े मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यह रैकेट विदेश में नौकरी दिलाने की आड़ में भारतीयों को रूस-यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में ले जाता था। सीबीआई ने इसके लिए सात शहरों में 10 से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर तलाशी के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह कार्यवाही दिल्ली, तिरुअनंतपुरम, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरई और चेन्नई में 10 से अधिक स्थानों पर की गई है। आकर्षक नौकरियों की आड़ में युवाओं को रूस-यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में काम पर भेजने के आरोप में विभिन्न वीजा कंसल्टेंसी फर्मों और एजेंटों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
- हाल के समय में देश के युवाओं को नौकरी के नाम पर दूसरे देश भेजकर उनसे धोखाधड़ी करने और मानव तस्करी के आरोप में क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 ने यूट्यूबर बॉबी कटारिया को भी गिरफ्तार किया है। कटारिया की कंपनी में पहले से ही करीब डेढ़ सौ भारतीय इसी तरह मानव तस्करी कर लाए गए जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। कई लोगों को बॉबी कटारिया ने ही नौकरी का झांसा देकर वहां भेजा था।
- यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के अनुसार मानव तस्करी की आधिकारिक परिभाषा फोर्स, फ्राड और डीसेप्शन यानी बलपूर्वक बहला फुसला कर, झांसा देकर मानव की तस्करी कर उनका शोषण करना है। इसी साल ऐसे ही एक मामले में नये कपड़े व मोबाइल फोन दिलाने के नाम पर दिल्ली लाकर 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपित की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मानव तस्करी के मामले में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। याचिका के अनुसार पीड़िता को आरोपित झारखंड से दिल्ली लेकर आया था।
- मानव तस्करी का मामला भारत के अलग-अलग राज्यों में बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी से सर्वाधिक प्रभावित राज्य 2022 में ओडिशा रहा जहां 1100 से अधिक मानव तस्करी के मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात जैसे राज्य अधिक प्रभावित रहे और बाल श्रम को मानव तस्करी के प्रमुख कारण के रूप में पाया गया। हाल ही में एक मामला छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले का है जहां 16 युवतियों को काम के बहाने दूसरे शहर ले जाने का मामला सामने आया। ये युवतियां बस में बैठकर राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंचीं। वहां ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। इसी बीच रेलवे सुरक्षा बल की नजर युवतियों पर पड़ी। आरपीएफ की टीम ने युवतियों से पूछताछ की जिसके बाद यह पता चला कि मामला मानव तस्करी से संबंधित है।

मानव अंगों का अवैध क्रय विक्रय एक संगठित अपराधः

- अमेरिका (US) की सरकारी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के अनुसार, मानव अंगों के तस्करी के बाजार को रेड मार्केट कहते हैं। गैर सरकारी संगठन ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी (Global Financial Integrity- GFI) के आंकलन के मुताबिक विश्व में मानव अंगों की तस्करी का बाजार $840 मिलियन से $1.7 बिलियन तक का है। GFI के अनुसार, हर साल दुनिया में 12,000 मानव अंगों का गैरकानूनी प्रत्यारोपण होता है और इनमें से 8000 किडनी होती है, इनके बाद, लिवर, हार्ट, फेंफड़े और पेनक्रियाज का नंबर आता है।
- मानव अंगों की तस्करी आम तौर पर भ्रष्ट अधिकारियों और आपराधिक समूहों की सांठ-गांठ से होता है। इसमें बिचौलिए शामिल होते हैं जो अंग देने के लिए लोगों को तैयार करते हैं, उनसे पैसे की बात करते हैं और ऐसे सेंटर्स और मेडिकल प्रोफेशनल की पहचान करते हैं जहां मानव अंगों की तस्करी की जा सकती है।

भारत में अंगदान का तरीकाः

- भारत में दो तरह के अंगदान होते हैं, केदेवेरिक डोनेशन (Cadaveric donation) जो ब्रेन डेड व्यक्ति के अंगों का दान होता है, दूसरा लाइव डोनेशन होता है जिसमें होटा एक्ट (Human Organ Transplant Act) के तहत मां बाप, बच्चे, पति-पत्नी,भाई-बहन एक दूसरे को कुछ अंग दान कर सकते हैं। दूर के रिश्तेदारों को अंग दान की अनुमति नहीं होती है।
- इसके लिए लीगल कमेटी बैठती है, वही कमेटी दूर के रिश्तेदारों की अंग-दान की याचिका पर फैसला करती है। भारत में अंगदान (Organ Donation) के लिए सबसे जरूरी है, HLA टाइपिंग। यह जेनेटिंग मैचिंग होती है। इससे मां-बाप या भाई-बहन होने के रिश्ते का पता चल जाता है, लेकिन रैकेट में शामिल लोग भ्रष्टाचार का सहारा लेकर अपने हित पूरे कर लेते हैं।

मानव अंगों की तस्करीः

- अमेरिका की सरकारी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के अनुसार, मानव अंगों की तस्करी (organ trafficking), आम तौर पर ऐसी आपराधिक गतिविधियों को कहते हैं जिसमें अवैध तरीके से किसी जीवित या मृत व्यक्ति से अंग निकाला जाना और फिर उसकी अवैध बिक्री और प्रत्यारोपण शामिल है जबकि कुछ विशेषज्ञ किसी अंग को पाने के लिए बंदी बनाना या दबाव डालने को भी मानव अंगों की तस्करी की श्रेणी में डालते हैं, अमेरिकी सरकार इसे अंग निकालने के लिए मानव तस्करी की श्रेणी में रखती है। जिसमें मानव-अधिकारों का हनन भी शामिल होता है। दुनिया में $1.7 बिलियन का मानव अंगों की तस्करी का बाजार है।
- अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसार कानूनी दायरे से जब मानव अंगों के प्रत्यारोपण की मांग पूरी नहीं होती है तब मानव अंगों की तस्करी को बढ़ावा मिलता है, जिसमें आपराधिक तत्व भी शामिल हो जाते हैं।
- मानव तस्करी विस्तृत अर्थों में केवल मानव अंगों के अवैध क्रय विक्रय से ही संबंधित नही है बल्कि इसका दायरा कई आपराधिक अवैधानिक गतिविधियों तक विस्तृत है। मानव तस्करी के मुख्य कारणों में बलात वेश्यावृत्ति शामिल है।
- यह एक ऐसा अपराध है जिसमें महिला या किशोरी का व्यावसायिक स्तर पर यौन संबंध बनाने के लिए शोषण किया जाता है। यौन तस्करी किसी व्यक्ति को वाणिज्यिक यौन कृत्य के उद्देश्य से भर्ती करना, आश्रय देना, परिवहन करना, प्रावधान करना, प्राप्त करना, संरक्षण देना या आग्रह करना है, जिसमें वाणिज्यिक यौन कृत्य बल, धोखाधड़ी या जबरदस्ती से प्रेरित किया जाता है या जिसमें ऐसा कृत्य करने के लिए प्रेरित व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करता है।
- बलात श्रम, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, बलात भिक्षावृत्ति, बलात विवाह, बल पूर्वक अपराध के कार्य में लगाने के लिए मानव तस्करी की जाती है। आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन ने यौन दासियां बनाने के लिए भी मानव तस्करी को बढ़ावा दिया है।

मानव तस्करी से निपटने के उपायः

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की भूमिकाः

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पिछले साल मानव तस्करी के मामलों में देश के 10 राज्यों में तलाशी ली। एनआईए ने जिन राज्यों में छापेमारी की और तलाशी ली उनमें शामिल हैं: त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, पुडुचेरी, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर।
- राज्य पुलिस बलों के साथ निकट समन्वय में इन मामलों से जुड़े संदिग्धों के आवासीय परिसरों और अन्य स्थानों पर छापेमारी की गई। उल्लेखनीय है कि नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी को अब मानव तस्करी से जुड़े अपराधों की जांच पड़ताल करने, मुकदमा चलाने, आरोप पत्र दायर करने, दोषियों को एन आई ए स्पेशल कोर्ट के जरिए दंडित करने का अधिकार दिया गया है।
- अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी देश भर में मानव तस्कर गिरोहों के खिलाफ छापे मार कर संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर रही है। चूंकि मानव तस्करी एक संगठित अपराध है और संगठित अपराध के तहत आने वाली सभी प्रमुख तस्करी अपराध के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति राष्ट्रीय जांच एजेंसी को मिल चुकी है, इसलिए एन आई ए इस दिशा में सक्रिय हो चुका है।
- 2023 में ही बेंगलुरु से एनआईए की एक टीम ने श्रीलंकाई मानव तस्करी मामले में तमिलनाडु से एक फरार आरोपी को भी गिरफ्तार किया था। एनआईए कुछ अन्य मानव तस्करी के मामलों की जांच कर रही है जिसमें तस्करों द्वारा निर्दोष लोगों को झूठे वादों के साथ लुभाया जाता है, जिसमें कनाडा में प्रवास के लिए वैध दस्तावेज प्राप्त करने और रोजगार के अवसर हासिल करने की संभावना और अन्य उद्देश्य शामिल हैं।

राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी):

- भारत सरकार ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर अंग व ऊतक प्रत्यारोपण संगठनों का एक नेटवर्क स्थापित करने और उन्हें

प्रत्यारोपण व फिर से प्राप्त करने वाले अस्पतालों व ऊतक बैंकों के साथ जोड़ने के लिए कार्य किया है।

- इसके लिए मृत दाताओं से अंगों व ऊतकों की खरीद और वितरण के लिए एक कुशल प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से अंग व ऊतक दाताओं और प्राप्तकर्ताओं की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत नए अंगों व ऊतक प्रत्यारोपण व फिर से प्राप्त करने की सुविधाओं को स्थापित करने या उन्नयन करने व ऊतक बैंकों की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- उल्लेखनीय है कि मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (थोटा)- 1994 चिकित्सीय उद्देश्यों और मानव अंगों व ऊतकों के वाणिज्यिक लेनदेन की रोकथाम के लिए मानव अंगों व ऊतकों को हटाने, भंडारण और प्रत्यारोपण के नियमन का प्रावधान करता है। उपरोक्त अधिनियम के तहत कृत्रिम अंगों का विषय विनियमित नहीं है।
- उपरोक्त माध्यमों के अलावा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, क्राइम - मल्टी एजेंसी सेंटर का गठन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की सक्रिय भूमिका, मानव तस्करी से जुड़ी खुफिया एजेंसियों को सक्रिय करना आदि उपाय अपनाए गए हैं। वाणिज्यिक यौन शोषण और बलात वेश्यावृत्ति के मकसद से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के अनैतिक देह व्यापार निरोधक कानून, 1956, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013, पास्को एक्ट, 2012 जैसे कानूनों में तस्करी को रोकने के कठोर प्रावधान किए गए हैं। आईपीसी की धारा 372 और 373 भी वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों के खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध लगाकर उसे दंडनीय अपराध बनाता है।

विविध संक्षिप्त मुद्दे

थाली से गायब पोषण: दुनिया में खाद्य निर्धनता और बच्चों की स्थिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा जारी नई रिपोर्ट 'चाइल्ड फूड पावर्टी: न्यूट्रिशन डेप्रिवेशन इन अर्ली चाइल्डहुड' में कहा गया की दुनिया में हर चौथा बच्चा खाद्य निर्धनता से जूझ रहा है। यह रिपोर्ट दुनिया के करीब 100 देशों में रहने वाले बच्चों में पोषक आहार की कमी, उसके प्रभावों और कारणों को उजागर करती है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

वैश्विक स्थिति:

- दुनिया में पांच वर्ष से कम आयु के 18.1 करोड़ बच्चे खाद्य निर्धनता के शिकार हैं, जो हर चौथे बच्चे का प्रतिनिधित्व करता है।
- इनमें से 65% बच्चे केवल 20 देशों में रहते हैं, जिनमें भारत भी शामिल है।

भारत की स्थिति:

- भारत में 76% बच्चे खाद्य निर्धनता का सामना कर रहे हैं।
- इनमें से 40% बच्चे गंभीर खाद्य निर्धनता और 36% बच्चे मध्यम खाद्य निर्धनता से जूझ रहे हैं।

खाद्य निर्धनता का प्रभाव:

- गंभीर खाद्य निर्धनता से पीड़ित बच्चों के जानलेवा कुपोषण (वेस्टिंग) से ग्रसित होने की आशंका 50% अधिक होती है।
- खाद्य निर्धनता बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित करती है।

विभिन्न कारण:

- बढ़ती महंगाई, खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल, जीवन यापन की बढ़ती लागत, जलवायु परिवर्तन, महामारी का प्रभाव और बढ़ते टकराव।
- स्वास्थ्य के लिहाज से हानिकारक खाद्य पदार्थों का बढ़ता बोलबाला और खाद्य प्रणालियों की विफलता।

खराब आहार का उदाहरण:

- अफगानिस्तान में बच्चे पूरे दिन में कुछ ब्रेड या दूध का सेवन कर पाते हैं। फल और सब्जियों की थाली में कमी होती है।

प्रगति और सफलता:

- बुर्किना फासो, नेपाल, और रवांडा जैसे देशों ने खाद्य निर्धनता के मामलों में कमी लाई है।
- इन देशों ने पोषक आहार की आपूर्ति बढ़ाने के सुनियोजित प्रयास किए हैं।

रिपोर्ट की सिफारिशें:

- बच्चों को पोषक आहार सुलभता से उपलब्ध कराने और गरीबी से निपटने पर जोर देना।
- स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना और सतत विकास के लक्ष्यों पर ध्यान देना।

खाद्य निर्धनता की परिभाषा:

- यूनिसेफ के अनुसार, जब बच्चों को अपने जीवन के शुरूआती वर्षों में स्वस्थ, पोषण और विविधता से भरपूर आहार नहीं मिलता, तो इसे खाद्य निर्धनता कहते हैं।

खाद्य निर्धनता का वर्गीकरण:

- **गंभीर खाद्य निर्धनता:** जब बच्चे हर दिन आठ में से दो या उससे कम खाद्य समूहों का सेवन करते हैं।
- **मध्यम खाद्य निर्धनता:** तीन से चार खाद्य समूहों का सेवन।
- **खाद्य निर्धनता से मुक्त:** पांच या उससे अधिक खाद्य समूहों का सेवन।

निष्कर्ष:

भारत में और दुनिया भर में खाद्य निर्धनता बच्चों के विकास के लिए एक गंभीर चुनौती है। बढ़ती महंगाई, कुपोषण और खाद्य प्रणालियों की विफलता इस समस्या को और भी जटिल बना रही हैं। स्वस्थ और पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि भावी पीढ़ी को स्वस्थ और समृद्ध भविष्य मिल सके।

पहाड़ी बच्चों में कुपोषण एवं नाटापन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर रहने वाले बच्चों में नाटेपन और कुपोषण की समस्या ज्यादा गंभीर है। इसकी पुष्टि भारतीय शोधकर्ताओं ने अपने एक नए अध्ययन में भी की है।

- **शोध समूह:** यह शोध इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ लदाख, मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज से जुड़े शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है, जिसके परिणाम अंतराष्ट्रीय जर्नल बीएमजे न्यूट्रिशन प्रिवेंशन एंड हेल्थ में प्रकाशित हुए हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष:

- समुद्र तल से 2000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर रहने वाले बच्चों में नाटेपन की आशंका 40% अधिक होती है।
- अध्ययन किए गए 36% बच्चे नाटेपन (स्टंटिंग) का शिकार थे।
- 18 से 59 महीनों के बच्चों में यह समस्या अधिक आम थी, इस आयु वर्ग के 41% बच्चे नाटेपन से प्रभावित थे।
- रिसर्च से यह भी पता चला है कि ऊंचाई और नाटेपन के बीच यह संबंध ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों में कहीं अधिक स्पष्ट था।
- उच्च शिक्षा प्राप्त माताओं की तुलना में अनपढ़ माताओं के बच्चों में नाटेपन की दर दुगने से भी अधिक थी। जिन बच्चों की मातायें स्कूल नहीं गयी थी उनके 48 फीसदी बच्चे नाटेपन से जूझ रहे थे, वहीं शिक्षित महिलाओं में यह दर 21 फीसदी रही।

प्रमुख कारण:

- **ऊंचाई का प्रभाव:** ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और कठोर जलवायु परिस्थितियों के कारण बच्चों में भूख कम हो जाती है और पोषक तत्वों का अवशोषण सीमित हो सकता है। इस कारण से इन क्षेत्रों में बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाता है।
- **पोषण की कमी:** पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा अधिक होती है, क्योंकि यहाँ फसलों की पैदावार कम होती है और पोषक आहार की उपलब्धता सीमित होती है।
- **स्वास्थ्य सेवाओं की कमी:** इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच भी अधिक चुनौतीपूर्ण होती है, जिससे बच्चों को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं।
- **शिक्षा का अभाव:** माताओं की शिक्षा का स्तर भी बच्चों के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के अभाव में पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कम होती है।

समाधान और सिफारिशें:

- **पोषण कार्यक्रमों का विस्तार:** पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जरूरी है ताकि बच्चों को पर्याप्त पोषक आहार मिल सके।
- **शिक्षा का विस्तार:** माताओं और परिवारों को पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा का विस्तार करना चाहिए।
- **स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच:** पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।
- **साक्ष्य-आधारित नीतियाँ:** कुपोषण से निपटने के लिए साक्ष्य-आधारित नीतियों और केंद्रित प्रयासों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

कुपोषण के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- मिशन पोषण 2.0.
- एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
- मध्याह्न भोजन योजना

निष्कर्ष:

भारत में नाटेपन और कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए व्यापक और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा शामिल हों। केवल तभी देश के बच्चों का स्वस्थ विकास सुनिश्चित हो सकता है।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार 61 प्रतिशत भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है।

रैंकिंग के महत्वपूर्ण बिंदु:

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे पिछले साल की 149वीं रैंक से इस साल 118वीं रैंक पर पहुंच गया है, जिसका कुल स्कोर 100 में से 56.3 रहा है।
- आईआईटी बॉम्बे के बाद आईआईटी दिल्ली और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु का स्थान है, दोनों संस्थान क्रमशः भारत में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर (आईआईटी-केजीपी) ने 2024 की रैंकिंग में 271वीं रैंकिंग के साथ चौथा स्थान हासिल किया है, जो इस बार 222वीं रैंकिंग पर है। आईआईटी केजीपी के बाद आईआईटी मद्रास का स्थान है, जो इस साल 58 रैंक (285 से 227) ऊपर चढ़ा है।
- सबसे बड़ा सुधार दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने किया है, जिसने 79 रैंक की छलांग लगाई है -पिछले साल के 407वें स्थान से इस साल 328वें स्थान पर आया है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय ने पिछले साल के नौवें स्थान से इस बार सातवें स्थान पर सुधार किया है।
- रैंकिंग के इस संस्करण में, 46 विश्वविद्यालयों का दावा करते हुए, भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व स्तर पर सातवें सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली और एशिया में तीसरे स्थान पर है, जो केवल जापान (49 विश्वविद्यालय) और चीन (मुख्यभूमि) (71 विश्वविद्यालय) से पीछे है।

वैश्विक रैंकिंग:

- एमआईटी ने नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष रैंक हासिल की है, इसके बाद यूके के इंपीरियल कॉलेज लंदन ने अपनी स्थिति में सुधार किया है जो पिछले साल से छठे स्थान से दूसरे स्थान पर आया है।
- तीसरी रैंक संयुक्त रूप से हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा ली गई है, जो एक रैंक ऊपर बढ़ा है, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जिसने पिछले साल से अपना तीसरा स्थान बनाए रखा है।

अंतर्राष्ट्रीय संकाय और छात्र अनुपात:

- भारत अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात और अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात संकेतकों में पिछड़ा हुआ है, जो अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आदान-प्रदान की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के अनुपात के लिए देश का स्कोर मात्र 2.9 है, जो वैश्विक औसत 26.5 से काफी कम है।

अंतर्राष्ट्रीय संकाय का अनुपात:

- भारत में अंतर्राष्ट्रीय संकाय के अनुपात का औसत स्कोर 9.3 है। यह स्कोर वैश्विक परिदृश्य की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय संकाय सदस्यों की कम उपस्थिति को दर्शाता है।

भारत में संकाय/छात्र अनुपात:

- भारत का संकाय/छात्र अनुपात स्कोर 16.2 है, जो वैश्विक औसत 28.1 से काफी कम है, जो संकाय संसाधनों पर संभावित दबाव और छात्रों के लिए बेहतर शैक्षिक परिणाम और व्यक्तिगत ध्यान सुनिश्चित करने के लिए अनुपात में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उन्नति ने तीव्र परिवर्तन लाया है, उससे वैश्विक उच्च शिक्षा परिदृश्य विकसित हो रहा है। भारतीय उच्च शिक्षा की बढ़ती प्रमुखता स्पष्ट है, अब 46 विश्वविद्यालयों को रैंक किया गया है और 61% ने अपनी स्थिति में सुधार किया है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का साहसिक कार्यान्वयन देश की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने, चुनौतियों का समाधान करने और अवसरों का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नाता प्रथा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों को 'नाता प्रथा' के संबध में नोटिस जारी किया है।

नाता प्रथा क्या है?

- महिलाओं और नाबालिग लड़कियों पर 'नाता प्रथा' के अनैतिक परिणामों को देखते हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इसके उन्मूलन का आह्वान किया है।
- नाता शब्द का अर्थ है संबंध और इसमें कम उम्र की लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर बेचना या उनकी शादी करवाना शामिल है, जो आमतौर पर उनके अपने परिवार द्वारा किया जाता है।
- यह प्रथा राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है, मुख्य रूप से भील जनजाति में, जो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा 'नाता प्रथा' पर सिफारिशें:

- **कानून बनाना:** आयोग ने नाता प्रथा से निपटने के लिए विशिष्ट कानून बनाने की सिफारिश की हैं जो इस प्रथा को स्पष्ट रूप से परिभाषित और इसके उन्मूलन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- इसके अलावा, महिलाओं को नाता प्रथा में धकेलने में शामिल व्यक्तियों पर मौजूदा मानव तस्करी कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। नाबालिग लड़कियों की बिक्री पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
- **ग्राम-स्तरीय समूह:** आयोग ने नाता प्रथा के मामलों को दर्ज करने के लिए गांव स्तर पर समूह स्थापित करने का सुझाव दिया। ये समूह निगरानीकर्ताओं के रूप में कार्य करेंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि घटनाओं की रिपोर्ट की जाए और उनका तुरंत समाधान किया जाए।
- **जागरूकता और शिक्षा:** नाता प्रथा के हानिकारक प्रभावों के

बारे में जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण है। समुदायों को महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों और ऐसी प्रथाओं में शामिल होने के कानूनी परिणामों के बारे में सूचित करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए।

- **आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण:** लड़कियों और महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना आवश्यक है। उन्हें सशक्त बनाकर, 'नाता प्रथा' से जुड़े शोषण और निर्भरता के चक्र को तोड़ा जा सकता है, जिससे दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन हो सकता है।

–: प्रीलिम्स इनसाइट :–

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में एक वैधानिक निकाय है, जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा छह सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर की जाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - प्रधानमंत्री
  - लोकसभा के अध्यक्ष
  - राज्यसभा के उपसभापति
  - लोकसभा में विपक्ष के नेता
  - राज्यसभा में विपक्ष के नेता
  - केंद्रीय गृह मंत्री
- NHRC को अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है और इसमें सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ हैं, जो इसकी कार्यवाही को न्यायिक चरित्र प्रदान करती हैं। हालाँकि, यह केवल एक वर्ष के भीतर मामलों की जाँच कर सकता है।

भीलों के बारे में:

- भील छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में रहने वाले सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक हैं। यह नाम 'बिल्लू' शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है धनुष। वे उत्कृष्ट तीरंदाज के रूप में जाने जाते हैं।

केस स्टडी:

- 15 जुलाई, 2020 को राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सलामगढ़ क्षेत्र के एक पिता ने शिकायत में दावा किया कि उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया गया था। बाद में उसका शव बांसवाड़ा जिले के दानपुर में मिला।
- जांच में पता चला कि पिता ने उसे 11 जुलाई, 2019 को 'नाता प्रथा' के तहत एक व्यक्ति को 2.5 लाख रुपये में शादी के सौदे में बेच दिया था। दूल्हे ने 60,000 रुपये का अग्रिम भुगतान किया, शेष राशि 10 जनवरी, 2020 तक देनी थी।
- जब दूल्हा शेष राशि का भुगतान करने में विफल रहा, तो पिता ने अपनी बेटी को वापस ले लिया और 32,000 रुपये में एक और 'नाता' सौदा तय किया।
- लड़की ने विरोध करते हुए अपने पहले पति के पास लौट आई और अपने पिता द्वारा उसे बेचने के बार-बार प्रयास करने और उसे जान से मारने की धमकियों के बारे में बांसवाड़ा एसपी से शिकायत की। उसकी शिकायतों के बावजूद, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण उसने 16 जून, 2020 को उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

निष्कर्ष:

नाता प्रथा वेश्यावृत्ति के आधुनिक रूपों के समान है। इस पारंपरिक प्रथा में अक्सर शादी के सौदे की आड़ में महिलाओं की बिक्री शामिल होती है, जिसका महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों और कल्याण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस सामाजिक बुराई को बहुआयामी रणनीति के माध्यम से संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि यह बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है।

बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर संधि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जिनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के सदस्यों ने बौद्धिक संपदा (IP), आनुवंशिक संसाधन (GRs) और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान (ATK) पर एक संधि संपन्न की है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में:

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) बौद्धिक संपदा (IP) सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है।
- संयुक्त राष्ट्र की एक स्व-वित्तपोषित हैं तथा इसके 193 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका सदस्य है।
- इसका मिशन संतुलित और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रणाली के विकास का नेतृत्व करना है जो सभी के लाभ के लिए नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है।
- WIPO पारंपरिक ज्ञान (TK) को ज्ञान, जानकारी, कौशल और प्रथाओं के रूप में परिभाषित करता है जो एक समुदाय के भीतर पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित, सतत रखा जाता है, जो अक्सर इसकी सांस्कृतिक या आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा बनता है।

इस तरह की संधि का प्रभावः

- मूल दायित्वों के प्रकटीकरण पर वैश्विक मानक बनाकर, यह संधि आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के प्रदाता देशों के लिए आईपी प्रणाली के भीतर एक अभूतपूर्व ढांचा बनाती है।
- समझौते के तहत पेटेंट आवेदकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे मूल देश या आनुवंशिक संसाधनों के स्रोत का खुलासा करें, यदि दावा किया गया आविष्कार उन सामग्रियों या संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है।
- इस संधि के माध्यम से वैश्विक बौद्धिक संपदा (आईपी) प्रणाली ने पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के अमूल्य योगदान को स्वीकार किया है, जिसने सदियों से अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों को आधार दिया है।
- यह मान्यता वैश्विक आईपी ढांचे के भीतर स्थानीय समुदायों और उनके आनुवंशिक संसाधनों (जीआर) और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के बीच अंतर्निहित लिंक को स्वीकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **संधि के निहितार्थः** यह संधि पेटेंट प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और नवाचार को मजबूत करने के साथ-साथ जैव विविधता की रक्षा करेगी।

भारत और ग्लोबल साउथ की जीतः

- यह संधि भारत और ग्लोबल साउथ के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है, जो लंबे समय से इस साधन का समर्थक रहा है। दो दशकों की बातचीत और सामूहिक समर्थन के बाद, इस संधि को बहुपक्षीय मंचों पर अपनाया गया है, जिसमें 150 से अधिक देशों के बीच आम सहमति है।
- संधि के समर्थन और लागू होने पर, अनुबंध करने वाले पक्षों को पेटेंट आवेदकों के लिए अनिवार्य प्रकटीकरण दायित्व लागू करने की आवश्यकता होगी, जब दावा किया गया आविष्कार आनुवंशिक संसाधनों या संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर आधारित हो।
- यह भारतीय जीआर और टीके को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा, जो वर्तमान में भारत में संरक्षित हैं, लेकिन उन देशों में दुरुपयोग की संभावना है, जिनके पास प्रकटीकरण दायित्व नहीं हैं।

निष्कर्षः

वर्तमान में, केवल 35 देशों में किसी न किसी रूप में प्रकटीकरण दायित्व हैं, लेकिन अधिकांश अनिवार्य नहीं हैं और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित प्रतिबंधों या उपायों का अभाव है। इस संधि के लिए विकसित दुनिया सहित अनुबंध करने वाले पक्षों को पेटेंट आवेदकों पर मूल के प्रकटीकरण दायित्वों को लागू करने के लिए अपने मौजूदा कानूनी ढांचे में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। यह संधि सामूहिक विकास को प्राप्त करने और एक स्थायी भविष्य के वादे को पूरा करने की दिशा में एक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है, एक ऐसा उद्देश्य जिसकी भारत सदियों से वकालत करता रहा है।

फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की एक टीम ने केरल के कासरगोड के घने जंगलों में बायोल्यूमिनसेंट मशरूम की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की है, जिसे वैज्ञानिक रूप से फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस के नाम से जाना जाता है।

फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस के बारे में:

- फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस मशरूम रात के समय हरे रंग की चमक उत्सर्जित करने की अपनी क्षमता के लिए अद्वितीय हैं। इन मशरूमों को आम बोलचाल की भाषा में 'इलेक्ट्रिक मशरूम' भी कहा जाता है, इनकी चमकने वाली विशेषता के कारण लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है, जो आमतौर पर स्थलीय कवकों में नहीं पाई जाती है।
- **आदर्श आवासः** रानीपुरम वन, जहाँ इन मशरूमों की खोज की गई थी, उनके विकास के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। उष्णकटिबंधीय, आर्द्र जलवायु और प्रचुर मात्रा में सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थ फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस के लिए आदर्श परिस्थितियाँ बनाते हैं। गिरे हुए पत्तों और शाखाओं से ढका जंगल का फर्श इन कवकों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर सब्सट्रेट प्रदान करता है।
- **विषाक्त पदार्थों की उपस्थितिः** उनके चमकदार गुण के आकर्षण के बावजूद, वैज्ञानिकों ने इन मशरूमों के सेवन के खिलाफ चेतावनी जारी की है। उनके बायोलुमिनेसेंस के लिए जिम्मेदार रसायन संभावित रूप से मनुष्यों के लिए विषाक्त हो सकते हैं, जिससे गंभीर जठरांत्र संबंधी समस्याएं या अन्य प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं।

कवक में बायोलुमिनेसेंस कैसे काम करता है?

- मशरूम में बायोलुमिनेसेंस एक प्रकार का केमिलुमिनेसेंस है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया जो प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया में ल्यूसिफरिन वर्णक और ल्यूसिफेरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन आवश्यक है।
- माना जाता है कि इन मशरूमों से निकलने वाली रोशनी कीटों को

आकर्षित करती है, जो फिर बीजाणुओं को फैलाने में मदद करते हैं, जिससे कवक के प्रजनन चक्र में सहायता मिलती है।

कासरगोड के बारे में:

- केरल के पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता में स्थित, कासरगोड वन चंद्रगिरी और बेकल किलों, चंद्रगिरी नदी, ऐतिहासिक कोलाथिरी राजाओं और रानीपुरम और कोट्टनचेरी पहाड़ियों के प्राकृतिक वातावरण के लिए जाना जाता है।

बायोलुमिनेसेंस क्या है:?

- बायोलुमिनेसेंस समुद्री प्लवक के कारण होता है जिसे डाइनोफ्लैगलेट्स कहा जाता है, जो पानी में हलचल होने पर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये प्लवक रात में समुद्र की सतह पर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। बायोलुमिनेसेंस आमतौर पर गहरे समुद्र में रहने वाली प्रजातियों में आम है।
- स्पंज, जेलीफिश, कीड़े, विभिन्न मछली प्रजातियाँ, आर्थ्रोपोड, इचिनोडर्म और एककोशिकीय शैवाल जैसे कई समुद्री जीव बायोलुमिनेसेंस प्रदर्शित करते हैं, इसका उपयोग शिकारियों से बचने, शिकार को आकर्षित करने या संभोग के दौरान करते हैं।

निष्कर्ष:

बायोलुमिनेसेंट मशरूम कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शोध के लिए नए अवसर प्रदान करते हैं। उनके जीन का अध्ययन करने से हमें बायोलुमिनेसेंस के बारे में अधिक जानने और नई प्रजातियाँ खोजने में मदद मिल सकती है, जिससे कवक पारिस्थितिकी तंत्र की हमारी समझ में सुधार होगा। फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस की खोज से पता चलता है कि कासरगोड के जंगलों में मशरूम की विविधता है। क्षेत्र में मशरूम की पूरी विविधता को समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। ये निष्कर्ष बताते हैं कि आने वाले समय में और भी खोजें हो सकती हैं, जो क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को उजागर करेंगी।

रज पर्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ओडिशा के कृषि उत्सव 'रज पर्व' के समारोह में भाग लिया और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को देखा। इस समारोह में मयूरगंज छऊ नृत्य, संबलपुरी नृत्य और कर्मा नृत्य प्रस्तुत किये गये।

रज पर्व के बारे में:

- मानसून की शुरुआत के दौरान मनाया जाने वाला कृषि उत्सव, राजा पर्व ओडिशा में सबसे अधिक मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। यह पृथ्वी देवी, बसु-माता को समर्पित है।
- 'रज' शब्द 'रजस्वला' (जिसका अर्थ है मासिक धर्म वाली महिला) शब्द से आया है और मध्यकाल के दौरान, यह त्योहार भगवान जगन्नाथ की पत्नी 'भूदेवी' की पूजा को दर्शाते हुए एक कृषि अवकाश के रूप में अधिक लोकप्रिय हो गया। भगवान जगन्नाथ के अलावा भूदेवी की एक चांदी की मूर्ति अभी भी पुरी मंदिर में पाई जाती है।
- रज पर्व के पहले, दूसरे और तीसरे दिन को क्रमशः 'पहिली राजो, मिथुन संक्रांति और भू दहा या बासी राजा' कहा जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि इस त्यौहार के पहले तीन दिनों के दौरान देवी पृथ्वी या भगवान विष्णु की दिव्य पत्नी मासिक धर्म से गुजरती हैं।
- चौथे दिन को वसुमती गढुआ कहा जाता है, जो भूदेवी के औपचारिक स्नान का प्रतीक है। जब तक त्यौहार चलता है, तब तक जुताई या बुवाई जैसी कोई कृषि गतिविधि नहीं होती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन तीन दिनों के दौरान धरती माता कायाकल्प से गुजरती है।

–: प्रीलिम्स इनसाइट :–

ग्रीक भूगोलवेत्ता टॉलेमी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'जियोग्राफिका' में महानंदा नदी के तट पर 'संबलका' नाम से दूसरी शताब्दी ईस्वी में संबलपुर के अस्तित्व का उल्लेख किया है। ये नाम आधुनिक संबलपुर और महानदी के अनुरूप हैं। फ्रांसीसी यात्री टैवर्नर के यात्रा वृत्तांतों में, 'सुमेलपुर' को रोमन साम्राज्य को आपूर्ति करने वाले हीरे से समृद्ध क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है, जो वर्तमान संबलपुर को संदर्भित करता है।

मयूरभंज छऊ नृत्य, संबलपुरी नृत्य और कर्मा नृत्य के बारे में:

मयूरभंज छऊ नृत्य:

- छऊ एक अर्ध-शास्त्रीय भारतीय नृत्य है जो मार्शल और लोक परंपराओं का मिश्रण है। यह तीन शैलियों में मौजूद है, जिनका नाम उनके क्षेत्रों के नाम पर रखा गया है: पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ, झारखंड में सेराइकेला छऊ और ओडिशा में मयूरभंज छऊ। मुखौटे पुरुलिया और सेराइकेला शैलियों की एक प्रमुख विशेषता हैं।

संबलपुरी नृत्य:

- यह लोकगीत नृत्य शैली है, जो पश्चिमी ओडिशा, विशेष रूप से पूर्व संबलपुर जिले से शुरु हुई है, जो अपने मूर्तिकला आधारित ओडिसी नृत्य के लिए जानी जाती है। इसका नाम मुख्य देवता 'समलाई' से लिया गया है, संबलपुर एक अलग सांस्कृतिक पहचान रखता है।

कर्मा नृत्य:

- कोसली का उड़िया में अर्थ 'भाग्य' होता है, यह देहाती संबलपुरी लोक नृत्य भाग्य के देवता या देवी (करम देवता या करमसनी देवी) की पूजा करने के लिए किया जाता है।

- भाद्र शुक्ल एकादशी से शुरू होने वाला यह नृत्य बलांगीर, कालाहांडी, सुंदरगढ़, संबलपुर और मयूरभंज जिलों में बिंझाल, खारिया, किसान और कोल जैसी अनुसूचित जाति जनजातियों के बीच लोकप्रिय है।

निष्कर्ष:

ओडिशा की जीवंत संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत का प्रतिनिधित्व रज पर्व उत्सव करता है। यह महत्वपूर्ण उत्सव प्रजनन क्षमता, नारीत्व और मानसून के मौसम के प्रारंभ का यशोगान करता है, जो राज्य के गहरे सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को दर्शाता है।

वैश्विक विस्थापित जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) ने वार्षिक विस्थापन रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दुनिया भर में विस्थापित आबादी की संख्या पर प्रकाश डाला गया है।

UNHCR द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु:

- 2023 के अंत तक, दुनिया भर में अनुमानित 117.3 मिलियन लोग उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन और सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर रूप से परेशान करने वाली घटनाओं के कारण जबरन विस्थापित हुए।
- परिचालित डेटा के आधार पर, UNHCR का अनुमान है कि 2024 के पहले चार महीनों में जबरन विस्थापन में वृद्धि जारी रही है और अप्रैल 2024 के अंत तक 120 मिलियन से अधिक होने की संभावना है। नतीजतन, पृथ्वी पर हर 69 लोगों में से एक अब विस्थापित है।
- उनमें से 68 मिलियन लोग अपने ही देशों में आंतरिक रूप से विस्थापित हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय (यूएनएचसीआर) की वार्षिक विस्थापन रिपोर्ट के अनुसार, शेष शरणार्थी सुरक्षा की आवश्यकता वाले (43.4 मिलियन) और शरण चाहने वाले (6.9 मिलियन) हैं।
- 2024 तक, सभी शरणार्थियों में से लगभग तीन-चौथाई (72 प्रतिशत) केवल पाँच देशों से आए थे: अफगानिस्तान (6.4 मिलियन), सीरिया (6.4 मिलियन), वेनेजुएला (6.1 मिलियन), यूक्रेन (6 मिलियन) और फिलिस्तीन (6 मिलियन)
- अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, शरणार्थी वे लोग होते हैं जिन्हें उत्पीड़न या अपने जीवन, शारीरिक अखंडता या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे से बचने के लिए अपने देश से भागने के लिए मजबूर किया जाता है।

जबरन विस्थापन के पीछे मुख्य कारण:

- दुनिया भर में चल रहे संघर्षों ने जबरन विस्थापन को बढ़ावा दिया है।
- सूडान में संघर्ष अप्रैल 2023 में शुरू हुआ, जिसने दुनिया के सबसे बड़े मानवीय और विस्थापन संकटों में से एक को जन्म दिया। देश के भीतर 6 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए और 1.2 मिलियन लोग पड़ोसी देशों में भाग गए।
- म्यांमार में, फरवरी 2021 में सैन्य अधिग्रहण के बाद हिंसा बढ़ने से 2023 में देश के भीतर 1.3 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हो गए।
- फिलिस्तीन राज्य में, UNRWA का अनुमान है कि अक्टूबर और दिसंबर 2023 के बीच, गाजा पट्टी में संघर्ष के कारण 1.7 मिलियन लोग (या आबादी का 75 प्रतिशत से अधिक) विस्थापित हुए, जिनमें से कुछ को कई बार भागने के लिए मजबूर होना पड़ा।

शरण प्रदान करने वाले प्रमुख देश:

- लगभग 70 प्रतिशत शरणार्थी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता वाले अन्य लोग अपने मूल देशों के बगल के देशों में रहते हैं।
- विश्व स्तर पर, सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी ईरान (3.8 मिलियन), तुर्की (3.3 मिलियन), कोलंबिया (2.9 मिलियन), जर्मनी (2.6 मिलियन) और पाकिस्तान (2 मिलियन) में है।
- ईरान और पाकिस्तान में लगभग सभी शरणार्थी अफगान हैं जबकि तुर्की में अधिकांश शरणार्थी सीरियाई हैं। पिछले दशक में, तुर्की को छोड़कर इन प्रमुख मेजबान देशों में शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जहाँ 2021 से संख्या में 14 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- जर्मनी एकमात्र प्रमुख मेजबान देश है जिसकी सीमा मुख्य शरणार्थी स्रोत देशों से नहीं लगती है। 2023 के अंत में जर्मनी में अधिकांश शरणार्थी यूक्रेन (1.1 मिलियन), सीरिया (705,800), अफगानिस्तान (255,100) और इराक (146,500) से थे।

निष्कर्ष:

वर्तमान में शरणार्थियों के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून न तो पर्याप्त हैं और न ही व्यावहारिक। विश्व में बढ़ती शरणार्थियों की समस्या तथा अवैध प्रवासन से निपटने के लिये सभी देशों द्वारा आपसी सहमति से एक प्रभावी कानून का निर्माण किया जाना चाहिये।

PAROS (बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकना)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्रिक्स मंत्रियों ने बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने और बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ (PAROS) और इसके शस्त्रीकरण को रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- ब्रिक्स बैठक के दौरान, मंत्रियों ने बाहरी अंतरिक्ष में गतिविधियों की

दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने और हथियारों की होड़ और इसके शस्त्रीकरण को रोकने के लिए अपने समर्थन को दोहराया।

- उन्होंने बाहरी अंतरिक्ष संधि (OST) में बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम (PAROS) से संबंधित प्रावधानों के महत्व पर प्रकाश डाला और PAROS के लिए एक कानूनी बहुपक्षीय साधन पर चर्चा करने का आह्वान किया।
- मंत्रियों ने 2014 में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती की रोकथाम, बाह्य अंतरिक्ष वस्तुओं के विरुद्ध बल प्रयोग या धमकी (पीपीडब्ल्यूटी) पर अद्यतन मसौदा संधि प्रस्तुत करने की बात स्वीकार की।
- उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पारदर्शिता और विश्वास-निर्माण उपायों (टीसीबीएम) जैसी व्यावहारिक, गैर-बाध्यकारी और स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं भी PAROS में योगदान दे सकती हैं।

बाह्य अंतरिक्ष संधि के बारे में:

- बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ को रोकने की अवधारणा 1950 के दशक में शुरू हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने पहली बार सैन्य उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष के उपयोग और अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के हथियारों की तैनाती पर रोक लगाने के प्रस्तावों पर विचार किया था।
- 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि में कहा गया है कि बाह्य अंतरिक्ष को विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए समर्पित किया जाना चाहिए। भारत 1982 में बाह्य अंतरिक्ष संधि की पुष्टि करके इसका एक पक्ष बन गया।
- यह संधि पृथ्वी की कक्षा में परमाणु हथियार या किसी अन्य प्रकार के सामूहिक विनाश के हथियारों को प्रतिबंधित करती है और आकाशीय पिंडों पर हथियारों को तैनात करने पर रोक लगाती है। इन प्रावधानों के बावजूद, संधि अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ को सीधे तौर पर नहीं रोकती है, जिससे एक अधिक व्यापक संधि के लिए चल रही चर्चाओं और प्रस्तावों को बढ़ावा मिलता है।
- 2008 में, रूस और चीन ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन (सीडी) में एक मसौदा संधि प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की नियुक्ति को रोकना और उपग्रह-रोधी हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना था। इस मसौदे को 2014 में संशोधित किया गया था लेकिन इसे अपनाया नहीं गया।

PAROS के बारे में:

- बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम (PAROS) एक संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव है जो शीत युद्ध के दौरान अंतरिक्ष के हथियारीकरण पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान करता है। यह प्रस्ताव बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकने में बाहरी अंतरिक्ष संधि की कमियों को पहचानता है।
- हालाँकि, संयुक्त राष्ट्र महासभा में संधि के लिए बातचीत संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोध के कारण बाधित हुई है।

निष्कर्ष:

बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम (PAROS) संधि का उद्देश्य किसी भी देश को पृथ्वी की कक्षा में या आकाशीय पिंडों पर हथियार ले जाने वाली वस्तुओं को रखने से रोककर बाहरी अंतरिक्ष संधि का विस्तार करना है। यह बाहरी अंतरिक्ष में वस्तुओं के खिलाफ बल के प्रयोग या धमकी पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास करता है। संधि पर बातचीत करने में एक महत्वपूर्ण चुनौती यह परिभाषित करना है कि अंतरिक्ष में हथियार क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका का तर्क है कि अंतरिक्ष हथियारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में असमर्थता ऐसी संधि के लिए एक प्राथमिक बाधा है। इसके अतिरिक्त, इस बात पर बहस चल रही है कि बाहरी अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है, किस प्रकार के हथियारों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और क्या संधि सत्यापन योग्य होगी।

इंडिकोनेमा, एक नया डायटम जीनस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट (एआरआई) के शोधकर्ताओं ने पूर्वी घाट के प्राचीन जल में गोम्फोनेमॉइड डायटम के एक नए जीनस इंडिकोनेमा की खोज की है।

नए जीनस के बारे में:

- इंडिकोनेमा नामक इस नए पहचाने गए जीनस को अद्वितीय वाल्व विशेषताओं द्वारा पहचाना जाता है, जिसमें समरूपता और सिर और पैर दोनों ध्रुवों पर छिद्र क्षेत्रों की उपस्थिति शामिल है।

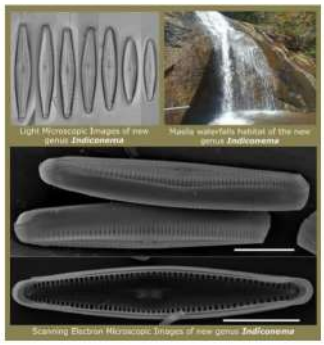

- जीनस का नाम भारत के भीतर इसके सीमित वितरण को दर्शाता है, जो देश की समृद्ध और अनूठी जैव विविधता पर जोर देता है।
- इंडिकोनेमा की दो प्रजातियाँ हैं: एक पूर्वी घाट से और दूसरी पश्चिमी घाट से।
- इंडिकोनेमा को पूर्वी अफ्रीका में पाए जाने वाले डायटम जीनस एफ्रोसिमबेला से निकटता से संबंधित पाया गया है। यह खोज भारत, पूर्वी अफ्रीका और मेडागास्कर में डायटम प्रजातियों के बीच समानता के पहले के अवलोकनों का समर्थन करती है।
- इन क्षेत्रों के बीच विकासात्मक संबंध भारतीय प्रायद्वीप में डायटम वनस्पतियों को आकार देने में मानसून और अलग-अलग नमी के महत्व को रेखांकित करता है।

डायटम प्रजातियों के बारे में:

- डायटम, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक सूक्ष्म शैवाल, वैश्विक ऑक्सीजन आपूर्ति का लगभग 25% उत्पादन करते हैं और जलीय खाद्य श्रृंखला के मूलभूत घटक के रूप में कार्य करते हैं।

- जल रसायन विज्ञान में परिवर्तनों के प्रति उनकी संवेदनशीलता उन्हें जल गुणवत्ता का उत्कृष्ट संकेतक बनाती है। इंडिकोनेमा की खोज पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता को बनाए रखने में डायटम की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है।

डायटम प्रजातियों की विशेषताएँ:

- **विविध समूह:** डायटम शैवाल का एक विविध समूह है, जिसमें 20,000 से अधिक ज्ञात प्रजातियाँ हैं।
- **अद्वितीय कोशिका भित्ति:** डायटम में सिलिका (SiO2) से बनी कोशिका भित्ति होती है, जो अलंकृत पैटर्न वाली होती हैं और उनके वर्गीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- **प्रकाश संश्लेषक:** डायटम प्रकाश संश्लेषक होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
- **जलीय आवास:** डायटम लगभग हर जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, मीठे पानी की झीलों और नदियों से लेकर महासागरों और आर्द्रभूमि तक।
- **खाद्य स्रोत:** डायटम कई जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत हैं, छोटे जूप्लैंकटन से लेकर बड़ी व्हेल तक।
- **महत्वपूर्ण संकेतक:** डायटम का उपयोग जल गुणवत्ता के संकेतक के रूप में किया जाता है, क्योंकि वे अपने पर्यावरण में परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं।
- **जीवाश्म रिकॉर्ड:** डायटम का एक समृद्ध जीवाश्म रिकॉर्ड है, जिसके प्रमाण बताते हैं कि वे 180 मिलियन से अधिक वर्षों से पृथ्वी पर हैं।
- **औद्योगिक अनुप्रयोग:** डायटम का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जिसमें जल निस्पंदन, बायोमेडिसिन, सौंदर्य प्रसाधन और खाद्य और पेय पदार्थ शामिल हैं।
- **पारिस्थितिक भूमिका:** डायटम जलीय खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वैश्विक कार्बन चक्र का एक प्रमुख घटक हैं।

निष्कर्ष:

इंडिकोनेमा की खोज न केवल डायटम विविधता के बारे में हमारे ज्ञान को समृद्ध करती है, बल्कि भारत के अद्वितीय और विविध आवासों की रक्षा और अध्ययन के महत्वपूर्ण महत्व को भी उजागर करती है।

नालंदा विश्वविद्यालय के नये परिसर का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन खंडहरों के स्थल के पास, बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया।

विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार के बारे में विवरण:

- नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का प्रस्ताव पहली बार 2000 के दशक की शुरुआत में पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, सिंगापुर सरकार और पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन (ईएएस) देशों के नेताओ ने लिया था।
- भारतीय संसद ने संस्थान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए सन् 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया।
- नालंदा विश्वविद्यालय भारत और पूर्वी एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय ज्ञान विनिमय को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त प्रयास है।
- बिहार सरकार ने प्राचीन खंडहरों के पास विश्वविद्यालय के लिए 455 एकड़ की जगह प्रदान की।
- विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण अध्ययन, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है।
- परिसर को सौर संयंत्र, जल उपचार संयंत्र, जल पुनर्चक्रण संयंत्र और अन्य पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं के साथ पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ बनाया गया है।
- परिसर एक 'नेट जीरो' ग्रीन कैंपस है और आत्मनिर्भर है।
- नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को 2016 में संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था।

नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में:

- **प्राचीन शिक्षा का केंद्र:** नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था और दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। इसकी स्थापना सन् 427 ई. में गुप्त साम्राज्य के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी।
- **बौद्ध अध्ययन:** नालंदा बौद्ध शिक्षा और विद्वत्ता का एक प्रमुख केंद्र था, जो पूरे एशिया से छात्रों को आकर्षित करता था।
- **नौ मिलियन पुस्तकें:** विश्वविद्यालय में नौ मिलियन से अधिक पुस्तकों वाला एक विशाल पुस्तकालय था, जो इसे प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े संग्रहों में से एक बनाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय छात्र निकाय:** कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की के छात्र नालंदा में पढ़ते थे।
- **बहु-विषयक पाठ्यक्रम:** विश्वविद्यालय ने दर्शन, तर्क, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित और कला जैसे विषयों में पाठ्यक्रम पेश किए।
- **प्रसिद्ध पूर्व छात्र:** नालंदा के पूर्व छात्रों में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन और पद्मसंभव शामिल हैं।
- **मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा विनाश:** 1197 ई. में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नालंदा को नष्ट कर दिया गया, जिसने प्राचीन भारत के शिक्षा के स्वर्ण युग का अंत कर दिया।
- **पुरातात्विक महत्व:** नालंदा के खंडहर अब यूनेस्को की विश्व ध रोहर स्थल और एक प्रमुख पुरातात्विक आकर्षण हैं।

निष्कर्ष:

नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार प्राचीन भारतीय ज्ञान और संस्कृति

के संरक्षण और संवर्धन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 2010 में स्थापित नया विश्वविद्यालय भारत की समृद्ध शैक्षिक विरासत और आधुनिक समय के अनुकूल होने की इसकी क्षमता का प्रतीक है। प्रसिद्ध वास्तुकार बी.वी. दोशी द्वारा डिजाइन किया गया परिसर पारंपरिक और आधुनिक वास्तुकला का मिश्रण है, जो आधुनिक सुविधाओं को शामिल करते हुए अतीत की भावना को दर्शाता है।

राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान (NIIMH)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान (NIIMH) को "पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान" (CC IND-177) के लिए WHO सहयोगी केंद्र (CC) के रूप में नामित किया है। यह पदनाम 3 जून, 2024 से शुरू कर चार साल की अवधि के लिए रहेगा। NIIMH, पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन का तीसरा सहयोगी केन्द्र है। इससे पहले आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (MDNIY), नई दिल्ली हैं।

सहयागी केन्द्र के रूप में NIIMH को लाभ:

- पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान में NIIMH की विशेषज्ञता की वैश्विक मान्यता।
- अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और संगठनों के साथ सहयोग और ज्ञान साझाकरण में वृद्धि।
- भारत में पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा को मजबूत करना।
- पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों और शब्दावली का विकास।
- NIIMH और भारत की पारंपरिक चिकित्सा विरासत के लिए दृश्यता और विश्वसनीयता में वृद्धि।
- अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और प्रकाशनों के अवसर।
- पारंपरिक चिकित्सा में शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण।
- साक्ष्य-आधारित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के विकास में योगदान।
- आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में पारंपरिक चिकित्सा का बेहतर एकीकरण।

डब्ल्यूएचओ सहयोग केंद्र के बारे में:

- डब्ल्यूएचओ सहयोग केंद्र (सीसी) एक संस्था है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा कार्य के विशिष्ट क्षेत्रों पर सहयोग करने के लिए नामित किया गया है। दुनिया भर में 800 से अधिक WHO CC हैं, जो विभिन्न विषयों पर काम कर रहे हैं जैसे:
  - संक्रामक रोग
  - गैर-संचारी रोग
  - मानसिक स्वास्थ्य
  - पोषण
  - पर्यावरण स्वास्थ्य
  - स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियाँ
  - पारंपरिक चिकित्सा

WHO सहयागी केन्द्र के कार्य:

- अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना।
- WHO के वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे का समर्थन करना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- ज्ञान और विशेषज्ञता का प्रसार करना।
- वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में योगदान देना।

राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान के बारे में:

- 1956 में राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत केंद्र (NCIMH) के रूप में स्थापित।
- मुख्यालय- दिलसुखनगर, हैदराबाद में स्थित
- आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) के तहत संचालित होता है।
- पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा में औषधीय-ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए समर्पित।
- चिकित्सा के इतिहास पर शोध सामग्री का व्यापक संग्रह, जो विश्व स्तर पर सुलभ है।
- आयुष और आधुनिक चिकित्सा में इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए संसाधन सामग्री की आपूर्ति करता है।
- चिकित्सा-ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान।
- 15वीं शताब्दी की 500 से अधिक भौतिक पांडुलिपियाँ और दुर्लभ पुस्तकें यहाँ मौजूद हैं।
- पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र (CC) के रूप में नामित।
- भारतीय चिकित्सा विरासत की पत्रिका प्रकाशित करता है और आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली विकसित करता है।

निष्कर्ष:

विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोगी केंद्र (CC) की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाकर, वैश्विक समुदाय स्वास्थ्य सेवा परिणामों को बेहतर बनाने, सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक खोज को आगे बढ़ाने के लिए पारंपरिक चिकित्सा के लाभों का उपयोग कर सकता है।

ब्रेन बूस्टर

ग्रीन अमोनिया

चर्चा में क्यों?

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के SIGHT कार्यक्रम के तहत ग्रीन अमोनिया उत्पादकों के चयन के लिए अनुरोध (RfS) जारी किया है। RfS प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से किया जाएगा। उत्पादन और आपूर्ति के लिए कुल 5.39 लाख मीट्रिक टन (MT)/वर्ष ग्रीन अमोनिया के लिए ई-बोली और ई-रिवर्स नीलामी के माध्यम से बोली लगाई जाएगी। उत्पादित ग्रीन अमोनिया को उर्वरक कंपनियों को आपूर्ति की जाएगी।

1. ग्रीन अमोनिया के बारे में

- ग्रीन अमोनिया एक प्रकार का अमोनिया है जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के बजाय पवन या सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है।
- यह इसे पारंपरिक अमोनिया के स्थान पर अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बनाता है।
- अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना एक रासायनिक यौगिक है, और इसके विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोग हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - **उर्वरक उत्पादन:** अमोनिया उर्वरकों के उत्पादन में एक प्रमुख घटक है, जो कृषि के लिए आवश्यक हैं।
  - **ऊर्जा भंडारण:** अमोनिया का उपयोग हाइड्रोजन के वाहक के रूप में किया जा सकता है, जिससे यह कम कार्बन ऊर्जा क्षेत्र में संक्रमण में एक संभावित विकल्प बन जाता है।
  - **औद्योगिक प्रक्रियाएँ:** अमोनिया का उपयोग विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है, जैसे प्लास्टिक, रंग और फार्मास्यूटिकल्स का उत्पादन।

2. ग्रीन अमोनिया के लाभ

- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी:** ग्रीन अमोनिया में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और अधिक सतत भविष्य प्राप्त करने में विभिन्न उद्योगों का समर्थन करने की क्षमता है।
- **शून्य-उत्सर्जन ईंधन:** ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने पर, ग्रीन अमोनिया दहन पर केवल पानी और नाइट्रोजन छोड़ता है, जिससे यह विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाता है।
- **सतत उर्वरक:** ग्रीन अमोनिया का उपयोग कृषि में एक सतत उर्वरक के रूप में किया जा सकता है।
- **शिपिंग और विमानन के लिए ईंधन:** ग्रीन अमोनिया का उपयोग शिपिंग, विमानन और अन्य परिवहन क्षेत्रों के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है।

3. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में

- जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया।
- उद्देश्य: भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना।

4. एनजीएचएम के लक्ष्य

- 2030 तक हर साल कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन।
- 2030 तक 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि।
- 2030 तक 600,000 से अधिक नौकरियों का सृजन।
- 2030 तक 100 बिलियन डॉलर से अधिक के निवेश को आकर्षित करना।
- 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 12.7 बिलियन डॉलर से अधिक की कमी।
- 2030 तक लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी।

5. निष्कर्ष

ग्रीन अमोनिया उर्वरक क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से भारत के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य में योगदान देगा और वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए प्रेरणा का काम करेगा।

ब्रेन बूस्टर

विश्व नारकोटिक दिवस

चर्चा में क्यों?

विश्व नारकोटिक दिवस, जिसे नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 26 जून को मनाया गया। यह दिन वैश्विक नशीली दवाओं की समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिसका अंतिम लक्ष्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त समाज बनाना है।

1. थीम

- विश्व नारकोटिक दिवस 2024 थीम: सबूत स्पष्ट है: रोकथाम में निवेश करें।

2. इतिहास

- 1909 में, शंघाई में मादक दवाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहाँ नशीली दवाओं के दुरुपयोग की वैश्विक समस्या को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1987 में विश्व ड्रग दिवस की स्थापना की।
- यह 1989 से हर साल 26 जून को मनाया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को चीन के ग्वांगडोंग में अफीम के व्यापार को खत्म करने के लिन जेक्सू के प्रयासों की याद में चुना गया था।
- इसी दिन, 26 जून 1971 में साइकोट्रॉपिक पदार्थों पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर भी हुए थे।

3. संयुक्त राष्ट्र के तीन ड्रग नियंत्रण सम्मेलन

नारकोटिक ड्रग्स पर एकल सम्मेलन (1961):

- इस सम्मेलन ने मौजूदा दवा नियंत्रण संधियों को समेकित किया और अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड (INCB) की स्थापना की।
- इसने दवाओं को उनके दुरुपयोग की क्षमता और चिकित्सा उपयोगिता के आधार पर चार अनुसूचियों में वर्गीकृत किया।

साइकोट्रोपिक पदार्थों पर सम्मेलन (1971):

- इस सम्मेलन ने उत्तेजक पदार्थों, अवसादकों और मतिभ्रम जैसे मनोदैहिक पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय दवा नियंत्रण को बढ़ाया।
- इसने इन पदार्थों के उत्पादन, व्यापार और उपयोग पर नियंत्रण भी स्थापित किया।

नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1988):

- इस सम्मेलन का उद्देश्य नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित अपराध से निपटना था।
- इसने धन शोधन, संपत्ति जब्ती और नशीली दवाओं के अपराधियों के प्रत्यर्पण को रोकने के उपाय पेश किए।

4. भारत में नशीली ड्रग्स की लत से निपटने के उपाय

- **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS), 1985:** यह किसी व्यक्ति को किसी भी मादक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक पदार्थ का उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन, भंडारण और/या उपभोग करने से रोकता है।

5. नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और सम्मेलन

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) नारकोटिक ड्रग्स पर कन्वेंशन (1961)
- संयुक्त राष्ट्र साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन (1971)
- संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ कन्वेंशन (1988)
- संयुक्त राष्ट्र ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम (यूएनटीओसी) 2000 के खिलाफ कन्वेंशन।

- **नशीली ड्रग्स की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2018:** यह निवारक शिक्षा, जागरूकता पैदा करने, पहचान, परामर्श, उपचार और पुनर्वास पर केंद्रित है।
- **नशीली ड्रग्स के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष:** यह अवैध तस्करी से निपटने, नशीली ड्रग्स और पदार्थों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, नशे की लत की पहचान करने, उनका इलाज करने और पुनर्वास करने के लिए किए गए उपायों में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए बनाया गया है।
- **नशा मुक्त भारत अभियान, 2020:** इसे मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे से निपटने और भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था।

ब्रेन बूस्टर

पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (आरएलवी)

चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (आरएलवी) 'पुष्पक' का तीसरा और अंतिम पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान लैंडिंग प्रयोग (आरएलवी लेक्स) आयोजित किया।

1. आरएलवी लेक्स के बारे में

- आरएलवी लेक्स-03 मिशन कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज (एटीआर) में आयोजित किया गया था।
- यान को भारतीय वायु सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किमी की ऊंचाई पर छोड़ा गया था।
- यान 320 किमी/घंटा से अधिक की गति से उतरा।
- मिशन का उद्देश्य एक पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान विकसित करना है जो अंतरिक्ष तक पहुँचने की लागत को कम कर सके।

2. पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के बारे में

- इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को अंतरिक्ष यान के रूप में विकसित किया है, जिसमें उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटने की क्षमता है।
- आरएलवी को रनवे पर ऊर्ध्वाधर टेकऑफ और क्षैतिज लैंडिंग (VTHL) के लिए डिजाइन किया गया है।
- आरएलवी एक पूर्णतः पुनः प्रयोज्य सिंगल-स्टेज-टू-ऑर्बिट (SSTO) वाहन का उपयोग करता है, जिसमें X-33 उन्नत प्रौद्योगिकी प्रदर्शक, X-34 टेस्टबेड प्रौद्योगिकी प्रदर्शक और उन्नत DC-XA उड़ान प्रदर्शक जैसे कई प्रमुख तत्व शामिल हैं।
- आरएलवी को अंतरिक्ष तक कम लागत वाली पहुँच प्रदान करने और भारत को विदेशी प्रक्षेपण वाहनों पर निर्भर हुए बिना अपने स्वयं के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है।
- आरएलवी ने कई सफल परीक्षण किए हैं, जिनमें 2016 में आरएलवी-टीडी (प्रौद्योगिकी प्रदर्शक) और 2023 और 2024 में आरएलवी-लेक्स (पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान - लैंडिंग प्रयोग) शामिल हैं।
- आरएलवी से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिससे देश अपने स्वयं के उपग्रहों को लॉन्च करने और विदेशी लॉन्च वाहनों पर अपनी निर्भरता कम करने में सक्षम होगा।

3. पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का महत्व

- **अंतरिक्ष प्रक्षेपण लागत को कम करना:** प्रक्षेपण यान का पुनः उपयोग करके, अंतरिक्ष में पेलोड लॉन्च करने की लागत को काफी कम किया जा सकता है।
- **प्रक्षेपण आवृत्ति बढ़ाना:** RLV अधिक बार पेलोड लॉन्च कर सकते हैं, जिससे वे उपग्रह समूहों और अन्य उच्च-मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं।
- **विश्वसनीयता बढ़ाना:** RLV को अनावश्यक प्रणालियों के साथ डिजाइन किया जा सकता है, जिससे समग्र विश्वसनीयता में सुधार होता है और प्रक्षेपण विफलताओं के जोखिम को कम किया जा सकता है।
- **संधारणीय अंतरिक्ष अन्वेषण का समर्थन:** पुनः प्रयोज्यता संधारणीयता के सिद्धांतों के साथ संरेखित होती है, अपशिष्ट को कम करती है और अंतरिक्ष अन्वेषण के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती है।
- **नए व्यवसाय मॉडल को सक्षम करना:** पुनः प्रयोज्यता उपग्रह सेवा, अंतरिक्ष पर्यटन और अन्य वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए अवसर खोलती है।
- **अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत करना:** RLV किसी देश की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण और विकास में रणनीतिक लाभ मिलता है।

4. इसरो के बारे में

- **मिशन:** भारत और मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना
- **मुख्यालय:** बेंगलुरु
- **स्थापना वर्ष:** 1969
- **पूर्ववर्ती:** भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR)
- **मूल संगठन:** अंतरिक्ष विभाग (DOS), भारत सरकार
- **उद्देश्य:** विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग करना

ब्रेन बूस्टर

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 जारी की गई है, जिसमें 146 देशों में जेंडर समानता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। यह रिपोर्ट का 17वां संस्करण है।

1. रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- 2024 में वैश्विक लैंगिक अंतर स्कोर 68.5% है, जो पिछले वर्ष से मात्र 0.1 प्रतिशत अंक बेहतर है।
- पूर्ण लैंगिक समानता तक पहुँचने में 134 वर्ष लगेंगे, जो 2030 के लक्ष्य से पाँच पीढ़ियों के बराबर है।
- 97% अर्थव्यवस्थाओं ने लैंगिक अंतर को 60% से अधिक कम कर दिया है, जो 2006 में 85% था।
- 146 देशों में से, 50.1% अर्थव्यवस्थाओं ने अपने स्कोर में वृद्धि की सूचना दी, जबकि 43.8% ने नकारात्मक परिवर्तन की सूचना दी।
- शीर्ष 10 देश आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, निकारागुआ, जर्मनी, नामीबिया, आयरलैंड और स्पेन हैं।
- हालाँकि किसी भी देश ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है, लेकिन शीर्ष नौ देशों ने अपने अंतर को 80% तक कम कर दिया है।
- वैश्विक स्वास्थ्य और उत्तरजीविता लिंग अंतर को 96%, शिक्षा में 94.9%, आर्थिक भागीदारी में 60.5% और राजनीतिक सशक्तिकरण में 22.5% तक पाटा गया है।
- आर्थिक भागीदारी और अवसर पैरामीटर 60.5% पर अब तक के अपने उच्चतम लिंग समानता स्कोर पर पहुंच गया है।
- राजनीतिक सशक्तिकरण उपसूचकांक पिछले वर्ष से लगभग कोई प्रगति नहीं दिखाता है, जिसका स्कोर 22.8% है।
- वैश्विक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 42% है और वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर उनकी हिस्सेदारी केवल 31.7% है।

2. भारत के संबंध में निष्कर्ष

- ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत 146 देशों में से 129वें स्थान पर है।
- देश का कुल जेंडर गैप स्कोर 64.1% है।

3. चारों सूचकांकों में भारत का प्रदर्शन

- **स्वास्थ्य और जीवन रक्षा:** इस सूचकांक में भारत दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है, जिसकी रैंकिंग 146 है।
- **आर्थिक भागीदारी और अवसर:** भारत 39.8% स्कोर के साथ 146 में से 143वें स्थान पर है।
- **शैक्षिक प्राप्ति:** भारत 107वें स्थान पर है।
- **राजनीतिक सशक्तिकरण:** भारत 48वें स्थान पर है।

4. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में

- ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है जो दुनिया भर के विभिन्न देशों में लैंगिक अंतर को मापती है।
- रिपोर्ट चार मुख्य क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर का आकलन करती है:
  - **स्वास्थ्य और जीवन रक्षा:** जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और जन्म के समय लिंग अनुपात।
  - **शैक्षिक प्राप्ति:** शिक्षा तक पहुँच, साक्षरता दर और स्कूलों में लैंगिक समानता।
  - **आर्थिक भागीदारी और अवसर:** श्रम शक्ति में भागीदारी, आय और कार्यबल में लैंगिक समानता।
  - **राजनीतिक सशक्तिकरण:** राजनीति, सरकार और निर्णय लेने वाले पदों में प्रतिनिधित्व।
- रिपोर्ट प्रत्येक देश के लिए एक स्कोर प्रदान करती है, जो 0 (पूर्ण असमानता) से लेकर 1 (पूर्ण समानता) तक होता है।
- फिर स्कोर का उपयोग देशों को उनके लैंगिक अंतर के आधार पर रैंक करने के लिए किया जाता है।

छोटे विकासशील द्वीप राज्यों पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

छोटे विकासशील द्वीप राज्यों पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (SIDS4) सेंट जॉन्स, एंटीगुआ और बारबुडा में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS) को टिकाऊ, जलवायु-लचीली अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के निर्माण में सहायता करना था।

थीम: 'लचीली समृद्धि की ओर मार्ग तैयार करना'

1. परिणाम

- 'एस.आई.डी.एस. के लिए एंटीगुआ और बारबुडा एजेंडा: लचीली समृद्धि के लिए एक नवीनीकृत घोषणा' को अपनाया गया।
- विश्व नेताओं ने अगले 10 वर्षों में एस.आई.डी.एस. को उनकी प्राथमिकताओं को प्राप्त करने में सहायता करने का वचन दिया।

2. अन्य प्रतिबद्धता

- एंटीगुआ और बारबुडा ने एस.आई.डी.एस. और ऋण स्थिरता सहायता सेवा के लिए उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक जलवायु वित्त को पिछले स्तर से चौगुना बढ़ाकर 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की।
- यूरोपीय संघ ने अपनी वैश्विक गेटवे निवेश रणनीति के माध्यम से सतत विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए 2027 तक सार्वजनिक और निजी निवेश में 300 बिलियन यूरो जुटाने का वचन दिया, जिसमें एस.आई.डी.एस. में कई पहल चल रही हैं।
- बारबाडोस ने सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यू.एन.आई.डी.ओ.)-बारबाडोस ग्लोबल एस.आई.डी.एस. हब के शुभारंभ की घोषणा की।
- यूएनडीपी ने यूएनईपी के साथ मिलकर शुरू किए गए 135 मिलियन डॉलर के नए ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की घोषणा की।
- ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 2030 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रबंधन करने के लिए अपना '50बाई30' विजन प्रस्तुत किया और फंड के प्रयासों को उन संस्थाओं के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए प्रस्तुत किया, जिनके साथ वह सहयोग करता है, ताकि देश महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकें।

3. प्रतिभागी

- राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख।
- संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और नागरिक समाज के प्रतिनिधि।

4. मुख्य बिंदु

- SIDS को जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 और ऋण सहित कई संकटों का सामना करना पड़ रहा है।
- महामारी ने SIDS को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, खासकर पर्यटन पर निर्भर लोगों को।
- जलवायु कार्रवाई तत्काल आवश्यक है, क्योंकि मौसम संबंधी आपदाएँ दो दशकों में दोगुनी हो गई हैं।
- SIDS जलवायु परिवर्तन के लिए कमजोर और कम जिम्मेदार हैं।
- SDG- और प्रकृति-सकारात्मक व्यवसायों के लिए वित्तपोषण अंतर को पाटने के लिए मिश्रित वित्त की आवश्यकता है।
- 39 देश और क्षेत्र हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर SIDS के रूप में मान्यता दी गई है।

5. छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) के लिए पहल

- **लचीले द्वीप राज्यों के लिए बुनियादी ढांचा (आईआरआईएस):** 2021 में भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य छोटे द्वीप देशों के बुनियादी ढांचे का विकास करना है।
- **आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई):** इस पहल का उद्देश्य छोटे द्वीप विकासशील राज्यों में क्षमता निर्माण और पायलट परियोजनाओं का संचालन करना है।

ब्रेन बूस्टर

लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव

चर्चा में क्यों?

भाजपा नेता ओम बिरला को 18वें सत्र के लिए लोकसभा का अध्यक्ष फिर से चुना गया। बिरला ने ध्वनि मत के दौरान इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के. सुरेश के खिलाफ जीत हासिल की। वे राजस्थान के कोटा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सांसद के रूप में कार्यरत हैं।

1. अध्यक्ष से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 93:** लोक सभा जल्द से जल्द सदन के दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी।
- **अनुच्छेद 94:** अध्यक्ष को सदन का सदस्य होना चाहिए। अध्यक्ष के चुनाव के लिए किसी सदस्य के लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
- अध्यक्ष लोकसभा के पूरे जीवनकाल तक पद पर बने रहते हैं, जब तक कि वे उपसभापति को लिखित रूप से इस्तीफा नहीं दे देते, लोकसभा के सदस्य नहीं रह जाते या सभी लोकसभा सदस्यों के बहुमत से स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा बर्खास्त नहीं हो जाते।
- अध्यक्ष बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन जब सदन अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा हो, तो वे अध्यक्षता नहीं करेंगे।
- कोरम के अभाव में अध्यक्ष को सदन स्थगित करने या सत्र स्थगित करने का अधिकार होता है।

2. स्पीकर की शक्तियाँ

- **पीठासीन अधिकारी:** स्पीकर सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है और व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखता है।
- **नियमों की व्याख्या:** स्पीकर सदन में प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के नियमों की व्याख्या करता है।
- **विशेषाधिकार के मामलों पर निर्णय लेना:** स्पीकर सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित मामलों पर निर्णय लेता है।
- **प्रस्तावों पर निर्णय करना:** स्पीकर सदस्यों द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करता है।
- **प्रश्न पूछना:** स्पीकर निर्णय के लिए सदन के समक्ष प्रश्न रखता है।
- **वोट डालना:** बराबरी की स्थिति में स्पीकर वोट डाल सकता है।
- **व्यवस्था बनाए रखना:** स्पीकर सदन में व्यवस्था बनाए रखता है और अनियंत्रित व्यवहार के लिए सदस्यों को दंडित कर सकता है।
- **समितियों की नियुक्ति:** स्पीकर समितियों के सदस्यों की नियुक्ति करता है और उनके अध्यक्षों को नामित करता है।
- **विधेयकों पर हस्ताक्षर करना:** स्पीकर सदन द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है, इससे पहले कि उन्हें राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाए।
- **सदन का प्रतिनिधित्व करना:** अध्यक्ष विभिन्न मामलों में सदन का प्रतिनिधित्व करता है और सुनिश्चित करता है कि इसकी गरिमा और प्रतिष्ठा बनी रहे।
- **कार्य संचालन:** अध्यक्ष सदन के कार्य का निर्णय लेता है और विभिन्न मदों के लिए समय आवंटित करता है।

3. मुख्य बिंदु

- **प्रथम अध्यक्ष:** गणेश वासुदेव मावलंकर (1952-1956)
- **प्रथम महिला अध्यक्ष:** मीरा कुमार (2009-2014)
- **दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले प्रथम अध्यक्ष:** एम. ए. अयंगर (1956-1962)
- **दूसरे गैर-लगातार कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले पहले अध्यक्ष:** एन. संजीव रेड्डी (1967-1969 और 1977)
- **पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम अध्यक्ष:** जी.एम.सी. बालयोगी (1998-2002)
- **सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले:** बलराम जाखड़ (1980-1989)
- **सबसे कम समय तक अध्यक्ष रहने वाले:** हुकम सिंह (1962-1967)
- **सबसे उम्रदराज अध्यक्ष:** सोमनाथ चटर्जी (2004-2009)
- **सबसे युवा अध्यक्ष:** ओम बिरला (2019-वर्तमान)

- **अनुमति देना:** अध्यक्ष सदस्यों को सार्वजनिक महत्व के मामले उठाने की अनुमति देता है। अध्यक्ष तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
- **सदस्यों को निलंबित करना:** अध्यक्ष सदन की कार्यवाही में बाधा डालने वाले सदस्यों को निलंबित कर सकता है।

ब्रेन बूस्टर

मानसून

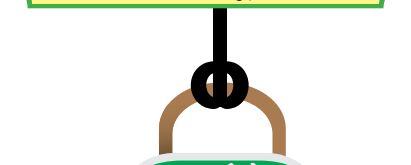

चर्चा में क्यों?

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून 1 जून की अपनी सामान्य तिथि से दो दिन पहले केरल तट पर पहुँच गया। मानसून की सुस्त गति ने भारत की वर्षा की कमी को प्रभावित किया है, जो इस जून में दीर्घावधि औसत से 19% कम हो गई है।

1. मानसून की परिभाषा

मानसून किसी क्षेत्र में प्रचलित या सबसे तेज हवाओं की दिशा में होने वाला मौसमी परिवर्तन है। मानसून के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गीले और सूखे मौसम होते हैं। मानसून को अक्सर हिंद महासागर से जोड़ा जाता है।

2. मानसून का आगमन

- भारत में वार्षिक वर्षा का 80% भाग मानसून के मौसम में होता है।
- दक्षिण-पश्चिम मानसून जून के पहले सप्ताह में शुरू होता है और सितंबर तक रहता है।
- पीछे हटने वाला मानसून या उत्तर-पूर्वी मानसून, अक्टूबर से नवंबर तक ठंडे महीनों के दौरान आता है।

3. भारत में मानसून के कारण

- भूमि और समुद्र के बीच तापमान का अंतर।
- भारतीय उपमहाद्वीप की स्थलाकृति।
- वैश्विक पवन पैटर्न।

4. भारत में मानसून के चरण

- **आरंभ:** जून में केरल में मानसून का आगमन होता है, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत को दर्शाता है।
- **प्रगति:** मानसून उत्तर की ओर बढ़ता है, जुलाई तक पूरे भारत को कवर करता है।
- **चरम:** जुलाई और अगस्त में मानसून की वर्षा सबसे अधिक होती है।
- **वापसी:** सितंबर में मानसून पीछे हटना शुरू होता है, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून के अंत को दर्शाता है।

5. भारत पर मानसून का प्रभाव

- **कृषि:** मानसून कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई फसलें मानसून की वर्षा पर निर्भर करती हैं।
- **जल संसाधन:** मानसून जलाशयों और भूजल सहित जल संसाधनों की भरपाई करता है।
- **अर्थव्यवस्था:** मानसून का भारत की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, अच्छे मानसून के मौसम से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
- **संस्कृति:** भारत में मानसून का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, जिसे विभिन्न त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।

6. क्षेत्रीय विविधताएँ

- **पूर्वोत्तर भारत:** यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, कुछ क्षेत्रों में 1,000 मिमी से भी अधिक वर्षा होती है।
- **पश्चिमी भारत:** यहाँ अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, कुछ क्षेत्रों में 500 मिमी से भी कम वर्षा होती है।
- **पूर्वी भारत:** यहाँ मध्यम वर्षा होती है।
- **दक्षिणी भारत:** यहाँ उत्तर-पूर्वी मानसून (अक्टूबर से दिसंबर) के दौरान वर्षा होती है।

7. भारतीय मानसून पर एल नीनो और ला नीना के प्रभाव

एल नीनो:

- मानसून की बारिश को कम करता है।
- सूखे और पानी की कमी की ओर ले जाता है।
- फसल की पैदावार और कृषि उत्पादकता को कम करता है।
- जंगल में आग लगने और हीटवेव की संभावना को बढ़ाता है।
- आमतौर पर कमजोर मानसून से जुड़ा होता है।

ला नीना:

- मानसून की बारिश को बढ़ाता है।
- बाढ़ और भारी बारिश की घटनाओं को बढ़ाता है।
- फसल की पैदावार और कृषि उत्पादकता को बढ़ाता है।
- जंगल में आग लगने और हीटवेव की संभावना को कम करता है।
- आमतौर पर मजबूत मानसून से जुड़ा होता है।

ब्रेन बूस्टर

आर्थिक सुधार और आर्थिक वक्र

चर्चा में क्यों?

एचएसबीसी के शोध कर्ताओं के अनुसार, आर्थिक विकास में असमान K-आकार की रिकवरी भारत में मुद्रास्फीति की गतिशीलता के लिए एक समान प्रक्षेपवक्र को बढ़ावा दे रही है, जिसमें खाद्य और ग्रामीण मूल्य वृद्धि क्रमशः अन्य वस्तुओं और सेवाओं में मुद्रास्फीति और शहरी उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली मुद्रास्फीति से आगे निकल रही है।

1. मुद्रास्फीति वक्रों के प्रकार

- **मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति:** तब होती है जब कुल मांग वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्ध आपूर्ति से अधिक हो जाती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं।
- **लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति:** उत्पादन लागत में वृद्धि, जैसे कि उच्च मजदूरी या कच्चे माल की लागत, के परिणामस्वरूप उच्च कीमतें होती हैं।
- **अंतर्निहित मुद्रास्फीति:** भविष्य में कीमतों में वृद्धि की उम्मीदें आज उच्च कीमतों की ओर ले जाती हैं, जिससे एक स्व-पूर्ति वाली भविष्यवाणी बनती है।
- **हाइपरइन्फ्लेशन:** अत्यधिक उच्च और त्वरित मुद्रास्फीति, जो अक्सर मौद्रिक नीति की गलतियों या राजनीतिक अस्थिरता के कारण होती है।
- **स्टैगफ्लेशन:** उच्च मुद्रास्फीति और स्थिर आर्थिक विकास का संयोजन, जिसके साथ अक्सर उच्च बेरोजगारी होती है।
- **रिफ्लेशन:** अपस्फीति या कम मुद्रास्फीति की अवधि के बाद मुद्रास्फीति में एक अस्थायी वृद्धि, जो अक्सर मौद्रिक नीति परिवर्तनों के कारण होती है।
- **अवस्फीति:** मुद्रास्फीति की दर में मंदी, परन्तु कीमतों में कमी नहीं।
- **अपस्फीति:** सामान्य मूल्य स्तरों में निरंतर कमी, जो अक्सर आर्थिक संकुचन का संकेत देती है।
- **K-आकार की मुद्रास्फीति:** असमान मुद्रास्फीति, जहां कुछ क्षेत्र या समूह दूसरों की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति दर का अनुभव करते हैं।

2. आर्थिक रिकवरी के प्रकार

- **V-आकार की रिकवरी:** एक तेज और मजबूत रिकवरी, जो "V" आकार की होती है, जहाँ अर्थव्यवस्था तेजी से मंदी से पहले की स्थिति में लौट आती है।
- **U-आकार की रिकवरी:** एक धीमी और अधिक क्रमिक रिकवरी, जो "U" आकार की होती है, जहाँ अर्थव्यवस्था को ठीक होने में समय लगता है।
- **W-आकार की रिकवरी:** एक डबल-डिप मंदी, जहाँ अर्थव्यवस्था थोड़े समय के सुधार के बाद दूसरी मंदी का अनुभव करती है।
- **L-आकार की रिकवरी:** एक लंबी और धीमी रिकवरी, जो "L" आकार की होती है, जहाँ अर्थव्यवस्था लंबे समय तक स्थिर रहती है।
- **K-आकार की रिकवरी:** एक रिकवरी जहाँ अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंड अलग-अलग दरों पर ठीक होते हैं, जो "K" आकार की होती है।
- **J-आकार की रिकवरी:** एक रिकवरी जहाँ अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट आती है, उसके बाद एक मजबूत और तेज रिकवरी होती है, जो "J" आकार की होती है।

3. आर्थिक वक्र के प्रकार

- **आपूर्ति वक्र:** किसी वस्तु की कीमत और आपूर्ति की गई मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है।
- **मांग वक्र:** किसी वस्तु की कीमत और मांग की गई मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है।
- **लाफर वक्र:** कर दरों और सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है।
- **फिलिप्स वक्र:** बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच व्यापार-बंद को दर्शाता है।
- **लोरेंज वक्र:** जनसंख्या में धन या आय के वितरण को दर्शाता है।
- **कुजनेट वक्र:** आर्थिक विकास और आय असमानता के बीच संबंध को दर्शाता है।
- **पर्यावरण कुजनेट वक्र:** आर्थिक विकास और पर्यावरणीय गिरावट के बीच संबंध को दर्शाता है।
- **जे-वक्र:** मुद्रा के मूल्यह्रास के बाद व्यापार संतुलन में अल्पकालिक गिरावट को दर्शाता है।
- **एस-वक्र:** धीमी प्रारंभिक वृद्धि, उसके बाद तेज वृद्धि और अंत में फिर से धीमी वृद्धि को दर्शाता है, जो अक्सर तकनीकी अपनाने में देखा जाता है।
- **गिनी गुणांक वक्र:** आय असमानता को मापता है, जिसमें 0 पूर्ण समानता को दर्शाता है और 1 पूर्ण असमानता को दर्शाता है।

ब्रेन बूस्टर

एमएसपी में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

19 जून, 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दी। पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि तिलहन और दलहन के लिए अनुशंसित की गई है।

1. एमएसपी क्या है?

- एमएसपी का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य है।
- यह वह न्यूनतम मूल्य है जो भारत सरकार किसानों को उनकी फसलों के लिए भुगतान करने की गारंटी देती है, ताकि उनके निवेश पर न्यूनतम रिटर्न सुनिश्चित हो सके और उन्हें कीमतों में किसी भी तेज गिरावट से बचाया जा सके।
- एमएसपी की घोषणा सरकार द्वारा प्रत्येक फसल मौसम की शुरुआत में की जाती है और यह कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर आधारित होती है।

2. एमएसपी की गणना

एमएसपी की गणना विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर की जाती है। जैसे:

- उत्पादन लागत
- बाजार मूल्य
- अंतर्राष्ट्रीय मूल्य
- घरेलू मांग और आपूर्ति
- किसानों का लाभ मार्जिन

3. उद्देश्य

- किसानों के लिए फसलों पर न्यूनतम रिटर्न सुनिश्चित करना।
- मूल्य में उतार-चढ़ाव के खिलाफ सुरक्षा जाल प्रदान करना।
- अनिश्चित बाजार स्थितियों में भी किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना।

4. मुख्य घटक

- **A2 (वास्तविक भुगतान की गई लागत):** इसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, ईंधन, सिंचाई, काम पर रखे गए श्रमिक और पट्टे पर दी गई भूमि शामिल है।
- **C2 (व्यापक लागत):** इसमें A2 के साथ-साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम, पूंजीगत संपत्ति और किराये का अनुमानित मूल्य और स्वामित्व वाली भूमि और पूंजीगत संपत्तियों पर छोड़ा गया ब्याज शामिल है।

5. MSP के अंतर्गत आने वाली खरीफ

- धान
- रागी
- बाजरा
- ज्वार
- मक्का
- कपास
- तूर (अरहर)
- मूंग
- उड़द
- मूंगफली
- सूरजमुखी के बीज
- सोयाबीन
- नाइजरसीड
- तिल

6. लाभ

- **आय सुरक्षा:** फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी देता है, जिससे किसानों के लिए बुनियादी आय सुनिश्चित होती है।
- **मूल्य स्थिरता:** मूल्य अस्थिरता को कम करता है, एक स्थिर बाजार वातावरण प्रदान करता है।
- **उत्पादन में वृद्धि:** किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होती है।

7. एमएसपी का दूसरा पहलू

- एमएसपी प्रणाली पहली बार 1960 के दशक में किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी देकर सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।
- कृषि एक राज्य विषय है, लेकिन मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए केंद्र सरकार इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है।
- एमएस स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) C2+50% फॉर्मूले पर आधारित होना चाहिए, जिसमें पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराया शामिल है, ताकि किसानों को उनके निवेश पर 50% रिटर्न मिल सके।

विशेष राज्य का दर्जा

चर्चा में क्यों?

केंद्र में गठबंधन सरकार बनने के बाद आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए 'विशेष राज्य का दर्जा' की मांग जोर पकड़ने की संभावना है। नई सरकार एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) के समर्थन पर निर्भर है, इसलिए एनडीए सरकार के लिए इस मांग को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा।

1. विशेष राज्य का दर्जा क्या है?

- विशेष राज्य का दर्जा (एससीएस) केंद्र द्वारा कुछ राज्यों को भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक असुविधाओं के आधार पर विकास में सहायता के लिए दिया गया वर्गीकरण है।
- यह योजना 1969 में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर शुरू की गई थी।

2. किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से पहले पाँच कारकों पर विचार किया जाता है (गाडगिल फॉर्मूला)

- पहाड़ी और कठिन इलाका।
- कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा।
- अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान।
- आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन।
- राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति।

3. कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

- वर्तमान में भारत के 11 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में एससीएस है।
- भारत के सबसे नए राज्य तेलंगाना को यह दर्जा दिया गया क्योंकि इसे दूसरे राज्य आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था।
- 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और तीन पहाड़ी राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों के लिए 'विशेष राज्य का दर्जा' खत्म कर दिया है।
- इसने ऐसे राज्यों के संसाधन अंतर को कर हस्तांतरण के माध्यम से 32% से बढ़ाकर 42% करने का सुझाव दिया।
- एससीएस विशेष दर्जे से अलग है जो बढ़े हुए विधायी और राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, जबकि एससीएस केवल आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित है।
- उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था।

4. विशेष राज्य के दर्जे को लेकर क्या चिंताएँ हैं?

- इससे केंद्रीय वित्त पर बोझ बढ़ता है।
- साथ ही, किसी राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने से दूसरे राज्यों की ओर से भी माँगें उठती हैं। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बिहार की माँगें।

5. विशेष राज्य के दर्जे के क्या लाभ हैं?

- एससीएस राज्यों को गैर-एससीएस राज्यों (30 से 50% अनुदान और 70 से 50% ऋण) की तुलना में केंद्रीय निधियों (90% अनुदान और 10% ऋण) का उच्च हिस्सा प्राप्त होता है।
- एससीएस राज्य केंद्र सरकार से रियायती ऋण और अनुदान के लिए पात्र हैं।
- एससीएस राज्यों को उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क जैसे कुछ करों का भुगतान करने से छूट दी गई है।
- एससीएस राज्यों को उद्योगों और निवेशों को आकर्षित करने के लिए निवेश सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन मिलते हैं।
- एससीएस राज्यों को केंद्र सरकार की विकास परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन में प्राथमिकता दी जाती है।
- एससीएस राज्यों को केंद्रीय योजनाओं के लिए मिलान अनुदान जैसे कुछ मानदंडों और विनियमों में छूट दी जाती है।
- एससीएस राज्य प्राकृतिक आपदाओं या अन्य संकटों के समय केंद्र सरकार से विशेष सहायता के लिए पात्र हैं।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए दो नई योजनाएँ

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री जीतन राम मांझी ने नई दिल्ली में विश्व एमएसएमई दिवस पर दो नई योजनाओं की शुरुआत की। ये योजनाएँ हैं 'एमएसएमई टीम' और यशस्विनी अभियान।

1. भारत में एमएसएमई के लिए योजनाएँ

- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में नई इकाइयाँ स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता करता है।
- **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई):** एमएसएमई को उनके द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाओं के लिए सदस्य ऋण संस्थानों को ऋण गारंटी सहायता प्रदान करता है।
- **उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी):** नए उद्यमों को बढ़ावा देता है, मौजूदा एमएसएमई की क्षमता का निर्माण करता है और देश में उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देता है।
- **एमएसएमई चौंपियंस योजनाएँ:** इसमें तीन घटक शामिल हैं- एमएसएमई-सस्टेनेबल (जेडईडी), एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (लीन) और एमएसएमई-इनोवेटिव (इनक्यूबेशन, आईपीआर, डिजाइन और डिजिटल एमएसएमई के लिए)।
- **सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी):** एमएसई के समग्र विकास के लिए उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है।
- **आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस):** बैंकों और एनबीएफसी को 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान करती है, ताकि वे कई बाजारों में भुगतान में देरी और लॉकडाउन के कारण नकदी की कमी का सामना कर रहे एमएसएमई को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित हों।

1. एमएसएमई टीम के बारे में

इस परियोजना का उद्देश्य ऑनबोर्डिंग, कैटलॉगिंग, खाता प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग डिजाइन के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करके पाँच लाख छोटे उद्यमों को डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क में शामिल होने में सहायता करना है।

2. यशस्विनी अभियान के बारे में

यह पहल महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए जागरूकता और समर्थन बढ़ाएगी। यह अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक रूप देने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और सलाह प्रदान करेगा।

3. MSME दिवस के बारे में

- अप्रैल 2017 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस के रूप में नामित किया।
- यह दिन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और नवाचार और रचनात्मकता का समर्थन करने में एमएसएमई की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
- एमएसएमई के लिए 2024 का विषय 'सतत विकास को गति देने और कई संकटों के समय में गरीबी को मिटाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की शक्ति और लचीलेपन का लाभ उठाना' है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, एमएसएमई दुनिया भर में 90% व्यवसायों, 70% रोजगार और 50% सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करते हैं।

4. भारत में एमएसएमई की परिभाषा

- **सूक्ष्म उद्यम:** निवेश सीमा 1 करोड़ रुपये से कम है, और टर्नओवर सीमा 5 करोड़ रुपये से कम है।
- **लघु उद्यम:** निवेश सीमा 1-10 करोड़ रुपये है, और टर्नओवर सीमा 1-25 करोड़ रुपये है।
- **मध्यम उद्यम:** निवेश सीमा 10-50 करोड़ रुपये है, और टर्नओवर सीमा 25-250 करोड़ रुपये है।
- एमएसएमई की यह परिभाषा 2006 के एमएसएमई अधिनियम के तहत 2020 में पेश की गई थी।

5. भारत में एमएसएमई

- एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं और देश में दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता हैं।
- भारत में लगभग 63 मिलियन एमएसएमई इकाइयाँ हैं, जिनमें से 99% से अधिक को लघु इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- एमएसएमई क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 28% से अधिक और विनिर्माण उत्पादन में लगभग 45% योगदान देता है।

ब्रेन बूस्टर

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को अगले साल 1 जनवरी से शुरू होने वाले दो साल के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सदस्य के रूप में चुना है। ये पांच देश इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विटजरलैंड की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त होगा।

1. UNSC के गैर-स्थायी सदस्यों का

- **उम्मीदवार:** सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र महासचिव को अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करते हैं।
- **क्षेत्रीय समूह:** उम्मीदवारों का चयन उनके संबंधित क्षेत्रीय समूहों (अफ्रीकी, एशियाई-प्रशांत, पूर्वी यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन, और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य) द्वारा किया जाता है।
- **गुप्त मतदान:** संयुक्त राष्ट्र महासभा गुप्त मतदान करती है।
- **आवश्यक बहुमत:** चुनाव के लिए दो-तिहाई बहुमत (193 सदस्य देशों में से 128 वोट) की आवश्यकता होती है।
- **पात्रता:** सदस्य दो वर्ष के अंतराल के बाद पुन: चुनाव के लिए पात्र होते हैं।
- **महासभा अध्यक्ष:** महासभा का अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करता है।

2. यूएनएससी के बारे में

- यूएनएससी की स्थापना 1946 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यूएन चार्टर के तहत की गई थी।
- परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य (चीन, फ्रांस, रूस, यूके, यूएस) और 10 गैर-स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।

3. यूएनएससी की शक्तियाँ

- **अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना:** यूएनएससी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने और युद्धों और संघर्षों को रोकने के लिए जिम्मेदार है।
- **प्रतिबंध लगाना:** यूएनएससी देशों या व्यक्तियों पर आर्थिक प्रतिबंध, हथियार प्रतिबंध और यात्रा प्रतिबंध लगा सकता है।
- **शांति मिशनों को अधिकृत करना:** यूएनएससी संघर्ष क्षेत्रों में शांति मिशनों को अधिकृत कर सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर निर्णय लेना:** यूएनएससी सीमा विवादों और क्षेत्रीय दावों सहित अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर निर्णय ले सकता है।
- **प्रवर्तन कार्रवाई को अधिकृत करना:** यूएनएससी सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सैन्य कार्रवाई सहित प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
- **संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चुनाव:** यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिए एक उम्मीदवार की सिफारिश महासभा में करती है।
- **नए सदस्यों को शामिल करना:** यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश के लिए नए सदस्यों की सिफारिश करती है।
- **निलंबन:** यूएनएससी अपने निर्णयों का पालन न करने पर निलंबित कर सकती है।

4. यूएनएससी और यूएन महासभा के बीच तुलना

बिंदु	यूएनएससी	यूएनजीए
उद्देश्य	अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, युद्धों और संघर्षों को रोकना।	शांति, सुरक्षा, विकास और मानवाधिकारों सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना और सिफारिशें करना।
संरचना	15 सदस्य (5 स्थायी, 10 अस्थायी)।	193 सदस्य देश (समान प्रतिनिधित्व)।
निर्णय लेना	न्यूनतम 9 वोटों (कम से कम एक स्थायी सदस्य सहित) द्वारा किए गए निर्णय।	साधारण बहुमत वोट (50% + 1) द्वारा किए गए निर्णय।
मतदान	शक्ति स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति होती है।	कोई वीटो शक्ति नहीं, सभी सदस्यों के लिए समान मतदान अधिकार।

चर्चा में रहे प्रमुख स्थल

सेनकाकू द्वीप

चीन के तटरक्षक जहाजों ने हाल ही में पूर्वी चीन सागर में जापान द्वारा नियंत्रित द्वीपों के पास के पानी में पिछले रिकॉर्ड को तोड़ कर 158 दिन बिताए हैं, जो 2021 में बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है।

सेनकाकू द्वीप के बारे में:

- पूर्वी चीन सागर में स्थित सेनकाकू द्वीप छोटे, निर्जन द्वीपों का एक समूह है। इस द्वीप समूह में पाँच निर्जन द्वीप और तीन बंजर चट्टानें हैं, जिनका आकार 800 वर्ग मीटर से लेकर 4.32 वर्ग किमी तक है।
- द्वीपों को अलग-अलग नाम दिए गए हैं ऊत्सुरी द्वीप, कुबा द्वीप, ताइशो द्वीप (जिसे कुमेकाशिमा द्वीप भी कहा जाता है), किताकोजिमा द्वीप, मिनामिकोजिमा द्वीप, टोबिस द्वीप, ओकिनोकिताइवा द्वीप और ओकिनोमिनामिवा द्वीप।
- जापान में सेनकाकू द्वीप, चीन में दियाओयू द्वीप और ताइवान में तियाओयूताई द्वीप के रूप में जाने जाने वाले इन द्वीपों की रणनीतिक स्थिति महत्वपूर्ण शिपिंग लेन और प्रचुर मात्रा में मछली पकड़ने के मैदानों के पास है।
- इसके अलावा, समुद्र तल के नीचे संभावित तेल और गैस भंडार, उनके भू-राजनीतिक महत्व को बढ़ाते हैं। इन द्वीपों पर नियंत्रण दावेदारों की सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है, जो पूर्वी एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता और व्यवस्था को आकार देता है।

पैंटानल वेटलैंड्स

ब्राजील में पैंटानल वेटलैंड्स असाधारण रूप से शुष्क मौसम के कारण असामान्य रूप से जंगली की आग का सामना कर रहे हैं।

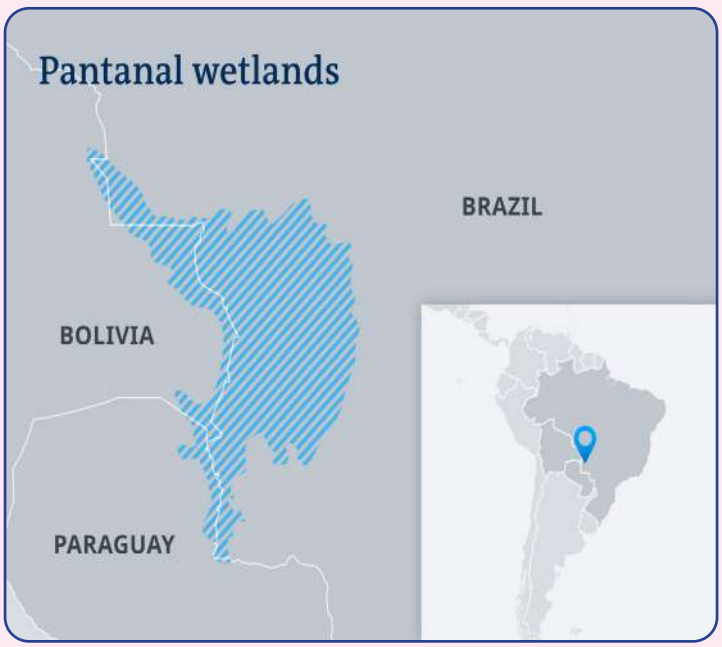

पैंटानल वेटलैंड्स के बारे में:

- पैंटानल वेटलैंड्स दक्षिण अमेरिका के केंद्र में स्थित दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वेटलैंड्स हैं। यह मुख्य रूप से ब्राजील में स्थित है, लेकिन बोलीविया और पैराग्वे तक फैला हुआ है। यह एक अनूठा और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है जिसकी विशेषता इसकी मौसमी बाढ़ है।
- अक्टूबर से मार्च तक, बाढ़ का पानी पैंटानल को एक विशाल जलाशय की तरह भर देता है और अप्रैल और सितंबर के बीच धीरे-धीरे बाहर निकल जाता है, जिससे लाखों लोगों के लिए आदर्श जलीय आवास, पोषक तत्व नवीनीकरण और बाढ़ नियंत्रण प्रदान होता है।
- इसके अतिरिक्त, पैंटानल 4,700 से अधिक पौधों और जानवरों की प्रजातियों के साथ ग्रह पर सबसे अधिक जैविक रूप से समृद्ध वातावरणों में से एक है। इसमें दक्षिण अमेरिका की कुछ वन्यजीव प्रजातियों की सबसे अधिक सांद्रता है, जिनमें जगुआर और कैमन शामिल हैं।

टोंगा

हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने अनुमान लगाया है कि टोंगा में हंगा टोंगा-हंगा हापाई (हंगा टोंगा) ज्वालामुखी के विस्फोट से शेष दशक के लिए असामान्य मौसम हो सकता है।

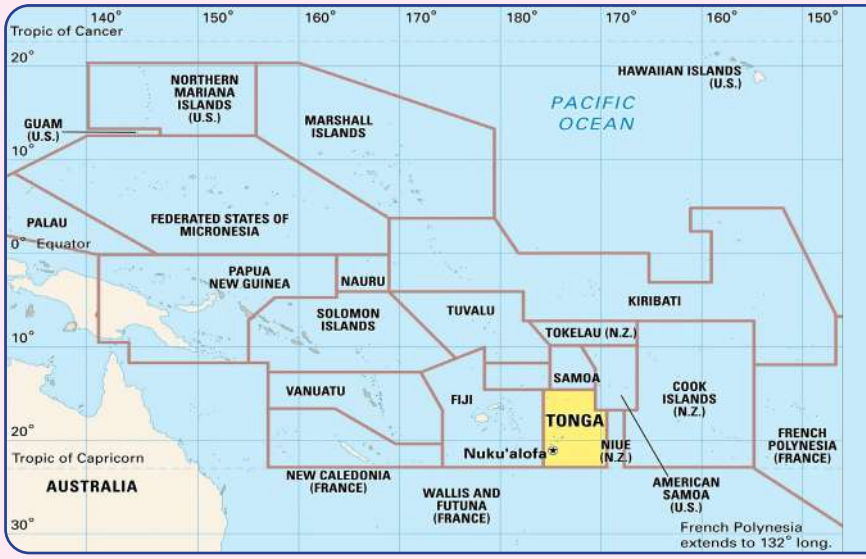

टोंगा के बारे में:

- टोंगा दक्षिण पश्चिमी प्रशांत में स्थित एक पोलिनेशियाई देश है। यह समोआ के दक्षिण में, फिजी के दक्षिण-पूर्व में और न्यूजीलैंड के उत्तर-पूर्व में स्थित है।
- भौगोलिक रूप से यह 176 द्वीपों से मिलकर बना एक द्वीपसमूह है, जिनमें से 36 पर लोग रहते हैं। इन द्वीपों को टोंगाटापु, हापाई, वावाऊ और निनस नामक चार मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है।
- टोंगा की राजधानी नुकुआलोफा टोंगाटापु के मुख्य द्वीप में स्थित है। टोंगा के पश्चिमी द्वीप ज्वालामुखीय हैं, जिनमें चार सक्रिय ज्वालामुखी समुद्र तल से काफी ऊपर हैं।

केन्या

हाल ही में वित्तीय विधेयक पारित होने के कारण केन्या की राजधानी नैरोबी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। वित्तीय विधेयक में प्रस्तावित कर वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और पानी की धार छोड़ी।

केन्या के बारे में:

- केन्या अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसकी सीमा दक्षिण-पूर्व में हिंद महासागर से लगती है।
- यह दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में युगांडा, उत्तर-पश्चिम में दक्षिण सूडान, उत्तर में इथियोपिया और पूर्व में सोमालिया के साथ भूमि सीमा साझा करता है।
- केन्या में विभिन्न भौगोलिक विशेषताएँ हैं, जिनमें ग्रेट रिफ्ट वैली, केन्याई हाइलैंड्स, मासाई मारा सवाना और हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र शामिल हैं। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर नैरोबी है।
- केन्या में विभिन्न जातीय समूहों की एक विविध आबादी है, जिसमें किकुयू, लुओ, लुह्या, मासाई और अन्य शामिल हैं।
- केन्या अपने वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है और सफारी के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है।
- मासाई मारा, अम्बोसेली और त्सावो सहित राष्ट्रीय उद्यान और रिजर्व, वनस्पतियों और जीवों की किस्मों सहित व्यापक जैव विविधता से परिपूर्ण हैं।

राज्य आधारित करेंट अफेयर्स

उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स

आई.आई.टी. कानपुर में खुलेगा स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी

हाल ही में कैबिनेट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी (आईआईटी), कानपुर में स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी (एसएमआरटी) और 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोले जाने का फैसला लिया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- आईआईटी कानपुर में स्थापित होने वाले एसएमआरटी में आंकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, काडियोवस्कुलर व थोरेसिक सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलाजी, नेफ्रोलाजी, यूरोलाजी व न्यूरोलाजी के सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे।
- इससे मेडिकल की विभिन्न विधाओं में विशेषज्ञ डाक्टर भी तैयार किए जा सकेंगे। 500 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल व एसएमआरटी के संचालन का पूरा व्यय आइआइटी कानपुर उठाएगा।
- इनके संचालन व उसके रख-रखाव के लिए गठित शासी निकाय में उप्र सरकार का एक सदस्य भी नामित किया जाएगा।
- दोनों ही प्रोजेक्ट के लिए आईआईटी के पूर्व छात्र लगातार आर्थिक मदद कर रहे हैं। यह योजना करीब 650 करोड़ रुपये की है, जिसमें पूर्व छात्रों की ओर से करीब 250 करोड़ रुपये की मदद की जा चुकी है।

उद्योग 4.0: उत्तर प्रदेश सरकार भविष्य के कार्यबल को एआई से करेगी लैस

हाल ही में उत्तर प्रदेश नोडल तकनीकी विश्वविद्यालय ने भविष्य के कार्यबल को आधुनिक उद्योग 4.0 अवधारणा के साथ जोड़ने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी प्रमुख आईबीएम के साथ समझौता किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- प्रदेश के अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU) ने 500 से अधिक सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नि:शुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए IBM के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- आईबीएम एकेटीयू नेटवर्क के तहत बीटेक स्ट्रीम के पंजीकृत छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करेगा।
- देश में उत्तर प्रदेश के पास चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इसलिए सरकार शिक्षा को इनक्यूबेटर के साथ एकीकृत करने और व्यावसायिक विचारों के लिए एंजल फंडिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है।
- वर्तमान में राज्य में 60 से अधिक इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं।

उद्योग 4.0:

- उद्योग 4.0 का तात्पर्य विनिर्माण और औद्योगिक प्रक्रियाओं में बुद्धिमान डिजिटल प्रौद्योगिकियों के एकीकरण से है। इसमें औद्योगिक IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) नेटवर्क, AI, बिग डेटा, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन जैसी प्रौद्योगिकियों का एक समूह शामिल है।

इनक्यूबेटर

- बिजनेस इनक्यूबेटर ऐसे संस्थान हैं जो उद्यमियों को उनके शुरुआती चरणों मे व्यवसाय को विकसित करने में सहायता करते हैं।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नई स्थानांतरण नीति 2024-25 को दी मंजूरी

हाल ही में नई स्थानांतरण नीति 2024-25 के तहत जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर चुके समूह क और ख के अधिकारियों का स्थानांतरण हो सकेगा। वहीं, समूह ग और घ में सबसे पुराने अधिकारियों का पहले तबादला किया जाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- समूह ग और घ में स्थानांतरण को पूरी तरह मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा। मानव संपदा की जो व्यवस्था शुरू की गई है उसके अंतर्गत स्थानांतरण के बाद कार्यभार मुक्ति और ग्रहण करने की व्यवस्था ऑनलाइन ही की जा सकेगी।
- यदि 10 प्रतिशत से ऊपर स्थानांतरण करना होगा तो इसके लिए विभाग के मंत्री की अनुमति आवश्यक होगी। वहीं, यदि समूह क और ख में 20 प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण करने की आवश्यकता होगी तो उसकी अनुमति मुख्यमंत्री से लेना आवश्यक होगा।

विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों के विस्तार में उत्तर प्रदेश देश में पहले पायदान पर

हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य के द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों के विस्तार के मामलों में देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- ❖ वित्तीय वर्ष 2024 में राज्य में कुल मिलाकर 6,993 सर्किट किलोमीटर (ckm) ट्रांसमिशन लाइनों (Transmission Lines) का विस्तार किया गया, जो कि निर्धारित लक्ष्य 11,002 सर्किट किलोमीटर (ckm) के सापेक्ष लगभग 64 प्रतिशत है।
- ❖ इस क्रम में दूसरे स्थान पर गुजरात की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत है। इस कार्य में तमिलनाडु तीसरे, आंध्र प्रदेश चौथे और बिहार पांचवें स्थान पर है।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2024 में राज्य उपयोगिता में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPTCL) ने 220 केवी या उससे ऊपर की 1,460 सर्किट किलोमीटर (ckm) ट्रांसमिशन लाइनें (Transmission Lines) विस्तारित की गई।

आईआईआईटी-ए ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में रैंकिंग हासिल की

हाल ही में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (आईआईआईटी -ए) ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में दुनिया भर में 1,401वां रैंक और समग्र श्रेणी में 46वां स्थान हासिल किया हैं।

- ❖ आईआईआईटी-ए यह वैश्विक रैंकिंग पाने वाला देश का एकमात्र आईआईआईटी हैं।
- ❖ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्वाक्वारेली सिमोंड्स द्वारा जारी किया जाता है।
- ❖ क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में इंस्टीट्यूट्स को 9 आधार पर परखा जाता है जो इस प्रकार हैं: इम्प्लॉयर रेपुटेशन, एकेडमिक रेपुटेशन, सिटेशन पर फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, इंप्लॉयमेंट आउटकम और सस्टेनबिलिटी।
- ❖ इस रैंकिंग में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडी कैटेगरी में 22 सी रैंक हासिल की है।
- ❖ रैंकिंग में इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी कैटेगरी में आईआईटी मुंबई और आईआईटी दिल्ली को संयुक्त रूप से 45वां स्थान दिया गया है।
- ❖ आर्ट एवं इम्यूनिटीज विषयों में दिल्ली यूनिवर्सिटी को 210 वां स्थान मिला है।

मुरादाबाद विश्वविद्यालय बना गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय

हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मुरादाबाद विश्वविद्यालय का नाम बदलने पर अपनी मुहर लगा दी। अब यह गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा।

- ❖ जिले के लोदीपुर विशनपुर में गुरु जम्भेश्वर (Guru Jambheshwar) का 493 साल पुराना मंदिर है। इस गांव में 90 प्रतिशत आबादी विश्नोई समाज की है। लोगों का कहना है कि 493 साल पहले विक्रमी संवत 1587 में गुरु जम्भेश्वर भगवान लोदीपुर विशनपुर में राजस्थान से आए थे।

बिहार करेंट अफेयर्स

बिहार की एकमात्र रामसर साइट कंवर झील के सामने अस्तित्व की चुनौती

हाल ही में पर्यावरणविदों ने भविष्य में कवर झील को लुप्त होने की संभावना जतायी हैं।

- ❖ कृषि कार्यों के लिए झील पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और जलाशय में पक्षियों की संख्या में भी कमी आ रही है।
- ❖ पक्षियों को आवास विनाश, आवास अतिक्रमण और बड़े पैमाने पर शिकार का सामना करना पड़ रहा है।
- ❖ कंवर जैसी आर्द्रभूमि का अपने अधिकांश हिस्सों में पानी कमी गंभीर चिंता का विषय है।
- ❖ कंवर झील के सूखने से इसके आस-पास रहने वाले हजारों मछुआरों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और कई लोगों को अन्य नौकरियों की तलाश में बाहर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

कंवर झील के बारे में:

- ❖ यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है।
- ❖ इसे कबरताल झील के नाम से भी जाना जाता है।
- ❖ यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है, जो गंगा की सहायक नदी गंडक के घुमावदार बहाव के कारण बनी है।
- ❖ यह उत्तरी बिहार में सिंधु-गंगा के मैदान के अधिकांश भाग को कवर करता है।
- ❖ यह वेटलैंड मध्य एशियाई फ्लाईवे पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां 58 प्रवासी जलीय पक्षी आराम करने और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आते हैं।
- ❖ यह मछली जैव विविधता के लिए भी एक मूल्यवान स्थल है, जहां 50 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं।

उच्च शिक्षा पर खर्च के मामले में बिहार अव्वल

केन्द्र सरकार की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है कि बिहार ने उच्च शिक्षा में सर्वाधिक खर्च किया है। केंद्र सरकार की आडिट रिपोर्ट के मुताबिक देश में उच्च शिक्षा में बेहतर काम करने वाले राज्यों की सूची में बिहार में गुणात्मक सुधार की दिशा में बेहतर कार्य हुआ है। यह

सूची उन राज्यों की है, जिन्होंने जीएसडीपी बजट का 1.75 प्रतिशत से अधिक खर्च किया है।

- केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने उच्च शिक्षा पर अपने जीएसडीपी का 2.17 प्रतिशत का वित्त व्यय किया है।
- आडिट रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तामिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य उच्च शिक्षा में खर्च करने में असफल रहे हैं।
- ये सभी ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने अपनी जीएसडीपी का एक प्रतिशत भी उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए खर्च नहीं किया है।
- बिहार में उच्च शिक्षण संस्थानों के निर्माण एवं नए आधारभूत संरचना का विकास पर हो रहे कार्यों की चर्चा भारत सरकार की हाल में प्रकाशित आडिट रिपोर्ट में गई है।
- रिपोर्ट में बिहार सरकार द्वारा शिक्षा के बजट को शीर्ष पर रखने जाने की भी चर्चा है। इससे पहले बिहार ने यह लक्ष्य पिछले 10-12 वर्षों में चार बार हासिल किया हैं।
- इससे पहले भी बिहार ने वित्तीय वर्ष 2019-20, 2014-15, 2013-14 और 2012-13 में उच्च शिक्षा पर सर्वाधिक राशि खर्च करने का लक्ष्य हासिल कर चुका है।

बिहार आरक्षण अधिसूचना रद्द

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने संबंधी अधिसूचना को रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय के द्वारा आरक्षण प्रणाली में संशोधन को रद्द करने का कारण:

- **केवल जनसंख्या आधार नहीं हो सकता:** उच्च न्यायालय ने विभिन्न आधारों पर कोटा बढ़ाने के बिहार सरकार के कदम को खारिज कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि जनसंख्या प्रतिशत इसके लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकता, योग्यता से पूरी तरह समझौता नहीं किया जा सकता और यह कदम संविधान के समानता के अधिकार के प्रावधानों का उल्लंघन है।
- **50 प्रतिशत आरक्षण सीमा पार करना:** संशोधनों ने बिहार में आरक्षण को 65% तक बढ़ा दिया, जो इंद्रा साहनी मामले (1992) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से अधिक था। न्यायालय ने कुल आरक्षण पर कानूनी प्रतिबंध के रूप में 50% की सीमा को बरकरार रखा।
- **आनुपातिक आधार का अभाव:** आरक्षण वृद्धि आनुपातिक प्रतिनिधित्व ढांचे पर आधारित नहीं थी, जो कि आरक्षण नीतियों को संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक है।
- **पर्याप्त अध्ययन का अभाव:** राज्य सरकार ने आरक्षण में वृद्धि की आवश्यकता और इसके प्रभाव को उचित ठहराने के लिए कोई गहन विश्लेषण या गहन अध्ययन नहीं किया, जिससे संशोधनों के पीछे के औचित्य पर चिंता उत्पन्न हुई।
- **न्यायिक मिसालें:** न्यायालय ने पिछले निर्णयों और संवैधानिक व्याख्याओं का हवाला दिया, जिसमें सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण पर संवैधानिक सीमाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया गया था।
- अन्य उदाहरण -महाराष्ट्र में कुल आरक्षण बढ़ाकर 68% कर दिया गया, जिसे 2021 में 50% की सीमा पार करने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया।

जलवायु-अनुकूल खेती योजना पुनः प्रारम्भ

बिहार राज्य आगामी रबी सीजन के लिए अपनी जलवायु अनुकूल कृषि योजना को पुनः शुरू करने के लिए तैयार है।

- आगामी रबी सीजन में जलवायु-अनुकूल कृषि योजना पुनः शुरू की जाएगी। जलवायु-अनुकूल कृषि कार्यक्रम 2019 में राज्य के 8 जिलों में शुरू हुआ था।
- इसके तहत प्रत्येक जिले की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर फसल चक्र निर्धारित किया जाएगा।
- उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को बढ़ावा दिया जाएगा जो प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना कर सकें।
- प्रत्येक जिले में कम से कम 20 एकड़ भूमि पर बीज उत्पादन किया जाएगा। राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से किसानों को शुद्ध बीज उपलब्ध कराया जाएगा।

चुनाव मित्र ऐप और व्हाट्सएप चैटबॉट का शुभारंभ

हाल ही में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने 'चुनाव मित्र ऐप' और व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया।

- मतदान से संबंधित विभिन्न जानकारी प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं, यह मतदान केन्द्रों के बारे में विवरण और मतदान केन्द्र तक पहुंचने के निर्देश तथा जिला नियंत्रण कक्ष एवं मतदाता हेल्पलाइन के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।

वास्तविक समय मतदाता जानकारी:

- यह ऐप उपयोगकर्ताओं को चुनाव के दिन मतदान केंद्रों पर उपस्थित मतदाताओं की संख्या के बारे में वास्तविक समय पर अपडेट प्राप्त करने की सुविधा देता है।

व्हाट्सएप चैटबॉट:

- मतदाता व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से मतदान से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बांका में सौर ऊर्जा संयंत्र

बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बांका, बिहार में चालू किया गया।

- बिहार ने बांका जिले में अवाडा ग्रुप द्वारा 50 मेगावाट का नया सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया, जिससे इसकी कुल सौर क्षमता बढ़कर 181.1 मेगावाट हो गयी।
- यह नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में तेजी लाकर भारत को 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में मदद मिलेगी तथा 2030 तक 50% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न की जा सकेगी।

बिहार पुलिस की आर्थिक एवं साइबर अपराध इकाई की रैंकिंग में सारण जिला रहा प्रथम

बिहार के साइबर पुलिस स्टेशनों का साइबर अपराध के विरुद्ध उनकी कार्रवाई के आधार पर मूल्यांकन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए मासिक रैंकिंग दी गई है।

- यह रैंकिंग प्रणाली विभिन्न कारकों पर विचार करती है, जिनमें दर्ज साइबर-संबंधित अपराधों की संख्या, गिरफ्तारियां और पीड़ितों को जारी की गई धनराशि शामिल हैं।
- अप्रैल माह की रैंकिंग में सारण जिला शीर्ष स्थान पर रहा, उसके बाद औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सहरसा जैसे जिले रहे।
- साइबर अपराधों से निपटने में सुपौल, शिवहर, नवादा, किशनगंज और खगड़िया का प्रदर्शन सबसे खराब रहा।

पटना महिला कॉलेज को मिला NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग

पटना महिला कॉलेज NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज बन गया है।

कॉलेज ने NAAC मूल्यांकन में 3.51 का प्रभावशाली समग्र CGPA प्राप्त किया।

- पटना महिला कॉलेज की स्थापना 1940 में बिशप बीजे सुलिवन एसजे, पटना के बिशप और मदर एम. जोसेफिन एसी सुपीरियर जनरल ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा की गई थी।
- यह बिहार में महिलाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया उच्च शिक्षा का पहला संस्थान था।

एनएएसी के बारे में:

- राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) भारत में एक सरकारी संगठन है जो उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन करता है।
- यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित एक स्वायत्त निकाय है।
- मुख्यालय: बैंगलोर

राजस्थान राज्य करेंट अफेयर्स

सरिस्का टाइगर रिजर्व: सुप्रीम कोर्ट ने खदानें बंद करने का आदेश दिया

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास खनन की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है।

- सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने क्रिटिकल टाइगर रिजर्व के एक किलोमीटर के दायरे में सभी गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश किया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 15 मई को राजस्थान सरकार को सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित 68 खदानों को बंद करने के लिए कहा।
- यह निर्णय बाघों के महत्वपूर्ण आवास से अवैध खनन को दूर रखने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है, जो 1990 के दशक से एक समस्या रही है।

सरिस्का बाघ अभयारण्य के बारे में:

- सरिस्का बाघ अभयारण्य अरावली पहाड़ियों में स्थित है और राजस्थान के अलवर जिले का एक हिस्सा है।
- सरिस्का को 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया तथा बाद में 1978 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया गया, जिससे यह भारत की प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन गया।
- सरिस्का बाघों के अलावा कई जानवरों का घर है, जिनमें तेंदुए, सांभर और चीतल शामिल हैं।यह रिजर्व लगभग 800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

राजस्थान में बनेगा महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट

हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 100 करोड़ रुपये के निवेश के साथ महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट का विकास किया जाएगा। यह घोषणा 8 जून 2023 को की गई थी।

- इस परियोजना के तहत, राजस्थान पर्यटन विकास निगम संग्रहालय की स्थापना करेगा, पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा और इन महत्वपूर्ण स्थानों के लिए सुधार कार्य करेगा
- महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट का उद्देश्य मेवाड़ के महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े स्थानों को विकसित करके क्षेत्र की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। इसमें शामिल है: उदयपुर, चावंड, हल्दीघाटी, गोगुन्दा, कुंभलगढ़, देवर,

चपली, चित्तौड़गढ़।

महाराणा प्रताप सिंह:

- प्रताप सिंह, जिन्हें महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के राजा थे, जो वर्तमान राजस्थान राज्य का एक क्षेत्र है।
- वह उदय सिंह द्वितीय (उदयपुर शहर के संस्थापक) के सबसे बड़े पुत्र थे।
- **हल्दीघाटी का युद्ध:** यह 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप की सेना और अम्बर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल बादशाह अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। मुगलों की जीत हुई, लेकिन प्रताप को पकड़ने में असफल रहे, जो बच निकले।
- **पुनरुत्थान:** बंगाल और बिहार में विद्रोह के बाद 1579 के बाद मेवाड़ पर मुगल दबाव कम हो गया। स्थिति का लाभ उठाते हुए, प्रताप ने कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंडा सहित पश्चिमी मेवाड़ को पुन: प्राप्त कर लिया। इस अवधि के दौरान, उन्होंने आधुनिक डूंगरपुर के पास एक नई राजधानी, चावंड का निर्माण भी किया।

राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल का निधन

- हाल ही में राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल का 15 मई 2024 को जयपुर, राजस्थान में निधन हो गया।
- वह 97 वर्ष की थीं। अपने लंबे राजनीतिक करियर के दौरान कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रहीं कमला बेनीवाल ने कई संवैधानिक पदों पर काम किया।
- 1954 में 27 साल की उम्र में उन्हें मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया। इस तरह वे राजस्थान में मंत्री बनने वाली पहली महिला बनीं। बाद में उन्होंने राज्य में विभिन्न कांग्रेस सरकारों में मंत्री के रूप में विभिन्न विभागों को संभाला।

कोटा में छात्राओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरा मान शुरू

- हाल ही में कोटा की पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन बताया कि कोटा शहर में अध्यनरत छात्राओं की समस्याओं एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन 'मेरा मान' चलाया जा रहा हैं।
- इसके तहत छात्राओं को सुरक्षा की विभिन्न तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी। हर परिस्थिति में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा।
- इसके लिए शुक्रवार को कोचिंग छात्राओं को उनके क्षेत्र में प्रतिदिन ड्यूटी में तैनात रहने वाली अभया टीम से परिचय करवाया गया

मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत की

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 जून को राज्य की राजधानी भोपाल के राजा भोज से अंतरराष्ट्रीय हवाई होटल से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराज्यीय हवाई सेवा की शुरुआत की। जिसे 'पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा' कहा जा रहा हैं।

- इसकी पहली उड़ान को राजधानी भोपाल से जबलपुर के लिए हरी झंडी दिखाई गई। यह सेवा मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड (एमपीटीबी) द्वारा दो विमान के साथ संचालित की जा रही है, जो राज्य के आठ शहरों- भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, उज्जैन, रीवा और सिंगरौली को जोड़ेगी।
- मध्य प्रदेश पर्यटन ने मेसर्स जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में पीपीपी मोड के तहत राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'पीएम श्री पर्यटन एयर सेवा' की शुरुआत की।
- ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा के लिए, एक फ्लाईओला वेबसाइट विकसित की गई है और इसे मंत्रालय में एक बैठक आयोजित करके लॉन्च किया गया है।
- हवाई सेवा को बढ़ावा देने के लिए 30 दिनों के लिए किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है. मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड (MPTB) हवाई सेवा का संचालन करेगा।
- इसे मेसर्स जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (फ्लायोला) के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर चलाया जा रहा है।
- 30 दिनों के लिए 50 प्रतिशत की छूट के बाद अंतर-राज्यीय सेवा का किराया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के किराए से थोड़ा अधिक होगा। तथा हवाई सेवा के जरिए भोपाल से इंदौर पहुंचने में मात्र 55 मिनट लगेंगे।

मंत्री अपने वेतन और भत्तों पर कर का भुगतान स्वयं करें: कैबिनेट निर्णय

- मध्य प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि राज्य के मंत्रियों को मंत्री के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते पर आयकर का भुगतान मंत्री खुद स्वयं करेंगे। राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में पेश किये गये इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गयी।
- 1972 में, मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत देय कर

का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और व्यक्तिगत मंत्रियों पर कोई बोझ नहीं होगा।

❖ राज्य सरकार ने यह फैसला आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत लिया था। इस तरह 52 साल बाद राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।

छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स

सेल-भिलाई छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करेगा

हाल ही में छत्तीसगढ़ में स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की एक प्रमुख इकाई, भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) राज्य की प्रमुख फ्लोटिंग सोलर परियोजना का उद्घाटन करने के लिए तैयार है। यह उद्यम छत्तीसगढ़ की अक्षय ऊर्जा की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करता है

मुख्य बिंदु:

❖ बीएसपी की अगुआई में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी परियोजना में दुर्ग जिले में स्थित विशाल मरोदा-1 जलाशय में 15 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा। 2.1 वर्ग किलोमीटर में फैला यह जलाशय 19 क्यूबिक मिलीमीटर (एमएम3) की जल भंडारण क्षमता के साथ न केवल प्लांट की पानी की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि आस-पास की टाउनशिप को भी सहारा देता है।

❖ फ्लोटिंग सोलर प्लांट से सालाना लगभग 34.26 मिलियन यूनिट ग्रीन पावर उत्पन्न होने का अनुमान है। इस अक्षय ऊर्जा का उपयोग भिलाई स्टील प्लांट द्वारा कैप्टिव पावर के रूप में किया जाएगा, जो इसके स्थिरता लक्ष्यों में प्रभावी रूप से योगदान देगा।

❖ इस परियोजना से भिलाई स्टील प्लांट के CO_2 उत्सर्जन में सालाना 28,330 टन की कमी आने की उम्मीद है।

नक्सलियों से मांगा गया पुनर्वास नीति के लिए सुझाव

हाल ही में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने पर नई पुनर्वास नीति के सुझाव मांगे हैं।

❖ इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में नक्सलवाद को समाप्त करना चाहती है तथा माओवादियों के पुनर्वास को सुनिश्चित कर राज्य को स्थिरता प्रदान करना चाहती है।

❖ माओवादियों का संकट राज्य से खत्म करने के लिए एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम नियद नेल्लानार योजना है। नक्सलियों से सुझाव मांगने का प्रयास इसी योजना के अंतर्गत लगाया गया है।

नियद नेल्ला नार योजना:

❖ नियद नेल्ला नार एक नवीनतम सरकारी विकास योजना है। यह योजना आदिवासियों के विकास से जुड़ी हुई है। नियद नेल्ला नार योजना का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है।

❖ इस योजना को शुरू करने की घोषणा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 15 फरवरी 2024 को विधानसभा सत्र के बजट सत्र दौरान की गई।

❖ इस योजना बस्तर के आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित है। सरकार का ऐसा कहना है कि बस्तर के धुर नक्सली क्षेत्रों में बंदूक का मुकाबला विकास क्रांति से होगा।

❖ इस योजना के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के गांवों का विकास किया जाएगा। यह योजना बस्तर में लागू की जाएगी।

❖ इस योजना के तहत पीएम आवास योजना, राशन, चना, नमक, हैंडपंप, बैंक सखी, एटीएम, मोबाइल टावर, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर आदि का लाभ दिया जाएगा।

नियद नेल्ला नार का अर्थ:

❖ 'नियद नेल्ला नार-Niyad Nella Nar' का अर्थ होता है 'आपका अच्छा गांव-Your Happy Village' यह वाक्य छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में बोली जाने वाली बोलियों से लिया गया है। यहाँ पर नार का अर्थ गाँव से है।

नियद नेल्ला नार का उद्देश्य:

❖ इस विकास योजना के द्वारा बस्तर में रहने वाले आदिवासियों को कई नवीनतम मूलभूत सुविधाएँ पहुँचायी जाएँगी। बस्तर अंचल में नक्सलियों का प्रभाव होने के कारण वहाँ सरकारी योजनाओं को लागू करने में छत्तीसगढ़ सरकार को कई तरह ही चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता रहा है।

❖ संक्षिप्त रूप में कहें तो, इस योजना के द्वारा राज्य सरकार आदिवासियों को भवन बनाकर देगी। बिजली की मुफ्त सुविधा भी होगी। बैंक की शाखाएँ खोली जाएँगी तथा जगह-जगह एटीएम भी खोले जाएँगे।

उत्तराखंड करेंट अफेयर्स

जोशीमठ तथा कोसियाकुटोली का नाम परिवर्तित

हाल ही में उत्तराखंड सरकार के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर

ज्योतिर्मठ और कोसियाकुटोली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम तहसील करने के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी मिल गई है।

नाम बदलने के पीछे तर्क:

- **धार्मिक पर्यटन:** नाम बदलने से इन क्षेत्रों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ेगा, जिससे धार्मिक पर्यटन के लिए प्रमुख गंतव्य के रूप में उत्तराखंड की स्थिति और मजबूत होगी।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** जोशीमठ और कोसियाकुटोली ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व रखते हैं, जो देश भर से और विदेशों से तीर्थयात्रियों और भक्तों को आकर्षित करते हैं।

ज्योतिर्मठ का महत्व:

- **आदि शंकराचार्य की विरासत:** आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार प्रमुख मठों में से एक, ज्योतिर्मठ, आध्यात्मिक ज्ञान और अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रसार का प्रतीक है।
- **दिव्य संबंध:** 'ज्योतिर्मठ' नाम आदि शंकराचार्य द्वारा अमर कल्पवृक्ष के नीचे तपस्या के दौरान प्राप्त ज्ञान के दिव्य प्रकाश से निकला है, जो गहन आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है।

ज्योतिर्मठ से जोशीमठ तक परिवर्तन:

- **भाषाई विकास:** समय के साथ, प्राचीन नाम 'ज्योतिर्मठ' धीरे-धीरे बोलचाल की भाषा में 'जोशीमठ' में परिवर्तित हो गया, जो किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना के बजाय भाषाई और सांस्कृतिक विकास को दर्शाता है।
- **परिवर्तन की हालिया मांगें:** मूल नाम को बहाल करने की निवासियों की मांग ने जोर पकड़ा, जिसके कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले वर्ष परिवर्तन की घोषणा की।

कोसियाकुटोली का परिवर्तन:

- **नाम परिवर्तन का औचित्य:** कोसियाकुटोली का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम तहसील करने से इसकी पहचान नीम करोली बाबा के कैंची धाम आश्रम से जुड़ जाएगी, जिससे मान्यता और श्रद्धा बढ़ेगी।
- **भौगोलिक महत्व:** 'कोसियाकुटोली' का नाम कोसी नदी से लिया गया है, जो इस क्षेत्र के पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व पर जोर देता है।

उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने का फैसला किया है। सरकार ने राजस्व गांवों को नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत लाने की घोषणा की है।

- मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, उत्तराखंड के 1,800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब राज्य पुलिस द्वारा संभाली जाएगी।
- उत्तराखंड प्रदेश में राजस्व पुलिस की व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 1861 में हुई थी। जिसके तहत पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार से लेकर मंडलायुक्त तक को राजस्व कार्य के साथ ही पुलिस के कार्य की जिम्मेदारी निभानी होती थी।
- इस व्यवस्था में एक बड़ा रोल पटवारी का रहता है। जिसके पास अपराधियों से टकराव के लिए आधुनिक हथियार नहीं है, महज एक डंडा रहता है।
- भारतीय कानून के अनुसार अस्त्र-शस्त्र केवल नियमित पुलिस को धारण करने का अधिकार है। राजस्व पुलिस को यह सुविधा नहीं मिलती। जिस कारण इस पुलिस कोट उत्तराखंड में गांधी पुलिस के नाम से भी जाना जाता है।

उत्तराखंड में खगोल पर्यटन के लिए नक्षत्र सभा का शुभारंभ

हाल ही में खगोल-पर्यटन कंपनी, स्टारस्केप्स और उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (UTDB) मिलकर नक्षत्र सभा नामक एक खगोल-पर्यटन अभियान शुरू करने जा रहे हैं।

- जून 2024 की शुरुआत में जॉर्ज एवरेस्ट, मसूरी में शुरू होने वाला यह अभियान 2025 के मध्य तक चलेगा, जिसमें पूरे राज्य में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- इस अभियान में कई गतिविधियां शामिल होंगी, जिनमें तारों को देखना, विशेष सौर अवलोकन, खगोल फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं, तारों के नीचे कैम्पिंग करना आदि शामिल हैं।
- इन कार्यक्रमों में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल और चमोली जैसे जिलों में संभावित रात्रि आकाश स्थलों का पता लगाया जाएगा, साथ ही क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा सेमिनार और वेबिनार का आयोजन किया जाएगा।
- खगोल पर्यटन न केवल खगोल विज्ञान और पर्यटन में रुचि रखने वाले स्थानीय उद्यमियों के लिए कौशल विकास के अवसर प्रदान करेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा।

झारखण्ड करेंट अफेयर्स

झारखण्ड सरकार करेगी रुपये 2 लाख तक का कर्ज माफ

हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा बजट में यह प्रावधान पारित किया है कि उन किसानों का भी ऋण माफ किया जाए जिन्होंने 2 लाख रुपए का ऋण ले रखा है। इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य ऐसे

किसानों का ऋण माफ करना है जो ऋण चुकाने में असमर्थ है।

- झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार ने 1.91 लाख से अधिक किसानों को राहत देने के प्रयास के तहत 2 लाख रुपये तक के एग्री लोन माफ करने का फैसला किया है।

झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना का उद्देश्य:

- झारखंड कृषि माफी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी कृषि करने वाले ऐसे किसान को ऋण के बोझ से राहत देना है जो ऋण को चुकाने में असमर्थ हैं।
- इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना है तथा नई फसल ऋण प्राप्ति को सुनिश्चित करके कृषक समुदाय के पलायन को से रोकना है इस योजना के माध्यम से झारखंड सरकार का प्राथमिक उद्देश्य कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है।

भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च

- कोयला मंत्रालय ने झारखण्ड के जामतारा जिले में कास्ता कोयला ब्लाक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरु की।
- ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के तत्वावधान में इस पहल का उद्देश्य कोयले को इन-सीटू गैसीकरण के माध्यम से मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित करके कोयला उद्योग में क्रांति लाना है।
- यह पायलट पहल कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है, जो भारत को अत्याधुनिक कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सबसे आगे रखती है।
- दिसंबर 2015 में, कोयला मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट से समृद्ध क्षेत्रों में यूसीजी(भूमिगत कोयला गैसीकरण) के लिए एक व्यापक नीति ढांचे को मंजूरी दी।

हरियाणा करेंट अफेयर्स

हरियाणा की नई आबकारी नीति

हाल ही में हरियाणा कैबिनेट ने वर्ष 2024-25 के लिये एक नई आबकारी नीति को अपनी मंजूरी दे दी। नई नीति में भारत में निर्मित विदेशी शराब और देशी शराब पर उत्पाद शुल्क में मामूली वृद्धि होगी।

- वर्ष 2024-25 के लिए आईएमएफएल का अधिकतम मूल कोटा 700 लाख प्रूफ लीटर (मापन इकाई) और देशी शराब के लिए 1,200 लाख प्रूफ लीटर होगा।
- आईएमएफएल और देशी शराब के लिए 2023-24 में शुरू की गई क्यूआर कोड-आधारित ट्रैक और ट्रेस प्रणाली को आयातित विदेशी शराब तक भी बढ़ाया जाएगा।
- नई नीति में खुदरा विक्रेताओं की अधिकतम संख्या वही रहेगी। ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड या परिवार पहचान पत्र, पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों के आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा और उसकी न्यूनतम निवल संपत्ति 60 लाख रुपये होनी चाहिए।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू

- हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित 10,000 करोड़ रुपये की परियोजना जल्द ही शुरू करेगी।
- जिसका पहला चरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले जिलों में लागू किया जाएगा और बाद में पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा।
- प्रारंभिक चरण में हरियाणा की वायु गुणवत्ता निगरानी अवसंरचना में वृद्धि शामिल है। इसमें एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना और चार मौजूदा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण शामिल है। इसके अतिरिक्त, परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी।

किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा समाप्त

- हरियाणा सरकार ने कृषि कार्य के दौरान मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में किसानों और कृषि श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना पर आयु सीमा हटा दी।
- अब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को भी योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। पहले इस योजना के तहत पीड़ित की आयु 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए थी
- इस योजना के अंतर्गत किसानों, खेतीहर मजदूरों, मार्केट यार्ड में काम करने वाले मजदूरों को कृषि मशीनरी पर कार्य करने के दौरान मृत्यु या अंगहानि होने पर 37,500 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पावर पैक्ड न्यूज

आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर

हाल ही में, पूर्वी अफ्रीका के जिबूती में मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित (GMO) मच्छर छोड़े गए।

आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों के बारे में:

- आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों को रोग फैलाने वाले मच्छरों की प्रजातियों की वृद्धि को नियंत्रित करके मलेरिया, डेंगू बुखार, जीका वायरस आदि जैसे वेक्टर जनित रोगों से निपटने के लिए तैयार किया गया है।
- इन मच्छरों को आनुवंशिक संशोधनों को शामिल करके बनाया गया है जो या तो बीमारियों को फैलाने की उनकी क्षमता को कम करते हैं या उनकी जनसंख्या वृद्धि को बाधित कर देते हैं।
- इन मच्छरों को विशेष रूप से एडीज एजिप्टी और एनोफेलीज स्टेफेंसी जैसी बीमारी फैलाने वाली मच्छर प्रजातियों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य जीवों को होने वाली क्षति को कम से कम किया जाता है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हान्स)

हाल ही में, बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हान्स) को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा वर्ष 2024 के लिए नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य संवर्धन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हान्स) के बारे में:

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हान्स) एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करता है।
- इसकी स्थापना 1974 में बेंगलुरु, कर्नाटक में मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्रों में विशेष देखभाल और अनुसंधान की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी।
- 2012 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया था।
- यह संस्थान मानसिक स्वास्थ्य, न्यूरोलॉजी, मनोरोग, मनोविज्ञान और संबद्ध विषयों के क्षेत्रों में व्यापक देखभाल प्रदान करने, अत्याधुनिक अनुसंधान करने और शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करने में विशिष्ट है।
- इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है।

नेल्सन मंडेला पुरस्कार:

- नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य संवर्धन पुरस्कार की स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा 2019 में की गई थी।
- यह पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों, संस्थानों, सरकारी या गैर-सरकारी संगठनों को सम्मानित करता है।

सुनकोसी नदी की सफाई के लिए सराहनीय पहल

नेपाल के बागमती प्रांत में सुनकोसी नदी को साफ करने के लिए हाल ही में एक सराहनीय पहल की गई थी। "PLEASE (प्लास्टिक मुक्त नदियाँ और दक्षिण एशिया के समुद्र)" कार्यक्रम के तहत, गोलांजोर ग्रामीण नगर पालिका में प्रोजेक्ट CAP (नदियों में प्लास्टिक रिसाव को रोकने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण) द्वारा आयोजित इस नदी सफाई अभियान में 134 लोगों ने भाग लिया।

सुनकोसी नदी के बारे में:

- सुनकोसी नदी नेपाल में स्थित कोसी नदी (बिहार का शोक) की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है।
- यह चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से निकलती है और नेपाल में हिमालय से होकर बहती है।
- यह अपने व्हाइट-वाटर राफ्टिंग अवसरों के लिए जानी जाती है और नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है।
- इस नदी को दूध कोसी, लिखू खोला, तामाकोशी और इंद्रावती जैसी विभिन्न सहायक नदियाँ समृद्ध करती हैं।
- भारत ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 के तहत 1 जुलाई 2022 से एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है।

ओगे जनजाति

हाल ही में अंडमान द्वीप समूह की ओगे जनजाति ने राजा टोटोको और रानी प्रिया के घर एक बच्चे के जन्म का उत्सव मनाया, जिससे जनजाति

की कुल आबादी बढ़कर 136 हो गई।

ओगे जनजाति के बारे में:

- ओगे एक स्वदेशी अंडमानी जातीय समूह है और भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है।
- वे पारंपरिक रूप से शिकारी-संग्राहक और मछुआरे हैं, लेकिन पौधों की खेती भी करते हैं।
- वे नेग्रिटो नस्लीय समूह का हिस्सा हैं, जिसे अफ्रीका से बाहर निकलने वाले शुरुआती प्रवास का अवशेष माना जाता है।
- वे खुद को एन-इरेगेल कहते हैं, जिसका अर्थ है 'संपूर्ण व्यक्ति'।
- यह जनजाति दुनिया के सबसे कम उत्पादक और बांझ समुदायों में से एक है।
- ओगे अर्ध-खानाबदोश हैं और लिटिल अंडमान, उत्तर-पूर्व में डुगोंग क्रीक और साउथ बे पर दो आरक्षित शिविरों में रहते हैं।
- 1940 के दशक तक, वे गौबलम्बाबे (लिटिल अंडमान के लिए ओगे नाम) के एकमात्र स्थायी निवासी थे।

स्टिकी मुद्रास्फीति

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा में स्टिकी मुद्रास्फीति के बारे में चिंताओं के कारण लगातार आठवीं बार रेपो दर को स्थिर रखा।

स्टिकी मुद्रास्फीति के बारे में:

- स्टिकी मुद्रास्फीति उस स्थिति को संदर्भित करती है, जहाँ मुद्रास्फीति की दरें लंबे समय तक लगातार उच्च बनी रहती हैं।
- यह मुद्रास्फीति मजदूरी-मूल्य सर्पिल, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और व्यवसायों तथा उपभोक्ताओं के बीच उच्च मुद्रास्फीति की लगातार अपेक्षाओं के कारण होती है।
- यह क्रय शक्ति को कम करती है, व्यवसाय नियोजन में अनिश्चितता उत्पन्न करती है और केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरें बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे उधार लेने की लागत के साथ आर्थिक विकास प्रभावित होता है।
- केंद्रीय बैंकों को नीतिगत देरी के कारण ब्याज दर समायोजन के माध्यम से स्टिकी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है, जिससे मुद्रास्फीति पर मौद्रिक नीति उपायों के प्रभावों को देखने में देरी होती है।
- स्थिर मुद्रास्फीति के उदाहरणों में 1970 के दशक की मुद्रास्फीति शामिल है, जिसमें स्थिर आर्थिक विकास और उच्च बेरोजगारी के साथ उच्च मुद्रास्फीति की विशेषता थी और हाल के रुझान जहां विभिन्न वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और बढ़ी हुई मांग के कारण महामारी के बाद लंबे समय तक मुद्रास्फीति के दबाव का सामना कर रही हैं।

राजीव तारानाथ

- हाल ही में 11 जून 2024 को भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और सरोदवादक राजीव तारानाथ की मृत्यु हुई।
- राजीव तारानाथ, एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और सरोदवादक थे, उनका जन्म बैंगलोर, कर्नाटक में हुआ था।
- उन्होंने संस्कार, कंचना सीता और कदावु सहित कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कन्नड़ फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया।
- उन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स के विश्व संगीत विभाग में भारतीय संगीत कार्यक्रम के प्रमुख के रूप में कार्य किया।
- उन्हें 2019 में पद्म श्री पुरस्कार मिला।
- उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राज्य संगीत विद्वान पुरस्कार, चौधिया पुरस्कार, कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अटलांटिक ब्लूफिन टूना

ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया, जिसमें पता चला कि गर्म होते समुद्र के कारण अटलांटिक ब्लूफिन टूना उत्तर की ओर पलायन कर रही है।

अटलांटिक ब्लूफिन टूना के बारे में:

- अटलांटिक ब्लूफिन टूना (थुन्नस थायनस) उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली एक बड़ी, प्रवासी मछली है।
- यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो स्क्विड और छोटी मछलियों जैसी शिकार प्रजातियों की आबादी को नियंत्रित करती है।

- ब्लूफिन की तीन प्रजातियाँ हैं: अटलांटिक (सबसे बड़ी और सबसे अधिक लुप्तप्राय), प्रशांत और दक्षिणी।
- यह व्यावसायिक रूप से सबसे मूल्यवान मछली प्रजातियों में से एक है, जो जापान में सुशी और साशिमी बाजारों में अपने उच्च गुणवत्ता वाले मांस के लिए मूल्यवान है।
- अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण इसकी आबादी वैश्विक स्तर पर गंभीर रूप से कम हो गई है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रयास और मछली पकड़ने के कोटा बढ़ गए हैं।
- वे अटलांटिक महासागर में व्यापक प्रवास करते हैं, भूमध्य सागर सहित भोजन और अंडे देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हैं।
- ICCAT (अटलांटिक ट्यूना के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग) जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकाय मछली पकड़ने के कोटा को विनियमित करते हैं और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए आबादी की निगरानी करते हैं।
- इसे IUCN रेड लिस्ट में 'सबसे कम चिंता' ("Least Concern") के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

ई-माइग्रेट पोर्टल

हाल ही में, विदेश मंत्रालय (एमईए) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ई-माइग्रेट पोर्टल पर डिजिटल भुगतान सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

ई-माइग्रेट पोर्टल के बारे में:

- ई-माइग्रेट पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारतीय श्रमिकों के लिए उत्प्रवास प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और ऑनलाइन बनाने में मदद करता है।
- इसे प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय (एमओआईए) द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया था।
- पोर्टल ईसीएनआर (उत्प्रवास जांच आवश्यक नहीं) श्रेणी के पासपोर्ट वाले प्रवासियों को विदेश में रोजगार के लिए स्वेच्छा से पंजीकरण करने की अनुमति देता है।
- यह विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा ब्लू-कॉलर श्रमिकों की मदद करने के लिए एक पहल है जो उन देशों में काम करना चाहते हैं जहां उत्प्रवास जांच (ईसीआर) की आवश्यकता होती है।
- इसका लक्ष्य उत्प्रवास प्रक्रिया को ऑनलाइन, आसान और सुरक्षित बनाना और प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।
- यह प्रवासन प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर और विदेशी नियोक्ताओं, पंजीकृत भर्ती एजेंटों और बीमा कंपनियों को जोड़ने वाला एक साझा मंच बनाकर ऐसा करता है।
- यह नागरिकों को पंजीकरण, दस्तावेज प्रबंधन और सेवा बुकिंग सहायता प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के साथ एकीकृत होता है।

धारीदार सीसिलिवन

हाल ही में एक रैपिड हर्पेटोफौना सर्वेक्षण के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में पहली बार एक अंगहीन उभयचर (धारीदार सीसिलियन) दर्ज किया गया।

धारीदार सीसिलिवन के बारे में:

- धारीदार सीसिलियन (इचथियोफिस एसपीपी) एक अंगहीन उभयचर है।
- 'सीसिलियन' नाम लैटिन शब्द कैकस से आया है, जिसका अर्थ है 'अंधा'।
- भारत का पश्चिमी घाट सीसिलियन के लिए एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जिसमें भारत में वर्णित 39 प्रजातियों में से 26 इस क्षेत्र के लिए स्थानिक हैं।
- सीसिलियन एक सामान्य शिकारी है जो मिट्टी के अकशेरुकी जैसे केंचुआ, चींटियाँ, दीमक और बीटल प्यूपा खाता है।
- यह पत्ती के ह्यूमस और अन्य पौधों के टुकड़े भी खाता है।
- यह मिट्टी के नीचे बिल बनाता है काजीरंगा की परिधि पर बाढ़ के मैदानों, आर्द्रभूमि, घास के मैदानों और पहाड़ी इलाकों जैसे विविध पारिस्थितिक तंत्रों में पाया जाता है।
- इसमें टेंटेकल्स, बुलेट के आकार की खोपड़ी और जबड़े को बंद करने वाली मांसपेशियों के दो सेट जैसी अनूठी विशेषताएं हैं। कुछ सीसिलियन प्रजातियाँ बिना आँखों वाली होती हैं, जबकि अन्य की त्वचा के नीचे छोटी आँखें छिपी होती हैं।

हल्ला टॉमसडॉटिर आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनीं

- 2 जून को आइसलैंड की बिजनेसवुमन हल्ला टॉमसडॉटिर ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। वे राष्ट्रपति गुनी जोहानसन की जगह लेंगी और 1 अगस्त को पदभार संभालेंगी।
- हल्ला टॉमसडॉटिर एक प्रसिद्ध व्यवसायी हैं जिन्हें पर्यटन, मत्स्य पालन और खुदरा क्षेत्र में अनुभव है। वह आइसलैंड की 7वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्सडॉटिर को हराया।
- हल्ला, विग्दिस फिनबोगाडॉटिर के बाद आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। विग्दिस फिनबोगाडॉटिर 1980 में आइसलैंड की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं थीं।
- उन्होंने अपने अभियान में जलवायु परिवर्तन से निपटने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और आइसलैंड के लोकतंत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया।
- टॉमसडॉटिर को पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों के लिए एक मजबूत वकील के रूप में जाना जाता है।
- राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, लेकिन इसकी भूमिका काफी हद तक प्रतीकात्मक होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल चार साल का होता है।
- राष्ट्रपति सरकार के गठन, कानूनों को मंजूरी देने और अंतरराष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करने जैसी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

क्लॉडिया शेनबॉम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गयी

- 2 जून को मैक्सिको में हुए आम चुनाव में सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी की क्लॉडिया शेनबॉम ने जीत हासिल की। मैक्सिको के 200 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब कोई महिला देश की राष्ट्रपति बनेगी।
- क्लॉडिया मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर रह चुकी हैं और लंबे समय से वामपंथी राजनीति से जुड़ी हुई हैं। विपक्षी शोचिल गालवेज दक्षिणपंथी नेशनल एक्शन पार्टी (PAN) से चुनाव लड़ीं। मैक्सिको ने पड़ोसी देश अमेरिका से पहले महिला राष्ट्रपति चुनकर इतिहास रच दिया।
- उनकी जीत महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है और यह दर्शाती है कि लैटिन अमेरिका में महिलाएं अब राजनीतिक नेतृत्व में सबसे आगे आ रही हैं।
- क्लॉडिया शेनबॉम के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमें अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, अपराध कम करना और भ्रष्टाचार से लड़ना शामिल है।
- अमेरिका में 1920 में ही महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिल गए थे, जबकि मैक्सिको में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1953 में मिला था।

जापान एयरलाइंस और इंडिगो ने एक महत्वपूर्ण कोडशेयर समझौते पर किए हस्ताक्षर

- 3 जून 2024 को जापान एयरलाइंस (JAL) और इंडिगो ने एक महत्त्वपूर्ण कोडशेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- इस समझौते के तहत, JAL अपनी कोड (JL) इंडिगो द्वारा संचालित 14 भारतीय शहरों (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि, अहमदाबाद, गोवा, पुणे, लखनऊ, वाराणसी, पटना, गया और त्रिवेंद्रम) के लिए उड़ानों पर लगाएगी।
- यह समझौता JAL को भारत में अपनी पहुंच का विस्तार करने और घरेलू बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद करेगा।
- इंडिगो के लिए, यह समझौता अंतरराष्ट्रीय यात्रियों तक पहुंच प्रदान करेगा और वैश्विक बाजार में इसकी उपस्थिति को बढ़ाएगा।

समझौते के मुख्य लाभ:

- भारत और जापान के बीच हवाई संपर्क में वृद्धि
- दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा
- ग्राहकों के लिए अधिक गंतव्यों तक पहुंच
- JAL और इंडिगो दोनों के लिए अधिक राजस्व
- यह समझौता भारत और जापान के बीच संबंधों को मजबूत करने में भी मदद करेगा।

राकेश मोहन जोशी की IIFT के कुलपति के रूप में नियुक्ति

राकेश मोहन जोशी को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले, वे IIFT के डीन और बेंगलुरु के भारतीय वाणिज्यिक प्रबंधन संस्थान के निदेशक थे।

- उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, IIFT, राजस्थान विश्वविद्यालय और करनाल के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से शिक्षा प्राप्त की है।
- जोशी ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, UNCTAD, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, और एशियाई उत्पादकता संगठन जैसे बहुपक्षीय संगठनों के साथ काम किया है।
- उन्होंने IIFT को विश्व स्तरीय बिजनेस स्कूल बनाने और भारत को वैश्विक व्यापार में एक ग्लोबल पावरहाउस बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

भारत और पेरू के मध्य यूपीआई को लेकर समझौता

- नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पेरू के सेंट्रल रिजर्व बैंक (BPRP) के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत NPCI पेरू में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को विकसित करेगा।
- पेरू, यूपीआई को अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है। इस पहल से पेरू में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पेमेंट नेटवर्क स्थापित होगा।
- यूपीआई के माध्यम से पेरू के उपयोगकर्ता तुरंत भुगतान कर सकेंगे, क्योंकि यह प्रणाली रियल टाइम में फंड ट्रांसफर की सुविधा देती है।
- सिंगापुर, मलेशिया, UAE, फ्रांस, नेपाल, ब्रिटेन, मॉरीशस, और श्रीलंका में पहले से ही यूपीआई सक्रिय है। यूपीआई को भारत सरकार ने 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया था।

आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर अपरिवर्तित

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 7 जून, 2024 को अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को लगातार आठवीं बार 6.5% पर अपरिवर्तित रखा।
- यह निर्णय वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता, मुद्रास्फीति के दबाव और घरेलू विकास की गति को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।
- आरबीआई ने अप्रैल 2024 में 4.8% रही हेडलाइन मुद्रास्फीति के लिए अपनी वृद्धि अनुमान को मार्च 2025 के अंत तक 5.7% तक बढ़ा दिया है। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है।
- मौद्रिक नीति एक जटिल उपकरण है जिसका अर्थव्यवस्था पर कई तरह का प्रभाव पड़ सकता है।

सुनील छेत्री ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से लिया संन्यास

- हाल ही में भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री ने 6 जून 2024 को कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप 2026 क्वालीफायर मैच के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया।
- यह भारतीय फुटबॉल के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। छेत्री 19 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और उन्होंने इस दौरान कई रिकॉर्ड बनाए हैं।
- छेत्री ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 151 मैचों में 94 गोल किए हैं।
- छेत्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा गोल करने वाले चौथे खिलाड़ी है। वह केवल क्रिस्टियानो रोनाल्डो (130 गोल), अली डेई (109 गोल) और लियोनेल मेसी (108 गोल) से पीछे हैं।
- छेत्री भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी है। इन्होंने भारत के लिए 150 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। वह इस रिकॉर्ड में बाईचुंग भूटिया (104 मैच) से आगे हैं।
- छेत्री सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले एशियाई खिलाड़ी भी है।

यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 अस्थायी सदस्यों का चयन

- 6 जून को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) ने 5 अस्थायी सदस्यों का चयन किया। इन 5 अस्थायी सदस्यों में पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, और सोमालिया शामिल हैं।
- ये देश UNSC में जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, और स्विटजरलैंड की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होगा। इस वोटिंग में, 193 सदस्यीय UNSC ने गुप्त मतदान के जरिए 5 देशों को चयनित किया।

- ये अस्थायी सदस्य 2025 से 2026 तक UNSC के सबसे बड़े सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य बनेंगे। वोटिंग में सोमालिया को अफ्रीकी और एशिया-प्रशांतीय देशों के लिए 179 वोट मिले, पाकिस्तान को 182 वोट मिले। पनामा को 183 वोट मिले, डेनमार्क को 184 वोट और ग्रीस को 182 वोट मिले।
- UNSC में कुल 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें 5 स्थायी (परमानेंट) और 10 अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और चीन शामिल हैं। 10 अस्थायी सदस्यों को 2 साल के लिए UNSC में चुना जाता है।

भारतीय सेना के नए सेना प्रमुख

- हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति हुई है। उन्होंने मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की जगह ली है।
- वे पूर्व में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर कार्यरत थे और इससे पहले भी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवा कर चुके हैं।
- लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने अपने करियर में सोमालिया हेडक्वार्टर्स UNOSOM II में भी सेवा की थी और सेशेल्स सरकार के सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य किया था।
- उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और AWC, महू में उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों में भी भाग लिया है। उन्हें सशस्त्र सेवा में 40 वर्ष का अनुभव है। उन्होंने भारतीय सेना के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अपने अद्वितीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।

भारत को हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी

- स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन (FIH) ने हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 के मेजबान देश के रूप में भारत को चुना है।
- भारत इससे पहले तीन बार 2013 में दिल्ली, 2016 में लखनऊ और 2021 में भुवनेश्वर में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है।
- इस बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार 24 टीमें शामिल होंगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत दिसंबर 2024 से होगी।
- पिछले हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन मलेशिया में हुआ था, जिसे जर्मनी ने जीता था।

पेमा खांडू बने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री

- हाल ही में पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रमुख नेता हैं और पहले भी इस पद पर रह चुके हैं। खांडू का जन्म 21 अगस्त 1979 को हुआ था और वे दिवंगत मुख्यमंत्री दोर्जी खांडू के पुत्र हैं।
- 2016 में, उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला था, जब नबाम तुकी ने पद से इस्तीफा दिया था। उनके नेतृत्व में, राज्य ने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार शामिल हैं।
- खांडू की राजनीतिक यात्रा 2011 में उनके पिता के निधन के बाद शुरू हुई। वे अपने क्षेत्र से विधायक बने और विभिन्न मंत्रालयों में कार्य किया। उनके कार्यकाल में शांति और स्थिरता बनी रही, जिससे राज्य में निवेशकों का विश्वास बढ़ा।
- वे एक सशक्त और दूरदर्शी नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश को विकास की नई ऊँचाइयों पर पहुंचाया है।

अजीत डोभाल पुनः नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त

- हाल ही में अजीत डोभाल को केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (NSA) के रूप में नियुक्त किया। यह उनकी तीसरी NSA नियुक्ति है।
- अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। वे 1968 बैच के IPS अधिकारी हैं और उन्होंने 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में शामिल होकर अपना करियर शुरू किया।
- उन्हें 1988 में वीरता के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था।
- अजीत डोभाल, भारतीय पुलिस पदक पाने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी है।

मियावाकी वृक्षारोपण

- राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित आवरण से परिपूर्ण करने के लक्ष्य को साकार करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्गों से सटे भूखंडों पर मियावाकी वृक्षारोपण करने की एक अनूठी पहल करेगा।
- मियावाकी वृक्षारोपण के लिए दिल्ली-एनसीआर में और उसके आसपास विभिन्न स्थानों पर कुल 53 एकड़ से अधिक भूमि क्षेत्र की पहचान की गई है।
- मियावाकी वृक्षारोपण को मियावाकी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। जापान का यह अनूठा दृष्टिकोण पारिस्थितिकी बहाली और वनीकरण विकास की पद्धति है। इस पद्धति का उद्देश्य कम समय में घने, देशी और जैव विविधता वाले वनों का निर्माण करना है।
- ये वन भूजल को बनाए रखते हैं और भूजल स्तर को रिचार्ज करने में मदद करते हैं। इस पद्धति से पेड़ दस गुना तेजी से बढ़ते हैं और वृक्षारोपण ध्वनि और धूल अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं।
- मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को सफल रूप से लागू करने के लिए, स्थानीय जलवायु और मिट्टी की स्थितियों में जीवित रहने वाले पौधों की स्वदेशी प्रजातियों के रोपण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

रामोजी राव

हाल ही में ईटीवी नेटवर्क के प्रमुख और हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

रामोजी राव के बारे में:

- चेरुकुरी रामोजी राव का जन्म 16 नवंबर, 1936 को आंध्र प्रदेश के पेडापरुपुडी में एक किसान परिवार में हुआ था। 10 अगस्त, 1974 को उन्होंने विशाखापत्तनम में तेलुगु दैनिक अखबार ईनाडु की स्थापना की। अखबार ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और चार साल के भीतर एक प्रमुख प्रकाशन बन गया।
- राव ने दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी की भी स्थापना की और टेलीविजन चैनलों के ईटीवी नेटवर्क का नेतृत्व किया।
- इसके अतिरिक्त, उन्होंने मार्गदर्शी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया।
- 2016 में, श्री राव को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने

- हाल ही में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। उन्होंने राज्य के इतिहास में सबसे अधिक बार पद संभालने का रिकॉर्ड बनाया है। जनसेना प्रमुख और अभिनेता पवन कल्याण ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
- 12 जून को तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के 24वें मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल अब्दुल नजीर ने विजयवाड़ा के केसरपल्ली आईटी पार्क में सीएम और मंत्रियों को शपथ दिलाई।
- आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ-साथ विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए गए।
- एनडीए ने विधानसभा की 175 में से 164 सीटें जीती हैं। इसमें नायडू की टीडीपी को 135, पवन कल्याण की जनसेना को 21 और भाजपा को 8 सीटें मिलीं।
- नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 25 सदस्य होंगे। मंत्रियों की सूची में पिछड़ा वर्ग से 8, अनुसूचित जाति से 3 और अनुसूचित जनजाति से 1 मंत्री शामिल है।
- शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एनडीए के मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे।

इबेरियन लिंक्स

दुनिया की सबसे दुर्लभ बिल्ली प्रजातियों में से एक इबेरियन लिंक्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) की लाल सूची में लुप्तप्राय की स्थिति से संवेदनशील की स्थिति में आ गई है।

इबेरियन लिंक्स के बारे में:

- इबेरियन लिंक्स यूरोप में पाई जाने वाली दो मांसाहारी प्रजातियों में से एक है (दूसरी यूरोपीय मिंक, मस्टेला लुट्रेओला है)।

- यह प्रजाति, अन्य बिल्ली प्रजातियों की तरह, यौन रूप से द्विरूपी है (एक ही प्रजाति में विभिन्न लिंग के प्राणी के बीच व्यवस्थित अंतर), जिसमें नर मादाओं की तुलना में भारी और लंबे होते हैं।
- यह लिंक्स आम तौर पर रात में सक्रिय होता है और इसकी गतिविधि पैटर्न उनके प्रमुख शिकार, खरगोश के साथ निकटता से समन्वयित होते हैं। यह प्रजाति, जो अपने नुकीले कानों, लंबे पैरों और तेंदुए की तरह धब्बेदार फर के लिए जानी जाती है, दो दशक पहले ही विलुप्त होने के कगार पर थी।
- यह अवैध शिकार, सड़क दुर्घटनाओं और बीमारी के कारण तथा लिंक्स के मुख्य शिकार जंगली खरगोशों की संख्या में नाटकीय गिरावट के कारण हुआ था जब 2002 में धब्बेदार निशाचर बिल्ली की पहली जनगणना की गई थी, तब इबेरियन प्रायद्वीप में 100 से भी कम नमूने थे।

संरक्षण स्थिति:

- IUCN लाल सूची: कमजोर
- CITES: परिशिष्ट II

मोहन चरण माझी ने ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री

- ओडिशा में पहली बार भाजपा के मोहन चरण माझी मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल रघुवरदास ने माझी को पद की शपथ दिलाई, इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे।
- 52 वर्षीय मोहन चरण माझी ने राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा, कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिदा ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
- यह चुनाव 24 साल बाद ओडिशा में एक आदिवासी मुख्यमंत्री की वापसी का प्रतीक है, इससे पहले कांग्रेस के हेमानंद बिस्वाल पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे और गिरिधर गमांग दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री थे।
- भाजपा ने पहली बार ओडिशा विधानसभा चुनाव में 147 में से 78 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। नवीन पटनायक की बीजू जनता दल (बीजेडी) ने 51 सीटें जीतीं, कांग्रेस ने 14, सीपीआई (एम) ने 1 और अन्य दलों ने 3 सीटें जीतीं।

भारत–जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास

हाल ही में भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक जापान-भारत द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास 'JIMEX 24' के 8वें संस्करण के लिए जापान के योकोसुका पहुंचा।

- इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्री दोनों चरण शामिल हैं। जापान का गाइडेड मिसाइल विध्वंसक JS युगिरी दोनों नौसेनाओं के हेलीकॉप्टरों के साथ भाग लेगा।
- 2012 में शुरू हुए 'JIMEX' अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना है।
- INS शिवालिक जैसे स्टील्थ फ्रिगेट को उन्नत जहाज कहा जाता है क्योंकि वे उच्च गति से चलने में सक्षम हैं और रडार से उनका पता लगाना मुश्किल है।

सेंसरिनुरल हियरिंग लॉस

- हाल ही में, गायिका अलका याग्निक ने सेंसरिनुरल हियरिंग लॉस (एसएनएचएल) की समस्या दर्ज की गयी। सेंसरिनुरल हियरिंग लॉस (एसएनएचएल) एक प्रकार की सुनने की दुर्बलता है जो आंतरिक कान या कान को मस्तिष्क से जोड़ने वाले तंत्रिका मार्गों को नुकसान के कारण होती है।
- एसएनएचएल वायरल संक्रमण, शोर के संपर्क में आने, उम्र बढ़ने, संक्रमण और बीमारियों और ओटोटॉक्सिक दवाओं के कारण हो सकता है।
- एसएनएचएल के लक्षणों में बात को समझने में कठिनाई, दबी हुई या विकृत आवाज, कानों में भिनभिनाहट, तेज आवाज सुनने में कठिनाई और संतुलन की समस्याएँ शामिल हैं।
- एसएनएचएल आमतौर पर स्थायी होता है और उपचार के विकल्पों में दवाएँ, कोक्लियर इम्प्लांट और श्रवण यंत्र शामिल हैं। प्रभावी उपचार के लिए एसएनएचएल का शुरुआती पता लगाना महत्वपूर्ण है।

पैराग्वे आईएसए में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया

हाल ही में पैराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में शामिल होने वाला 100वां सदस्य देश बन गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में:

- इसे 30 नवंबर, 2015 को पेरिस में कॉप 21 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन द्वारा लॉन्च किया गया, ISA एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है जिसमें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देश शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति को उत्प्रेरित करना है
- ISA का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है।

टी20 वर्ल्ड कप 2024

हाल ही में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता। टीम के कप्तान रोहित शर्मा और टीम के कोच पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी राहुल द्रविड़ थे।

आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के बारे में:

- ICC पुरुष टी20 विश्व कप द्विवार्षिक ट्वेंटी 20 अंतर्राष्ट्रीय (T20) टूर्नामेंट का नौवां संस्करण है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा आयोजित किया जाता है और पुरुषों की राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेला जाता है।
- वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सह-मेजबानी में, यह टूर्नामेंट 1 से 29 जून, 2024 तक हुआ।
- 2024 तक कुल आठ टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेले जा चुके हैं।
- केवल वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ने ही दो-दो बार टी20 विश्व कप चैंपियनशिप जीती है। अब भारत इस बेंचमार्क को हासिल करने वाला तीसरा देश बन गया है।
- इस टी20 विश्वकप के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवीन्द्र जडेजा ने टी20 क्रिकेट प्रारूप से सन्यास ले लिया है।

यूरोपीय संघ ने प्रकृति बहाली कानून पारित किया

हाल ही में यूरोपीय संघ (ईयू) की पर्यावरण परिषद ने प्रकृति बहाली कानून को मंजूरी दी है। ईयू के पर्यावरण मंत्रियों ने लाइव-स्ट्रीम सत्र के दौरान कानून के पक्ष में मतदान किया। यह कानून ईयू के सभी 27 सदस्य देशों पर लागू होगा और पर्यावरण की रक्षा के लिए इसे लागू किया गया है।

प्रकृति बहाली कानून के बारे में:

- प्रकृति बहाली कानून का उद्देश्य जंगलों को फिर से उगाना और यह सुनिश्चित करना है कि दलदलों और नदियों में पर्याप्त प्राकृतिक पानी हो। कानून में 2030 तक ईयू के कुल भूमि और समुद्री क्षेत्र का कम से कम 20% बहाल करने और 2050 तक सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- यूरोपीय संघ के 20 सदस्य देशों ने कानून के पक्ष में मतदान किया। ये देश ईयू देशों की 66% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ईयू के अनुसार, सदस्य देशों में लगभग 80% प्राकृतिक आवास और 10% मधुमक्खी और तितली प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसके अतिरिक्त, ईयू देशों में 70% मिट्टी अस्वस्थ स्थिति में बताई गई है।

पावो नूरमी खेलों में नीरज चोपड़ा ने जीता स्वर्ण

- 18 जून को विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के तुर्कू में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
- यह चैंपियनशिप पावो नूरमी स्टेडियम में हुई, जहां उन्होंने 85.97 मीटर का थ्रो किया। दूसरे थ्रो में पिछड़ने के बावजूद नीरज ने बाद में प्रतियोगिता में जोरदार वापसी की।
- टोनी केरेनन ने 84.19 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक जीता।
- ओलिवियर हेलैंडर ने 83.96 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता।
- नीरज चोपड़ा 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों में भी हिस्सा लेंगे।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बना

- विमानन विश्लेषण फर्म OAG के आंकड़ों के अनुसार, भारत ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है। भारत में अब घरेलू मार्गों पर 1.55 करोड़ यात्रियों की क्षमता है, जो एक दशक पहले 79 लाख यात्रियों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है।
- घरेलू एयरलाइनों के मामले में, अमेरिका पहले स्थान पर है, उसके बाद चीन दूसरे सबसे बड़े बाजार के रूप में है। पिछले एक दशक में, भारत ने हवाई सीटों में 6.9% की मजबूत औसत वार्षिक वृद्धि दिखाई है, जो शीर्ष 5 देशों में सबसे अधिक है। तुलनात्मक रूप से, अमेरिका में औसत 2.4% और इंडोनेशिया में इसी अवधि में औसत 1.1% की वृद्धि हुई है।
- इंडिगो 2014 से भारत में सबसे बड़ी एयरलाइन है, जिसकी घरेलू मार्गों पर सबसे अधिक वार्षिक यात्री वृद्धि दर 13.9% है। मुंबई-दिल्ली मार्ग वैश्विक स्तर पर 8वां सबसे व्यस्त मार्ग बना हुआ है, जो 6.6 लाख से अधिक सीटों की सेवा प्रदान करता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत की घरेलू एयरलाइन क्षमता 2005 से 2024 तक 8.7% की औसत वार्षिक दर से बढ़ने का अनुमान है, जब की विश्व औसत ६% है।

कोझिकोड भारत का पहला 'साहित्य का शहर' बना

- 23 जून को केरल के शासन मंत्री एमबी राजेश ने घोषणा की कि अरब सागर के तट पर स्थित कोझिकोड को यूनेस्को के प्रतिष्ठित 'साहित्य के शहर' का दर्जा दिया गया है।
- 96.8% साक्षरता दर के साथ, कोझिकोड यूनेस्को से यह मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है।
- 'कोझिकोड' नाम 'कोइल-कोटा' से लिया गया है जिसका अर्थ है 'किलेबंद महल'।
- यह शहर वार्षिक 'केरल साहित्य महोत्सव' की मेजबानी करता है और केरल में दूसरा सबसे बड़ा महोत्सव है। इसे पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था।
- मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने भी संगीत श्रेणी में यूनेस्कों के लिस्ट में जगह पाई है।

अरुंधति रॉय ने जीता 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार

- 27 जून को ब्रिटिश लाइब्रेरी ने भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार का विजेता घोषित किया। नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेरोल्ड पिंटर की याद में 2009 में स्थापित यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 10 अक्टूबर 2024 को अरुंधति रॉय को प्रदान किया जाएगा।
- 24 नवंबर 1961 को मेघालय में जन्मी अरुंधति रॉय को उस समय अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली जब उन्हें 1997 में उनके पहले उपन्यास 'द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स' के लिए बुकर पुरस्कार मिला।
- उन्हें उपन्यास के लिए एक मिलियन पाउंड (लगभग 8 करोड़ रुपये) का अग्रिम भुगतान मिला, जो मई में प्रकाशित हुआ और जून तक 18 देशों में बेस्टसेलर बन गया।

मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया

- 26 जून को, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को अगला महासचिव नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति को ब्रसेल्स में गठबंधन के मुख्यालय में नाटो राजदूतों द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसमें 32 सदस्य देश शामिल हैं।
- 14 फरवरी, 1967 को नीदरलैंड में जन्मे मार्क रूटे 2010 से नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
- वे 1 अक्टूबर, 2024 को नाटो महासचिव की भूमिका संभालने वाले हैं, जो नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री जेन्स स्टोलटेनबर्ग का स्थान लेंगे, जिन्होंने 2014 से इस पद को संभाला था।

नाटो के बारे में:

- 1949 में स्थापित नाटो, जिसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, एक सैन्य गठबंधन है जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन सहित 32 सदस्य देश शामिल हैं।
- यह गठबंधन सोवियत संघ के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया था, और यह सामूहिक रक्षा के सिद्धांत के तहत काम करता है, जिसके तहत किसी भी सदस्य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाता है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. हाल ही में चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR), कलपक्कम के नए डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने बी. वेंकटरमण की जगह ली है। इससे पहले, चंद्रशेखर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), मुंबई के रिएक्टर ग्रुप के डायरेक्टर थे।
2. ओडिशा के क्योंझर के प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार मगुनी चरण कुआंर का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2023 में उन्हें रॉड कठपुतली कला को जीवित रखने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही, 2012 में उन्हें ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2004 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
3. 3 जून को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल टैक्स में वृद्धि की घोषणा की। देशभर के सभी टोल टैक्स की दरों में औसतन 5% की बढ़ोतरी की गई है। यह वृद्धि सालाना होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) पर आधारित है, जो टोल हाईवे यूजर फीस को प्रभावित करता है। नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स की दरें थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर बढ़ाई जाती हैं।
4. गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में विजया भारती सयानी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा की जगह ली है, जो 1 जून को सेवानिवृत्त हुए थे।
5. 1 जून को लंदन के वेम्बली स्टेडियम में यूरोपियन फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, UEFA चैंपियंस लीग (UCL) का फाइनल मैच हुआ। इसमें स्पैनिश क्लब रियल मैड्रिड 15वीं बार UCL का विजेता बना। दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग 'चैंपियंस लीग' का यह 32वां सीजन है, जिसकी शुरुआत 1955-56 में हुई थी। इस टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा लेती हैं, जिन्हें 8 ग्रुप में बांटा जाता है।
6. भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर केदार जाधव ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। जाधव ने 2014 से 2020 के बीच भारत के लिए 73 वनडे और 9 टी20 मैच खेले हैं।
7. 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का पौधा लगाया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुए एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में मनाया गया था। इस साल पर्यावरण दिवस की थीम 'भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव' है। इस साल सऊदी अरब इस दिवस का वैश्विक मेजबान है।
8. स्लोवेनिया फिलीस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने वाला नया यूरोपीय देश बन गया है। इसके पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी फिलीस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। यह कदम इजरायल-फिलीस्तीनी संघर्ष के एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। स्लोवेनिया यूरोपीय संघ का 13वां ऐसा देश बन गया है जिसने फिलीस्तीन को मान्यता दी है। इससे पहले, स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी 2024 में ही फिलीस्तीन को मान्यता दी थी।
9. हाल ही में भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जिससे भारत को टूर्नामेंट में अपना पहला स्वर्ण पदक मिला। सरबजोत ने फाइनल में चीन के शूआईहांग बू को हराया। उन्होंने क्वालिफिकेशन दौर में भी 588 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था।
10. तमिलनाडु के अरक्कोणम में INS रजाली पर पासिंग आउट परेड के समारोह में सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव को हेलीकॉप्टर पायलट की ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त हुई। अनामिका बी राजीव नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। उन्हें सी किंग्स, AHL ध्रुव, चेतक, और MH-60R सीहॉक्स जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाने की परमिशन मिलेगी। इन पायलटों को नौसेना की विभिन्न फ्रंट-लाइन ऑपरेटिंग यूनिट में नियुक्ति दी जाएगी।
11. हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। अब जोशीमठ को उसके प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ से जाना जाएगा। साथ ही, नैनीताल जिले की कोश्याकुटोली तहसील का नया नाम श्रीकैंची धाम करने की भी मंजूरी दी गई है। जोशीमठ को बद्रीनाथ धाम का प्रवेशद्वार माना जाता है।
12. ऑस्ट्रेलियन स्विमर एरियन एलिजाबेथ टिटमस ने 12 जून को ऑस्ट्रेलियन ओलिंपिक ट्रायल्स में महिला 200 मीटर फ्रीस्टाइल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। टिटमस ने इस रेस को 1 मिनट 52.23 सेकंड में पूरा करके गोल्ड मेडल जीता।
13. हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) के पूर्व वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का बेंगलुरु में निधन हो गया। श्रीनिवास हेगड़े ने 1978 से 2014 तक ISRO में अपनी सेवा दी थी।
14. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2024-2027 के लिए SAARC करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क को संशोधित किया, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों को भुगतान संतुलन और तरलता संकट से निपटने के लिए बैकअप लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करना है।

15. महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व ने एक AI-सक्षम अग्नि पहचान प्रणाली शुरू की, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक चरण में जंगल की आग का पता लगाना और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान से बचाना है।
16. ओम बिरला को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा (संसद के निचले सदन) के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया।
17. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) को नवरत्न का दर्जा दिया गया, जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पदनाम है, जिन्होंने अपने प्रदर्शन में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है।
18. वैश्विक अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 जून को विश्व स्तर पर MSME दिवस के रूप में मनाया गया।
19. वित्तीय नियोजन में बीमा के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए 28 जून को भारत में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया।
20. रोहित शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल कप्तान बन गए, उन्होंने पाकिस्तान के बाबर आजम के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
21. हाल ही में बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका अरुंधति रॉय को हाशिए पर पड़े और उत्पीड़ित लोगों के संघर्षों को उजागर करने वाले उनके काम के लिए पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
22. राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है, जहाँ वे सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करेंगे।
23. विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को ब्रिटेन की बेलमार्श जेल से रिहा कर दिया गया है।
24. केरल के कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर भारत के पहले यूनेस्को 'साहित्य के शहर' के रूप में मान्यता दी गई है।
25. 2024 के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत को 146 देशों में से 129वें स्थान प्राप्त हुआ है।
26. सात बार सांसद रह चुके भर्तृहरि महताब ने 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप शपथ दिलाई गयी।
27. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया।
28. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पैट कमिंस ने टी-20 विश्व कप में दो हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बनकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।
29. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस बार की थीम 'स्वयं और समाज के लिए योग' थी।
30. विश्व स्तर पर प्रशंसित फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा प्रतिष्ठित 'नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।
31. भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 2024 पावो नूरमी खेलों में एक और स्वर्ण पदक हासिल किया।
32. 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, जिसमें दुनिया भर में स्वैच्छिक रक्तदाताओं के निस्वार्थ योगदान को मान्यता दी गई।
33. पेमा खांडू ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
34. अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है।
35. सऊदी अरब ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने 80 साल के पेट्रोडॉलर सौदे को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है। मूल रूप से 8 जून, 1974 को हस्ताक्षरित यह समझौता अमेरिकी वैश्विक आर्थिक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
36. लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है।
37. स्पेन के कार्लोस अल्काराज गार्फिया ने अपना पहला फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता।
38. पोलैंड के इगा स्विएटेक ने फ्रेंच ओपन गेम में रोलैंड गैरोस में इटली की जैस्मीन पाओलिनी को हराया।
39. सुमित नागल जर्मनी में आयोजित हीलब्रॉन नेकरकप चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में विजयी हुए, जो उनके करियर की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
40. भारत के उत्तर प्रदेश की पूजा तोमर ने अल्टीमेट फाइटिंग चौंपियनशिप (UFC) में बाउट जीतने वाली पहली भारतीय बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।
41. यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने देश में राजदूत के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के अवसर पर यूएई में पैराग्वे गणराज्य के राजदूत जोस अगुएरो अविला को स्वतंत्रता का प्रथम श्रेणी पदक प्रदान किया।
42. हाल ही में, आतंकवाद-रोधी भारत-जापान संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक हुई।
43. भारत 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) की वार्षिक सभा की मेजबानी करेगा, जो दुनिया भर में 330 से ज़्यादा एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है।

44. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने एक पूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स (AIPI) डैशबोर्ड जारी किया है।
45. मोरेना पार्टी की क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गईं।
46. पीवी सिंधु, ग्रीनडे के 'बेटर न्यूट्रिशन' की ब्रांड एंबेसडर बनीं।
47. नोकिया और गति शक्ति विश्वविद्यालय ने 5G/6G अनुसंधान पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्ति की।
48. रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए एक समर्पित टेली मानस सेल स्थापित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है।
49. गोल्डमैन सैक्स ने 2024 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया।
50. सेबी ने निवेशकों के लिए 'साथी 2.0' ऐप लॉन्च किया।
51. आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून, 2024 को मनाया गया।
52. विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 2024 को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय वास्तव में 'हमारी भूमि, हमारा भविष्य है। हम #GenerationRestoration हैं। इस दिन की स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी।
53. रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए एक समर्पित टेली मानस सेल स्थापित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है।
54. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष, एचआरआई संजय कुमार अग्रवाल ने हरियाणा के रोहतक में आधिकारिक तौर पर जीएसटी भवन का शुभारंभ किया।
55. भारत 2025 में दिल्ली में 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की मेजबानी करेगा।
56. 12 देशों ने जीरो डेब्रिस चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जो अंतरिक्ष मलबे के गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक पहल है। 2023 में अनावरण किया गया, चार्टर हस्ताक्षरकर्ताओं को 2030 तक मलबे-तटस्थ अंतरिक्ष गतिविधियों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध करता है।
57. मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर को लगातार आठवीं बार 6.5% पर अपरिवर्तित रखा गया है।
58. विश्व महासागर दिवस 8 जून, 2024 को मनाया गया।
59. भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने बायोफार्मास्युटिकल्स गठबंधन शुरू किया।
60. पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस ने जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर और स्विट्जरलैंड की जगह लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीटें हासिल कीं।
61. पूर्वी नेपाल में भारतीय सहायता से निर्मित 900 मेगावाट की अरुण III जलविद्युत परियोजना ने हाल ही में एक सुरंग निर्माण में सफलता के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।
62. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने कैमरून के पूर्व प्रधान मंत्री फिलेमोन यांग को 79वें UNGA सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना।
63. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपना तीसरा वैश्विक हैकथॉन, HaRBInger 2024 शुरू किया है।
64. डेनमार्क 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है।
65. अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (AIBEA) ने बैंक ग्राहक शिकायत निवारण के लिए बैंक सहायता नामक एक पहल शुरू की है।
66. डीपी मनु ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता।
67. अरुणाचल प्रदेश में एक विशिष्ट, नीले रंग की चींटी प्रजाति की खोज की गई।
68. विराट कोहली को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तम्बाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया।
69. दुबई की भारतीय व्यापार और व्यावसायिक परिषद ने डिजिटल भुगतान और मुद्रा निपटान तंत्र में प्रगति को उजागर करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भागीदारी की है।
70. एक भारतीय त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (ILC) के 112वें सत्र में भाग लिया।
71. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया।
72. मई 2024 में भारत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 12 महीने के निचले स्तर 4.75% पर आ गई।

मुख्य परीक्षा विशेषः इतिहास व कला एवं संस्कृति

1. भू-विरासत स्थलों और भू-अवशेषों का क्या महत्व है? भू-विरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक, 2022 का मसौदा भू-विरासत स्थलों और भू-अवशेष में पाई जाने वाली प्राकृतिक संपदा के संरक्षण में कैसे योगदान देता है?

उत्तर:

परिचय

भू-विरासत भूवैज्ञानिक विशेषताओं को संदर्भित करता है जो पृथ्वी के विकास, इतिहास और वैज्ञानिक शिक्षा में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के कारण स्वाभाविक या सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण देश में भू-विरासत स्थलों और राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों की पहचान और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार मुख्य संस्था है। भू-अवशेषों को ''भूवैज्ञानिक महत्व या रुचि की सामग्री या अवशेष, जैसे तलछट, चट्टानें, खनिज, उल्कापिंड या जीवाश्म'' के रूप में परिभाषित किया गया है। जीएसआई को संरक्षण और रखरखाव के उद्देश्यों के लिए भू-अवशेष प्राप्त करने का अधिकार है।

- **पृष्ठभूमि**
  - खान मंत्रालय के तहत 1851 में स्थापित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) देश में कोयला और अन्य खनिज संसाधनों की जांच और आकलन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर अन्वेषण करता है।
  - यह भू-विरासत स्थलों और राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों को नामित करता है और उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों हेतु राज्य सरकारों के साथ सहयोग करता है।
  - भारत में 32 भू-विरासत स्थल 13 राज्यों में वितरित हैं और जीवाश्म पार्क (जैसे, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक जीवाश्म पार्क), भूवैज्ञानिक आश्चर्य (जैसे, महाराष्ट्र में लोनार झील) और रॉक स्मारक (जैसे, कर्नाटक में राष्ट्रीय प्रायद्वीपीय शैल स्मारक) सहित विविध स्थानों को शामिल करता हैं।
- **भू-विरासत स्थलों और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक, 2022 की विशेषताएं-**
  - प्रस्तावित विधेयक केंद्र सरकार को भू-विरासत स्थल को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण घोषित करने के लिए अधिकृत करता है, जो भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR अधिनियम) के प्रावधानों के तहत काम करता है।
  - आधिकारिक राजपत्र में एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से, सरकार अधिग्रहण के अधीन क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है, जिसके सन्दर्भ में आपत्तियां दो महीने के भीतर उठाई जा सकती हैं।
  - RFCTLARR अधिनियम में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य के साथ, इस अधिनियम के तहत शक्तियों के प्रयोग के कारण नुकसान या नुकसान उठाने वाले भूस्वामियों या कब्जाधारियों को मुआवजा प्रदान किया जाता है।
  - यह विधेयक भू-विरासत स्थल क्षेत्र के भीतर किसी भी भवन के निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण पर प्रतिबंध लगाता है, जब तक कि यह संरक्षण, रखरखाव या आवश्यक सार्वजनिक कार्यों के लिए न हो।
  - भू-विरासत स्थल के भीतर जीएसआई के महानिदेशक द्वारा दिये गए किसी भी निर्देश के अवमानना, विरूपण या उल्लंघन के लिए दंड निर्दिष्ट हैं। उल्लंघन के परिणामस्वरूप छह महीने तक की कैद, 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। निरंतर उल्लंघन के मामलों में, प्रति दिन 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।

आलोचना

- ऐसे स्थलों को संरक्षित करने और विशिष्ट कानूनों को लागू करने की आवश्यकता को लंबे समय से मान्यता दी गई है, परन्तु विधेयक में उल्लिखित शक्तियों के वितरण के संबंध में चिंताएं उठाई गई हैं।
- गुंटुपल्ली वी आर प्रसाद, दिल्ली विश्वविद्यालय के जीवाश्म विज्ञानी, जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश में टाइटनोसॉरस के घोंसलों की खोज करने वाली टीम का नेतृत्व किया, ने कहा, ''जीएसआई को व्यापक अधिकार दिए गए हैं।'' ये शक्तियाँ भू-विरासत के खजाने की पहचान करने और अध्ययन करने में अन्य प्रतिभागियों के 'केंद्रीय भूमिका की अवहेलना' करती हैं, और गैर-जीएसआई शोधकर्ताओं द्वारा अनुसंधान गतिविधियों को 'प्रभावी रूप से समाप्त करने का कार्य करेगी'।
- शोधकर्ताओं को डर है कि जीएसआई का एकाधिकार लालफीताशाही को बढ़ाएगा और विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के साथ-साथ निजी संग्रहकर्ताओं के शोध की स्वायत्तता का उल्लंघन करेगा।
- इन साइटों की सुरक्षा के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण का मुद्दा (जैसा कि जीएसआई ने भूगर्भीय महत्व के स्थलों और उनके अधिग्रहण पर नियंत्रण के संबंध में अधिकार दिए हैं) संभावित रूप से स्थानीय समुदायों के साथ संघर्ष का कारण बन सकता है क्योंकि यह अधिग्रहण

के कई मामलों में देखा गया है जिसके परिणामस्वरूप सरकार के खिलाफ स्थानीय समुदाय द्वारा आंदोलन किया गया है।

निष्कर्ष

विशेषज्ञ राष्ट्रीय भू-विरासत प्राधिकरण के समान एक अधिक समावेशी निकाय की स्थापना की वकालत करते हैं, जो ''भू-ऐतिहासिक'' महत्व के स्थानों का चयन लोकतांत्रिक रूप से कर सकता है और प्रभावी संरक्षण रणनीतियों को तैयार कर सकता है।

2. चोलों के स्थानीय प्रशासन के बारे में विस्तार से बताएं जैसा कि उत्तरमेरुर शिलालेख से पता चलता है।

उत्तर:

परिचय:

भारत, जिसे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, लोकतांत्रिक शासन के इतिहास में एक प्रमुख स्थान रखता है। इसका प्रमाण तमिलनाडु के 1,100 साल पुराने उत्तरमेरुर शिलालेख में पाया जा सकता है, जो चोल वंश के दौरान स्थानीय लोकतंत्र और प्रशासन पर प्रकाश डालता है।

मुख्य भाग :

उत्तरमेरुर शिलालेख से चोलों के स्थानीय प्रशासन के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है:

- चोल साम्राज्य में दो प्रकार के गाँव शामिल थे। प्रथम वे जिनमें विविध जाति की आबादी निवास करती थी और द्वितीय जिन्हें ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जिन्हें अग्रहारा गाँव कहा जाता था।
- जाति-आधारित गाँवों को नियंत्रित करने वाली सभा को ''उर'' कहा जाता था, जबकि अग्रहारा गाँवों में एक सभा होती थी जिसे ''सभा'' या ''महासभा'' के रूप में जाना जाता था।
- अग्रहारा गांवों को काफी हद तक स्वायत्तता प्राप्त थी, उनके मामलों का प्रबंधन एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता था। शिक्षित संपत्ति मालिकों के बीच यादृच्छिक चयन या रोटेशन के माध्यम से समिति के सदस्यों का चुनाव किया गया।
- परांतक । के समय का उत्तरमेरुर शिलालेख, ग्राम परिषदों के गठन और कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।
- प्रत्येक गांव को तीस वार्डों में विभाजित किया गया था, और प्रत्येक वार्ड से सदस्यों को ग्राम परिषद बनाने के लिए नामित किया जाता था।
- वार्ड सदस्यता के लिए पात्रता मानदंड में भूमि का स्वामित्व, एक व्यक्तिगत निवास स्थान, तीस से सत्तर वर्ष के बीच की आयु और वेदों का ज्ञान शामिल था।
- सदस्यता के लिए अयोग्यताओं में पिछली समिति सदस्यता, खाते की जानकारी जमा करने में विफलता, कुकृत्यों में शामिल होना, या चोरी शामिल थे।
- चयन प्रक्रिया में ताड़ के पत्तों पर पात्र व्यक्तियों के नाम लिखना और उन्हें कुदावोलाई प्रणाली का उपयोग करके एक बर्तन से निकालना शामिल थे।
- शिलालेख में सभा के भीतर विभिन्न समितियों की रूपरेखा भी दी गई है, जिनमें से प्रत्येक के विशिष्ट कर्तव्य थे। ये समितियाँ ग्राम प्रशासन के विभिन्न दायित्तों के लिए जिम्मेदार थीं, और उनके सदस्य प्रस्तावों को पारित करने के लिए एकत्रित होते थे।
- समिति के सदस्य सेवानिवृत्त पूर्व 360 दिनों तक सेवा करते थे। गलत कामों या खातों में विसंगतियों में लिप्त लोगों को तुरंत हटा दिया जाता था और जालसाजी जैसे अपराधों में शामिल व्यक्तियों को सजा का सामना करना पड़ा, जैसे कि गधे की सवारी करना।

निष्कर्ष:

शासन के प्रति चोल प्रशासन के दृष्टिकोण ने ग्राम परिषदों और समितियों को महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान की। उत्तरमेरुर शिलालेख प्राचीन और मध्ययुगीन काल के स्थानीय विकेंद्रीकरण और प्रभावी शासन में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो भारत में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के स्वदेशी विकास को प्रदर्शित करता है।

3. भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से प्रकृति पूजा के बढ़ते महत्व पर उदाहरण देते हुए प्रकाश डाले।

परिचय:

पूरे इतिहास में भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों को आकार देने में धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न धार्मिक विश्वासों, विचारों और प्रथाओं में समय के साथ परिवर्तन और विकास हुआ है, इस संदर्भ में प्रकृति पूजा का अत्यधिक महत्व है।

मुख्य भाग :

1. **सिंधु घाटी सभ्यता:**
   - वृक्षों और पशुओं की पूजा का प्रचलन था।

- पृथ्वी को उर्वरता की देवी के रूप में देखा जाता था, यह मिस्र में नील नदी की देवी आइसिस की पूजा के समान था।
- टेराकोटा की मूर्तियाँ महिलाओं को उनके भ्रूण से उगने वाले पौधों के साथ चित्रित करती हैं, जो प्रकृति और जीवन के बीच संबंध का प्रतीक है।

2. **पूर्व वैदिक और वैदिक धर्म:**
   - लोग सूर्य और चंद्रमा जैसी प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे।
   - ऋग्वेद से इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य और रुद्र जैसे कई देवताओं में विश्वास के बारे में पता चलता है।
   - बलि चढ़ाना और अग्नि में आनुष्ठानिक प्रसाद देना आम धार्मिक प्रथाएं थीं।
   - सामवेद और यजुर्वेद में यज्ञों के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की गई है।
   - ब्राह्मणों में कर्मकांड को और विस्तृत किया गया।
3. **समकालीन समय में प्रकृति पूजा:**
   - जैन धर्म ने कीड़ों को भी महत्व दिया, छोटे जीवों को नुकसान से बचाकर अहिंसा का अभ्यास किया।
   - जानवरों ने वांछनीय विशेषताओं और प्राकृतिक चक्रों का प्रतिनिधित्व किया।
   - हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे धर्मों में कुछ जीवों के पारिस्थितिक महत्व को स्वीकार किया गया और उन्हें संस्थागत बनाया गया।
   - तुलसी, पीपल और बेल जैसे पवित्र पौधों की पूजा की जाती है।
   - पवित्र उपवन, स्थानीय समुदायों द्वारा पवित्र समझे जाने वाले संरक्षित वन क्षेत्र भारत में मौजूद हैं।
   - चिपको आंदोलन जैसे पर्यावरणीय आंदोलन और बिश्नोई संप्रदाय के बलिदान प्रकृति की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
4. **भारतीय संस्कृति और मानस से जुड़ाव:**
   - प्रकृति से गहरा जुड़ाव भारतीय जीवन शैली का अभिन्न अंग है।
   - सूर्य पूजा और तुलसी की पूजा जैसे अनुष्ठान इस संबंध को प्रदर्शित करते हैं।
   - प्रकृति-पूजा आज भी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग बनी हुई है।

निष्कर्ष:

प्रकृति पूजा भारतीय जीवन शैली और मानस में गहराई से समाई हुई है। भारतीय प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध रखते हैं, जो सुबह और शाम को सूर्य पूजा जैसे अनुष्ठानों के साथ-साथ पवित्र पौधों के प्रति सम्मान से स्पष्ट होता है। यद्यपि प्रकृति पूजा का अभ्यास समय के साथ प्रतीकात्मक रूप से विकसित हुआ है, यह भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है।

4. समानताओं को साझा करने के बावजूद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दर्शन में मूलभूत अंतर हैं जो उन्हें अलग धर्म के रूप में स्थापित करते हैं। इन दो विश्वास प्रणालियों के बीच समानताओं और असमानताओं का अन्वेषण और विश्लेषण करें।

उत्तर:

परिचय:

छठी शताब्दी ई.पू. इतिहास में एक उल्लेखनीय अवधि के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें बुद्ध, महावीर, हेराक्लिटस, जोरास्टर, कन्फ्यूशियस और लाओ त्से जैसे प्रभावशाली विचारकों की उपस्थिति देखी गई, जिन्होंने इस युग के दौरान अपने विचारों का प्रचार किया। उनमें से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे सफल के रूप में उभरे, जिन्होंने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा।

मुख्य भाग :

बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समानताएं:

धर्मों का उदय: छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धार्मिक अशांति के कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने लोकप्रियता हासिल की। बाद के वैदिक काल में जिन जटिल कर्मकांडों और बलिदानों की वकालत की गई, उन्हें आम लोगों ने स्वीकार नहीं किया।

मुख्य दर्शन: जैन धर्म त्रिरत्नों पर जोर देता है, जिसमें सही विश्वास, ज्ञान और आचरण शामिल हैं। इसी तरह, बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग को बढ़ावा देता है, जिसमें सम्यक वाणी, संकल्प, व्यवसाय और अन्य के साथ-साथ इन तीन पहलुओं को भी शामिल किया गया है।

अहिंसा: दोनों धर्म अहिंसा को जीवन के मूलभूत सिद्धांत के रूप में मानते हैं।

संघ: महावीर ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए संघ की स्थापना की, जबकि बुद्ध के दो प्रकार के अनुयायी थे- भिक्षु और उपासक। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए भिक्षुओं को संघ में संगठित किया गया था।

समानता: जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने अपने संघों में पुरुषों और महिलाओं दोनों का स्वागत किया।

बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच अंतर:

- **तपस्या और त्याग:** जैन धर्म ने आत्म-यातना, भुखमरी और नग्नता सहित तप और त्याग की प्रथाओं को चरम स्तर तक ले गये। इसके विपरीत, बौद्ध धर्म ने ऐसी चरम क्रियाओं का समर्थन नहीं किया। बौद्ध धर्म ने सामाजिक और आध्यात्मिक आचरण के हर पहलू में मध्यम मार्ग दिखाया।
- **कृषि की धारणा:** जैन धर्म कृषि को एक पापपूर्ण कार्य मानता है, क्योंकि इससे पृथ्वी, कीड़े और जानवरों को नुकसान होता है। बौद्ध ध र्म में ऐसा कोई निषेध या भेद नहीं था।
- **जाति व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण:** जबकि बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को खुले तौर पर चुनौती दी, जैन धर्म ने स्पष्ट रूप से इस पर हमला नहीं किया। हालाँकि, महावीर ने सामाजिक भेदों का विरोध किया और सभी पृष्ठभूमि के लोगों का स्वागत किया।
- **भाषा:** प्राकृत प्राथमिक भाषा थी जिसके माध्यम से जैन धर्म का प्रचार किया गया, जबकि पाली और अन्य स्थानीय भाषाओं का विकास बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से हुआ।
- **सामाजिक बनाम धार्मिक क्रांति:** बौद्ध धर्म का जोर सामाजिक सुधार, व्यावहारिक नैतिकता सिखाने और सामाजिक समानता की वकालत पर अधिक था। दूसरी ओर, जैन धर्म अपने धार्मिक संदर्भ में अधिक निहित रहा।
- **उपमहाद्वीप के बाहर फैलाव :** सम्राट अशोक के मिशनरी प्रयासों के माध्यम से, बौद्ध धर्म पश्चिम एशिया और सीलोन में फैला, जिससे यह एक स्थानीय धार्मिक संप्रदाय से, एक वैश्विक धर्म में बदल गया। इसके विपरीत, जैन धर्म काफी हद तक भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित रहा।

निष्कर्ष:

बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने लोगों को अपने समय की प्रतिगामी धार्मिक प्रथाओं और कर्मकांडों का विकल्प प्रदान किया। वे वंचितों और शोषितों के लिए आशा की किरण बन गए। इस प्रकार, जबकि दोनों धर्मों के बीच कई समानताएँ देखी जा सकती हैं, सूक्ष्म अंतर भी मौजूद हैं।

5. बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच वैश्विक चुनौतियों के संभावित समाधान के रूप में गांधीजी के दृष्टिकोण की प्रासंगिकता पर विस्तृत रूप से चर्चा करें।

उत्तर:

परिचय:

गांधीजी ने एक दार्शनिक, राजनीतिक कार्यकर्ता और लेखक के रूप में जीवन के दार्शनिक तरीके की अवधारणा में क्रांति ला दी। उनके गहन विचार उन्हें बुद्ध और सुकरात जैसे प्रख्यात दार्शनिकों की श्रेणी में रखते हैं। गांधी की रणनीति में सत्य, बलिदान, अहिंसा, नि:स्वार्थ सेवा और सहयोग शामिल था। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में उनकी प्रभावशाली भूमिका ने देश के शासन को आकार दिया और इसके नेताओं पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा।

मुख्य भाग :

गांधीवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण:

- **अहिंसा और सत्य:** वर्तमान समय में इन सिद्धांतों का महत्व बढ़ गया है। सत्य में हेट स्पीच और फेक न्यूज को दूर करने की शक्ति है, जो अक्सर मॉब लिंचिंग जैसी हिंसक घटनाओं को जन्म देती हैं। दूसरी ओर, अहिंसा, ऐसी घटनाओं के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करती है और समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने में मदद करती है, जैसा कि फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान प्रदर्शित किया गया था।
- **सत्याग्रह:** गांधी ने अहिंसक कार्रवाई के अपने तरीके को सत्याग्रह के रूप में संदर्भित किया, जिसमें अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्धतम आत्म-बल का उपयोग किया जाता है। यह दूसरों को नुकसान पहुँचाने के बजाय व्यक्तिगत पीड़ा के माध्यम से अधिकारों को हासिल करने पर जोर देता है। स्वतंत्रता संग्राम के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के दौरान देखे गये अहिंसक सत्याग्रह का पालन करना, 2021 गणतंत्र दिवस में हुए किसान विरोध प्रदर्शनों के हिंसक झड़पों को रोक सकता था।
- **ट्रस्टीशिप:** गांधी के ट्रस्टीशिप के सामाजिक-आर्थिक दर्शन ने सुझाया कि अमीर ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं जो सामान्य जन के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाना अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटता है और एक अधिक न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देता है जहां व्यक्ति खुद को ट्रस्टी मानते हैं और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करते हैं।

समकालीन समय में प्रासंगिकता:

- **विश्व शांति:** अहिंसा, गांधीवाद का एक मूलभूत पहलू है जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक शक्तिशाली हथियार के रूप में कार्य किया। वर्तमान वैश्विक संघर्षों में इस सिद्धांत को लागू करना, जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच की स्थिति, संभावित रूप से युद्धों को रोक सकती है और शांतिपूर्ण प्रस्तावों को बढ़ावा दे सकती है।

- **साहस और सहनशीलता:** गांधीजी का मानना था कि अहिंसा और सहनशीलता के लिए बड़े साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। हिंसा और आतंकवाद से जूझ रही दुनिया में अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांतों पर जोर देना और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सिद्धांत आक्रामकता की प्रचलित संस्कृति का प्रतिकार कर सकते हैं और एक अधिक शांतिपूर्ण और सहिष्णु समाज का निर्माण कर सकते हैं।
- **वर्गहीन समाज:** भारत जाति व्यवस्था की दृढ़ता से जूझ रहा है। एक जातिविहीन समाज की स्थापना में गांधी के दर्शन की प्रासंगिकता का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें हर व्यक्ति को उनकी जाति की परवाह किए बिना समान व्यवहार किया जायेगा। गांधी के समावेशी आदर्शों की आवश्यकता को प्रदर्शित करते हुए पश्चिमी दुनिया में नस्लवाद और भारत में जाति आधारित हिंसा के मुद्दों को संबोधित करने में एक वर्गहीन समाज का विजन भी लागू होता है।
- **गांधीवादी समाजवाद:** गांधीवादी समाजवाद राजनीति से परे है और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। गांधीजी ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के साथ गरीबी, भूख, बेरोजगारी और असमानता से मुक्त समाज की कल्पना की थी। ये मूल्य सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं, संघर्ष को कम करते हैं और सभी को समृद्धि की ओर ले जाते हैं।
- **निरस्त्रीकरण:** अहिंसा और शांति पर गांधी का जोर निरस्त्रीकरण के प्रयासों की नींव के रूप में काम कर सकता है। उनकी शिक्षाएँ संवाद, बातचीत और गैर-आक्रामक तरीकों से संघर्षों को हल करने को बढ़ावा देती हैं। उनके सिद्धांतों को अपनाकर, राष्ट्र निरस्त्रीकरण की दिशा में काम कर सकते हैं और सैन्य व्यय के बजाय मानव विकास हेतु संसाधनों का आवंटन कर सकते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:** सततता और प्रकृति के प्रति सम्मान के लिए गांधीजी का समर्थन, जलवायु परिवर्तन के समाधान के अनुरूप है। उनकी शिक्षाएं पर्यावरण के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध को प्रोत्साहित करती हैं और जिम्मेदार उपभोग को बढ़ावा देती हैं। उनके सिद्धांतों को लागू करने से स्थायी प्रथाओं, संरक्षण प्रयासों और स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण हो सकता है।
- **जातीय संघर्ष:** गांधीजी का एकता, सहिष्णुता और समझ का दर्शन जातीय संघर्षों को संबोधित करने में सहायक हो सकता है। उनकी शिक्षाएं संवाद, विविधता के प्रति सम्मान और न्याय की खोज को बढ़ावा देती हैं। उनके सिद्धांतों को अपनाकर, समाज मेल-मिलाप की दिशा में काम कर सकते हैं, विभाजन को पाट सकते हैं और समावेशी वातावरण बना सकते हैं जहां सभी समुदाय शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।
- **गरीबी:** गांधी की शिक्षाएं सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन के महत्व पर जोर देती हैं। 'ग्राम स्वराज' (ग्राम स्वशासन) की उनकी दृष्टि संसाधनों के समान वितरण और हाशिए के समुदायों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। उनकी शिक्षाओं को लागू करके समाज समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और निष्पक्ष आर्थिक व्यवस्था के लिए प्रयास कर सकता है।
- **अन्य वैश्विक मुद्दे:** गांधी के सत्य, करुणा और नैतिक आचरण के सिद्धांतों को वैश्विक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू किया जा सकता है। उनकी शिक्षाएँ व्यक्तियों और समुदायों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार से लड़ने और सामाजिक उत्थान की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती हैं।

निष्कर्ष:

गांधी की विचारधाराएं दुनिया भर में व्यक्तियों और भारतीय नीति निर्माताओं के लिए समान रूप से मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में काम करती हैं। सर्व शिक्षा अभियान (सभी के लिए शिक्षा) और आयुष्मान भारत (यूनिवर्सल हेल्थ केयर) जैसी गरीबी उन्मूलन की पहलों से लेकर कौशल भारत जैसे कार्यक्रमों तक, गांधीवाद एक प्रमुख प्रेरणा बना हुआ है। समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने और अधिक सामंजस्यपूर्ण और समावेशी दुनिया के पोषण के लिए गांधी की शिक्षाओं के सार को अपनाना आवश्यक है।

6. दोनों विश्व युद्धों में चार मिलियन से अधिक ब्रिटिश भारतीय सैनिकों के योगदान और विभिन्न युद्ध थिएटरों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से बताएं।

उत्तर:

परिचय:

ग्लासगो, स्कॉटलैंड में ब्रिटिश भारतीय सेना को समर्पित एक स्मारक का निर्माण किया जायेगा। यह स्कॉटलैंड में उन लाखों भारतीय सैनिकों को सम्मानित करने के लिए पहला स्थायी स्मारक है, जिन्होंने दोनों विश्व युद्धों के दौरान अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस स्मारक का उद्देश्य ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा की गई अमूल्य सेवा और बलिदान को स्वीकार करना और याद रखना है।

मुख्य भाग :

प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों का योगदान:

- ब्रिटिश भारतीय सेना ने मित्र देशों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए प्रथम विश्व युद्ध के यूरोपीय, भूमध्यसागरीय और मध्य पूर्वी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- विभिन्न धार्मिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 1.5 मिलियन भारतीय सैनिकों ने भारतीय अभियान दल में भाग

लिया।

- भारतीय सैनिकों ने बहादुरी और निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ी, जिसमें 70,000 से अधिक सैनिक मारे गए और 67,000 घायल हुए।
- उन्हें 11 विक्टोरिया क्रॉस, ब्रिटिश साम्राज्य में सर्वोच्च सैन्य अलंकरण सहित कई सम्मान प्राप्त हुए।
- युद्ध के दौरान भारत ने आवश्यक उपकरण, सामग्री और जानवर भी प्रदान किए।
- भारतीय सैनिकों ने फ्रांस, बेल्जियम, मेसोपोटामिया, मिस्र, सिनाई, गैलीपोली और जर्मन पूर्वी अफ्रीका सहित विभिन्न क्षेत्रों में सेवा प्रदान की।
- उनके योगदान के बावजूद, भारत को युद्ध के बाद स्व-शासन के अपने वादे से वंचित कर दिया गया था, और रौलेट एक्ट जैसे दमनकारी उपायों को लागू किया गया था।
- प्रथम विश्व युद्ध के कुछ अच्छे सैनिकों में अरसला खान, अवल नूर, प्रताप सिंह आदि शामिल हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों का योगदान:

- लगभग 2.5 मिलियन भारतीय सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध में सेवा दी थी।
- भारतीय सैनिकों ने जर्मनी, इटली और जापान धुरी शक्तियों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ाई लड़ी थी।
- 36,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, 34,000 घायल हुए, और 67,000 युद्ध बंदी बने।
- भारतीय सैनिकों ने दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया में आगे बढ़ रही जापानी सेना से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उन्होंने पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका, इटली, बर्मा, सिंगापुर, मलय प्रायद्वीप, गुआम और भारत-चीन के अभियानों में भाग लिया।
- भारतीय सेना ने नेपाली गोरखा सैनिकों के साथ, बर्मा और पूर्वोत्तर भारत में जापानी सेना को सफलतापूर्वक पीछे धकेला।
- भारतीय वायु सेना के पायलटों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, और भारतीय डॉक्टरों, नर्सों और सहायक कर्मियों ने विभिन्न स्थानों पर सेवाएं दी।
- भारत ने सैनिकों और एशियाई युद्ध बंदियों को 1.7 मिलियन से अधिक भोजन के पैकेट और आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की।
- भारत ने सैनिकों की सहायता के लिए डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस को भी चीन भेजा।

निष्कर्ष:

दोनों विश्व युद्धों में भारतीय सेना का योगदान महत्वपूर्ण था, भारतीय सैनिकों ने युद्ध के विभिन्न थिएटरों में बहादुरी और बलिदान का प्रदर्शन किया। हालाँकि, उनके योगदान को अक्सर अनदेखा और कम मान्यता दी गई है। ग्लासगो में ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल का निर्माण उनकी अमूल्य सेवा को सम्मान देने और याद रखने की दिशा में एक कदम है।

7. इस बारे में आपकी क्या राय है कि 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों ने आधुनिकता को अपनाने और देश के अतीत की भव्यता को पुनर्जीवित करने के बीच एक बुनियादी विरोधाभास प्रदर्शित किया? कृपया इस मुद्दे पर अपने विचार रखते हुए टिप्पणी करें।

परिचय:

19वीं शताब्दी की शुरुआत से, संचार के नए रूपों के विकास के कारण सामाजिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं के बारे में बहस और चर्चाओं ने एक नया चरित्र ग्रहण किया। सुधारकों के मन में सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी विचारों के बीच एक अंतर्विरोध था। कुछ आधुनिकीकरण के ज्ञान को फैलाने के इच्छुक थे, जबकि अन्य अतीत के गौरव और रीति-रिवाजों को उजागर करने में रुचि रखते थे।

मुख्य भाग:

सामाजिक सुधारों के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण:

- पाश्चात्य विचारधारा का अंधपालन नहीं किया गया, बल्कि स्वदेशी संस्कृति में सुधार किया गया। इस प्रकार, आधुनिकीकरण सुधारकों का उद्देश्य था।
- आंदोलन तर्कवाद और धार्मिक सार्वभौमिकता में विश्वास करते थे। प्रचलित सामाजिक प्रथाओं के लिए एक तर्कसंगत और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए, बाल विवाह का विरोध करने के लिए चिकित्सा विज्ञान के दृष्टिकोण को एक सहायता के रूप में उद्धृत किया गया था।
- उन्होंने ऐसी प्रथाओं को चुनौती देने के लिए विश्वास का प्रयोग किया। उन्होंने अतीत के उन अवधियों का उल्लेख किया जहां ऐसी कोई प्रथा मौजूद नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसे केवल एक सहायता और उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। इस प्रकार, वे यह साबित करना चाहते थे कि सती, बाल विवाह आदि जैसी प्रथाओं को धर्म द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया।
- इन आन्दोलनों ने भय से उत्पन्न अनुरूपता और पुरोहितों और अन्य वर्गों द्वारा शोषण के प्रति आलोचनात्मक अधीनता से व्यक्तियों की मुक्ति की दिशा में योगदान दिया। उदाहरण के लिए, ब्रह्म समाज और उसके विभिन्न प्रकार।

- भारत के सभी हिस्सों में विभिन्न आंदोलन, जैसे कि मंदिर प्रवेश आंदोलन, का उद्देश्य दलितों और उच्च जातियों के बीच सामाजिक समानता प्राप्त करना था और दलितों के साथ अधिक मानवीय तरीके से व्यवहार करने का प्रयास भी किया। केरल के नारायण गुरु ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिन्होंने समाज में प्रचलित जातिगत अन्याय और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक प्रसिद्ध नारा दिया ष्एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर सभी के लिएष।

पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण:

- थियोसोफिस्टों ने हिंदू धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम के प्राचीन धर्मों के पुनरुद्धार और मजबूती की वकालत की। उन्होंने आत्मा के संचरण के सिद्धांत को मान्यता दी।
- 1830 में ब्रह्म समाज के विचारों का मुकाबला करने के लिए धर्म सभा ने यथास्थिति की वकालत की और सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किया।
- आर्य समाज ने 'वेदों की ओर लौटो' का पालन किया, जबकि तबलीग आंदोलन का उद्देश्य आम मुसलमानों तक पहुंचना और उनके विश्वास को पुनर्जीवित करना था।
- पुनरुत्थानवादी आंदोलनों का मानना था कि पश्चिमी सोच और मिशनरी प्रचार भारतीय संस्कृति और लोकाचार को नष्ट कर देगा, और इस प्रकार धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता थी।
- वे पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रकाश में लाई गई भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी प्रभावित थे और उन्होंने पाया कि यह पश्चिमी संस्कृति से भी श्रेष्ठ थी।
- वहाबी आन्दोलन एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आन्दोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम को शुद्ध करना और उसे उसके मौलिक और सरल रूप में पुनर्स्थापित करना था।
- पीछे की ओर देखने की प्रवृत्ति, अतीत की महानता को आकर्षित करना, और शास्त्रों के अधिकार पर भरोसा करना।
- अतीत की महानता की अपीलों ने मिथ्या अभिमान और आत्ममुग्धता पैदा कर दी, जबकि अतीत में श्स्वर्णिम युगश खोजने की आदत ने आधुनिक विज्ञान की पूर्ण स्वीकृति पर रोक लगाने का काम किया और वर्तमान को बेहतर बनाने के प्रयास में बाधा उत्पन्न की।
- इस घटना के बुरे पहलू तब स्पष्ट हो गए जब यह पाया गया कि राष्ट्रीय चेतना के तेजी से उदय के साथ-साथ एक और चेतना – सांप्रदायिक चेतना – मध्य वर्गों के बीच उठनी शुरू हो गई थी।

निष्कर्ष

सामाजिक-धार्मिक सुधार औपनिवेशिक निर्णय और देशी पिछड़ेपन के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। आंदोलन का उदय हुआ और पतन भी हुआ लेकिन विचारों और समाज पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ा। इसने भारतीयों को तुलनात्मक रूप से अधिक आत्मविश्वास, आत्म-सम्मान और देशभक्ति की भावना बनाये रखने में मदद की। इन्हीं से आम लोगों में मानवता और नैतिकता का प्रसार हुआ और राजनीतिक स्वतंत्रता और आधुनिक विकास की भावना का विकास हुआ।

8. जनजातीय विद्रोह अज्ञात नायकों के योगदान का प्रतीक है जिन्होंने औपनिवेशिक उत्पीड़न के अपने सामूहिक अनुभवों के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन की नैतिक चेतना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रासंगिक उदाहरण के साथ मूल्यांकन करें।

परिचय:

ब्रिटिश हस्तक्षेप से पहले, आदिवासी भोजन, ईंधन और चारे सहित जीविका के लिए जंगलों पर निर्भर थे। उन्होंने ''झूम'' और ''पोडू'' जैसी स्थानांतरण कृषि का अभ्यास किया, जिसमें वे नए वन भूमि में चले जाते, जब उनकी वर्तमान कृषि भूमि की उर्वरकता समाप्त हो जाती। हालांकि, 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान, औपनिवेशिक सरकार ने इन प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिसके कारण जनजातियों द्वारा हिंसक और भयानक विद्रोह हुए।

मुख्य भाग :

जनजातीय विद्रोहों के कारण:

- **भू-राजस्व बंदोबस्त लागू करना:** अकाल, भू-राजस्व की बढ़ती माँगों और आर्थिक संकट जैसे कारकों ने मिदनापुर और बांकुरा जिलों (बंगाल) के जंगल-महल के चुआर आदिवासियों को हथियार उठाने के लिए मजबूर किया।
- **ब्रिटिश नीतियां और अधिनियम:** 1864 में वन विभाग की स्थापना, सरकारी वन अधिनियम (1865), और भारतीय वन अधिनियम (1878) ने वन क्षेत्रों में जनजातीय गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया, जिससे अंग्रेजों के प्रति उनकी नाराजगी भड़क गई। विशेष रूप से कोया विद्रोह, आदिवासियों को वन क्षेत्रों पर अधिकारों से वंचित करने के कारण हुआ था।
- **व्यवस्थित कृषि का विस्तार:** आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश विस्तार के कारण 1778 में राजमहल की पहाड़ियों के मार्शल पहाड़ियों द्वारा विद्रोह

शुरू कर दिया।

- **नए आबकारी नियम:** आदिवासियों द्वारा अपनी शराब बनाने पर प्रतिबंध लगाने, जो उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ने असंतोष को हवा दी।
- **बड़े पैमाने पर वन भूमि का हस्तांतरण:** कोल मुखियाओं से बाहरी लोगों (दीकू) और साहूकारों को भूमि का हस्तांतरण, जो अक्सर दमनकारी नीतियाँ और अत्यधिक कर लगाते थे।
- **झूम खेती पर प्रतिबंध:** खासी और गारो विद्रोह जैसे उदाहरण, पहाड़ों पर कब्जे और झूम खेती पर प्रतिबंध के कारण उभरे।
- व्यापारियों और साहूकारों द्वारा शोषण: संथाल विद्रोह ने साहूकारों और व्यापारियों को निशाना बनाया, जबकि उलगुलान विद्रोह को साहूकारों के खिलाफ था।
- ईसाई मिशनरियों का प्रभाव और हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे अन्य धर्मों में हस्तक्षेप के खिलाफ प्रतिरोध, ताना भगत आंदोलन द्वारा अनुकरणीय है।

इन जनजातीय आंदोलनों की कमजोरियाँ :

- जनजातीय विद्रोह व्यापक दायरे में थे फिर भी अलग-थलग और स्थानीय थे। वे स्थानीय स्तर के मुद्दों और शिकायतों के परिणाम थे।
- विद्रोह में मजबूत नेतृत्व का अभाव था क्योंकि इसके सदस्यों में अर्ध-सामंती विशेषताएं थीं, एक पारंपरिक मानसिकता थी, और समाज में यथास्थिति का कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं था।

राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने में महत्व

- विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की दमनकारी प्रकृति के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध को बढ़ावा दिया।
- उन्होंने आदिवासी समुदायों को एकजुट करने और एक राष्ट्र की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- जनजातीय विद्रोहों ने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों, विशेष रूप से उनकी भूमि पर अतिक्रमण और वन संसाधनों पर अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई पर प्रकाश डाला।

निष्कर्ष:

ईस्ट इंडिया कंपनी के युग सहित औपनिवेशिक शासन ने कई जनजातीय विद्रोह और गड़बड़ी देखी। इन विविध शिकायतों की परिणति 1857 के विद्रोह में हुई, जो शुरू में भारतीयों के विशिष्ट समूहों को लक्षित करने के बावजूद, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत से पहले ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रमुख विद्रोह के रूप में सामने आया।

9. उन कारकों का विश्लेषण करें जिन्होंने भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को आकार देने में भूमिका निभाई। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों द्वारा प्रदर्शित बहादुरी और देशभक्ति तथा स्वतंत्रता के लिए व्यापक संघर्ष पर उनके कार्यों के प्रभाव पर चर्चा करें।

परिचय:

19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में क्रांतिकारी विचारधारा का उदय, युवाओं को प्रभावित करने वाले विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों से प्रभावित था। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभिक चरण बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी, उड़ीसा, बिहार और मद्रास प्रांतों में केंद्रित था, जिसमें बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब सबसे अधिक राजनीतिक रूप से सक्रिय क्षेत्र थे।

मुख्य भाग:

क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में योगदान करने वाले कारक:

- **युवाओं में राष्ट्रवाद:** देशवासियों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों का 'आर्थिक शोषण' और बंगाल का विभाजन था। विभिन्न राष्ट्रवादी नेताओं, जैसे जतींद्रनाथ बनर्जी, वीरेंद्र घोष और बरिंद्र कुमार घोष ने 'युगान्तर' जैसे प्रकाशनों के माध्यम से इस भावना को व्यक्त किया।
- **उदारवादी और उग्रवादी कांग्रेस की विफलता:** राष्ट्रीय उग्रवाद चरण के पतन के बाद युवा तत्व पीछे हटने को तैयार नहीं थे। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का नतीजा तात्कालिक कारण था।
- युवाओं की क्रांतिकारी ऊर्जा का दोहन करने में नेतृत्व की विफलता। सरकारी दमन ने विरोध के लिए कोई शांतिपूर्ण व्यवस्था नहीं रहने दी।
- आयरिश राष्ट्रवादियों या रूसी शून्यवादियों की तर्ज पर व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्रवाई से प्रेरित।
- **विचारों की वैचारिक अपील:** क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता, वीरतापूर्ण कार्रवाई, सर्वोच्च बलिदान, अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या, शासकों में आतंक पैदा करना और लोगों को बलपूर्वक अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए नए राष्ट्रवादियों को आकर्षित किया।

भारतीय राष्ट्रवाद पर क्रांतिकारियों का प्रभाव:

- क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने और देश और विदेश में राष्ट्रवाद के संदेश को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- हिंसक क्रांति के युग के कारण पूरे देश में गुप्त समितियों की स्थापना हुई, जिसमें अनुशीलन समिति जैसे संगठन प्रमुख रहे।
- क्रांतिकारियों के प्रभाव ने भी कांग्रेस की रणनीति को आकार दिया, जिससे ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी हुई।
- रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल एम.ए. अंसारी, मदन लाल ढींगरा और एस. अजीत सिंह सहित कई क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय सीमाओं से परे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का विस्तार किया।
- यह जनता को लामबंद नहीं कर सका। वास्तव में, इसका लोगों के बीच कोई आधार नहीं था। वे व्यक्तिगत वीरता में विश्वास करते थे।
- यह आंदोलन स्वतंत्रता के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, कई क्रांतिकारी, जो कैद में थे, पुनर्विचार की एक प्रक्रिया से गुजरे, और उनमें से बहुतों ने अंततः मार्क्सवाद को अपना लिया।

निष्कर्ष:

यद्यपि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन अंततः सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से स्वतंत्रता के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, इसने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन और राजगुरु जैसे व्यक्ति भारतीय लोगों के बीच राष्ट्रीयता की भावना को प्रेरित और जगाने वाले घरेलू नाम बन गए। अपने इच्छित उद्देश्यों को पूरा न करने के बावजूद, क्रांतिकारी सत्ता को चुनौती देने और शासकों में डर पैदा करने में कामयाब रहे, जिससे भारतीय इतिहास पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा।

10. विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति बनाए रखने में लीग ऑफ नेशंस की प्रभावशीलता की जांच करें। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में इसकी व्यापक भूमिका का एक महत्त्वपूर्ण विश्लेषण प्रदान करें।

परिचय:

अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य से प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा सिद्धांतों के माध्यम से विवादों को सुलझाना और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना था। हालांकि इसने कुछ सफलताएं हासिल कीं, लेकिन इसकी समग्र प्रभावशीलता महत्वपूर्ण विश्लेषण के अधीन रही है।

मुख्य भाग :

1. **विवाद समाधान:**
   - राष्ट्र संघ ने बुल्गारिया को मुआवजा देने के लिए ग्रीस को राजी करके ग्रीस-बुल्गारिया संघर्ष जैसे क्षेत्रीय विवादों को सफलतापूर्वक हल किया।
   - इसने पेरू और कोलंबिया के बीच क्षेत्रीय विवाद को सुलझाने में भी भूमिका निभाई।
   - जर्मनी और पोलैंड के बीच ऊपरी सिलेसिया विवाद में, राष्ट्र संघ ने एक समझौते की व्यवस्था दी और दोनों पक्षों के बीच क्षेत्र का विभाजन किया गया।
2. **अफीम व्यापार और शरणार्थी दुर्दशा का मुकाबला:**
   - राष्ट्र संघ ने सक्रिय रूप से अफीम और यौन दासता के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुकाबला करने के लिए काम किया।
   - इसने शरणार्थियों की दुर्दशा को कम किया, विशेष रूप से तुर्की में, नानसेन पासपोर्ट की शुरुआत करके, स्टेटलेस शरणार्थियों के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पहचान पत्र जारी किया।
3. **जनादेश शासन और जनमत:**
   - लीग के स्थायी शासनादेश आयोग ने राष्ट्र संघ के शासनादेशों के शासन की प्रभावी निगरानी की।
   - इसने जर्मनी के SAAR क्षेत्र जैसे विवादित क्षेत्रों में जनमत संग्रह का आयोजन किया, जिससे निवासियों को अपनी पसंद का देश निर्धारित करने की अनुमति मिली।
4. **मानव कल्याण को बढ़ावा देना:**
   - लीग के स्वास्थ्य संगठन ने विभिन्न महामारियों के कारणों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
   - इसने रूस में टायफस महामारी का सफलतापूर्वक मुकाबला किया, जिससे यूरोप के अन्य भागों में इसके प्रसार को रोका जा सका।
5. **निरस्त्रीकरण के प्रयास:**
   - भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण का सक्रिय प्रचार।
   - हथियारों की होड़ को सीमित करने और सैन्य खर्च को कम करने के लिए सम्मेलनों और वार्ताओं का आयोजन।
   - 1924 का जिनेवा प्रोटोकॉल, रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग पर रोक लगाता है।
6. **आर्थिक सहयोग:**
   - सदस्य राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन।
   - व्यापार समझौतों और टैरिफ में कटौती पर बातचीत की सुविधा।

- स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान।
- प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी जैसे देशों में आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु सहायता।

7. **अंतर्राष्ट्रीय कानून पर प्रभाव:**
   - अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में योगदान।
   - समुद्री कानून, शरणार्थी संरक्षण और युद्ध बंदियों के उपचार जैसे क्षेत्रों में संहिताकरण और कानूनी ढांचे की स्थापना।
8. **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का गठन:**
   - 1919 में ILO की स्थापना में राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
   - ILO का उद्देश्य काम करने की स्थिति में सुधार करना, श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देना और विश्व स्तर पर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है।
   - लीग के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाने और निष्पक्ष श्रम प्रथाओं को बढ़ावा मिला।
   - ILO 1946 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई और आज भी अपना काम जारी रखे हुए है।

राष्ट्र संघ की सीमाएँ:

1. संघ में संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कभी शामिल नहीं हुआ, और सोवियत संघ, जो केवल थोड़े समय के लिए शामिल हुआ, जैसी प्रमुख शक्तियों की भागीदारी का अभाव था। इस अनुपस्थिति ने लीग के अधिकार और निर्णयों को लागू करने की क्षमता को कमजोर कर दिया, वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर दिया।
2. लीग को अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने में सीमित सफलता मिली क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध के लिए महत्वपूर्ण संघर्षों में हस्तक्षेप करने में विफल रही, जैसे कि एबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण, स्पेनिश गृहयुद्ध और दूसरा चीन-जापान युद्ध।
3. वर्साय की संधि का उल्लंघन करने वाली प्रमुख घटनाओं के सामने यह काफी हद तक शक्तिहीन और मौन था, जिसमें हिटलर द्वारा राइनलैंड का पुनर्सैन्यीकरण, सुडेटेनलैंड पर कब्जा, और ऑस्ट्रिया के साथ एंस्क्लस शामिल थे।
4. संगठन के भीतर सामान्य कमजोरियां, जैसे जटिल मतदान संरचनाएं और विश्व राष्ट्रों का अधूरा प्रतिनिधित्व, संकल्पों के अनुसमर्थन और निर्णायक कार्रवाई में बाधा डालती थीं।
5. संयुक्त राज्य अमेरिका के इसमें शामिल होने से इनकार करने से लीग की प्रभावशीलता और सीमित हो गई, जिसने इसे एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के प्रभाव और संसाधनों से वंचित कर दिया।
6. सदस्य देश अक्सर सामूहिक कार्रवाई और लीग के उद्देश्यों के ऊपर अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते थे। इसके परिणामस्वरूप प्रतिबंधों को लागू करने या आक्रामक राष्ट्रों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के आवश्यक कदमों की अवहेलना हुई, जिससे संघर्षों को हल करने में लीग का प्रभाव कम हो गया।
7. लीग ने आर्थिक मंदी और महामंदी की अवधि के दौरान कार्य किया। इस वित्तीय तनाव ने सदस्य राज्यों को आर्थिक सहायता और सहायता प्रदान करने की अपनी क्षमता को सीमित कर दिया, जिससे वैश्विक आर्थिक चुनौतियों को प्रभावी ढंग से हल करने की क्षमता प्रभावित हुई।

निष्कर्ष:

अंत में, राष्ट्र संघ ने विवादों को सुलझाने, अवैध गतिविधियों का मुकाबला करने, शासनादेशों की निगरानी करने और मानव कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालाँकि, इसकी सीमाओं, जिसमें संघर्षों को रोकने में विफलताएँ, प्रमुख घटनाओं के लिए अपर्याप्त प्रतिक्रियाएँ, संरचनात्मक कमजोरियाँ और अमेरिकी भागीदारी की अनुपस्थिति शामिल हैं, ने वैश्विक शांति को बनाए रखने में इसकी समग्र प्रभावशीलता को कम किया। हालांकि लीग ने अंतरराष्ट्रीय कानून के विकास और तनाव को कम करने में योगदान दिया, लेकिन यह अंततः सदस्य देशों को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करने से रोकने में असमर्थ रहा।

11. भारत की समृद्ध विरासत, रंगमंच और कहानी कहने की समृद्ध परंपरा में गहराई से निहित है। हालाँकि, डिजिटल मनोरंजन के आगमन ने रंगमंच के अस्तित्व पर चुनौती पेश की है, जिससे एक अस्तित्वगत संकट पैदा हो गया है।

परिचय:

रंगमंच की कला संगीत, नृत्य, नाटक, शैलीगत भाषण और तमाशा का एक संयोजन है। यह भारत की स्थानीय पहचान और मूल संस्कृति से गहरा संबंध रखता है। देश कई पारंपरिक कलाओं, प्रदर्शन कलाओं और शिल्पों का दावा करता है जो सदियों से जीवित हैं। इन कलात्मक रूपों ने न केवल अतीत में लोगों का मनोरंजन किया जब मनोरंजन के विकल्प सीमित थे बल्कि धार्मिक शास्त्रों, मिथकों और लोक कथाओं के माध्यम से ज्ञान को प्रसारित करने के माध्यम के रूप में भी काम करते थे, जो अक्सर नैतिक संदेश देते थे।

भारतीय रंगमंच का विकास:

- नाट्यशास्त्र, प्रदर्शन कलाओं पर एक प्राचीन ग्रंथ, विभिन्न प्रकार के नाटकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, उन्हें प्रमुख (रूपक) या मामूली (उपरूपक) के रूप में वर्गीकृत करता है।
- भारत में लोक रंगमंच संगीत, नृत्य, मूकाभिनय, पद्य सस्वर पाठ, महाकाव्य कथावाचन, ग्राफिक कला, धर्म और उत्सव के तत्वों को शामिल करते हुए कला रूपों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है।
- भारतीय लोक रंगमंच को मोटे तौर पर धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः अनुष्ठानिक रंगमंच और मनोरंजन का रंगमंच होता है। लोक और पारंपरिक शैलियों के साथ ये रूप एक-दूसरे को प्रभावित और पूरक करते हैं, जो अक्सर गायन और सस्वर पाठ जैसे कथा या मुखर तत्वों पर निर्भर करते हैं।
- जबकि स्थानीय रीति-रिवाजों के आधार पर प्रत्येक नाट्य शैली की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, विभिन्न रूपों में निष्पादन, मंचन, वेशभूषा, श्रृंगार और अभिनय शैलियों में समानताएँ होती हैं।
- दक्षिणी भारतीय रूप, जैसे केरल में कथकली और कृष्णाट्टम, नृत्य पर जोर देते हैं, नृत्य नाट्य के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत, उत्तर भारतीय रूप गीतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे राजस्थान में ख्याल, मध्य प्रदेश में माच, उत्तर प्रदेश में नौटंकी और पंजाब में स्वांग। अन्य रूप, जैसे बंगाल में जात्रा, महाराष्ट्र में तमाशा और गुजरात में भवई, संवाद, हास्य और व्यंग्य पर जोर देते हैं।
- कठपुतली थिएटर भारत में भी विकसित हुआ, जिसमें छाया (कर्नाटक के गोम्बेयट्टा, उड़ीसा के रावण छाया), दस्ताना (ओडिशा में गोपालिला, तमिलनाडु में पवई कुथु), गुड़िया (तमिलनाडु और मैसूर में बोम्मालट्टम, बंगाल में पुतुल नाच), और स्ट्रिंग कठपुतली (राजस्थान में कठपुतली, ओडिशा में सखी कुंदेई) जैसे विभिन्न रूपों के साथ फला-फूला।
- भारत नाट्यम, कथक, ओडिशी, और मोहिनीअट्टम जैसे शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूपों के साथ-साथ बंगाल में गंभीरा और पुरुलिया छाऊ, बिहार में सरायकेला छाऊ, और ओडिशा में मयूरभंज छाऊ जैसे लोक नृत्यों में नाटकीय तत्व पाए जाते हैं। कुछ अनुष्ठान समारोह, विशेष रूप से केरल में, नाटकीय तत्वों को शामिल करते हैं, जैसा कि मुदियेट्टु और तेय्यम में देखा गया है।

एक कला के रूप में रंगमंच का महत्व:

- रंगमंच परंपराओं, रीति-रिवाजों और सुधार की निरंतरता, सदियों पुराने रूपों और नवीनता की इच्छाओं को जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- यह समाज को आईना दिखाता है, इसकी खामियों और गुणों को उजागर करता है। उदाहरण के लिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान रंगमंच ने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- नसीरुद्दीन शाह, इरफान खान, डॉ. राजकुमार और शबाना आजमी जैसे प्रसिद्ध भारतीय कलाकारों ने थिएटर में अपने कौशल को निखारा।

अस्तित्व के संकट का सामना करना:

- डिजिटल मीडिया और अमेजॅन प्राइम, नेटफ्लिक्स आदि जैसे ओटीटी प्लेटफार्मों के उदय ने फिल्मों, सीरीज और रियलिटी शो सहित मनोरंजन के विभिन्न रूपों को स्मार्टफोन और टेलीविजन के माध्यम से आसानी से सुलभ बना दिया है।
- स्मार्टफोन और टेलीविजन के व्यापक उपयोग के कारण, ग्रामीण भारत में भी पारंपरिक रंगमंच में रुचि कम हो रही है।
- महामारी ने थिएटर प्रस्तुतियों में अत्यधिक नुकसान पहुँचाया है, जिससे उबरना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
- दर्शकों का फास्ट कंटेंट की ओर अधिक झुकाव हो रहा है और शारीरिक रूप से शामिल नहीं होना पसंद करते हैं।

निष्कर्ष:

हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए, भारतीय रंगमंच को प्रौद्योगिकी के अनुकूल और एकीकृत होना होगा। पेशेवर थिएटर उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है, जो इमर्सिव अनुभव बनाने के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ काम करने के अवसर प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी को अपनाने से भारतीय रंगमंच को पुनर्जीवित करने में मदद मिल सकती है और इसके गहरे सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखते हुए इसे आधुनिक युग में प्रासंगिक बनाए रखा जा सकता है।

12. प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति के लिए ज्ञान और महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। चर्चा करें।

उत्तर:

भारत के पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समृद्ध विरासत है। विज्ञान के विकास से प्रकृति पर निर्भरता को दूर किया जा सकता है। प्राचीन भारत में, धर्म और विज्ञान निकटता से कार्य करते थे। भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक लंबी परंपरा के साथ सबसे पुरानी सभ्य संस्कृतियों में से एक है। विज्ञान के उनके इतिहास का अन्य आधुनिक सभ्यताओं की तुलना में एक अलग संदर्भ में अध्ययन किया जा सकता है।

मुख्य भाग:

1. **गणित:**
   - हड़प्पा की नगर योजना से पता चलता है कि लोगों को मापन और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान था।
   - तीसरी शताब्दी ईस्वी तक, गणित अध्ययन की एक अलग धारा के रूप में विकसित हुआ। भारतीय गणित की उत्पत्ति शुल्वसूत्रों से मानी जाती है।
   - ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्पुट सिद्धांत सबसे पहला ग्रंथ है जिसमें शून्यश को एक संख्या के रूप में वर्णित किया गया है, इसलिए ब्रह्मगुप्त को शून्य का खोजकर्ता माना जाता है। उन्होंने शून्य को अन्य संख्याओं के साथ प्रयोग करने के नियम दिए।
   - आर्यभट्ट ने बीजगणित की खोज की और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल भी तैयार किया, जिससे त्रिकोणमिति की उत्पत्ति हुई।
2. **खगोल विज्ञान:**
   - ज्योतिषवेदांग ग्रंथों ने खगोल विज्ञान में व्यवस्थित श्रेणियों की स्थापना की, लेकिन अधिक बुनियादी समस्या का समाधान आर्यभट्ट (499 ईस्वी) द्वारा किया गया। उनका आर्यभट्टीय एक संक्षिप्त पाठ है जिसमें 121 छंद हैं। इसमें खगोलीय परिभाषाओं, ग्रहों की वास्तविक स्थिति का निर्धारण करने के तरीके, सूर्य और चंद्रमा की गति का विवरण और ग्रहणों की गणना पर अलग-अलग खंड शामिल हैं।
3. **धातु विज्ञान:**
   - वैदिक लोग अनाज और फलों के किण्वन, चमड़ा शोधन और रंगाई की प्रक्रिया के बारे में जानते थे।
   - पहली शताब्दी ईसवी तक, लोहा, तांबा, चांदी, सोना जैसी धातुओं और पीतल और कांस्य जैसी मिश्र धातुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा था। कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ उस समय उपलब्ध उच्च गुणवत्ता की मिश्रधातु का सूचक है।
4. **चिकित्सा:**
   - 600 ई.पू. से तर्कसंगत विज्ञानों का काल शुरू हुआ। तक्षशिला और वाराणसी चिकित्सा और शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरे।
   - इस क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण ग्रन्थ चरक कृत चरक संहिता और सुश्रुत कृत सुश्रुत संहिता हैं।

प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति के लिए ज्ञान और महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है:

1. **आयुर्वेद :**
   - चरक संहिता में उल्लिखित पौधे और जड़ी-बूटियाँ आज भी प्रासंगिक हैं और आयुर्वेद की नींव हैं।
   - पिछले कुछ दशकों में, विश्व स्तर पर चिकित्सा के वैकल्पिक रूपों में रुचि बढ़ रही है।
   - आधुनिक बायोमेडिकल अवधारणाओं के साथ रोग की प्रकृति की आयुर्वेदिक समझ को सहसंबंधित करने के लिए बायोमेडिकल और आयुर्वेदिक शोधकर्ताओं द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।
2. **योग :**
   - कई पश्चिमी देशों ने मानसिक और शारीरिक तंदुरूस्ती के लिए योग को अपनाया है। इस संबंध में और शोध किए जा रहे हैं।
   - योग अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम करने, पुराने पीठ दर्द को कम करने, तनाव के स्तर को कम करने, मस्तिष्क प्रक्रियाओं को बढ़ाने और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने वाला पाया गया है।
3. **दशमलव प्रणाली:**
   - आज हम जिस आधुनिक दशमलव प्रणाली का उपयोग करते हैं, वह भारत में पूरी तरह से संकलित किया गया था। हालाँकि अन्य संस्कृतियों ने संख्यात्मक प्रणाली की कुछ विशेषताओं को पहले ही प्रस्तुत किया था, यह भारत में 9वीं शताब्दी ईस्वी तक पूरा हो गया था।
   - मैट्रिक प्रणाली में आज हम जितनी भी गणनाएं करते हैं, वे केवल "0" और दशमलव प्रणाली की खोज के कारण ही संभव हैं।
4. **चंद्रशेखर सीमा:**
   - भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर ने मृत होते तारे का क्या होगा, इसका भविष्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली गणना की खोज की।
   - यदि तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर की सीमा से कम है, तो यह एक सफेद बौना (ूपजम कूंत) बनने के लिए सिकुड़ जाएगा, और यदि यह बड़ा है, तो तारा फट जाएगा, एक सुपरनोवा बन जाएगा।
   - ऐसा कहा जाता है कि वह प्राचीन खगोलीय ग्रंथों से प्रभावित थे, जैसे मुंडकोपनिषद् जिसमें विश्वरुचि का उल्लेख है, जो ब्रह्मांड में सब कुछ अवशोषित कर लेता है, यानी ब्लैक होल।
5. **भौतिकी और परमाणु ऊर्जा:**
   - परमाणु की अवधारणा का पता आचार्य कणाद द्वारा लगाया गया है। कणाद ने दर्शन के वैशेषिक स्कूल की स्थापना की जहां उन्होंने परमाणु और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में अपने विचार सिखाए।
   - वर्तमान में भारत उन देशों में से एक है, जिनके पास परमाणु तकनीक है।

निष्कर्ष:

जैसा कि ऊपर बताया गया है, आधुनिक विज्ञान जो आज भारत में और अन्य देशों में मौजूद हैं, उनकी जड़ें भारत के प्राचीन वैज्ञानिक

अतीत में हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई प्रगति भारत में मौजूद बुनियादी मूलभूत ज्ञान में देखी जा सकती हैं। मध्यकाल में इस ज्ञान का प्रसार अरबों और फारसियों द्वारा प्राचीन भारतीय पुस्तकों के अनुवाद के माध्यम से किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के विकास ने भारत के ज्ञान को यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों तक पहुँचाया।

13. हड़प्पा सभ्यता की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत की व्याख्या करें, इसकी उन्नत सामाजिक विशेषताओं, ज्यामितीय सटीकता, परिष्कार, विस्तार पर ध्यान देते व्याख्या करें।

परिचय:

तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान, पश्चिमी भारत में फैले सिंधु नदी के किनारे एक संपन्न सभ्यता का उदय हुआ। इस सभ्यता के उल्लेखनीय पहलू इसकी कल्पनाशील रचनात्मकता और कलात्मक संवेदनाएँ थीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्रमुख शहर इस सभ्यता की उल्लेखनीय उपलब्धियों के उदाहरण हैं।

मुख्य भाग:

सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं:

टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर:

- **लेआउट:** शहरों को सावधानीपूर्वक एक आयताकार ग्रिड पैटर्न में रखा गया था, जिसमें उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम दिशा में चलने वाली सड़कें समकोण पर काटती थीं।
- **निर्माण:** निर्माण के लिए मानकीकृत आयामों की पकी ईंटों का उपयोग किया गया था, और बड़ी सड़कों ने घरों को मुख्य सड़कों से जोड़ने वाली छोटी गलियों के द्वारा शहरों को ब्लॉकों में विभाजित कर दिया था।
- **भवनों के प्रकार:** आवास गृहों, सार्वजनिक भवनों और सार्वजनिक स्नानागारों के अवशेष खोजे गए हैं।
- **योजना:** शहरों को दो भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पश्चिमी खंड में एक ऊंचा गढ़ था, जिसमें अन्न भंडार, प्रशासनिक भवन और आंगन जैसी बड़ी संरचनाएं थीं। कुलीन वर्ग गढ़ में निवास करता था।
- **अन्न भंडार:** अन्न भंडार में रणनीतिक वायु मार्ग थे और भंडारण के लिए ऊंचे मंच थे, जो अनाज को कीटों से बचाते थे। उदाहरणों में मोहनजोदड़ो में बड़ा अन्नभंडार और हड़प्पा में छः अन्नभंडार की दो कतारें शामिल हैं।
- **सार्वजनिक स्नानागार:** सार्वजनिक स्नानागारों की उपस्थिति सिंधु घाटी संस्कृति में अनुष्ठानिक सफाई को दिए गए महत्व को इंगित करती है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, विशेष रूप से, अपनी उल्लेखनीय इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, जिसमें कोई दरार या रिसाव नहीं है।
- **ड्रेनेज सिस्टम:** परिष्कृत ड्रेनेज सिस्टम एक विशिष्ट विशेषता है, जिसमें घरों से निकलने वाली छोटी नालियां मुख्य सड़कों के साथ-साथ बड़ी नालियों से जुड़ती हैं। समय-समय पर रखरखाव के लिए नालों को ढीला ढका गया था, और नियमित अंतराल पर सेसपिट लगाए गए थे।
- **मुहरों का उपयोग:** मुहरों का मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था, और वे वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार और त्रिकोणीय सहित विभिन्न आकारों में आती थीं। कुछ मुहरों का उपयोग ताबीज के रूप में भी किया जाता था, और मुहरों पर पाई गई चित्रात्मक लिपियाँ उनके संभावित शैक्षिक उपयोग का संकेत देती हैं। उदाहरण के लिए यूनिकॉर्न मुहर और पशुपति मुहर शामिल हैं।
- **ब्रॉन्ज कास्टिंग:** ब्रॉन्ज कास्टिंग व्यापक रूप से उपयोग में थी, जिसमें लॉस्ट वैक्स तकनीक या साइर पेरड्यू तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। उल्लेखनीय कांस्य कलाकृतियों में मोहनजोदाड़ो की नृत्य करने वाली लड़की और कालीबंगन की कांस्य बैल शामिल हैं।
- **मिट्टी के बर्तन:** लाल और काले मिट्टी के बर्तनों सहित सादे और चित्रित मिट्टी के बर्तनों का उपयोग छिद्रों के माध्यम से भंडारण, सजावट और शराब को छानने के लिए किया जाता था।
- **आभूषण और वस्त्र:** पुरुषों और महिलाओं दोनों ने हार, पट्टिका, बाजूबंद और अंगूठियों जैसे आभूषणों का उपयोग खुद को सजाने के लिए करते थे। महिलाओं भी करधनी और पायल पहनी थी। नीलम, क्वार्ट्ज और सेलखड़ी जैसी विभिन्न सामग्रियों से बने मनके लोकप्रिय थे। कपड़े के लिए कपास और ऊन का उपयोग किया जाता था, और तकली और कोड़े महँगे मिट्टी या सस्ती मिट्टी से तैयार किए जाते थे।

डॉकयार्ड:

- लोथल, जिसे ''सिंधु घाटी के मैनचेस्टर'' के रूप में जाना जाता है, में एक अच्छी तरह से संरक्षित डॉकयार्ड था।
- साइट में जहाज के अवशेष और कोणों को मापने के उपकरण मौजूद थे।
- लोथल के डॉकयार्ड को दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड माना जाता है, जो शहर को साबरमती नदी के एक प्राचीन मार्ग से जोड़ता है।
- गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए उत्खनन से समुद्री माइक्रोफॉसिल्स और नमक क्रिस्टल प्राप्त हुए, जिनसे यह ज्ञात हुआ कि संरचना वास्तव में एक डॉकयार्ड थी।

निष्कर्ष:

सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन, चार प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी। इसकी विशेषताएं, जैसे सड़कों, घरों, जल निकासी प्रणालियों और उल्लेखनीय इंजीनियरिंग कौशल के सावधानीपूर्वक नियोजित नेटवर्क, उस युग के दौरान मौजूद उन्नत ज्ञान और रचनात्मकता को दर्शाते हैं और आज भी संशोधित रूप में जारी हैं।

14. उपनिवेशवाद के व्यापक और गहरे प्रभाव को देखते हुए, जिसका असर दुनिया भर में उपनिवेशित क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ा है, भारत की वर्तमान स्थिति किस हद तक अपने औपनिवेशिक अतीत के स्थायी प्रभाव को दर्शाती है?

परिचय:

उपनिवेशवाद, जिसे किसी राष्ट्र की प्रणाली या नीति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत अन्य लोगों या क्षेत्रों पर अपना अधिकार बढ़ाने या बनाए रखने की मांग करता है, इसमें आर्थिक निष्कर्षण के उद्देश्य से लोगों के जीवन और संस्कृतियों का वर्चस्व शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य उपनिवेश से आर्थिक लाभ प्राप्त करना है।

मुख्य भाग:

भारत और उपनिवेशवाद:

- प्रत्यक्ष भारत-यूरोपीय वाणिज्य व्यापार की प्रक्रिया वास्को डी गामा द्वारा 1498 में भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज के साथ शुरू हुई। पुर्तगालियों ने शीघ्र ही गोवा, दमन, दीव और मुंबई में व्यापारिक चौकियां स्थापित कीं।
- डच, अंग्रेज और फ्रेंच ने इसका अनुसरण किया। भारतीय राज्यों के बीच आंतरिक संघर्षों, यूरोपीय लोगों की तकनीकी श्रेष्ठता और वाणिज्य के आर्थिक लाभों के कारण, यूरोपीय व्यापारियों ने धीरे-धीरे राजनीतिक और सैन्य प्रभाव प्राप्त किया और भूमि हड़प ली।
- हालाँकि विभिन्न यूरोपीय शक्तियों ने दक्षिणी और पूर्वी भारत के क्षेत्रों को नियंत्रित किया, लेकिन अंततः उन्होंने पांडिचेरी, त्रावणकोर में डच बंदरगाह और गोवा, दमन और दीव की पुर्तगाली उपनिवेशों जैसी कुछ चौकियों को छोड़कर, ब्रिटिशों ने क्षेत्र जीत लिए।

उपनिवेशवाद का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव:

- बाजारों का विऔद्योगीकरण पहली दुनिया के देशों की विषम औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप हुआ, जिससे विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ गई।
- वाणिज्यवाद उपनिवेशवाद का कारण और प्रभाव दोनों था, क्योंकि व्यापारिक आर्थिक नीतियों ने उपनिवेशीकरण और औपनिवेशिक शोषण के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य किया और व्यापारिक पूंजीवाद की विचारधारा को और मजबूत किया, जिससे उपनिवेशवादियों के लिए व्यापार की मात्रा में वृद्धि हुई और उपनिवेशों के लिए आनुपातिक दुष्प्रभाव हुए।
- उपनिवेशवाद के आर्थिक प्रभाव में उत्पादन और व्यापार पर नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और बुनियादी ढांचे में सुधार के माध्यम से धन की निकासी शामिल थी।
- राजनीतिक वंचना ने भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की अनुपस्थिति को अनिवार्य कर दिया, कानून और नियम पूरी तरह से अंग्रेजों के कल्याण के लिए बनाए गए थे। भारतीयों की प्रशासन में न्यूनतम भागीदारी थी, और भारतीयों के कल्याण के संबंध में निर्णय ब्रिटेन में प्रशासकों द्वारा लिए जाते थे।
- श्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उपनिवेशवादियों ने शुरू में देशी आबादी को गुलाम बनाने का सहारा लिया। हालांकि, देशी आबादी में गिरावट के साथ, अफ्रीका से दासों को एक आकर्षक विकल्प के रूप में आयात किया गया था।
- सामाजिक असमानता व्याप्त थी क्योंकि भारतीयों को अंग्रेजों की तुलना में हीन माना जाता था, उनके हितों और परंपराओं की अवहेलना की जाती थी। उचित सम्मान प्राप्त किए बिना भारतीयों को ब्रिटिश सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप होने के लिए मजबूर किया गया। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच समानता न के बराबर थी।
- कोलंबियन एक्सचेंज यूरोपीय औपनिवेशीकरण और व्यापार के परिणामस्वरूप 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान अमेरिका और यूरेशिया के बीच पौधों, जानवरों, संस्कृति, मानव आबादी, प्रौद्योगिकी और विचारों के व्यापक आदान-प्रदान को संदर्भित करता है।
- अफ्रीकी महाद्वीप में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा ने जातीय, भाषाई और जलवायु परिस्थितियों की जमीनी वास्तविकताओं को अनदेखा करके केवल अधिकतम लाभ कमाने के लिए, देश की सीमा के अनुचित और अप्राकृतिक विभाजन का कारण बना। प्राकृतिक और मानव संसाधनों के शोषण पर आधारित इस औपनिवेशिक मंशा के परिणामस्वरूप जातीय संघर्ष, देशों के बीच सीमा विवाद, धार्मिक तनाव और कई अन्य के रूप में अफ्रीकी देशों के बीच और भीतर लगातार तनाव बना रहा। इथियोपिया में गृह युद्ध, दक्षिण सूडान की स्तिथि, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में संघर्ष आदि को अफ्रीकी उपमहाद्वीप में औपनिवेशिक नियमों के परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- अफ्रीकी महाद्वीप से गुलामों के रूप में या भारतीय उपमहाद्वीप (विशेषकर उत्तर भारत से) 'गिरमिटिया मजदूरों' (विश्व 'गिरिमिटिया'

'समझौते' का एक रूप है) के रूप में जबरन प्रवासन के परिणामस्वरूप इन प्रवासियों को शोषण के रूप में भारी कष्टों का सामना करना पड़ा। कई नागरिक युद्ध, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में जातीय तनाव, मध्य अमेरिकी देशों, लैटिन अमेरिकी देशों और प्रशांत द्वीप राष्ट्रों को दुनिया भर में विभिन्न उपनिवेशों से फोर्स माइग्रेशन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

वर्तमान समय में भारत के औपनिवेशिक अतीत का प्रभाव:

- आज की दुनिया की समस्याओं और खतरों को समझने में उपनिवेशवाद एक प्रासंगिक कारक बना हुआ है। हमारी बहुत सी समस्याओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद के प्रभाव और औपनिवेशिक शासकों की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- 1857 के बाद उपमहाद्वीप में ब्रिटिश नीति द्वारा ''फूट डालो और राज करो'' की औपनिवेशिक प्रशासनिक नीति ने व्यवस्थित रूप से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच राजनीतिक विभाजन को बढ़ावा दिया, जिसका अंत दुखद विभाजन से हुआ।
- औपनिवेशिक काल के दौरान खींची गई सीमाएं, स्वतंत्रता के बाद अपरिवर्तित होने के बावजूद, राष्ट्रीय एकता में अत्यधिक समस्याएं पैदा कर रही हैं।
- एक गरीब देश में अवसंरचना का असमान विकास, उपनिवेशवादियों के लाभों को प्राथमिकता देना, संसाधनों के असमान वितरण का कारण बन सकता है, जो सड़कों, रेलवे, बिजली स्टेशनों, दूरसंचार, पुलों और नहरों के द्वारा उपेक्षित क्षेत्रों के बीच समाज को आगे विभाजित कर सकता है।
- वैश्विक पूंजीवाद में खिलाड़ी बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे कई दक्षिणी देशों में बढ़ते अविकसितता के परिणामस्वरूप अत्यधिक गरीबी, पारिस्थितिक पतन और जड़विहीन, बेरोजगार आबादी कमजोर राज्य प्रणालियों के नियंत्रण से बाहर हो गई है।
- आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों और इन क्षेत्रों में विकास की कमी के कारण देश में वामपंथी उग्रवाद, उत्तर-पूर्व में जातीय संघर्ष जैसे मणिपुर में हाल ही में चल रही हिंसा और कई अन्य प्रमुख समस्याएं हैं।

निष्कर्ष:

उपनिवेशवाद का विश्व और भारत पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। आज की कई समस्याएँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से औपनिवेशिक परिणामों से जुड़ी हैं। भारत के औपनिवेशिक अतीत का वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जबकि भारत ने आजादी के बाद के दशकों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, उपनिवेशवाद की विरासत पर काबू पाने में अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

15. क्या आप मानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण, जिसमें कांग्रेस द्वारा याचिकाओं के माध्यम से मांग करना और अपने शुरुआती दो दशकों के दौरान कानून की सीमाओं के भीतर काम करना शामिल है, को विफलता के रूप में माना जाना चाहिए? समालोचनात्मक विश्लेषण करें।

परिचय:

नरमपंथियों ने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक चरम दृष्टिकोण के बजाय एक उदारवादी दृष्टिकोण के द्वारा, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्व-शासन प्राप्त करना था।

मुख्य भाग:

उदारवादी चरण के लक्षण:

- नरमपंथियों की राजनीतिक माँगें अपेक्षाकृत नरम थीं:
- 1885 और 1892 के बीच, उनका मुख्य ध्यान विधान परिषदों के विस्तार और सुधार, लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की वकालत और इन परिषदों के लिए शक्तियों में वृद्धि पर था।
- उन्होंने भारत में भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) परीक्षा आयोजित करने की वकालत की, जिससे अधिक भारतीय प्रशासन में भाग ले सके।
- उन्होंने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने पर जोर दिया।
- उन्होंने भाषण, अभिव्यक्ति और संघों के गठन की स्वतंत्रता की मांग की।
- उन्होंने 1878 के शस्त्र अधिनियम को निरस्त करने का आह्वान किया।
- उन्होंने भारतीय शिक्षा पर खर्च बढ़ाने पर जोर दिया।

हालाँकि, नरमपंथियों की आर्थिक माँगें अधिक कट्टरपंथी थीं:-

- विशेष रूप से, नरमपंथी प्रेस और प्रकाशनों के माध्यम से ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की व्यवस्थित और तथ्य-आधारित आलोचना में लगे हुए थे।
- दादाभाई नौरोजी द्वारा लोकप्रिय ड्रेन सिद्धांत, यह तर्क देते हुए राष्ट्रवादी आलोचना का केंद्र बिंदु बन गया कि ब्रिटेन आर्थिक रूप से भारत

का शोषण कर रहा है।

- अन्य राष्ट्रवादी नेताओं जैसे आर.सी. दत्त ने अपनी रचनाओं में नौरोजी के विचारों को प्रतिध्वनित किया।
- नरमपंथियों ने सार्वजनिक वित्त पर भारतीय नियंत्रण की मांग की, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से ''प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं'' का नारा दिया।
- उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बढ़े हुए आवंटन के साथ सैन्य खर्च में कमी की वकालत की।
- उन्होंने भू-राजस्व में कमी, नमक कर को समाप्त करने, और धनी और मध्यम वर्ग द्वारा उपभोग किए जाने वाले उत्पादों पर आयकर और आयात शुल्क का समर्थन करने का आह्वान किया।
- विदेशी पूंजी को नौरोजी और अन्य लोगों द्वारा भारतीय संसाधनों के शोषण और विनाश के रूप में देखा गया था।
- उन्होंने आयात पर अधिक टैरिफ और सरकारी समर्थन के माध्यम से भारतीय उद्योगों के विकास और संरक्षण की मांग की।
- भारतीय वस्तुओं का उपयोग करके और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करके भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने वाले स्वदेशी के विचार ने लोकप्रियता हासिल की।

उदारवादी चरण की सीमाएँ इस प्रकार थीं:-

- कई नरमपंथियों ने ब्रिटिश शासन को आधुनिकीकरण के संभावित साधन के रूप में देखा।
- अंग्रेजी जनतांत्रिक उदारवादी राजनीतिक परंपरा में उनकी आंतरिक आस्था के कारण उनमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठन और आंदोलन का अभाव था।
- उनके लक्ष्य और तरीके सीमित थे, वे पूर्ण निष्कासन के बजाय ब्रिटिश शासन के भीतर सुधार चाहते थे।
- उन्होंने स्वतंत्रता को वर्ग विशेषाधिकार के साथ जोड़ा और छोटे-छोटे सुधारों का समर्थन किया।
- कांग्रेस के शुरुआती सदस्यों को अधिक लोकप्रिय तरीकों के बजाय शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन में विश्वास था।
- आंदोलन में मुख्य रूप से शिक्षित वर्ग शामिल थे और जनता की भागीदारी में विश्वास की कमी के कारण, प्रभावी ढंग से शामिल नहीं किया।
- उनकी तत्काल मांग पूरी आबादी को शामिल करने के बजाय शिक्षित भारतीयों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों पर केंद्रित थी।

हालाँकि, उदारवादी चरण में कुछ सफलताएँ मिलीं:-

- नौरोजी, दत्त और वाचा जैसे नरमपंथियों ने ब्रिटिश शासन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया और भारत के ब्रिटिश शोषण की व्याख्या करने के लिए ष्ड्रेन सिद्धांतष प्रस्तुत किया।
- उन्होंने भारत की गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण के रूप में ब्रिटिश शासन पर प्रकाश डालते हुए एक अखिल भारतीय जनमत तैयार किया। उनकी मांगों में भू-राजस्व को कम करना, नमक कर को समाप्त करना और बागान श्रमिकों के लिए काम करने की स्थिति में सुधार करना शामिल था।
- उन्होंने परिषदों के विस्तार और सुधार में योगदान दिया, जिससे अधिक भारतीय भागीदारी और वित्त पर नियंत्रण की अनुमति मिली।
- उन्होंने लोकतांत्रिक स्वशासन के दीर्घकालिक उद्देश्य की दिशा में काम किया।
- उन्होंने सामान्य प्रशासनिक सुधारों, सरकारी सेवाओं के स्वदेशीकरण, और न्यायिक और कार्यकारी कार्यों को अलग करने के लिए अभियान चलाया।
- उन्होंने दमनकारी नौकरशाही, एक महंगी न्यायिक प्रणाली, आक्रामक विदेश नीतियों की आलोचना की और कल्याण, शिक्षा और कृषि सुध ारों की वकालत की।
- उन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार, संघ, और एक स्वतंत्र प्रेस, लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार और स्वतंत्रता संग्राम में नागरिक अधिकारों को शामिल करना शामिल है।

निष्कर्ष:

नरमपंथियों ने एक राष्ट्रीय आंदोलन के निर्माण और साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, जनता, विशेष रूप से महिलाओं को शामिल करने और सार्वभौमिक मताधिकार की मांग करने में उनकी विफलता ने आंदोलन के लोकतांत्रिक आधार को सीमित कर दिया। इन सीमाओं के बावजूद, उदारवादी चरण ने राजनीतिक जागरूकता, परिषदों के सुधार, आर्थिक आलोचना और नागरिक अधिकारों की रक्षा के मामले में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
2. अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन (आईएसओ) अंतर-सरकारी स्तर पर प्रमुख चीनी उत्पादक, उपभोक्ता और व्यापारिक देशों द्वारा विचारों के आदान-प्रदान के लिए एकमात्र विश्वव्यापी मंच है।
3. ब्राजील 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करने वाला है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी 3
D. कोई नहीं

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ग्रेट निकोबार द्वीप भारत का सबसे दक्षिणी छोर है।
2. ग्रेट निकोबार जारवा जनजातियों का घर है।
3. लेदरबैक कछुआ और निकोबार मेगापोड वन्यजीव (संरक्षण अधिनियम), 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी 3
D. कोई नहीं

3. लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 'प्रोटेम स्पीकर' शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है।
2. अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है।
3. अध्यक्ष का चुनाव भारत के प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित तिथि को होता है।
4. दसवीं अनुसूची अध्यक्ष को अपने पद पर निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा देने की अनुमति देती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल दो
B. केवल तीन
C. सभी चार
D. कोई नहीं

4. नोटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, इंदौर लोकसभा को देश में लोकसभा चुनावों के इतिहास में सबसे अधिक नोटा वोट मिले।
2. नोटा को भारत में पहली बार 2014 में पेश किया गया था।
3. नोटा में वोटों की गिनती की जाती है लेकिन यह चुनाव परिणाम को प्रभावित नहीं करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी 3
D. कोई नहीं

5. लिविंग विल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश सोनक गोवा में लिविंग विल पंजीकृत करने वाले पहले व्यक्ति बने
2. लिविंग विल, जिसे उन्नत चिकित्सा निर्देश के रूप में भी जाना जाता है, एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की जीवन के अंत में चिकित्सा उपचार वरीयताओं को रेखांकित करता है।
3. इसका उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहां रोगी स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं।
4. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध कर दिया, जो व्यक्ति के पास लिविंग विल होने पर निर्भर करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 4
C. केवल 1, 2 और 3
D. 1, 2, 3 और 4

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि सहकारी समितियों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का अनुपालन करना आवश्यक नहीं है।
2. न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि तमिलनाडु सहकारी

समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी समिति आरटीआई अधिनियम की सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है।

3. यह फैसला पिछले सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप है, जिसमें लगातार यह माना गया है कि सहकारी समितियां आरटीआई अधिनियम के अधीन नहीं हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी 3
D. कोई नहीं

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अटल इनोवेशन मिशन (AIM) ने ओपन इनोवेशन वाटर चैलेंज (AIM – ICDK वाटर चैलेंज 4.0) के चौथे संस्करण को लॉन्च करने के लिए इनोवेशन सेंटर डेनमार्क (ICDK) के साथ सहयोग किया है।
2. इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण जल-संबंधी चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान खोजना है।
3. यह चैलेंज भारत-डेनमार्क द्विपक्षीय हरित रणनीतिक साझेदारी का एक हिस्सा है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी 3
D. कोई नहीं

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं।
2. कैबिनेट समितियाँ सीधे संसद को रिपोर्ट करती हैं।
3. कैबिनेट समितियों का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी 3
D. कोई नहीं

9. निम्नलिखित पर विचार करें कथन:

1. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 15 जून, 2024 को साइबरस्पेस संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी किया।
2. सिद्धांत आधुनिक युद्ध के जटिल सैन्य परिचालन वातावरण में साइबरस्पेस संचालन और युद्ध प्रयासों के संचालन में कमांडरों का मार्गदर्शन करेगा।
3. इसका उद्देश्य भारतीय सेना की तीनों सेवाओं के बीच संचालन को सुव्यवस्थित करने में मदद करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी 3
D. कोई नहीं

10. डाकघर अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. डाकघर अधिनियम 2023 18 जून, 2024 को लागू हुआ, जिसने 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त कर दिया।
2. अधिनियम अब केंद्र को किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने या रोकने और उसे सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंपने की अनुमति देता है।
3. अधिनियम में राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा या अन्य कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के लिए प्रावधान नहीं हैं।
4. अधिनियम पहली बार निजी कूरियर सेवाओं को भी नियंत्रित करता है।
5. अधिनियम की धारा 12 डाकघर और उसके अधिकारियों को सेवा के दौरान नुकसान, गलत डिलीवरी, देरी या क्षति के लिए किसी भी दायित्व से छूट देती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 1, 2 और 4
C. केवल 1, 2 और 5
D. 1, 2, 3, 4 और 5

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत ने 2023-24 में अपने शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से नौ के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया।
2. चीन, रूस, कोरिया और हांगकांग के साथ 2022-23 की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में व्यापार घाटा बढ़ा।
3. यूएई, सऊदी अरब, रूस, इंडोनेशिया और इराक के साथ व्यापार घाटा कम हुआ।
4. चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका दोतरफा वाणिज्य मूल्य 118.4 बिलियन डॉलर है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4
C. केवल 1, 2 और 3
D. 1, 2, 3 और 4

12. लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII) को 363 के रूप में अधिसूचित किया है।
2. CII का उपयोग परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है और मुद्रास्फीति के लिए समायोजन करते समय करदाताओं के लिए आवश्यक है।
3. पिछले वित्त वर्ष के लिए CII 348 था और 2022-23 के लिए यह 331 था।
4. CII में वृद्धि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को दर्शाती है, जिसके कारण समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 4
C. केवल 1, 2 और 3
D. 1, 2, 3 और 4

13. एसआरओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक क्षेत्र में स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) के लिए एक ढांचा स्थापित किया है।
2. एसआरओ को बाहरी प्रभाव से मुक्त स्वतंत्र निकायों के रूप में कार्य करना चाहिए।
3. एसआरओ को नियामक मानकों को स्थापित और लागू करना, विवादों को सुलझाना और नैतिक आचरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
4. एसआरओ के पास विविध शेयरधारिता होनी चाहिए, जिसमें कोई भी इकाई अपनी चुकता शेयर पूंजी का 20% से अधिक नहीं रख सकती।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 4
C. केवल 1, 2 और 3
D. 1, 2, 3 और 4

14. बाजरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत एशिया में बाजरे के उत्पादन का 80% और विश्व स्तर पर 20% उत्पादन करता है।
2. भारत में बाजरे की उत्पादकता चीन, इथियोपिया और रूस जैसे अन्य प्रमुख उत्पादकों की तुलना में कम है।
3. बाजरे को आमतौर पर वर्षा आधारित परिस्थितियों में उगाया जाता है, लेकिन सुनिश्चित सिंचाई से उपज में सुधार हो सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी 3
D. कोई नहीं

15. GAAR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. तेलंगाना उच्च न्यायालय ने जनरल एंटी-एवॉइडेंस रूल (GAAR) के मामले में एक करदाता के खिलाफ फैसला सुनाया, जो 1 अप्रैल, 2017 को लागू होने के सात साल बाद GAAR पर पहला फैसला है
2. GAAR कर अधिकारियों को ऐसे लेनदेन या व्यवस्थाओं पर कर लाभ से इनकार करने का अधिकार देता है जिनका कोई वाणिज्यिक सार नहीं है और जिनका एकमात्र उद्देश्य कर से बचना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. उपरोक्त सभी
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

16. विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 को UNCTAD (संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन) द्वारा 20 जून, 2024 को जारी किया गया था।
2. वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 2023 में 2% घटकर $1.3 ट्रिलियन रह गया।
3. सतत विकास लक्ष्य क्षेत्रों के लिए नए वित्तपोषण में 10% से अधिक की गिरावट आई।
4. भारत में FDI में 43% की गिरावट देखी गई, जो $49 बिलियन से $28 बिलियन हो गई।
5. बहुराष्ट्रीय निगम 2023 में अधिक सावधान हो गए, जिससे FDI में समग्र गिरावट आई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 1, 2 और 4

C. केवल 1, 2 और 5
D. 1, 2, 3, 4 और 5

17. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, भारत ने 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक (ATCM-46) और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति (CEP-26) की सफलतापूर्वक मेजबानी की।
2. पार्टियों ने अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्रों (ASPA) के लिए 17 संशोधित और नई प्रबंधन योजनाओं को अपनाया।
3. ATCM-46 लोगो के साथ कस्टमाइज किया गया माईस्टैम्प इंडिया पोस्ट के सहयोग से जारी किया गया।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी 3
D. कोई नहीं

18. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने बताया कि 2022 में, विकसित देशों ने विकासशील देशों को जलवायु वित्त में $115.9 बिलियन का योगदान दिया।
2. यह उपलब्धि मूल लक्ष्य वर्ष 2020 के दो साल बाद आई है।
3. यह राशि 2021 से 20% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी 3
D. कोई नहीं

19. जबरन विस्थापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी (UNHCR) के अनुसार पिछले पाँच वर्षों में विस्थापन में 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, दुनिया भर में जबरन विस्थापन का स्तर एक नए उच्च स्तर पर पहुँच गया है।
2. मई 2024 में जबरन विस्थापन बढ़कर 120 मिलियन हो गया, जो लगातार 12वीं वार्षिक वृद्धि है।
3. प्रमुख योगदान कारकों में सूडान में प्रतिद्वंद्वी सेनाओं के बीच युद्ध, कांगो और म्यांमार के लोकतांत्रिक गणराज्य में क्रूर लड़ाई और गाजा में संघर्ष शामिल हैं।
4. सीरिया अपनी सीमाओं के भीतर और बाहर दोनों जगह जबरन विस्थापित लोगों की विशाल संख्या का रिकॉर्ड रखता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 4
C. केवल 1, 2 और 3
D. 1, 2, 3 और 4

20. INCOIS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. INCOIS (भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र) ने एल नीनो और ला नीना स्थितियों की भविष्यवाणी करने के लिए एक गहन शिक्षण-आधारित बायेसियन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (BCNN) मॉडल विकसित किया है।
2. यह मॉडल 15 महीने के लीड टाइम के लिए एल नीनो विकास के संभाव्य पूर्वानुमान प्रदान करता है, जो व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली गतिशील पूर्वानुमान प्रणालियों की भविष्यवाणी क्षमता से अधिक है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. उपरोक्त सभी
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

21. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि 2004 से मनुष्यों और पर्यावरण में DDT के स्तर में गिरावट आई है, लेकिन समान गुणों वाले अन्य स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POP) के स्तर में वृद्धि हुई है।
2. स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन की 2004 में पुष्टि के बाद मनुष्यों और पर्यावरण में DDT के स्तर में गिरावट आई है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. उपरोक्त सभी
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

22. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों की कुल संख्या वैश्विक स्तर पर 8.1 मिलियन और भारत में 2.1 मिलियन थी।
2. भारत और चीन, 35% के साथ, वैश्विक वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के बहुमत के लिए जिम्मेदार हैं।
3. भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों की संख्या सबसे अधिक 169,400 थी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी 3
D. कोई नहीं

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ZiG की शुरुआत की।
2. ZiG ने जिम्बाब्वे डॉलर की जगह ली है।
3. केंद्रीय बैंक का उद्देश्य कीमती खनिजों या विदेशी मुद्रा में समतुल्य मूल्य सुनिश्चित करके मुद्रा को मूल्य खोने से रोकना है।
4. जिम्बाब्वे में मौद्रिक अस्थिरता का इतिहास में ZiG 15 वर्षों में शुरू की गई छठी मुद्रा है।
5. सरकार का लक्ष्य स्थानीय मुद्रा में विश्वास बढ़ाना और अमेरिकी डॉलर के उपयोग को कम करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 1, 2 और 4
C. केवल 1, 2 और 5
D. 1, 2, 3, 4 और 5

24. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत और कतर ने 6 जून को नई दिल्ली में निवेश पर संयुक्त कार्यबल (JTFI) की उद्घाटन बैठक आयोजित की।
2. दोनों देशों ने कतर और भारत के बीच निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यबल के साथ-साथ ऊर्जा पर एक संयुक्त कार्यबल स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है।
3. कतर भारत का LNG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो भारत के वैश्विक LNG आयात का 48 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी 3
D. कोई नहीं

25. 50वें जी7 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 50वां जी7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून, 2024 तक इटली के अपुलिया के फसानो में आयोजित किया गया था।
2. शिखर सम्मेलन में G7 सदस्य देशों के नेताओं, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने भाग लिया था।
3. पोप फ्रांसिस ने इतिहास में पहली बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
4. G7 नेताओं ने 2028 के अंत तक यूक्रेन को 50 बिलियन डॉलर का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 4
C. केवल 1, 2 और 3
D. 1, 2, 3 और 4

26. परमाणु शस्त्रागार पर सिपरी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया के लगभग 90% परमाणु हथियार हैं।
2. जनवरी 2024 में परमाणु हथियारों की वैश्विक सूची 12,121 थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 391 कम है।
3. भारत ने अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार किया है, अब उसके पास 172 परमाणु हथियार हैं, जो पाकिस्तान के 170 हथियारों से अधिक है।
4. चीन के परमाणु शस्त्रागार में 2023 में 410 से बढ़कर 500 वारहेड हो गए हैं।
5. संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल सहित सभी नौ परमाणु-सशस्त्र राज्य अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहे हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 1, 2 और 4
C. केवल 1, 2 और 5
D. 1, 2, 3, 4 और 5

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत और कंबोडिया व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके डिजिटल भुगतान पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की।
2. देश दवा क्षेत्र में निवेश संधि और सहयोग पर भी चर्चा की।
3. कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) का सदस्य है और भारत के साथ उसका मुक्त व्यापार समझौता है।
4. भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 366.44 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 403.78 मिलियन डॉलर हो गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 4
C. केवल 1, 2 और 3
D. 1, 2, 3 और 4

28. PREFIRE मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर

विचार करें:

1. PREFIRE भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत है।
2. यह 2024 में लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को सुविधाजनक बनाना है।
3. पोत का संचालन राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR) द्वारा किया गया है।
4. PREFIRE विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और उपकरणों से सुसज्जित है।
5. अनुसंधान फोकस क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन, समुद्र विज्ञान, भूविज्ञान और जीव विज्ञान शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 1, 2 और 4
C. केवल 1, 2 और 5
D. 2, 3, 4 और 5

29. वायरल संक्रमण का पता लगाने के लिए नए प्रकाश-आधारित उपकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उपकरण संक्रमित कोशिकाओं से गुजरते समय प्रकाश में विकृतियों का पता लगाने के लिए एक सरल माइक्रोस्कोप का उपयोग करता है।
2. उपकरण वायरियन को निष्क्रिय करने के लिए स्पेक्ट्रम में प्रकाश का उपयोग करता है।
3. यह विधि लिफाफे वाले वायरस के प्रसार को रोक सकती है।
4. यह विधि वायरियन को निष्क्रिय करने के लिए आयनकारी विकिरण (गामा किरण, एक्स-रे, न्यूट्रॉन और उच्च ऊर्जा पराबैंगनी) और गैर-आयनकारी फोटो-निष्क्रियता (लेजर और नीली रोशनी) का उपयोग करती है।
5. यह विधि दवा प्रतिरोध और अन्य अवांछित दुष्प्रभावों के जोखिम के बिना वायरस को निष्क्रिय कर सकती है।
6. यह विधि अन्य सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय करने के लिए भी उपयोगी हो सकती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल तीन
B. केवल चार
C. केवल पाँच
D. सभी छह

30. निडोवायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. निडोवायरस आरएनए वायरस हैं जो कशेरुकियों में महामारी और घातक बीमारियों का कारण बन सकते हैं।
2. इन वायरस में सामान्य विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य आरएनए वायरस से अलग करती हैं।
3. निडोवायरस विभिन्न कशेरुकियों में पाए जा सकते हैं, मछली से लेकर कृंतक तक, जिनमें कोरोनावायरस भी शामिल हैं।
4. ये वायरस विभिन्न प्रजातियों के बीच आनुवंशिक सामग्री का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 4
C. केवल 1, 2 और 3
D. 1, 2, 3 और 4

31. 3D प्रिंटेड रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अग्निकुल कॉसमॉस ने पूरी तरह से 3D-प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया।
2. आईआईटी मद्रास में इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस ने 30 मई, 2024 को रॉकेट लॉन्च किया था।
3. रॉकेट 435 मील की कक्षा में 660 पाउंड तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी 3
D. कोई नहीं

32. WIPO की नई संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) ने बौद्धिक संपदा अधिकारों और आनुवंशिक संसाधनों के संबंध में एक संधि की है।
2. संधि पेटेंट आवेदकों के लिए आनुवंशिक संसाधनों की उत्पत्ति का खुलासा करना अनिवार्य बनाती है यदि आविष्कार उन सामग्रियों या संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है।
3. इसका उद्देश्य भारत जैसे देशों के आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना है।
4. संधि के तहत देशों को पेटेंट आवेदकों के खुलासे के लिए अपने कानूनी ढांचे में बदलाव करना होगा।
5. संधि को 24 मई, 2024 को अपनाया गया था और इस पर 192 देशों और 86 पर्यवेक्षकों ने सहमति दी थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 1, 2 और 4
C. केवल 1, 2 और 5

D. 1, 2, 3, 4 और 5

33. IIT बॉम्बे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. IIT बॉम्बे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में 31 पायदान ऊपर चढ़कर 108वें स्थान पर पहुंच गया है।
2. इन रैंकिंग में भाग लेने के बाद से यह पहली बार है कि IIT बॉम्बे को शीर्ष 150 संस्थानों में स्थान दिया गया है।
3. IIT बॉम्बे ने नियोक्ता प्रतिष्ठा के मामले में सबसे बड़ी ताकत दिखाई, इस श्रेणी में वैश्विक रैंक 63 रही।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी 3
D. कोई नहीं

34. रज पर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पहली बार, ओडिशा का कृषि त्योहार, रज पर्व, राष्ट्रपति भवन में मनाया गया।
2. यह त्योहार मानसून की शुरुआत के दौरान मनाया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. कोई नहीं

35. NIIMH के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैदराबाद में राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान (NIIMH) को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए एक सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है।
2. NIIMH आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) के तहत एक इकाई है।
3. NIIMH 'पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान' के लिए पहला WHO सहयोगी केंद्र है।
4. यह मान्यता चार साल की अवधि के लिए दी जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 4
C. केवल 1, 2 और 3
D. 1, 2, 3 और 4

36. इंडिकोनेमा जीनस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इंडिकोनेमा जीनस की खोज पूर्वी घाट में की गई थी।
2. यह प्रजाति सूक्ष्म शैवाल का एक प्रकार है जो दुनिया की 25% ऑक्सीजन आपूर्ति का उत्पादन करती है।
3. यह खोज भारत की अनूठी जैव विविधता को दर्शाती है, क्योंकि भारत में लगभग 6,500 डायटम टैक्सा पाए जाते हैं।
4. माना जाता है कि इंडिकोनेमा पूर्वी अफ्रीका में पाए जाने वाले एक प्रजाति अफ्रोसिमबेला से संबंधित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 4
C. केवल 1, 2 और 3
D. 1, 2, 3 और 4

37. बायोल्यूमिनसेंट मशरूम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बायोल्यूमिनसेंट मशरूम की दुर्लभ प्रजातियों को फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस या 'इलेक्ट्रिक मशरूम' कहा जाता है।
2. ये मशरूम अपनी कोशिकाओं में रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण रात के अंधेरे में एक चमकदार, अलौकिक हरी रोशनी उत्सर्जित करते हैं।
3. इस प्रजाति की खोज केरल के कासरगोड के जंगलों में केरल वन और वन्यजीव विभाग के कासरगोड डिवीजन और मशरूम ऑफ इंडिया समुदाय द्वारा की गई थी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

उत्तर

1.	(B)	11.	(D)	21.	(C)	31.	(C)
2.	(B)	12.	(D)	22.	(B)	32.	(D)
3.	(A)	13.	(C)	23.	(B)	33.	(B)
4.	(B)	14.	(C)	24.	(C)	34.	(C)
5.	(C)	15.	(C)	25.	(C)	35.	(D)
6.	(C)	16.	(D)	26.	(D)	36.	(D)
7.	(C)	17.	(C)	27.	(D)	37.	(C)
8.	(A)	18.	(B)	28.	(D)		
9.	(B)	19.	(D)	29.	(D)		
10.	(B)	20.	(C)	30.	(D)		

प्रीलिम्स आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. वायुमंडलीय अमोनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वायुमंडलीय अमोनिया (NH_3) नाइट्रोजन चक्र का एक प्रमुख घटक है और वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित क्षारीय गैस है।
2. इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक और मानवजनित दोनों स्रोतों से होती है।
3. औद्योगिक प्रदूषण मानवजनित अमोनिया उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने **गलत** हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

2. SWATI Portal के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह STEMM में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक एकल ऑनलाइन पोर्टल है।
2. इसका विकास और रखरखाव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च (NIPGR) द्वारा किया जाता है।
3. यह लैंगिक-अंतराल की चुनौतियों का समाधान करने वाला भारत का पहला पोर्टल है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

3. HAPS प्रौद्योगिकी अपनी क्षमता के कारण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है:

(a) विशाल सीमा क्षेत्रों में वास्तविक समय की इमेजरी और डेटा अधिग्रहण प्रदान करना।
(b) उग्रवाद की आशंका वाले दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर संचार बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराना।
(c) दुश्मन की पहचान सीमा से परे अत्यधिक ऊंचाई वाले टोही मिशनों का संचालन करना।
(d) उपर्युक्त सभी

4. भारत की बंजर भूमि को हरा-भरा करने की कृषि वानिकी (GROW) रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रिपोर्ट हरियाली और बहाली परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों और उद्योगों का समर्थन करने के लिए राज्य-वार और जिला-वार विश्लेषण प्रदान करती है।
2. यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. फ्लोर टेस्ट 1954 में प्रारंभ की गई संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय नवाचार है।
2. अनुच्छेद 163 के तहत, किसी राज्य का राज्यपाल उस समय शक्ति परीक्षण करा सकता है जब सदन का सत्र नहीं चल रहा हो।
3. जब सदन का सत्र चल रहा हो तो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विश्वास मत का आह्वान किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

6. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

	संरक्षित क्षेत्र	**राज्य**
1.	गुप्तेश्वर वन	- झारखण्ड
2.	थानथाई पेरियार अभयारण्य	- केरल
3.	वेदानथंगल पक्षी अभयारण्य	- तमिलनाडु

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

7. e-Jagriti के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक एकीकृत पोर्टल है जो सभी स्तरों पर सरल, तीव्र और लागत प्रभावी उपभोक्ता विवाद निवारण सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करता है।

2. यह विवाद समाधान परिदृश्य में दक्षता और नवीनता को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करता है।
3. इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित, डिजाइन और संरक्षित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

8. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. बेल्ट एंड रोड पहल
2. लिविंग इंडस पहल
3. महान हरित दीवार पहल
4. एक्सियन एंडिना सामाजिक आंदोलन

उपर्युक्त में से कौन सी परियोजनाएँ विश्व पुनर्स्थापना फ्लैगशिप का हिस्सा हैं?
(a) केवल 2 और 3
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

9. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. वांडेरू
2. भारतीय हाथी
3. नीलगिरि तहर
4. ग्रेटर एक सींग वाला गैंडा
5. एशियाई शेर

उपर्युक्त में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है?
(a) केवल 3, 4 और 5
(b) केवल 1, 3 और 5
(c) केवल 2, 3, 4 और 5
(d) केवल 1, 3, 4 और 5

10. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

	जीव		**सहजीवी संबंध**
1.	बार्नाकल और तैरने वाले केकड़े	–	परजीविता
2.	क्लाउनफिश और समुद्री एनीमोन्स	–	सहभोजिता
3.	बार्नाकल और हंपबैक व्हेल	–	पारस्परिकता
4.	मूंगे और स्पंज	–	प्रतिस्पर्धा

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

11. गल्फ स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक गर्म समुद्री धारा है जो मेक्सिको की खाड़ी से निकलती है।
2. यह एक महत्वपूर्ण कन्वेयर बेल्ट के रूप में कार्य करता है और दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है।
3. यह अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) का हिस्सा है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

12. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

	मार्शल आर्ट		**उद्गम राज्य**
1.	क्राव मागा	–	असम
2.	कलारीपयट्टू	–	केरल
3.	गतका	–	पंजाब
4.	खुकुरी नृत्य	–	नागालैंड

उपर्युक्त कितने युग्म सही सुमेलित हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

13. प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे बॉन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वावधान में एक पर्यावरण संधि है।
2. यह एकमात्र वैश्विक और संयुक्त राष्ट्र-आधारित अंतरसरकारी संगठन है जो विशेष रूप से स्थलीय, जलीय और प्रवासी पक्षी के प्रजातियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है।
3. जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (COP-14) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक ब्राजील सरकार द्वारा आयोजित की गई है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

14. चुनावी बांड के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चुनावी बांड ब्याज मुक्त वाहक बांड या धन उपकरण हैं जिन्हें भारत में कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकता है।
2. ये बांड 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में उपलब्ध हैं।
3. चुनावी बांड केवल 15 दिनों के लिए वैध हैं और इसका उपयोग राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

15. माइसेलर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. माइसेलर जल उत्पादों में मिसेल्स होते हैं, जो अणुओं के समूह होते हैं और चिकने संदूषकों को समाप्त करने में बेहद प्रभावी होते हैं।
2. यह आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला त्वचा देखभाल करने वाला उत्पाद है जो आपकी त्वचा से अशुद्धियाँ और मेकअप हटाने में मदद करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

16. कैसिनी अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कैसिनी-ह्यूजेंस शनि पर नासा, ईएसए और इसरो का एक सहयोगी मिशन था।
2. यह 2015 में लॉन्च किए गए सबसे बड़े अंतरग्रहीय अंतरिक्षयान में से एक था।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

17. यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह वर्ष 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है।
2. इसका उद्देश्य यूरोप और वैश्विक स्तर पर अपने सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

18. निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार कीजिए:

यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है। यह सतपुड़ा की मैकाल श्रेणी में बसा है, जो भारत का हृदय है और मध्य भारतीय उच्चभूमि का निर्माण करता है। रुडयार्ड किपलिंग के प्रसिद्ध उपन्यास, द जंगल बुक में चित्रित जंगल को कुछ लोग जंगलों पर आधारित मानते हैं, जिसमें यह अभ्यारण्य भी शामिल है। यह आधिकारिक तौर पर शुभंकर," भूरसिंह द बारासिंघा " आरम्भ करने वाला भारत का पहला बाघ अभयारण्य भी है। पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ, स्लॉथ भालू और भारतीय जंगली कुत्ते की महत्वपूर्ण/सार्थक आबादी है।

उपर्युक्त अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य से संबंधित है?

(a) पन्ना टाइगर रिजर्व
(b) पेंच टाइगर रिजर्व
(c) बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
(d) कान्हा टाइगर रिजर्व

19. कार्यक्रम (YUVIKA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. YUVIKA, शहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता देने वाले युवा छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के लिए इसरो का एक शिक्षण और जागरूकता उत्पन्न करने वाला कार्यक्रम है।
2. जिन छात्रों ने 10वीं कक्षा पूरी कर ली है और वर्तमान में 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, वे कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
3. प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से दो छात्र हर साल इस कार्यक्रम में भाग लेंगे , जिसमें CBSE, ICSE और राज्य-बोर्ड पाठ्यक्रम शामिल होंगे।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

20. एंटी-सैटेलाइट हथियार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे उन उपग्रहों को निष्क्रिय करने या नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है जो पहले से ही कक्षा में हैं और सक्रिय हैं।
2. ये सभी हमले हवाई, निचली कक्षा या यहां तक कि जमीनी प्रतिष्ठानों से भी शुरू किए जा सकते हैं।
3. 'मिशन शक्ति' भारत का पहला एंटी-सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

21. इंडिया स्टैक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) का एक सेट है जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप और डेवलपर्स को एक अद्वितीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने की अनुमति देता है।
2. चूंकि इस परियोजना के नाम में इंडिया शब्द है, इसलिए इंडिया स्टैक का दृष्टिकोण केवल भारत तक ही सीमित है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

22. म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर संवाद के लिए विश्व का अग्रणी मंच है।
2. इसका आयोजन यूरोपीय संघ द्वारा किया जाता है।
3. इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय के तहत निरंतर, क्यूरेटेड और अनौपचारिक बातचीत को बनाए रखते हुए विश्वास का निर्माण करना और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान में योगदान देना है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

23. मध्य एशियाई फ्लाईवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह आर्कटिक और हिंद महासागरों तथा संबंधित द्वीप श्रृंखलाओं के मध्य यूरेशिया के एक बड़े महाद्वीपीय क्षेत्र को कवर करता है।
2. फ्लाईवे एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें प्रवासी प्रजातियों का समूह अपना वार्षिक चक्र-प्रजनन, मॉलिंग, स्टेजिंग और गैर-प्रजनन को पूरा करता है।
3. विश्व में कुल पांच फ्लाईवे हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

24. रबर बोर्ड के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह रबर अधिनियम, 1947 के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है।
2. इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

25. क्वासर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. क्वासर एक अत्यंत सक्रिय और चमकदार प्रकार का सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियस है।
2. ऐसा माना जाता है कि क्वासर ब्रह्मांड के उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां पदार्थ का बड़े पैमाने पर घनत्व औसत से बहुत अधिक है।
3. ये ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे चमकदार, शक्तिशाली और जीवंत वस्तुओं में से हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

26. रोडामाइन-बी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक पानी में घुलनशील रासायनिक यौगिक है।
2. यह आमतौर पर कपड़ा, कागज, चमड़ा और पेंट उद्योग में रंगाई के लिए एक रंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाने वाला रसायन है जो लाल और गुलाबी रंग प्राप्त करने में मदद करता है।
3. यह विशेष रूप से खतरनाक हो जाता है जब इसे खाद्य

उत्पादों के साथ मिलाया जाता है, जिससे समय के साथ कैंसर और ट्यूमर होता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

27. रायसीना डायलॉग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य दुनिया के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना है।
2. यह 2015 से प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
3. 2024 संस्करण का विषय "चतुरंग: संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण" है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

28. निएंडरथल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I:
निएंडरथल पुरातन मानवों की एक विलुप्त प्रजाति है जो लगभग 40,000 साल पहले तक उत्तरी अमेरिका में रहते थे।

कथन II:
निएंडरथल अंततः विलुप्त होने से पहले लंबे समय तक आधुनिक मनुष्यों के साथ सह-अस्तित्व में थे।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है।
(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I के लिए सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन-I सही है किन्तु कथन-II गलत है।
(d) कथन-I गलत है किन्तु कथन-II सही है।

29. ग्रीन एनाकोंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वजन और लंबाई के आधार पर यह दुनिया का सबसे बड़ा सर्प है।
2. इनका मूल स्थान उत्तरी अमेरिका है, तथा यह आम तौर पर पर्णपाती वनों में पाये जाते हैं।
3. यह कंस्ट्रिक्टर्स परिवार का सदस्य है, जो बहुत जहरीले सांप होते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

30. तुअर-दाल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक महत्वपूर्ण फलीदार फसल और प्रोटीन युक्त भोजन है जिसे भारत में मुख्य रूप से दाल के रूप में उपभोग किया जाता है।
2. यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है, जिसकी खेती मुख्य रूप से भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में की जाती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

31. उचित एवं लाभकारी मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सरकार द्वारा घोषित मूल्य है, जिसे मिलें किसानों को उनसे खरीदे गए गन्ने के लिए भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।
2. एफआरपी कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा तय किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

32. सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कैबिनेट समितियाँ संविधानेतर होती हैं।
2. सीसीएस का नेतृत्व लोक सभा अध्यक्ष करता है।
3. सीसीएस भारत की रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का निस्तारण करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

33. पॉजिट्रोनियम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पॉजिट्रोनियम एक अल्पकालिक हाइड्रोजन जैसा परमाणु है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और उसके समकक्ष एंटीमैटर, एक पॉजिट्रॉन होता है।
2. इसका जीवन बहुत छोटा होने के कारण यह 142 नैनो-सेकंड के आधे जीवन में नष्ट हो जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

34. चित्तीदार हिरण (चीतल) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चित्तीदार हिरण या चीतल भारतीय उपमहाद्वीप की मूल स्थानीय हिरण प्रजाति है।
2. यह एशिया में व्यापक रूप से पायी जाती है, विशेष रूप से भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान के एक छोटे समूह में।
3. इसे IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

35. ब्लैनेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ब्लैनेट अन्य ग्रहों के समान हैं, लेकिन वे किसी तारे या भूरे बौने के बजाय एक ब्लैक होल की परिक्रमा करते हैं।
2. उनके पास अपने गुरुत्वाकर्षण द्वारा गोल होने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान है, लेकिन थर्मोन्यूक्लियर संलयन शुरू करने और तारे बनने के लिए पर्याप्त नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

36. एडवर्ड्स सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह क्रोमोसोम 18 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होने वाला एक ऑटोसोमल क्रोमोसोमल विकार है।
2. यह एक बहुत ही गंभीर आनुवंशिक स्थिति है जो बच्चे के शरीर के विकास और वृद्धि को प्रभावित करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

37. G-33 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. G-33 (कृषि क्षेत्र में विशेष उत्पादों के मित्र) विकसित और विकासशील देशों का एक गठबंधन है।
2. भारत इस समूह का सदस्य नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

38. गर्भिनी-GA2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह दूसरी और तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला में भ्रूण की समयावधि का सटीक निर्धारण करने वाला पहला भारत-विशिष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मॉडल है।
2. इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (टीएचएसटीआई), फरीदाबाद के शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

39. एरोसोल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वे हवा या गैस में निलंबित छोटे ठोस या तरल कण हैं।
2. एरोसोल प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे कोहरा या ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैस या कृत्रिम जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से निकलने वाला धुआं।
3. एरोसोल कण या तो सीधे वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं (प्राथमिक एरोसोल) या वायुमंडल में पूर्ववर्ती गैसों (द्वितीयक एरोसोल) से उत्पन्न होते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

40. अतिरिक्त टियर-1 (AT-1) बांड के संदर्भ में निम्नलिखित

कथनों पर विचार कीजिए:
1. AT-1 बांड स्थायी बांड हैं जिनकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं है।
2. इन बांड्स में निवेशकों को उनका मूलधन वापस मिल जाता है।
3. AT-1 बांड पर अन्य बांड की तुलना में कम ब्याज दर होती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

41. जनरल डायरी (GD) और प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रत्येक एफआईआर की एक प्रति वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है जबकि जीडी की प्रति न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी जाती है, हालांकि इसकी प्रति एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भेजी जाती है।
2. जनरल डायरी एक आंतरिक पुलिस रिकॉर्ड है, जबकि एफआईआर के मामले में, इनकी एक प्रति शिकायतकर्ता को प्रदान की जाएगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

42. निम्नलिखित देशों को नाममात्र जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के संदर्भ में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. भारत
2. चीन
3. यूएसए
4. जर्मनी
5. जापान

सही उत्तर चुनिए:
(a) 3-2-4-1-5
(b) 3-2-5-1-4
(c) 3-2-4-5-1
(d) 3-2-5-4-1

43. राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह मूल्य सूचकांक है जो सभी बिक्री चैनलों से कीमतों को शामिल करता है और कोयला ब्लॉकों के वाणिज्यिक खनन में नीलामी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2. सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है।
3. सूचकांक की अवधारणा और डिजाइन केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान (CMPDI) द्वारा विकसित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

44. भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति *(SIDE)* रिपोर्ट, 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे नीति आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष दो बार जारी किया जाता है।
2. अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटलीकृत देश है।
3. रैंकिंग कनेक्ट, हार्नेस, इनोवेट, प्रोटेक्ट और सस्टेन (CHIPS) ढांचे के 5 स्तंभों पर आधारित है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

45. वैभव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसका उद्देश्य भारतीय STEMM प्रवासी भारतीयों को भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से जोड़ना है।
2. यह योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
3. यह फेलोशिप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में काम करने वाले सभी वैज्ञानिकों के लिए है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

46. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे 1974 में तेल की आपूर्ति में बड़े व्यवधानों पर सामूहिक प्रतिक्रिया के समन्वय में मदद करने के लिए बनाया गया था।
2. IEA में पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आर्थिक सहयोग

और विकास संगठन (OECD) की सदस्यता एक शर्त है।
3. उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट IEA की एक पहल है।

उपर्युक्त कितने कथन गलत हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

47. इंडियन स्कीमर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक प्रवासी प्रजाति है जो रूस और पूर्वी एशिया में प्रजनन करती है।
2. वे अपना अधिकांश जीवन चक्र वृक्षरेखा के ऊपर बिताते हैं।
3. यह प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन (सीएमएस) के तहत सूचीबद्ध है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

48. अनुच्छेद 142 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह उन स्थितियों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को असाधारण अधिकार प्रदान करता है जहां मौजूदा कानूनों या कानूनों में पर्याप्त उपचार की कमी हो सकती है।
2. अनुच्छेद 142 के तहत जारी किए गए आदेशों या डिक्री को संसद द्वारा स्थापित मौजूदा कानूनों का पालन करना होगा।
3. अनुच्छेद 142 सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं है और इसे प्रत्येक मामले में लागू नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

49 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत या विदेश में पारस्परिक लाभ के लिए सहकारी विपण न के विकास के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के साथ सहयोग करना।
2. वेयरहाउसिंग अधिनियम के तहत वेयरहाउस के रूप में कार्य करना।
3. सहकारी संस्थाओं की विपणन और व्यापारिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना, समन्वय करना और बढ़ावा देना।
4. कृषि उपज और अन्य वस्तुओं की ग्रेडिंग, पैकिंग, मानकीकरण, वैज्ञानिक उपचार और प्रक्रिया के अंतर्गत आता है।

उपर्युक्त में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ *(NAFED)* के उद्देश्य हैं?
(a) केवल 1, 3 और 4
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

50. आउटकम बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा धन के परिव्यय को उनके अपेक्षित परिणामों से जोड़ता है।
2. आउटकम बजटिंग की अवधारणा भारत में 2005 में शुरू की गई थी।
3. सभी राज्य विधानसभाओं के लिए आउटकम बजटिंग का पालन करना अनिवार्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

51. यू-रिपोर्ट, युवा लोगों के लिए एक डिजिटल समुदाय, पहल है:
(a) क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (CAN)
(b) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)
(c) संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF)
(d) संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)

52. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह 1987 में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है।
2. यह संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है।
3. यह एक सांस्कृतिक संग्राहक और प्राचीन ग्रंथों का संरक्षक है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

53. *INSAT-3DS* मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर

विचार कीजिए:
1. इसे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV) का उपयोग करके लॉन्च किया गया था।
2. यह मिशन पूरी तरह से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा वित्त पोषित है।
3. यह मिशन पर्यावरण निगरानी, मौसम पूर्वानुमान और आपदा राहत कार्यों में सहायता करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

54. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड *(NBWL)* के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है जिसमें सेना प्रमुख और रक्षा सचिव सहित अन्य सदस्य होते हैं।
2. इसका गठन भारतीय वन्यजीव बोर्ड के स्थान पर वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किया गया था।
3. बोर्ड को वर्ष में कम से कम दो बार बैठके करना होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

55. बलीन व्हेल दांतेदार व्हेल से किस प्रकार भिन्न हैं?
1. दांतेदार व्हेल समुद्री जल से शिकार को छानती हैं जबकि बलीन व्हेल सक्रिय रूप से मछली, स्क्विड और अन्य समुद्री जीवों का शिकार करती हैं।
2. ब्लू व्हेल एक बलीन व्हेल है जबकि डॉल्फिन और पोर्पोइज दांतेदार व्हेल से संबंधित हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

56. हाल ही में समाचारों में देखा जाने वाला मोरोधारो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
(a) धोलावीरा के पास हाल ही में खोजा गया हड़प्पा स्थल
(b) यह कॉटन कैंडी में पाया जाने वाला एक कैंसर जनित पदार्थ है।
(c) हाल ही में रूसी सेना द्वारा यूक्रेन में कब्जा किया गया एक शहर है।
(d) अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी में स्थित एक सबसे बड़ा बौद्ध मठ

57. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. AWBI पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत स्थापित एक वैधानिक सलाहकार निकाय है।
2. AWBI पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तत्वावधान में काम करता है।
3. राजकुमारी अमृत कौर ने बोर्ड की स्थापना का नेतृत्व किया, जिसका मुख्यालय चेन्नई में था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने **गलत** हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

58. समाचारों में रहे निम्नलिखित शहर और उनसे सम्बन्धित देशों पर विचार कीजिए:

	शहर	–	देश
1.	राफा	–	सीरिया
2.	सिनाई	–	सऊदी अरब
3.	बेलगोरोड	–	बेल्जियम
4.	एंगोस्टूरा	–	टर्की

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

59. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. मीथेन
2. ब्लैक कार्बन
3. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन
4. ग्राउण्ड लेवल ओजोन

उपर्युक्त में से किसे सुपर प्रदूषक के रूप में जाना जाता है?
(a) केवल 1, 3 और 4
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1, 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

60. घड़ियाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह अनुसूची I की प्रजाति है और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है।
2. गंडक घड़ियाल रिकवरी परियोजना राष्ट्रीय जैव विविध

ता प्राधिकरण (एनबीए) की एक पहल है।
3. वे खारे पानी में रहते हैं और भोजन के लिए विशेष रूप से मछलियों पर निर्भर रहते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

61. एलोरा गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. एलोरा की गुफाएँ महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं।
2. गुफाओं को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
3. क्षेत्र की स्थलाकृति अर्धवृत्त के आकार में एक चट्टानी पठार से बनी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

62. राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है।
2. संविधान ने राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल निधारित किया है।
3. राष्ट्रपति कला, विज्ञान, खेल और समाज सेवा में अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामांकित करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

63. व्हिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. व्हिप शब्द का उल्लेख न तो भारत के संविधान में, न सदन के नियमों में और न ही संसदीय कानून में किया गया है।
2. भारत में सभी दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

64. अवरोधन आदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. गृह सचिव, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सूचना को रोकने, निगरानी करने और डिक्रिप्ट करने के आदेशों को निष्पादित करने वाली नोडल एजेंसी है।
2. निगरानी डेटा को छह माह के अन्दर हटाना होता है।
3. आईटी नियम, 2009 उस प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट करते हैं जिनका सरकार को सूचना के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्शन का पालन करना होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

65. बढ़ते समुद्र और भीषण तूफान धीरे-धीरे तुवालु द्वीप को डुबो रहे हैं। तुवालु स्थित है?
(a) आर्कटिक महासागर
(b) प्रशांत महासागर
(c) हिंद महासागर
(d) दक्षिणी महासागर

66. बौद्ध और जैन साहित्य के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बौद्ध कथाएँ और साहित्य चरित्र में उपदेशात्मक हैं, जबकि जैन कथाएँ नहीं हैं।
2. प्राचीन/मध्यकालीन बौद्ध साहित्य संस्कृत में उपलब्ध है, जबकि प्राचीन/मध्यकालीन जैन साहित्य की रचना संस्कृत में नहीं की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

67. भक्ति साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ज्ञानेश्वर एक मराठी भक्ति कवि थे।
2. तुकाराम, ज्ञानेश्वर के समकालीन थे जिन्होंने गुजराती में भक्ति गद्य लिखा था।
3. एकनाथ ने काव्यात्मक आख्यान और भक्तिपूर्ण अभंग लिखे।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक

(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

68. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संगीत से संबंधित गंधर्व वेद अथर्ववेद का उपवेद है।
2. जैमिनी ब्राह्मण सामूहिक रूप से नृत्य और संगीत की बात करता है।
3. ऐतरेय आरण्यक संगीत वाद्ययंत्रों की चर्चा करता है।
4. संगीत सिद्धांत का पहला उल्लेख भरत के नाट्यशास्त्र में किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

69. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नाट्य शास्त्र मुखौटों और रंगमंच में उनके उपयोग के बारे में बताता है।
2. सिन्धु घाटी सभ्यता में मुखौटों के प्रयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।
3. पूर्वी भारत में चौथी शताब्दी के टेराकोटा मुखौटे की खुदाई के दौरान खोज की गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

70. तीन सिरों वाले रॉककट शिवा, महेश-मूर्ति, किस गुफा में पायी जा सकती है?
(a) अजंता
(b) एलोरा
(c) एलीफेंटा
(d) मालोवा

71. पेट्राड्यूरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसमें गुंबद जैसी संरचनाओं को सहारा देने के लिए लंबे स्तंभों की एक श्रृंखला होती है।
2. शाहजहाँ द्वारा इसका विस्तृत उपयोग ताज महल में किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने **गलत** हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

72. तिरुमलाईपुरम पेंटिंग को संरक्षण दिया गया:
(a) विजयनगर साम्राज्य
(b) पांड्य
(c) चोल
(d) पल्लव

73. "मसीतखानी" शैली किससे सम्बंधित है:
(a) दारा सिकोह
(b) जहांगीर
(c) इब्राहीम लोदी
(d) तानसेन

74. भारत में 19वीं सदी के दौरान राजनीतिक संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बंगभाषा प्रकाशिका सभा का गठन राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा किया गया था।
2. बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना सिसिर कुमार घोष ने लंदन में की थी।
3. इंडियन लीग की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में की थी.

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

75. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अठारहवीं सदी के अंत और उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में जोतदारों के नाम से जाने जाने वाले धनी किसानों के एक वर्ग ने गांवों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली और भूमि के विशाल क्षेत्रों का अधिग्रहण कर लिया।
2. जोतदार जमींदारों के प्रति वफादार थे और उन्हें रैयतों से राजस्व इकट्ठा करने में मदद करते थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा **असत्य** हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

76. मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा अनुपस्थित थी।
2. मौर्य शासन का अपने साम्राज्य के सभी क्षेत्रों पर समान नियंत्रण था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1

(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

77. संविधान के अनुच्छेद 87 में निहित भारत की संसद में राष्ट्रपति के संबोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति का अभिभाषण पूर्व वर्ष की सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है और आने वाले वर्ष के लिए व्यापक शासन एजेंडा निर्धारित करता है।
2. राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, दोनों सदन राष्ट्रपति को उनके भाषण के लिए धन्यवाद देने के लिए एक प्रस्ताव पेश करते हैं।
3. अब तक संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन पारित होने का कोई उदाहरण नहीं है.

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

78. राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का संविधान राज्य सभा के मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई योग्यता निर्दिष्ट नहीं करता है।
2. राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को वे सभी शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जिनके लिए निर्वाचित सांसद हकदार होते हैं।
3. उन्हें भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

79. भारत के उपराष्ट्रपति पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान कहता है कि उपराष्ट्रपति लोक सभा का पदेन अध्यक्ष होगा।
2. भारत के उपराष्ट्रपति का पद वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद आता है।
3. उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

80. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूमि सुधारों को जांच से छूट दी गई
2. संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा प्रदान की गई।
3. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाया गया।

भारत के संविधान के पहले संशोधन में उपर्युक्त में से कौन सा प्रावधान शामिल था?
(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) 1, 2 और 3
(d) कोई भी नहीं

81. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो संविधान केंद्र सरकार को कानून बनाने की अनुमति देता है।
2. किसी राज्य का राज्यपाल केवल राष्ट्रपति की मंजूरी से ही अध्यादेश जारी कर सकता है।
3. किसी अध्यादेश को केवल एक बार ही पुन: प्रख्यापित किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से **गलत** है/हैं?
(a) केवल 3
(b) केवल 2
(c) 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

82. राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्यसभा का सभापति सदस्यों में से उपाध्यक्षों का एक पैनल नामित करता है।
2. राज्यसभा के सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में पैनल का कोई भी सदस्य सदन की अध्यक्षता कर सकता है।
3. राज्यसभा के नियमों के अनुसार, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य पैनल के सदस्य बनने के पात्र नहीं होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

83. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रमुख है, और

सभी मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है।

2. जबकि राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय किसी की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है, वह केवल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही किसी मंत्री की नियुक्ति कर सकता है।
3. त्रिशंकु विधानसभा में राज्यपाल यह निर्धारित कर सकते हैं कि किसी पार्टी को अपना बहुमत साबित करने के लिए कितना समय चाहिए या ऐसा करने के लिए किस पार्टी को पहले आमंत्रित करना चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

84. भारतीय रिजर्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य कमजोर बैंकों के संचालन की अधिक बारीकी से निगरानी करना और उन्हें प्रोत्साहित करना है पूंजी बचाएं और जोखिम से बचें।
2. यह वित्तीय रूप से कमजोर बैंकों द्वारा लाभांश वितरण और शाखाओं के विस्तार पर कुछ प्रतिबंध लगाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा **गलत** है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

85. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संबंध में अदालतों द्वारा अक्सर "अनिवार्यता का सिद्धांत" का उपयोग किया जाता है?

(a) अनुच्छेद 14
(b) अनुच्छेद 19
(c) अनुच्छेद 21
(d) अनुच्छेद 25

86. सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ), जिसे अक्सर बजट और आर्थिक सर्वेक्षणों में देखा जाता है, अनिवार्य रूप से संदर्भित करता है:

(a) जनता के हाथों में धन का संचलन
(b) बैंकिंग क्षेत्र का पूंजीकरण
(c) उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में प्रत्यक्ष खुदरा निवेश
(d) बुनियादी ढांचे या टिकाऊ आर्थिक संपत्तियों का निर्माण

87. लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला संबंधित है:

(a) अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से
(b) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से
(c) संसद सदस्य की अयोग्यता से
(d) भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार से।

88. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सरकार के विभिन्न स्तर समान नागरिकों पर शासन करते हैं, लेकिन प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है।
2. सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार की आम तौर पर संवैधानिक गारंटी है।
3. सरकार के प्रत्येक स्तर को अपने सभी वित्तीय संसाधन दूसरे स्तर से स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने चाहिए।

उपर्युक्त में से कौन सी संघवाद की विशेषताएं हैं?

(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

89. संघीय सरकार का तात्पर्य ऐसी सरकार से है:

(a) केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है और संघीय और राज्य न्यायपालिकाओं के बीच भी
(b) सभी शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं और क्षेत्रीय सरकारें अपना अधिकार राष्ट्रीय सरकार से प्राप्त करती हैं।
(c) बड़ी संख्या में शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं और क्षेत्रीय सरकारें, कुछ स्वतंत्र शक्तियों के साथ, राष्ट्रीय सरकार से अपना अधिकार प्राप्त करती हैं।
(d) संविधान द्वारा शक्तियों को राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य विभाजित किया जाता है और दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

90. भारत के संविधान के भाग *IX* में इसके संदर्भ में प्रावधान हैं:

1. पंचायतें
2. नगर पालिकाएँ
3. सहकारी समितियाँ

सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

91. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत जारी किए जाते हैं।
2. भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के पास राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को लागू करने और यह

सुनिश्चित करने की वैधानिक शक्ति है कि उनका नेतृत्व प्रत्येक पांच वर्ष में नवीनीकृत, परिवर्तित या पुन: निर्वाचित हो सके।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा **गलत** है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

92. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 धार्मिक आस्था वाले संगठनों को राजनीतिक दलों के रूप में पंजीकृत होने से रोकता है।
2. भारत का संविधान भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति प्रदान करता है।
3. चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 राजनीतिक दलों को धार्मिक या सांप्रदायिक आस्था वाले प्रतीक रखने से रोकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

93. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक *(CAG)* के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. CAG एक संवैधानिक निकाय है, जो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख है।
2. CAG का कर्तव्य वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है।
3. CAG सार्वजनिक धन का संरक्षक है और देश की वित्तीय प्रणाली को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नियंत्रित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

94. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सभी सदस्यों का चुनाव सदन द्वारा किया जाना चाहिए।
2. यह अपनी रिपोर्ट सदन के अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत करता है।
3. इसे केंद्र के किसी भी मंत्रालय के साथ एक सलाहकार समिति का दर्जा प्राप्त होना चाहिए।

उपर्युक्त से कौन सी संसदीय समितियों की कुछ सामान्य विशेषताएँ हैं/हैं?

(a) केवल 2
(b) 1 और 2
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

95. शीतोष्ण वर्षावनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. समशीतोष्ण वर्षावन अधिकतर तटीय, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
2. ठंडा तापमान और अधिक स्थिर जलवायु अपघटन को धीमा कर देती है, जिससे अधिक सामग्री जमा हो जाती है।
3. समशीतोष्ण वर्षावन विश्व में सबसे अधिक जैविक रूप से विविधतापूर्ण स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

96. निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र का हिस्सा नहीं है?

(a) ओन्टारियो झील
(b) ग्रेट स्लेव लेक
(c) मिशिगन झील
(d) एरी झील

97. निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'डोलड्रम्स' का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

(a) पृथ्वी का ठंडा क्षेत्र जहां वायुमंडलीय परिसंचरण बहुत कम है।
(b) भूमध्यरेखीय क्षेत्र में शांत क्षेत्र की बेल्ट जहां विद्यमान व्यापारिक पवनें मिलती हैं।
(c) हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां अक्सर चक्रवात उत्पन्न होते हैं।
(d) उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च दबाव क्षेत्र जहां पछुआ पवनें उत्पन्न होती हैं।

98. वलित पर्वतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वलित पर्वत तब बनते हैं जब बड़े क्षेत्र टूट जाते हैं और लंबवत विस्थापित हो जाते हैं।
2. उनमें शंक्वाकार चोटियाँ होने की संभावना सबसे कम है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन **गलत** है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

99. थर्मोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. थर्मोस्फीयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बहुत तेजी से घटता है।
2. पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इसी परत द्वारा वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं।
3. अंतरिक्ष शटल और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन दोनों थर्मोस्फीयर में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

100. उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उद्भव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ हैं?
1. क्षोभमंडल के माध्यम से अस्थिर स्थिति
2. मजबूत कोरिओलिस बल
3. तीव्र ऊर्ध्वाधर पवन
4. गर्म और आर्द्र राशि की निरंतर आपूर्ति।

सही उत्तर चुनिए:
(a) 1, 2 और 3
(b) 1, 2 और 4
(c) 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर

1	a	21	a	41	c	61	d	81	c
2	c	22	c	42	c	62	b	82	b
3	d	23	b	43	a	63	c	83	b
4	a	24	a	44	b	64	c	84	d
5	b	25	c	45	b	65	b	85	d
6	a	26	c	46	a	66	d	86	d
7	c	27	b	47	d	67	b	87	c
8	b	28	d	48	c	68	c	88	b
9	b	29	a	49	d	69	b	89	d
10	b	30	c	50	b	70	c	90	d
11	b	31	a	51	c	71	a	91	b
12	b	32	b	52	b	72	b	92	b
13	b	33	c	53	c	73	d	93	b
14	c	34	c	54	c	74	a	94	a
15	c	35	c	55	b	75	b	95	b
16	d	36	c	56	a	76	d	96	b
17	c	37	d	57	b	77	b	97	b
18	d	38	c	58	d	78	a	98	c
19	d	39	c	59	d	79	a	99	b
20	c	40	a	60	a	80	c	100	b

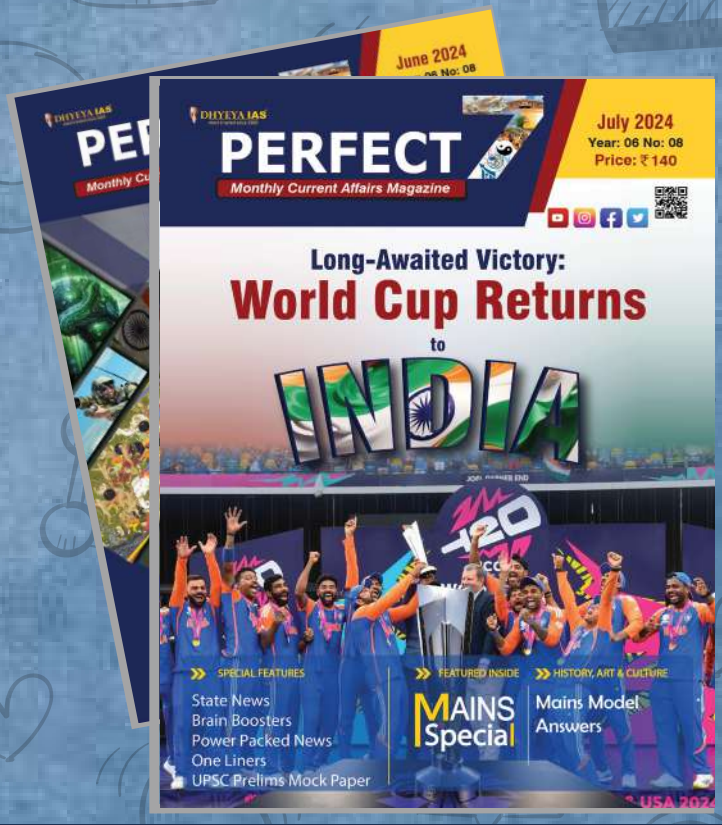

ध्येयIAS®
most trusted since 2003
MORE ELABORATE
MORE PRECISE
MORE PERFECT
June 2024
DHYEYA IAS
PERFECT 7
Monthly Current Affairs Magazine
July 2024
Year: 06 No: 08
Price: ₹140
Long-Awaited Victory:
World Cup Returns
to
INDIA
SPECIAL FEATURES
State News
Brain Boosters
Power Packed News
One Liners
UPSC Prelims Mock Paper
FEATURED INSIDE
MAINS Special
HISTORY, ART & CULTURE
Mains Model Answers
Your
'Perfect'
Preparation Partner!
OUR PROGRAMMES
आरण्यक
Centre for Excellence
Centre for Excellence
IAS/PCS MAINS MENTORSHIP
अभिव्यक्ति
PERFECT 7
Monthly Current Affairs Magazine
ध्येयPCS
ध्येय TV
YOUTUBE CHANNEL
EDUCATION
UPSC
IPS
LEARNING
TRAINING
IAS
ADYATAN "अद्यतन"
CURRENT AFFAIRS PROGRAMME
लक्ष्यभेद
TEST SERIES PROGRAMME
UDAAN
A journey to success
बातें यूपी की
ध्येय LAW®
An enterprise of Dhyeya IAS
For More Information: 9369227134, 9506256789

ध्येयIAS®
most trusted since 2003
UDAAN
A journey to success
TICKET
TO
LBSNAA
IAS/PCS की तैयारी
ग्रेजुएशन के साथ
DHYEYA IAS OLYMPIAD
ENTRANCE TEST 2024
FREE
SCHOLARSHIP
UPTO
100%
25TH
AUGUST
HURRY
UP!
REGISTER
NOW
9319991061
A-12, SECTOR J, ALIGANJ, LUCKNOW